CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी सहजानन्द सरस्वती

का सामाजिक-आर्थिक चिन्तन

दलीप कुमार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भारतीय सामाजिक-आर्थिक संरचना में स्वामी सहजानन्द सरस्वती का वर्ग दृष्टिकोण भारतीय विकास के क्रम में उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप जन्मा है। किसान वर्ग की व्यक्तिवादिता को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है कि किसान अपने छोटे से खेत के टुकड़े के आगे नहीं देख पाता। आज ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, खेत-मज़दूरों की समस्याएं महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण व्याप्त हिंसा, जातीय दंगा, क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हो रहा है। इसका एक मात्र कारण है भारतीय जनवाद के अनुसार आर्थिक सुधारों की कमी। हदबन्दी, फाजिल जमीनों का भूमिहीनों में बंटवारा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबन्धन सघन खेती की व्यवस्था आदि के कारगर ढंग से लागू न करने का परिणाम है कि कृषि क्षेत्रों में समस्याएं बनी हुई हैं।

यह पुस्तक स्वामी जी जैसे महान और अडिग किसान योद्धा एवं जननायक की आर्थिक एवं सामाजिक विचारधारा सामान्य जन-समुदाय तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम बन सकेगा। इनके तमाम आर्थिक सिद्धांत एवं सुझाव वर्तमान आर्थिक परिवेश में सत्य परिलक्षित हो रही है। वर्तमान समाज में फैली आर्थिक विषमता और भूमि संबंधी विवादों को देखते हुए स्वामी सहजानन्द सरस्वती के सुझावों पर शिद्दत से सोचने-विचारने और उसे कारगर रूप से लागू करने की आवश्यकता है ताकि खेत-मजदूरों की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। हमें पूर्ण विश्वास है कि किसानों के सामाजिक-आर्थिक चिंतन पर कार्य करने वाले शोधकर्ताओं के लिए यह पुस्तक मार्ग दर्शन का कार्य करती रहेगी।

ISBN : 81-7827-0080-0

मूल्यः रु. 350

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

7.3

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ॐ

पूज्य स्वामी आनन्दानन्द सरस्वती जी

को सादर समर्पित:

- दिलीप कुमार 24/6/2019

09213979078.

श्री अम्बिका फाउण्डेशन
कोपा कलां, (नौबतपुर)
पटना, बिहार-801109

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी सहजानन्द सरस्वती
का सामाजिक-आर्थिक चिन्तन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी सहजानन्द सरस्वती का सामाजिक-आर्थिक चिन्तन

दलीप कुमार

मानक
पब्लिकेशन्स (प्रा.) लि.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रस्तुत शोधग्रन्थ का प्रकाशन भारतीय सामाजिक विज्ञानअनुसंधान परिषद् के आर्थिक सहयोग से साकार हुआ है। इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किये गये तथ्यों, मतों अथवा निस्सृत निष्कर्मों का उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण लेखक पर है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् इसके लिये उतरदायित्व नहीं रखता।

यह पुस्तक पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा स्वीकृत एवं पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त शोध प्रबन्ध है।

ISBN : 81-7827-0080-0

© लेखक, 2001

लेखक : दलीप कुमार
प्रथम संस्करण : 2001
प्रकाशक : **मानक पब्लिकेशन्स प्रा. लि.**
जी-19, विजय चौक, लक्ष्मी नगर
दिल्ली-110 092 फोन : 2453894
अक्षर संयोजक : एस.पी. प्रिंटेक, दिल्ली-110 092
मुद्रक : नाईस प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली

Socio-Economic Philosophy of Swami Sahajanand Saraswati
by Dalip Kumar

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

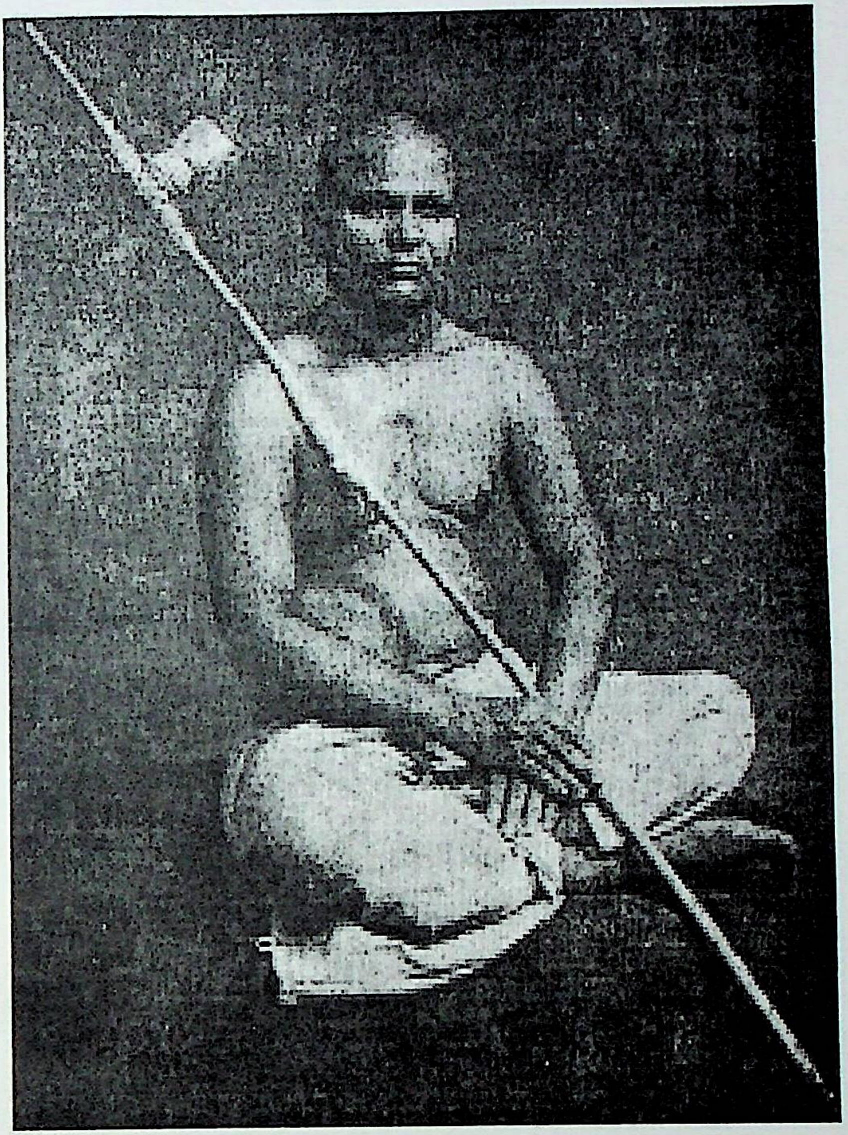

जननायक स्वामी सहजानन्द सरस्वती

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

समर्पण

अपने प्राणोपम छोटे भाई स्वर्गीय अशोक
कुमार को जिसे अपने जीवन के केवल सात
वसंत ही देखने का सौभाग्य मिला।

दलीप

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्राक्कथन

डा. दलीप कुमार ने प्रस्तुत शोध-ग्रंथ 'स्वामी सहजानन्द सरस्वती के सामाजिक-आर्थिक चिन्तन' में स्वामी जी के अर्थगत विचारों को समाहित करते हुए उनकी सामाजिक उपयोगिता की पहचान की है। उनकी यह विचारधारा आंधुनिक युग के अर्थशास्त्रियों के सम्मुख आर्थिक क्षेत्र के चिन्तन के नवीन आयाम उपस्थित करती है। यह विद्वतापूर्ण विवेचन एक प्रकार से स्वामी जी की सहज परिवर्तनकारी आर्थिक भूमिका पर आधारित समाज के भविष्य एवं भविष्य के समाज को आंकने का प्रयास है।

ऐसे युग में जबकि सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य गहरे अवमूल्यन के दबाव में निरन्तर निरर्थक होकर नई दिशा की तलाश कर रहे हैं, स्वामी जी के ये विचार आर्थिक चिन्तन के क्षेत्र में एक नई दिशा देंगे। स्वामी जी ने समाज के परिप्रेक्ष्य में जितना आर्थिक चिन्तन किया, वह भले ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों को चिन्तन की नई पद्धति से विभिन्न-सा लगता है, कुछेक को निष्प्रयोजन सा प्रतीत होता है, किन्तु लेखक ने उनके चिन्तन को मथकर जो तथ्य उभारकर प्रस्तुत किया है वह भावी चिन्तकों को एक नई दिशा प्रदान करेगा।

स्वामी जी की दृष्टि भारतीय किसानों के मसीहा की दृष्टि है। उनकी यह दृष्टि उनके कर्मठ जीवन के 30 वर्षों की सम-विषम परिस्थितियों के संघातों के मध्य जन्मी एवं विकसित हुई है। आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी इस दृष्टि को परिमूर्त तो नहीं कहा जा सकता, पर मेरा इतना विश्वास अवश्य है कि उनका यह दृष्टिकोण विकास की नई दिशाओं का मार्ग अवश्य प्रशस्त करेगा। स्वामी जी की मूल मान्यता है कि सृष्टि में विकास का जितना भी काम है इसका मूल आधार मानव की श्रम की पद्धति है। श्रम शक्ति पर आधारित विकास एवं श्रमाधार पर अर्जित उपज का वास्तविक अधिकारी किसान है क्योंकि श्रम के आधार पर किसान ने ही भूमि को उत्पादन के लिए उपयोगी बनाया और श्रम के सहयोग से ही उसने मानव समाज के लिए जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रकार समस्त प्रगति के मूल्य में श्रम की प्रक्रिया ही काम करती दिखाई देती है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी जी की मान्यता है कि सीधे उत्पादन करने वाले कृषक की दृष्टि से सामाजिक विकास का ढांचा बनना चाहिये, न कि उत्पादन पर अधिकार करने वाले की दृष्टि से आर्थिक नीतियां तय होनी चाहिये, स्वामी जी की भू-स्वामित्व की धारणा का आधार यही है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का मूल प्रयास भी यही है। स्वामी जी का आर्थिक सामाजिक-चिन्तन इस भू-स्वामित्व की मूल समस्या पर आधारित है। उनका विश्वास है कि राजसत्ता की अकर्मण्यता के कारण यह समस्या दिन-प्रतिदिन और अधिक विषम होती जा रही है। भारत के कुछ राज्यों में भूमि सुधार की समस्या काफी कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। इस भूमि सुधार की समस्या कृषि के साथ-साथ आर्थिक जगत् में काफी बाधक हैं जिसका ज्वलंत उदाहरण बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान आदि राज्यों में देखा जा सकता है।

लेखक ने स्वामी जी के विचारों को आधार मानकर इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का सराहनी प्रयास किया है। उदाहरण के रूप में खेत-मजदूर के प्रति उपेक्षा भरा दृष्टिकोण, परम्परागत जाति प्रथा, पूंजीवादी मान्यता, जमींदारों द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक शोषण, सरकार की कराधान नीति आदि में परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। वर्गहीन समाज की मान्यता, किसान-मजदूरों के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण, देश के आर्थिक विकास में किसानों की क्रांतिकारी भूमिका—आदि उपायों को जब तक कार्यान्वित नहीं किया जाएगा तब तक किसानों की दशा प्रत्येक दृष्टिकोण से दयनीय ही बनी रहेगी।

मेरे दृष्टिकोण से यह पुस्तक किसानों, ग्रामीण कार्यकर्त्ता, किसान नेता, कृषि क्षेत्र में शोधकर्त्ता, कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि के क्षेत्र में नीति निर्धारकों के लिए अति उपयोगी होगी।

मुझे इस पुस्तक का प्राक्कथन लिखने में काफी प्रसन्नता हो रही है।

जी. एस. भल्ला

(प्रो. जी.एस. भल्ला)
जवाहरलाल नेहरू विश्वविघालय
नई दिल्ली

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भूमिका

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध जो ''स्वामी सहजानन्द सरस्वती का सामाजिक-आर्थिक चिन्तन शीर्षक के अन्दर समाहित कर लिखा गया है, प्रथम ऐसा लग सकता है कि एक व्यक्ति के, जिसके ऊपर अन्य कोई कई शोधकर्ता कार्य कर चुके हैं, व्यक्तित्व और कृतित्व की ही पुनरावृत्ति होगी। इस तरह की मनः स्थिति पैदा होने के पर्याप्त कारण भी हैं, जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता मगर साथ ही एक अन्य तथ्य भी है, जो इससे अविच्छिन्न रूप से जुड़ा है और वह यह है कि स्वामीजी एक व्यक्ति के साथ-साथ संस्था भी थे, जिसका बहुआयामी स्वरूप उनके समकालीन भारत में तो प्रकट हुआ ही, उसकी प्रासंगिकता आज भी भारतीय ग्रामीण-व्यवस्था के पुनर्निर्माण में अपना महत्व बनाये हुए हैं। खास कर आजादी के पश्चात भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत विकास की जो रणनीति और कार्यनीति का प्रतिपादन करते हुए, कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व को ध्यान में रख, जब उसे लघु उद्योगों तथा लद्यु व्यापार के साथ प्राथमिकता की सूची में रखा गया तब ऐसा प्रतीत हुआ था कि इस नियोजित अर्थव्यवस्था में कृषि-सुधारों को प्राथमिकता देकर देश की अर्थव्यवस्था में उसे एक निर्णायक आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित होने का प्रयास किया जायेगा। और इस प्रयास में स्वामीजी के वे सपने मूर्तरूप धारण करेंगे जिनको उन्होंने 'बिहार प्रान्तीय किसान सभा का घोषणा पत्र' और 'किसानों के दावे और कार्यक्रम का खरीता' में संजोया था।

समस्या का स्वरूप

अनुभव क्या बताता है? अनुभव बताता है कि आजादी के बाद के भी करीब नौ वर्षों के जद्दोजहद के बाद 1956 में बिहार में जमींदारी का उन्मूलन किया गया। मगर स्वामीजी की मुआवजा न देने की नीति के खिलाफ भी जमींदारी को भारी मुआवजा नगद और बाण्डों के रूप में दिया गया उसी का स्वामी जी आजीवन विरोध करते रहे थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उसी तरह 'जमीन जोतने वालों की' बकाश्त, भावली आदि कृषि समस्याओं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के प्रति, जिनके लिए स्वामी जी ने संघर्ष किया और जिस संघर्ष की एक राजनीतिक दिशा भी थी, शोषणविहीन समाज और किसान-मजदूरों के राज्य की स्थापना, उनका क्या परिणाम निकला यह विषय हमेशा नई भौतिक परिस्थिति जन्य कालों में हरदम नई व्याख्या की हमसे अपेक्षा करता रहेगा। इस प्रकार बदलती तकनीक, विकसित विज्ञान और हमारे आर्थिक-सामाजिक सम्बन्धों का उनके साथ हर रोज होता नया समागम स्वामीजी के चिन्तनों को नया परिवेश प्रदान करता रहेगा। इस तरह स्वामीजी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, शोध'-कार्य चाहे कितना कर लिया जाय, उनके आर्थिक-सामाजिक दर्शन का नया परिवेश नये शोध-क्षितिज को जन्म देता रहेगा; उसे विस्तारित करता रहेगा। हो सकता है कि एक शोध-कार्य और दूसरे शोध-कार्यों में लक्ष्यों का समावेश एक-सा हो, शब्दावलियां मिलती-जुलती रहें, उद्धरण एक ही जगह से लिए गए हों मगर जब बदली परिस्थितियों के वैज्ञानिक कनवास में उन्हें तराशा जाएगा तब विश्लेषण निष्कर्ष और दिशा-निर्धारण बदल जाएगा। एक छोटा उदाहरण जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जिसके लिए स्वामीजी हमेशा लड़ते रहे, का विश्लेषण 1956 की अवधि में, जब उसे उन्मूलित किया गया था एक क्रान्तिकारी कदम लगा था तथा ऐसा लगा था कि किसान-सभा की एक अति प्रमुख मांग का कार्यान्वयन किया गया है। मगर आज के संदर्भ के उसकी मीमांसा एक दूसरी प्रतिक्रिया को ग्राह्य बना दिया है। वास्तविकता यह है कि भूमि-सुधारों को इंग्लैण्ड के *जुकरों* के ढंग के भू-स्वामी पूंजीवादी के दकियानूस रास्ते को ही भारत में आगे बढ़ाया गया, भूमि पर प्रभावी इजारेदारियों को बनाये रखा गया है जबकि गैर हाजिर मिल्कियत की ज्यादतियों पर और गैर कानूनी वसूलियों पर अंकुश लगाया गया है। जमींदारी उन्मूलन के नाम पर भूतपूर्व बिचौलियों को घरेलू फार्मों या खुदकाश्त के नाम पर बड़ी-बड़ी जमीने अपने पास बनाये रहने दी गयीं हैं या फिर भाड़े के मजदूरों से खुद खेती कराने के नाम पर आसामियों को बेदखल करने की इजाजत दे दी गई औरउन जमीनों पर भू-स्वामियों को हस्तांतरणीय मालिकाना अधिकार दे दिए गए। दूसरी तरफ सरकार ने जो थोड़ी बहुत जमीने अपने कब्जों में ली उनके बदले में जमींदारों को बाण्डों तथा नगद राशियों में उदारता में मुआवज़ा दिए गए। प्रो. ए. एम. खुसरों ने बताया कि भारी मात्रा में जमींदारों को मुआवजा राशि मिली जिसने भारत में वर्ग विभाजित सामाजिक स्थिति को बरकरार रखा। घनी तथा गरीब की श्रेणी बनी रही।

जमीन की मिल्कियत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (नेशनल सैम्पल सर्वे) के आंकड़ें हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भूमि का केन्द्रीयकरण ज्यों-का-त्यों बना हुआ था उसमें कुछ बढोत्तरी ही हुई है। लगभग 76 प्रतिशत छोटे सीमांत किसान

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जमीन के एक तिहाई के मालिक हैं जबकि लगभग 4 प्रतिशत बड़े किसान करीब 23 प्रतिशत जमीन के मालिक हैं। इसका प्रमाण कृषि गणना के आंकड़ों से मिलता है। कुछ राज्यों जैसे बिहार, पंजाब, गुजरात आदि में यह केन्द्रीयकरण बढ़ा था।

योजना आयोग की शोध कार्यक्रम कमेटी तैयार कराई गई मूल्यांकन रिपोर्ट दर्शाती है कि मझले से लेकर गरीब तबके तक के गैर मालिकाना काश्तकारों को आम बेदखलियों का सामना करना पड़ा है जिसमें से बहुत बड़े हिस्से के पास बेदखली के बाद खेती की कोई जमीन ही नहीं रह गई। बाद में उन्हें या तो मालिक की मनमर्जी पर निर्भर गैर रिकार्ड सुदा असामियों के रूप में दोबारा रख लिया गया था फिर वे दिहाड़ी कमाने वाले मजदूरों के रूप में उनकी कतारों में शामिल हो गए। इधर किसानों के वर्गीय ढांचे के अन्दर दूसरे सिरे पर मुट्ठी भर घनी खाते-पीते भूपति-कम काश्तकार, सरकार द्वारा हाथ में ली गई जमीन की मिल्कियत खरीदने में कामयाब हुए। वे अपनी खेती का पैमाना बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके और अनेक मामलों में मेहनत में सीधे-सीधे हिस्सेदारी से पूरी तरह से अलग हो गए। इस प्रकार की नयी घटनाओं का प्रादुर्भाव जमींदारी उन्मूलन के बाद कृषि क्षेत्र के विकास की गलत नीतियोंका परिणाम है, जो स्वामी जी के चिन्तन को इस परिवेश में व्याख्यायित करने की मांग करता है। इस प्रकार जमींदारी उन्मूलन जो स्वामी की मांग पूरी हो जाने के बाद भी जमींदारी को मिल्कियत के प्रश्न पर स्वामी जी प्रासंगिक अभी भी हैं।

स्वामीजी द्वारा उठाये नए भू-स्वामित्व में मूलगामी परिवर्त्तनों को कार्यान्वित्त न करने के कारण ही आज देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय रूप से बहुत ही असमान और सामाजिक रूप से बहुत ही संकीर्ण आधार वाले पूंजीवादी उत्पादन के आधार के सम्मान वाले तथा समूची अर्थव्यवस्था तथा खासकर ग्रामीण कृषि क्षेत्र के भावी विकास के लिए क्या निहितार्थ है? आज इसके निहितार्थ को तीन परस्पर सम्बद्ध प्रक्रियायों के रूप में देखा जा सकता है। ये प्रक्रियायें हैं; अन्य चीजों की अपेक्षा जाति पर आधारित प्रभुत्व तथा गुलामी के रिश्तों का इस्तेमाल करते अतिरिक्त मूल्य को निचोड़ने की दर बढ़ाने का रुझान, जन-उपभोग के औद्योगिक मालों के ग्रामीण बाजार के संतुलित होने का रुझान और वास्तविकता उत्पादकता के बीच खाई बढ़ते जाने का रुझान।

वास्तविकता यह है कि वर्ग-विभाजित राजसत्ता में, जिसका विरोध स्वामी जी करते थे तथा एक वर्ग-विहीन समाजवादी राजसत्ता के लिए संघर्ष करते रहे, भू-स्वामी पूंजीवादी संक्रमण की जिस क्रांतिकारी रास्ते का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर अन्य मार्क्सवादियों की भांति स्वामीजी ने भी सार रूप में दो बातों को

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

देखा था। इसमें पहली यह कि संक्रमण का यह रास्ता ज्यादा तकलीफदेह होगा, क्योंकि मालिक मजदूर के पूर्व पूंजीवादी संबंधों की दासता के चरित्र को बनाये रखेगा तथा दूसरा, अपने संकीर्ण सामाजिक आधार के चलते यह संक्रमण कहीं ज्यादा धीमा और लम्बा खींचनेवाला होगा। स्वामीजी स्पष्ट मानते थे कि प्रथम पहल में भू-स्वामी प्रभुत्व तथा गुलामी की जाति पर आधारित परम्परागत रिश्तों को बनाये ही नहीं रखते हैं, बल्कि वास्तव में उनका जानबूझ कर इस्तेमाल करते हैं ताकि श्रम शक्ति को फालतू रखना सुनिश्चित कर सकें और निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के तरीकों से अतिरिक्त मूल्य निचोड़ने की दर बढ़ा सकें। इसी कारण स्वामीजी ने किसान-सभा की सभी जातियों, धर्मों और संप्रदायों के तमाम शोषित-पीड़ित जनता का वर्ग-संगठन बनाया ताकि परम्परागत जातीय वरीयता को इस्तेमाल कर अतिरिक्त मूल्य निचोड़नेकी एक प्रक्रिया का रूप ग्रहण न कराया जा सके। इतिहास के उन उदाहरणों को स्वामी जी जानते थे, जहां परम्परागत शोषणकारी, सामाजिक सम्बन्धों के ऊपर से व्यापारी-करण का बाजार के लिए उत्पादकता का थोपा जाना, गुलामी के आधार पर इन सम्बन्धों को मजबूत करने की ओर ही ले जाता है न कि मजदूर के लिए और ज्यादा स्वतंत्रता की दिशा में द्वार खोलता है। इसी कारण स्वामी ने पूंजीवादी राजसत्ता का विरोध किया, क्योंकि वह ऐसे ही कृषि सम्बन्धों को जन्म देता।

पूर्वी यूरोप के संदर्भ में जहां भूतपूर्व भू-दास श्रम का उपयोग कर पूंजीवादी खेती की तरफ सामंती जमींदारी संक्रमण कर रहे थे, तो लेनिन ने अंर्ध-सामंती पूंजीवाद की बातें कही थीं, तो इसका सार सम्भवतः यही था। स्वामीजी ने बिना भूमि-सुधार को अपनाए भारतीय कृषि में इसी तरह की अर्ध-सामंतवादी पूंजीवादी के विकास का अन्दाजा लगाया था, जो आज ग्रामीण अर्थतंत्र में देखने को मिल रहा है।

जाति-प्रथा परम्परागत रूप से उत्पादन प्रक्रियाओं में लगे लोगों को अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारीक श्रेणीक्रम में बांटे गए अलग-अलग ग्रूपों में तोड़ने की प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती आई है। आधुनिक भू-स्वामी पूंजीपति दरिद्रीकृत किसानों के मुकाबले हरिज़न मजदूरों के साथ ज्यादा बुरा बर्ताव करता है, क्योंकि उसका हरिजन होना यह परम्परागत प्रतिकूलतायें लाद देता हैं, आदिवासी कुल के मजदूरों के साथ सबसे बुरा बर्ताव करता है और यह बात खेती के लिहाज से सबसे उन्नत इलाकों पर भी होता है। इस भावी आशंका का ही परिणाम था कि स्वामीजी के चिन्तन में झारखंड के किसानों की मांगों के स्वरूप-निर्धारण में हरिजनों से भी ज्यादा आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक अनुकूलता लाने का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रयास किया गया। भू-स्वामी विरोध की सीमा के कितनी दूर तक जा सकते हैं, उसका एक स्वरूप 'हरिजन दहन' में देखने को मिलता है। इस तरह की घटनाएं आये दिन काफी बढ़ गई हैं। स्वामीजी ऐसी परम्परागत जमींदार-जुल्म का डट कर विरोध कर रहे थे।

कृषि-क्षेत्र में उत्पादन रूपान्तरण न होने की प्रस्थापना के आधार पर यह दलील दी जा सकती है कि आखिरकार कुल कृषि उत्पादन के हिसाब से भारत की प्रगति अच्छी खासी रही है। 1951 से 1991 के दशकों में खाद्यान्न उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़कर लगभग 18 करोड़ टन यात्री तीन गुणा से भी अधिक बढ़ गया। वाकई अगर आजादी के पूर्व के गतिरोध को सामने रखकर देखें तो यह प्रगति काफी आशाजनक है। फिर भी आजादी के बाद खेती के पैदावार के बहुत ही निचले स्तर से हम प्रस्थान कर रहे हैं, उसे देखते हुए यह पैदावार उस आकांक्षा से काफी कम है जिसकी उम्मीद की जाती थी। भू-स्वामित्व की इजारेदारियां के डैनों के नीचे भारत का ईकाई भूमि पर पैदावार चीन की तुलना में तिहाई है-शायद कम है, और प्रति व्यक्ति उत्पादकता चीन के मुकाबले 66 प्रतिशत जबकि चीन की जनसंख्या भारत से ज्यादा है। इन कठिनाइयों का प्रमुख कारण भू-स्वामित्व में हजारेदारियां को कायम रखना और राजसत्ता का वैसा ही चरित्र रहना जो क्रांतिकारी भूमि-सुधार को लागू न कर सका।

स्वामीजी द्वारा मांग की जाने वाली भूमि-सुधार की प्रक्रिया की राजसत्ता द्वारा निरस्त कर दिये जाने का मूलगामी परिणाम अब प्रकट हो रहा है। भूमि पर हज़ारेदारी बनाये रखते हुए और भू-स्वामी पूंजीवाद पर निर्भर रहते हुए खेती का जो विकास किया गया उसकी बुनियादी समस्या यह रही है कि यहां ऐसे व्यावहारिक तकनीकी परिवर्तनों के एक के बाद एक निरंतर जारी चक्रों के रूप में लगातार उत्प्रेरणा की जरूरत होती है, जो भूमि के प्रति ईकाई पर एक निश्चित परिमाण में उत्पादन बढ़ा सके। किसान पूंजीवाद के अंतर्गत मिलनेवाली स्थिति के विपरीत यहां पैदावार में थोड़ी-सी या धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी निवेश के लिए प्रेरित करने के वास्ते काफी नहीं होता है। लिहाजा पैदावार बढ़ानेवाले तकनीकी बदलाव के कृषि-चक्र की सम्भावनाएं ज्यों-की त्यों प्राप्त कर ली जाती हैं, वैसे-वैसे उत्पादक निवेश घटता जाता है और निवेश के लिए उपलब्ध धन सामाजिक रूप में अनुत्पादक निवेशों में या टिकाऊ उपयोग वस्तुओं को बटोरने में जाने लगता है और यही भारत में हो रहा है। हाल के अनेक अध्ययनों ने यह उजागर किया है कि भारत में कृषि क्षेत्र में निवेश घटा है जिसका बुरा असर उत्पादन, उत्पादकता एवं रोजगार पर पड़ रहा है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

2. अध्ययन की स्थापनाएं

प्रस्तुत शोध-प्रबंध वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी के आर्थिक-सामाजिक चिन्तन में व्याप्त सूक्ष्म दृष्टि-बिन्दु की गहराई तक मापकर स्थापित करना चाहता है कि उनके द्वारा जिन मांगों को लेकर किसानों को उद्वेलित किया गया था उसका स्वरूप मात्र ढांचा परिवर्तन ही की मांग नहीं करता था, बल्कि राजसत्ता के स्वरूप में बुनियादी परिवर्तन कर अर्थव्यवस्था में व्याप्त वर्गीय असंतुलन को मिटाने का हल प्रस्तुत करता है। अध्ययन यह स्वीकारता है कि भारत जैसे वर्ग विभाजित भूखंड और पूंजीवादी राजसत्ता के चरित्र वाले समाज में भी भूमि के मूलगामी पुनर्वितरण के बाद किसानों के बीच से पूंजीवादी उत्पादन की जो व्यापक आधारवाली प्रवृत्ति विकसित होती है उसकी तुलना में भूमि-सुधारों से वंचित कृषि ढांचे के अन्तर्गत कृषि-उत्पादन को दीर्घावधि विकास दर धीमी रहती है और उसके धीमे रहने की बुनियादी वजह उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया में निहित है। हाल के हुए कुछ शोध कार्य बताते हैं कि भू-स्वामित्व में क्रांतिकारी परिवर्तन के अभाव ने अतिरिक्त मूल्य का उपयोग कृषि-विकास में नही, बल्कि बैंकों में धनराशि जमा करने हेतु अन्य वित्तीय सम्पत्तियां जुटाने, घर बनाने, बच्चों को महंगी शिक्षा, *डोनेशन* (दान) आदि देकर भी डाक्टर, इंजीनियर आदि बनाने और टिकाऊ उपभोक्ता-सामान बटोरने में ही हो रहा है।

भू-लगान की दर जो कोई भू-स्वामी अपने बटाईदारों, ठेकेदारों आदि से पता है उसकी दर काफी ऊंची इस कारण होती जा रही है कि आर्थिक विकास की गलत नीतियों के कारण रोजगार-सृजन तथा रोजगार चाहनेवालों के बीच संख्यात्मक दृष्टि से बड़ी लम्बी खाई का निर्माण हो गया है जिससे ग्रामीण सर्वहारा के एक बड़े हिस्से ने भूमि पर जनसंख्या के दबाव को बढ़ाते हुए अतिरिक्त श्रम का एक पहाड़-सा खड़ा कर दिया है। जिसे अपनी जीविका के लिए खेती के अलावा अन्य साधनों का अभाव होने के कारण भू-लगान की भूखमरी के लगान तक बढ़ा दिया है। लिहाजा स्वामी भूमिपति बिना कुछ खर्च किए, सिर्फ इसलिए कि सरकारी दस्तावेजों में जमीन उसके नाम अंकित है, कम-से-कम अपनी जमीन की बटाई या ठीके पर लगा उत्पादन का आधा हिस्सा ले लेता है जो किसी भी अन्य व्यापार में प्राप्त मुनाफा से ज्यादा होता है। इस प्रकार के निचोड़े गए अतिरिक्त मूल्य को वह खेती के विकास पर न लगा अन्य मुनाफे के कार्यों में निवेश करता है, जिसमें ग्रामीण हल्कों में सूदखोरी एक प्रमुख रोजगार है। इस प्रकार भू-इजारेदारियों पर भू-लगान को वर्तमान व्यवस्था कृषि-विकास में अवरोधक का कार्य कर रही है, क्योंकि भू-स्वामी द्वारा निचोड़े गये अतिरिक्त मूल्य को कृषि निवेश में लगाने की

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अब शर्त हो गई है कि वे उसे अपने खेत से कम-से-कम इतना मुनाफा जरूर मिले जो इसे भू-लगान के अपने-अपने असामियों से और उसके अपने अतिरिक्त धन की अन्य जगहों पर किए गए निवेशों से प्राप्त लाभ के कुल योगफल से कम-से-कम बराबर हो। इस प्रकार लगान एक अवरोधक का कार्य कृषि-विकास में कर रहा है। यही कारण है कि स्वामीजी भू-वितरण के लिए आन्दोलन करते रहे तथा उन्होंने भू-इजारेदारियों का विरोध किया।

राज्य के साधनों का बढ़ता संकट, जिसके चलते पूंजी-निर्माण की वास्तविक दर में कमी आई है, कृषि के क्षेत्र पर मुख्यतः सिंचाई में साधनों पर निवेश के रास्ते से असर डाल रहा है। कृषि के क्षेत्र में पहले के विकास की दरों को बनाये रखने में सिंचाई पर निवेश की दरों को जिस हद तक बढ़ना चाहिए उसमें या तो कमी आई है या वह धीमी रफ्तार से चल रही है। सिंचाई के क्षेत्र में निजी निवेश अब तक सकारात्मक रूप से और मजबूती के साथ सार्वजनिक निवेश से जुड़ा रहा है। अबतक पैदावार में जे सम्मानजनक बढ़ोत्तरी प्रदर्शित हुई है उसमें मुख्यतः दो घटक क्रियाशील रहे हैं–खेती के रकवे का बढ़ना जो प्रायः पूर्णरूप में 1960 के दशक में प्रभावी रहा तथा दूसरी ईकाई कृषि-भूमि पर पैदावार का बढ़ना, जिसने बाद के दशकों में मुख्य भूमिका अदा की। ईकाई भूमि पर पैदावार का बढ़ना सिंचित भूमि के पैदावार की बढ़ोत्तरी से सीधा जुड़ा हुआ था।

अब, जब उत्पादन के प्रसार और आधार पैदावार को बढ़ाने के आसान रास्ते लगभग चुक गए हैं, भविष्य में पैदावार में बढ़ोत्तरी के लिए और ज्यादा संकट आनेवाला है और वह संकट ईकाई भूमि पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए और ज्यादा निवेश तब तक करनेवाले नहीं है जब तक कि भूमि का पैदावार बढ़ाने वाले तकनीकी बदलाव का एक और दौर संभव नहीं हो जाता। गौर करनेवाली बात यह है कि संभव पैदावार (जिसे जापानी तथा चीनी कृषि की उपलब्धियों से नापा जा सकता है) और हमारा वास्तविक पैदावार के बीच का अन्तर घट नहीं रहा है, बल्कि बढ़ता जाता है। स्वामी जी सम्पूर्ण सिंचाई प्रबन्ध को राज्य की जिम्मेदारी देकर इस अस्थिरतावाद को समाप्त कर देना चाहते थे।

कृषि अर्थ-व्यवस्था पर एक और बुरा असर आज की कृषि के प्रति गलत नीति के कारण हुआ है। विकास के लिए साधन जुटाने के लिए गैर समताकारी रास्ते पर चला गया है तथा सार्वजनिक निवेश की गति धीमी रहने के कारण आम उपभोग के औद्योगिक सामानों का ग्रामीण बाजार काफी संकुचित रहा है। यह आम तौर पर खेत-मजदूरों का वास्तविक आय में गिरावट तथा किसानों की आय

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का जहां-का-तहां बना रह जाना है। कुल ग्रामीण आबादी में खेत-मजदूर 30 प्रतिशत तथा कुल कृषकों का सीमांत और छोटे किसान लगभग 75 प्रतिशत हैं। 15 एकड़ से कम जोत वाले किसानों तथा खेत-मजदूरों के एक सूत्री सर्वेक्षण से पता चला था कि कुल आबादी का यह गरीब किसान और खेत-मजदूर तबका, जो 60 प्रतिशत था, योजना आयोग की एक रपट के मुताबिक भी इनका अधिकांश भाग गरीबी रेखा पार नहीं कर पाया था।

अध्ययन इसी प्रकार की कई अन्य स्थापनाओं को प्रमाणित करता है और एतत् सम्बन्धी स्वामी जी के विचारों के आधारों पर प्रमाणित करता है कि मूल कारण भू-स्वामित्व में क्रांतिकारी परिवर्तन का अभाव है।

अध्ययन की उपलब्धियां

अध्ययन इस प्रामाणिकता को और ज्यादा सम्पुष्ट करता है कि आर्थिक क्षेत्र में होनेवाली क्रांतिकारी प्रक्रियाओं को गति प्रदान करने में वस्तुगत तथा मनोगत दोनों ही प्रकार की स्थितियां जरूरी हैं। भारत का कृषि-क्षेत्र जिस अवरोधकों का सामना कर रहा है उनमें प्रमुख हैं भू-स्वामित्व की इजारेदारियों का वर्तमान रहना, अतिरिक्त श्रम की बहुलता, जो रोजगार-सुजन की अपर्याप्त सुविधा के कारण मजबूरन कृषि पर दबाव बढ़ा रहा है, भू-स्वामी पूंजीवादी का वह स्वरूप जो जातिगत, परम्परागत तथा वर्तमान जाति-प्रथा में हरिजनों को दरिद्रीकृत किसानों की तुलना में ज्यादा आर्थिक, सामाजिक शोषण करता है, भू-लगान को वर्तमान व्यवस्था, जो कृषि में पूंजी निवेश को रोक रही है तथा परम्परागत तरीकों का ही उपयोग कर भू-स्वामी अतिरिक्त मूल्य निचोड़ने की दर को बढ़ा देता है, आदि। उपर्युक्त अवरोधकों की जननी है सरकार की असमतामूलक कराधान-नीति, घाटे की वित्त-व्यवस्था तथा कर्ज आधारित योजना, जो बड़ी पूंजी और बड़े भू-स्वामियों के हिस्से की कुल राष्ट्रीय आय में बढ़ा देते हैं तथा गरीब और मध्यम किसानों-सहित खेत मजदूरों को वास्तविक आमदनियों को घटाकर औद्योगिक मालों के ग्रामीण बाजार को संकुचित कर देते हैं।

संसाधनों को जुटाने तथा खर्च करने की एक बहुआयामी गलत नीति का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे समेकित विकास योजनाओं, जवाहर रोजगार योजना या अन्य इसी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण सम्पन्न वर्ग उठा रहा है। सड़कें गांवों को बाजारों से जोड़ने लगती हैं तब पूंजीवादी बाजार का प्रभाव गांवों पर पड़ता है, घनी किसान अपने अतिरिक्त माल को मंडियों तक ले जाता है। कीमतों की वृद्धि ने मजदूरों का स्वरूप बदल दिया है अब वस्तु नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मुद्रा के रूप में मजदूरी दी जाने लगी है, जबकि मजदूर सामानों (फसल के रूप में मजदूरों) को मांग करते हैं।

पूंजीवादी उत्पादन का असंतुलित विकास अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र को जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गया, शोषण विकसित क्षेत्रों द्वारा करने का अवसर प्रदान कर एक आन्तरिक उपनिवेशवाद को पनपाया गया है जिसमें विकसित और पिछड़े दोनों क्षेत्र हमारी एकता-अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं; कहीं विकास के कारण, तो कहीं पिछड़ेपन की वजह से। इन सबके मूल में है राजसत्ता का पूंजीवादी चरित्र जिसका विरोध स्वामीजी हमेशा करते आए हैं।

इस राजसत्ता के खिलाफ एक वामपक्षी रुझानवाली सरकार, जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को सदा-सर्वदा के लिए समाप्त कर दे, के निर्माण का एक मात्र रास्ता जैसा स्वामी जी की अवधारणा थी है शोषित वर्गों के संयुक्त मोर्चा का निर्माण जो क्रान्ति का वाहक बने। इस प्रकार इस मूल समस्या और इसका समाधान स्वामीजी के चिन्तन में यही था, जिसने उन्हें वामपंथ की तरफ मुखातिब तथा कांग्रेस से विरक्त कराया।

क्रान्ति की वैज्ञानिक अवधारणा, कांग्रेस का चरित्र, वर्गों का विश्लेषण तथा क्रान्ति-कार्यों के सम्पादन में वर्गों की भूमिका, किसान-मजदूर-एकता का प्रश्न आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजनीतिक सत्ता तथा किसानों को क्रान्तिकारी भूमिका, का वैज्ञानिक विश्लेषण स्वामी जी द्वारा किया जाना तथा उसे कार्य रूप में लागू करने को राजनीतिक तथा कार्यनीति से परिचित होना, तथा उसकी वर्तमान समय में भी उपादेयता को समझना आदि अध्ययन को अपलब्ध्यिां हैं।

अध्यायीकरण

प्रस्तावना और इस भूमिका को छोड़ समस्त शोध कार्य मूल पांच अध्यायों में विभाजित है तथा हर का अपना महत्व अपनी जगह पर है।

प्रथम अध्याय ''स्वामी जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व'' शीर्षक में आबद्ध है जो उनके समस्त जीवन में आए उतार-चढ़ाव, बचपन की शिक्षा, पारिवारिक परिवेश से होते हुए अध्यात्मवाद, तपस्या की कामना, संस्कृत वाड़मय के अध्ययन से लेकर जातीय उत्थान तथा आजादी की लड़ाई में गांधीवाद के प्रति आस्था, जेल-जीवन से होते हुए किसान-सभा के कार्यों के माध्यम से वामपंथ की ओर मुखातिब होना, कांगेस छोड़ना साम्यवादियों से मतभेद तथा वामपंथी का जिक्र तथा उनमें आई क्रमशः विकास के उच्च स्तर का प्रतिपादन किया गया है। कृतियां उनके जीवन के विकास को दिशा को प्रतिबिम्बित करती हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दूसरा अध्याय- ''तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक परिवेश और स्वामी जी का उदय'' शीर्षक में स्वामी जी के समकालीन आर्थिक सामाजिक परिवेशों का वर्णन है और उनका प्रभाव स्वामी जी के चिन्तन पर है। वास्तव में भारतीय मुक्ति-आंदोलन में हुए विकास ने, जो प्रारम्भिक धार्मिक पुनरुत्थानवाद से चलकर एक जन-आंदोलन बन गया जिसका स्वरूप समग्रता में साम्राज्यवाद-विरोधी हो गया, जिसके अनुरूप स्वामीजी के चिन्तन का परिवेश भी बदलता गया। बाद में वामपंथ के उदय ने उसके मजबूत होने और व्यापक आन्दोलनों में किसान मजदूरों की भागीदारी का सिलसिला स्वामीजी के चिन्तन का स्वरूप भी बदलता गया। बाद में वामपंथ के उदय ने उसके मजबूत होने और व्यापक आन्दोलनों में किसान मजदूरों की भागीदारी का सिलसिला स्वामीजी को मार्क्सवादी बना दिया।

अध्याय तीन-"स्वामी जी के आर्थिक दर्शन के आयाम" स्वामी जी के चिंतन में वर्ग आधारित समाज शोषण का विरोध क्रांति की परिकल्पना एवं उसका अर्थ, क्रान्तिकारी परिवर्तनों में किसान मजदूरों की भूमिका आदि के चिंतन का विवेचन करता है। स्वामी जी के वर्ग-संघर्ष के प्रबल समर्थक तथा उनके द्वारा किसान-सभा को एक वर्गीय संस्था का स्वरूप देने का प्रयास, राजसत्ता का चरित्र आदि पर प्रकाश डालते हुए किसानों की तात्कालिक एवं मूलगामी मांगों का विवेचन है। स्वामी जी के लिए अर्थनीति साध्य तथा राजनीति साधन है जो कांग्रेस को नीतियों के ठीक उल्टा है। स्वामी जी की संकल्पना में राजसत्ता का स्वरूप वर्गीय होता है इसलिए क्रान्ति राजसत्ता के वर्गीय स्वरूप में परिवर्तन को ही कहते हैं। इस सन्दर्भ में स्वामी जी पूर्णतः मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र को मानते हैं।

अध्याय चार-"किसानों एवं मजदूरों की समस्यायें एवं स्वामी जी" में किसानों मजदूरों की मुख्य मांगों, झारखंड के किसानों की स्थिति, खेत-मजदूरों की समस्यायें तथा उनके हल के उपायों के प्रति स्वामी जी का दर्शन है। किसानों और मजदूरों के स्वार्थों के अन्तर्विरोध को स्वामी जी ऐसा नहीं मानते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन की तरह रह बल्कि सत्ता के स्वरूप में परिवर्तन कर, किसान-मजदूरों के राज्य की स्थापना कर इसे पाटा जा सकता है। किसानों की समस्याओं में जमींदारों का शोषण, भावली, बकाश्त ईख-उत्पादकों की मांगें आदि का वर्णन तथा इसके लिए स्वामी जी का संघर्ष आदि का वर्णन है। किसान-सभा तथा खेत-मजदूर की समस्याओं पर स्वामी जी एक वर्गीय दृष्टि रखने वाले राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे हैं।

अध्याय पांच-इन सबों का "निष्कर्ष तथा स्वामी जी की प्रासंगिकता" को प्रदर्शित करते हुए स्थापित करता है कि आज के भारत में कृषि की बहुत सारी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

समस्याओं का निदान स्वामी जी की कल्पनाओं में सन्निहित है। खास कर भूस्वामित्व के इजारेदारों को कायम रखना ग्रामीण हल्कों में हिंसा को जन्म दे रहा है।

अध्ययन की पद्धति :-

मुख्य रूप से अध्ययन समाज-विज्ञान की जिस शोध-पद्धति को अपना कर चला है उसे ऐतिहासिक गवेषणात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें ऐतिहासिक लक्ष्यों, सूचनाओं एवं आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है तथा उसके परिणाम स्वरूप निकले निष्कर्षों को स्थापित कर उनकी सत्यता प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। हां, इन उपलब्ध सूचनाओं और आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए यह ख्याल रखा गया है कि उनके सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं को दृष्टिगत रखा जाय ताकि एकपक्षीय निष्कर्षों से बचा जा सके। इस अर्थ में अध्ययन द्वन्द्वात्मक पद्धति को अपनाकर चला है।

तथ्य एवं आंकड़े मात्र प्रकाशित, अप्रकाशित स्रोतों से ही नहीं एकत्रित किए गए हैं बल्कि कतिपय मूल दस्तावेजों, सरकारी फाइलों तथा कई व्यक्तियों के व्यक्तिगत सम्पर्क सूत्रों से भी उपलब्ध किए गए हैं। इस प्रसंग में एक स्थापना की जा सकती है कि इसमें कुछ हद तक गवेषणात्मक (इम्पीरियल) पद्धति का भी उपयोग किया गया है। संक्षेप में कहा जाय कि शोध-प्रबन्ध ने किसी एक शोध-पद्धति पर आश्रित न रहकर कई पद्धतियों के उपयोग को आधार बनाया है, कहीं किसी एक की प्रधानता है तो कहीं दूसरे की, मगर सर्वत्र जो भावना मौजूद रही है वह है निष्कर्षों की स्थापना में विसंगतियों से बचना। इसमें कहां तक सफलता मुझे मिल सकी है इसका निर्णय विशेषज्ञ पाठक ही कर सकेंगे।

अध्ययन के स्रोत

शोध प्रबंध सबसे पहले किसी स्थापना को प्रमाणित करने के प्रसंग में स्वामी जी की कृतियों का हमेशा मुखापेक्षी रहा है। इस कारण के स्वामी जी ने तमाम रचनाओं, उनके मुख्य भाषणों को एकत्र कर उनका उपयोग किया है, हालांकि कई रचनाओं की प्रासांगिकता को न देखते हुए उनको अन्यथा ढंग से उद्धृत करने से बचा भी है, मगर देखा सबों को है। इनमें से प्रायः मूल रचनाओं और पुस्तकों को देखा है जो कुछ सीताराम आश्रम बिहटा, बिहार प्रदेश किसान सभा के पदाधिकारियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में प्रान्तीय कार्यालय तथा कई अन्य व्यक्तियों के सौजन्य से प्राप्त हुईं। कुछ सरकारी दस्तावेज तथा संचिकाएं बिहार सरकार के अभिलेखागार पटना से प्राप्त हुए हैं। ए.एन. सिन्हा सामाजिक शोध

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

संस्थान पटना की भूमिका काफी रही है। इसके अलावा अन्य सामग्रियां जो राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित है उनकी प्रति सिन्हा लाइब्रेरी, पटना में संगृहीत कांग्रेस महाधिवेशनों के दस्तावेजों तथा *आर्यावर्त* एवं *सर्चलाइट*, *इन्डियन नेशन* एवं *प्रदीप* की फाइलों से मिल सका है।

इसमें कई पुस्तकालयों, तथा राजनीतिक दलों के सौजन्य से सामग्री प्राप्त हुई है जिनमें ब्रह्मर्षि समाज कानपुर प्रमुख है जिसने *ब्रह्मर्षि संदेश* को उपलब्ध कराया तथा स्वामी सहजानन्द सरस्वती विद्यापीठ महाविद्यालय गाजीपुर के प्रयासों से 'निवेदिता' के कुछ अंक प्राप्त हो सके हैं जिनका उपयोग किया गया है।

शोध प्रबन्ध को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसकी मौलिकता बनी रहे तथा किसी एक *रॉटलोजी* या लकीर की फकीर जैसा स्वरूप लेकर न आए। इसमें चार परिशिष्ट संलग्न हैं, जो मौलिक हैं। अन्य तमाम मौलिक दस्तावेजों को जो उपलब्ध थे, उन्हें परिशिष्ट में शामिल कर देने का अर्थ था शोध प्रबंध की आकृति को विशाल कर देना, और इसी कठिनाई को ध्यान में रखकर स्वामी जी के भाषणों आदि को परिशिष्ट में शामिल न कर उनका उद्धरण या *रेफेरेन्स* संदर्भ सूची में दिया गया है ताकि आगे के शोधकर्ता इसे आसानी से पा सकें।

इसके अन्त में एक अति आवश्यक स्रोत सूची का समावेश किया गया है जिसमें स्वामी जी कालीन और आज के कई लेखकों, समाजवैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं के लेखों, पुस्तकों, सरकारी दस्तावेजों तथा स्वामी जी की कृतियों की सूची दी गई है। संख्यात्मक दृष्टि से कम होते हुए भी यह स्रोत सूची मात्र इतना दर्शाती है कि इनके अवलोकन बिना स्वामी जी पर किया गया कार्य प्रायः अधूरा रहेगा तथा उनकी प्रासंगिकता आय के सन्दर्भ में प्रमाणित नहीं की सकती। परिश्रमपूर्वक एकत्र की गई सामग्री के आधार पर प्रस्तुत यह शोध प्रबंध अगर भूमि-सुधार और ग्रामीण-अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रेरणा दे सका तो यह मेरी एक सफलता होगी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबंध "स्वामी सहजानन्द सरस्वती का सामाजिक-आर्थिक चिन्तन" के सम्पूर्ण प्रणयन में मैं अपने पर्यवेक्षक प्रोफेसर भगवान प्रसाद सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय का अतिशय आभारी हूं कि उन्होंने मुझे गुरुतर कार्य के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित किया, बल्कि इसका निर्देशन करने जैसे कठिन कार्य की जिम्मेवारी भी स्वीकार की। शोध प्रबंध के प्रणयन में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उनका अनुभव कर जब मैं किंचित विचलित होता था तब मेरे कर्तव्य बोध से जिस ढंग से इन्होंने हमें अवगत कराया वह एक ऐसी सहज प्रक्रिया के रूप में ठीक उसी तरह रही जिस तरह एक विचारवान श्रेष्ठ व्यक्तित्व किसी को उसकी प्रगति के मार्ग के प्रति उत्प्रेरित करता है। सबसे बढ़कर विषय वस्तु के प्रति उनकी गहरी विद्वतापूर्ण पैठ हमारी हर समय, हर किस्म की कठिनाइयों का समाधान करती रही। चाहे सूचनाओं और तथ्यों के संग्रह का काम हो या उन्हें विश्लेषित करके उनके आधार पर निष्कर्षों का निरूपण करने या अन्य कार्य वे हमेशा अध्ययनपूर्ण विद्वता से हमारा निर्देशन करते रहे। मैं उनकी इस कृपा के लिए आजीवन आभारी रहूंगा।

यों तो, मालती धारी कॉलेज नौबतपुर के मेरे प्राध्यापक साथियों का सहयोग एवं सान्निध्य मुझे इस काम में बराबर मिलता रहा किन्तु सहायकों एवं मार्गदर्शन में निदेशक के बाद लोगों में प्रमुख हैं अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य श्री तृप्ति नारायण शर्मा, मैं उनके संबंध में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि सामाजिक दायित्त्वों को पूरा करते हुए ज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जो स्थान बना लिया है, वह इस तरह के लोगों में शायद ही पाया जाता है। मैं इनके विद्वतापूर्ण सहयोग, मेरे शोध के व्याकरणिक स्वास्थ्य कार्य के प्रति लगन और विश्लेषण की अपूर्व प्रतिभा के सामने सदानतमस्तक रहूंगा। प्रो. नवल किशोर प्र. सिंह एवं ऐसे सहयोगियों को मदद एवं प्रेरणा के लिए मैं सदा याद करता रहूंगा।

डा. ब्रज कुमार पाण्डेय, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आर.एन. कालेज, हाजीपुर के प्रति बिना आभार प्रकट किए नहीं रह सकता, जिनकी मूल पूंजी है उनकी विद्वता तथा घटनाओं, पर्यघटनों एवं क्रियाओं को एक सिद्धान्तनिष्ठ वैज्ञानिकी के आधार पर सिद्धान्त निरूपण कर देने की कला।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मैं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्थान "भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" के प्रति भी अत्यन्त आभारी हूं जिसने इस शोध प्रबन्ध के विषय वस्तु को प्रकाशन के लिए स्वीकार किया तथा इसके प्रकाशन हेतु आर्थिक अनुदान स्वीकृत किया।

प्रो. पी.के. चौबे जो सम्प्रति भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं, के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस पुस्तक की मूल पांडुलिपियां पढी तथा इसकी विषय वस्तु की सराहना करते हुए भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद को प्रकाशन हेतु अपनी सहमति दी।

स्व. डा. विजय चन्द्र प्रसाद चौधरी, अवकाश प्राप्त उपनिदेशक, काशी प्रसाद जायसवाल, शोध संस्थान पटना, जो एक जाने माने इतिहासज्ञ हैं, जिनके सहयोग एवं सहायता के लिए भी मैं आभारी हूं। यथोचित परामर्श देते रहने में इन्होंने बड़ी कृपा की जिसके लिए मैं हृदय से इनका कृतज्ञ हूं।

मेरे पूज्य पिता श्री अम्बिका सिंह, मेरी ममतामयी मां श्रीमती सुनयना देवी और मेरे चाचा श्री बलिष्ट. सिंह (शिक्षक) तथा परिवार के अन्य सदस्यगण ने जिस तरह से इस कार्य को सफल बनाने में आर्थिक मदद से लेकर मानसिक सान्त्वना मुझे दी है वह चिरस्मरणीय रहेगी। पत्नी शैल शर्मा, दो पुत्रियों निवेदिता, अरुन्धति तथा पुत्र आनन्द को भी धन्यवाद देना कभी नहीं भूल सकता इन लोगों ने जिस तत्परता, धैर्य, सहनशीलता का परिचय दिया है वह अविस्मरणीय है। अपने पूज्यपाद संगीत गुरु स्व. सत्यदेव शर्मा के प्रति आभार प्रदर्शन कैसे करुं?

डा. अलख नारायण शर्मा, निदेशक, इन्स्टीट्यूट फार हूमैन डेवलपमेंट, नई दिल्ली तथा एडिटर-'दि इंडियन जनरल आफ लेबर इकोनोमिक' डा. इन्द्रदेव शर्मा, अनुग्रह नारायण शोध संस्थान पटना, तथा डा. देवेन्द्र त्यागी, देशबन्धु कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विशेष रूप में हर तरह से मेरी मदद करते रहे हैं। प्रो. रुद्र दत्त, पूर्व प्राचार्य, पत्रकारिता महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, जिन्होंने हमारे शोध पत्र का मूल्यांकन कर पटना विश्वविद्यालय को पी. एच.डी. के लिए स्वीकृति प्रदान की तथा प्रो. देवेन्द्र भूषण गुप्ता, नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लायड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली, जो हमारे इस कार्य में काफी प्रेरणा-स्रोत रहे, इनका भी मैं सदा आभारी रहूंगा।

विभिन्न पुस्तकालयों, लेखागारों तथा राजनीतिक दलों के लोगों ने जिस मुस्तैदी से तथ्य संग्रह में मेरा हाथ बंटाया है उन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। निःस्वार्थ सेवा के ये ऐसे प्रतीक हैं जो किसी से भी ऊंचा स्थान रखते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मैं श्री देवनाथ शर्मा, टाइपिस्ट को सीमित अवधि में बिना धन्यवाद ज्ञापन के मैं नहीं रह सकता जिन्होंने अपने व्यस्त क्षणों के बावजूद इस शोधकार्य को न सिर्फ साफ-साफ टंकण किया बल्कि दुरूह से दुरूह शब्दावलियों को ठीक ढंग से टाइप कर शोध प्रबंध की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया है।

अन्त में, श्री मथुरा प्रसाद यादव (मानक पब्लिकेशंस प्रा. लिमिटेड, दिल्ली) को भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस शोध प्रबंध को यथाशीघ्र प्रकाशित करने में अपनी ओर से काफी उत्साह दिखाया। वास्तविकता है कि उत्पादक का चरित्र सामूहिक श्रम पर आधारित रहता है और इस शोध प्रबंध को पैदा करने में भी सामूहिक श्रम ने अपनी भूमिका का पूर्ण निर्वाह किया है। मैं श्रम के इस चरित्र के प्रति भी कृतज्ञ हूं।

इसकी त्रुटियां, अगर कहीं हैं, तो वे मेरी हैं और सफलता, अगर कुछ है तो इसका श्रेय सबों के सामूहिक श्रम एवं निर्देश को जाता है।

दलीप कुमार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विषय-सूची

प्राक्कथन *ix*

भूमिका *xi*

आभार *xxiii*

अध्याय-1: स्वामी जी : व्यक्तित्व एवं कृतियां **1-49**

प्रारम्भिक जीवन

स्वामी जी की दार्शनिकता

जाति प्रथा के प्रति विचार

राजनीति एवं स्वतंत्रता संग्राम में

किसान आन्दोलन में स्वामी जी

स्वामी जी की कृतियां

पत्रकार एवं सम्पादक

अध्याय-2: तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक परिवेश और स्वामी जी का उदय **50-88**

स्वामी जी का ग्रामीण एवं पारिवारिक परिवेश

ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक-नीति और भारतीय परिवेश

तत्कालीन कृषि की स्थिति

साम्प्रदायिकता

सामाजिक स्थिति

भू-स्वामित्व के खिलाफ आन्दोलन का परिवेश

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जातीय स्थितियां

दिसम्बर 1921 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के बाद की राजनीतिक स्थिति

वामपंथ का प्रभाव

अध्याय-3: स्वामी जी के आर्थिक दर्शन के आयाम 89-138

औपनिवेशिक भारत की कृषि

मार्क्सवाद दर्शन में प्रति स्वामी जी का रुझान

स्वामी जी के क्रान्ति विषयक अवधारणा

स्वामी जी की आर्थिक रणनीति और कार्यनीति

अखिल भारतीय किसान सभा की आर्थिक नीति और स्वामी जी

कांग्रेस और किसान सभा अर्थनीति के सम्बन्ध में

वर्ग संघर्ष और राष्ट्रीयता

व्यापारिक फसलों के सम्बन्ध में स्वामी जी की अर्थ नीति

झारखण्डी किसानों के लिए स्वामी जी की मांगें

स्वामी जी की कृषि नीति

स्वतंत्रता के बाद की देशी अर्थनीति और स्वामी जी

अध्याय-4: किसानों एवं खेत मजदूरों की समस्याएं और स्वामी जी 139-180

किसानों की मांगे

किसान-मजदूर एकता का प्रश्न

किसान-मजूदरों की समस्याओं का स्वरूप

अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन में किसान मजदूर समस्या पर विचार

आजादी के पश्चात् किसान मजदूरों की समस्यायें और स्वामी जी

बकाश्त आंदोलन की समस्या और स्वामी जी

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा अन्य समस्यायें

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

किसान-मजदूरों का प्रश्न कांग्रेस में मतभेद के कारण
किसान-मजदूरों के हाथ में सत्ता सौंपने के प्रति
स्वामी जी का विचार

अध्याय-5: सारांश एवं निष्कर्ष तथा स्वामी जी की प्रासंगिकता 181-198
राष्ट्रीय आन्दोलन में
किसान सभा के बाद
नमक सत्याग्रह और उसके बाद
स्वामी जी का वर्ग दृष्टिकोण
स्वामी जी का राज्य सत्ता के प्रति दृष्टिकोण
सहयोग असहयोग के मुद्दे
स्वामी जी की प्रासंगिकता

परिशिष्ट 199-218
i. स्वामी सहजानन्द सरस्वती का संक्षिप्त जीवन वृत्त
ii. अखिल भारतीय किसान सभा की नियमावली
iii. 13, फरवरी 1942 को अखिल भारतीय किसान कौंसिल द्वारा पारित नागपुर प्रस्ताव
iv. मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी?

ग्रंथ एवं सन्दर्भ सूची 219-225
अनुक्रमणिका 227-234

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-1

स्वामी जीः व्यक्तित्व एवं कृतियां

प्रारम्भिक जीवन

स्वामी जी का जन्म एक मध्यमवर्गीय, पिछड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन की एक रूपरेखा निम्नांकित कथन से स्पष्ट है :

"मुझे ठीक याद नहीं कि मां के गर्भ से मैं कहां आया। जब यह जान सकता था तब तो इसकी कोशिश ही न की, और अब अर्धशताब्दी से ज्यादा समय गुजर जाने पर पता लगाना एक प्रकार से असंभव है। इसीलिए इस बात की फिक्र ही छोड़ दी। फिर भी पढ़ने के समय स्कूल में जो अवस्था मोटी-मोटी लिखी-लिखाई जाती है उसी के आधार पर मैंने यह अनुमान किया कि सन् 1889 के आरम्भ के महीनों मे यह दुनिया मूक रूप से देखी थी। जहां तक फिर भी पता लग सका है, फरवरी महीने में फागुन को महाशिवरात्रि का दिन था, हालांकि पक्की जानकारी नहीं हो सकी है"।[1]

उपर्युक्त उद्धरण इस प्रामाणिकता की कसौटी प्रस्तुत करता है कि स्वामी सहजानन्द सरस्वती के बाल्यकाल का पारिवारिक परिवेश शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टियों से अशिक्षित, पिछड़ा एवं मध्यम वर्गीय किसान परिवार का था, जो चतुर्दिक वातावरण में ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा जबरन थोपी गई सामंती एवं औपनिवेशिक दासता का माहौल व्याप्त था। उसका स्पष्ट असर वर्तमान था। अशिक्षा तथा पिछड़ापन का दबाव उतना प्रबल था कि परिवार अपने नवजात शिशु का जन्म दिन भी कहीं अंकित नहीं कर सका था।

स्वामी जी का गांव सादियाबाद परगना के बिरनों थाना में अवस्थित है, जो गाजीपुर जिले के शैदपुरा शहर के उत्तर-पश्चिम सीमा पर उत्तर पूर्व रेलवे के दूलहपुर स्टेशन के पास है[2]। नजदीकी कस्बे और एक छोटे सामंती शहर में बचपन के थोड़े से दिन गुजारने के बाद, 17-18 वर्ष की आयु में वे संन्यासी बन बैठे।[3] सामंतवाद और खासकर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में, औपनिवेशवाद

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

और सामंतवाद का जो अभूतपूर्व घोल-मेल कराया गया था, उसमें सामंतवादी धार्मिकता के प्रभाव तले सांसारिक वृत्तियों से परे परम मोक्ष का दर्शन प्रबल प्रभाव लिए भारतीय सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रहा था। स्वामी जी ऐसी धार्मिक मान्यताओं के प्रभाव में करीबन 7-8 साल तक उत्तर भारत के महत्वपूर्ण साधना केन्द्रों का भ्रमण किसी मोक्षदाता गुरु की तलाश में करते रहे तथा संस्कृत वांड्मय के अध्ययन में उनका समय गुजरा।

भारतीय वांड्मय में तपस्वियों, मनीषियों एवं योगियों की साधनाओं के साहित्य एवं इतिहास के सम्पर्क में आने के बाद उनकी उपर्युक्त दार्शनिक अवधारणा का उदय एक स्वाभाविक परिणति थी। अन्य संन्यासियों की ही तरह स्वामी जी भी देश, समाज आदि विषयक कल्याणकारी कार्यों के प्रति उदासीन थे–ठीक ऐसे जैसे वे सब तुच्छ वृत्तिवालों का कार्य है। जब वे दण्डी स्वामी की दीक्षा के क्रम में परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 108 दण्डी स्वामी अच्युतानन्द जी सरस्वती से विधिवत दीक्षा ग्रहण कर दण्डी स्वामी हो गये और उसका विरोध ब्राह्मणों ने किया।[4] तब कई दिनों के शास्त्रार्थ के बाद स्वामी जी ने यह सिद्ध किया कि भूमिहार भी ब्राह्मण ही हैं।

स्वामी जी का परिवार जिस आर्थिक, सामाजिक परिवेश में रह रहा था या गाजीपुर जिले का जो आर्थिक सामाजिक परिवेश उनके जीवन काल में था वह पूर्णतः सामंतवादी भले न रहा हो मगर ब्रिटिश शासन काल में भू-स्वामित्व की जो नई प्रणाली चलाई गई थी, उसने सम्पूर्ण क्षेत्र पर जमींदारों का दबदबा कायम कर दिया था। क्षेत्र में भू-स्वामी जमींदारों एवं कास्तकारों के बीच शोषण की एक नई प्रणाली ने जड़ जमा ली थी तथा ब्रिटिश शासन काल में ध्वस्त की गई स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी उद्योगों का विकास न होना जमीन पर जनसंख्या के दबाव को बढ़ा दिया था। पुरानी स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ध्वस्त होना और रोजगार के अन्य साधनों का सृजन न होना ग्रामीण गरीब आबादी को अर्ध-दास के रूप में खड़ा कर दिया था। वाल्यावस्था में कुश्ती लड़ना, भैंस चराना आदि स्वामी जी के कार्य एक अति अविकसित ग्रामीण व्यवस्था की मौजूदगी के द्योतक हैं, और उन्होंने स्वामी जी के बाल्यकाल को काफी प्रभावित किया। बचपन में ही मां की मृत्यु और उनकी मौसी द्वारा उनका पालन पोषण होना ऐसे कारण थे, जिन्होंने स्वामीजी की चेतना को शुरू के दिनों में भावनात्मकता का आधार प्रदान किये। आर्थिक-सामाजिक परिवेश का सामंती या अर्धसामंती होना, उपनिवेशवाद के तहत हो रहे सार्वजनिक शोषण से जन आयाम की तबाही, औपनिवेशिक दासता के खिलाफ हो रहे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

संघर्ष का धार्मिक पुनरुत्थानवादी होना तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा व्यापक पैमाने पर ईसाई धर्म का प्रचार किया जाना और आर्य समाज तथा अन्य धार्मिक संगठनों द्वारा ईसाई धर्म के खिलाफ तथा वैदिक धर्म और सनातन हिन्दू धर्म की महानता आदि का प्रचार एक ऐसी भौतिक परिस्थिति को पैदा कर रहे थे जिसमें एक नवरंग राय[5] की चेतना को धार्मिकता के प्रति उन्मुख होना ही था। स्वामी जी का शुरु का जीवन इन परिस्थितियों में धार्मिकता के प्रति उन्मुख हो गया, नित प्रति स्नान करना, रामायण एवं गीता का पाठ करना, शंकर जी को प्रतिदिन बेलपत्र आदि चढ़ाना ही उनका काम था।

ब्रिटिश शासन के वर्ग-चरित्र का वित्तीय पूंजीवादी होने के बाद से भारतीय ग्रामों का शोषण और ज्यादा बढ़ गया था और खास कर स्वामी जी का निवास क्षेत्र बिहार के बगल में होने के कारण अंग्रेज निलहों को दमनकारी कार्यवाइयों का प्रभाव भी उस क्षेत्र पर व्यापक रूप से पड़ रहा था। कृषि की पुरानी व्यवस्था को ढूंढने तथा औपनिवेशिक शासन द्वारा अवाम पर लादी गई बदहवाली के कारण स्वामी जी का परिवार[6] भी एक अशिक्षित मध्यमवर्गीय परिवार का स्वरूप ग्रहण कर चुका था जो सामंती और औपनिवेशिक शोषण के तले दबा था और स्वामी जी से उसको कुछ अपेक्षाएं थीं। यही कारण था कि परिवार स्वामी जी की धर्म-उन्मुक्तता को पसंद नहीं करता था। भारतीय सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था की एक कुरीति थी, बाल विवाह और स्वामी जी भी इस कुरीति के शिकार हुए और मात्र 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह 1905 में कर दिया गया जब उन्होंने मात्र मिडिल स्कूल की पढ़ाई (सप्तम श्रेणी) ही पूरी की थी।

यह वह जमाना था जब भारतीय राष्ट्रीय जीवन में औपनिवेशिक दासता के खिलाफ बहुआयामी संघर्षों का विकास हो रहा था। 1904 में मिडिल पास करने के बाद उनका नामांकन गाजीपुर जर्मन मिशन स्कूल में हुआ। 1905 में बंगभंग के खिलाफ भारत में संघर्ष का जो नया दौर शुरू हो रहा था उसमें तिलक का पुराना धार्मिक पुनरुत्थानवाद का जोर हालांकि कम पड़ता जा रहा था फिर भी स्वामी जी के जीवन पर पुरानी तिलकवादी धार्मिकता का असर काफी प्रभावपूर्ण था। मिशन स्कूल को शिक्षा के तौर तरीके ने भी उन्हें धार्मिक प्रवृत्तियों को अपनी-चेतना में समाहित करने तथा ईसाई धर्म के ऊपर पौराणिक भारतीय संन्यासी-धर्म की महानता को प्रतिष्ठित करने को बाध्य कर रही थी। धार्मिकता के माहौल को भारत की पिछड़ी आर्थिक-सामाजिक संरचना काफी महत्व प्रदान कर रही थी और स्वामी जी समस्याओं के हल को धार्मिक वृत्तियों में खोज रहे थे। चूंकि स्वामी जी के आस-पास की भौतिक परिस्थिति ही धार्मिकता का पुट लिए हुई थी अतः

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उनकी चेतना के सृजन में उन्होंने व्यापक योगदान किया और स्वामी जी का बाल्यकाल धार्मिकता पर आधारित हो गया, इसलिए आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। एक अर्द्ध-सामंती समाज में जिस पर एक विकसित पूंजीवादी ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन चल रहा था, और उसके खिलाफ संघर्ष में धर्म पर आधारित आंदोलनों को गठित कर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया जा रहा था कि पौराणिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति ब्रिटिश पूंजीवादी सभ्यता संस्कृति से उच्च थी, और वही साम्राज्यवाद का कारगर विकल्प हो सकती है, ने स्वामी जी की पौराणिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन के लिए बाध्य किया। चूंकि पौराणिक भारतीय सभ्यता संस्कृति वर्णाश्रम धर्म पर आधारित सामाजिक संरचना थी और उसका केन्द्र पौराणिक मठ था। भारतीय सभ्यता संस्कृति और चिन्तन में महारत हासिल करने के लिए ऐसे स्वामी की खोज में 1907 को फरवरी के महाशिवरात्रि को घर से निकल पड़े।

स्वामी जी की दार्शनिकता

उक्त 7-8 वर्ष की अवधि के अध्ययन का परिणाम था स्वामी जी के चिन्तन में दार्शनिक भावों का उद्‌भव जो अभी सनातन हिन्दू प्रवृत्तियों, संस्कारों एवं मान्यताओं के आधार पर ही उनके चेतन मन को प्रभावित किया और अध्यात्मवादी दार्शनिकता को उन्मुक्त किया, परन्तु उनका अध्यात्मवाद काल्पनिक नैसर्गिक सुख की प्रधानता के साथ-साथ उसकी उपलब्धि के लिए सांसारिक तत्वों के महत्व को स्थगित करने वाला होने के कारण एक "अनजानी वैज्ञानिकता" का पुट लिए अवतरित हुआ जो मिथ्या आदर्श और "अनजानी वैज्ञानिकता" का एक अपूर्व सम्मिश्रण का उदाहरण है, किसान मानसिकता में व्याप्त मिथ्या आदर्श के प्रति शुरू के जीवन का व्यवहार–"खाने-पीने के मामले में कट्‌टर पोंगापंथी थे तथा भोजन रसोइये की पवित्रता सम्बन्धी विश्वासों पर यकीन करते थे।"[7]

संस्कृत वांड्‌मय तथा भारतीय दर्शन की दीक्षा का प्रभाव था जिसने उन्हें निष्काम कर्म की पौराणिक भारतीय दार्शनिकता के सम्पर्क में लाया। काशी के अपारनाथ मठ के अच्युतानन्द जी महाराज से संन्यास धम्र की दीक्षा ग्रहण कर सहजानन्द हुए।[8] उसी अपारनाथ मठ में श्री हरिनारायण जी त्रिपाठी जी से सिद्धांत-कौमुदी का अध्ययन किया। तत्पश्चात दर्शनशास्त्र के अध्ययन में प्रविष्ट हुए। दरभंगा में श्री लालकृष्ण मिश्र से न्याय का अध्ययन किया और इसी प्रसंग में दिल्ली, जयपुर, अजमेर आदि का भ्रमण भी किया। पौराणिक भारतीय संस्कृत वाड्‌मय का अध्ययन उन्हें जिस दिशा में भी प्रेरित किया हो मगर वे हमेशा किसी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सिद्ध योगी की तलाश कर उससे शिक्षा ले सांसारिकता के बंधन से, जिसे प्राचीन भारतीय दर्शन से सविस्तार वर्णन किया गया है, मुक्ति पाना चाहते थे। सनातनी प्रभाव कितना प्रबल था स्वामी जी खुद लिखते हैं, "चाहे कितना ही उच्च कोटि का परोपकारी काम क्यों न हो, उस समय मेरी दृष्टि में वह नाचीज सांसारिक काम ही था। फिर देश-कोष की बात का कहना क्या?[9]

अध्यात्मवाद की चरम अभिव्यक्ति स्वामी जी के जीवन के प्रथम चरण में वैसी नहीं थी जैसी बाद में देखी गयी। प्रथम चरण में वे भारतीय दर्शन के उस बिन्दु को पकड़े हुए थे जिसे यूरोपीय दर्शन में हीगेल एवं फायरबांक प्रतिपादित किए हुए थे, और जो था एक परम सत्ता की खोज और प्राप्ति जिस भारतीय अध्यात्मवाद में सर्वसत्तावान भगवान के रूप में प्रतिपादित किया गया है। स्वामी जी कहते हैं, "मैं तो पागलों की तरह उसे ही ढूंढ़ने निकला था।"[10]

प्राचीन भारतीय वांड्मय में वर्णन आता है कि देहाभिमान विषयक चिन्ता के साथ ही कर्म-विषयक चिन्ता उपस्थित होती है। शास्त्रीय आदर्शों से विशेष अनुगत होने के कारण स्वामी जी जानते थे कि पंचकोश के आहार के लिए कर्म, चित्त की प्रसन्नता के लिए कर्म एवं ऐहिक उन्नति, अनभीष्ट की अप्राप्ति पार्थिव सुख अथवा मुक्ति के लिए कर्म इत्यादि क्रियामान वैध कर्म समूह देह, प्राण, मन, ज्ञान, आनन्द का पोषण करते हैं। 'देवी सूक्त' की चिन्तन प्रणाली 'भगवत गीता' के सांख्य योग तथा निष्काम कर्मयोग प्रणाली के दो प्रमुख आधार-संस्कार एवं शिक्षा, जिनकी सम्पूर्ति से ही देहधारी में कर्म वैशिष्ट्य दृष्टिगोचर होता है, स्वामी जी के दार्शनिक जीवन के विशेष पहलू हैं। संस्कार उनकी आत्मा से संयुक्त था और शिक्षा उनको निजी स्वाध्याय एवं अध्यवसाय से प्राप्त थी। उनके जीवन पर गीता के सांख्य बुद्धि, योग बुद्धि, जिसे स्थितप्रज्ञ के पहले की भूमिका कहा गया है अथवा ब्रहमविद्या शास्त्र कहा गया है। योग-बुद्धि की आत्मज्ञान के अनुसार जीवन कला कहा गया और दोनों के योग से ब्रह्म विद्या को पूर्ण होना बताया गया है, और जिसके लिए तत्व ज्ञान और आचरण दोनों का योग अनिवार्य बतलाया गया है, का प्रभाव स्पष्ट दिखाता है। अपने योग बुद्धि से कर्त्तव्य के निश्चय के पश्चात् एकाग्रता पूर्वक उसके सम्पादन मे, बिना फल की इच्छा किए लग जाना, किन्तु जिस कर्त्तव्य में सामूहिक अनैतिकता का आभास हो उसे तत्काल त्याग देना, उनको दार्शनिक विशेषता थी।

स्वामी जी की दार्शनिक मीमांसा में व्यक्ति वह केन्द्र है जिसके संदर्भ में कार्य-प्रयोजन व्यवस्थित रहता है। मानव जीवन का मुख्य प्रयोजनीय, उनकी दृष्टि में असन और वसन ही है, जिसमें "असन" देह रक्षा के लिए अपरिहार्य है तो

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

"वसन" किंचित मूल्य होने पर भी विशेषतः मान, यश, प्रतिष्ठा, दम्भ, दर्प, मदमत्रता, प्रभूति मिथ्याभिमान संबंधी कृत्रिमता का प्रलेय मात्र जो व्यक्ति एवं समाज के जीवन को पंकिल बना देता है। इसका सामाजिक परिणाम यही होता है कि मानव केवल अपने जीवन के लक्ष्य और प्रयत्न को ही नष्ट नहीं करता वरन् अर्थ सम्पदा और उपकरण के यत्न की कर्म-ताड़ना में अपने को नष्ट कर देता है। स्वामी जी ने निष्काम कर्म को दार्शनिक भावना को ही अपने जीवन का उदान्त लक्ष्य बनाया मगर आध्यात्मिकता के धरातल पर।

वास्तव में स्वामी जी की इस दार्शनिकता का मूलाधार उनकी उन परिस्थितियों से उत्पन्न था, जो पिछड़ी किसान मनोवृत्ति, अवैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण और परम्परागत सामंती आन्तरिक संरचना द्वारा पोषित और फलित होता है। स्वामी जी का यह वर्गाधार उनके प्रारम्भिक जीवन के हर पहलू राजनीति, सामाजिक चिन्तन, दार्शनिक मान्यताओं और उनके प्रति एक विशिष्ट आकर्षण के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।

उनका मध्यम किसान चरित्र उन्हें जाति-संगठन की तरफ आकृष्ट करता है[11] तो दूसरी तरफ उनका यही वर्गाधार उन्हें वहां भी सामंतवाद विरोधी बनाये रखता है। उन्हें किसानों के वर्ग संघर्ष की तरफ ले गया, तथा अंततः उन्हें उस ग्रामीण सर्वहारा को जो ब्रिटानी शासनकाल की भू-व्यवस्था के तहत उत्तरोत्तर बढ़ना और सामंती जुल्म का शिकार होता जा रहा था, समझने और उसके लिए संघर्ष करने योग्य बनाया। इसी वर्गाधार का असर है कि स्वामी जी जहां एक तरफ अपने को वेदान्त से जोड़ते हैं, जिसने उनके दार्शनिक जीवन का निर्माण किया वहीं वे स्वय कहते हैं, "मैं व्यावहारिक वेदान्ती हूं, किताबी वेदान्ती नहीं हूं। अनुभव के आधार पर मैंने अपना विकास किया है।"[12] एक सफल वेदान्ती की क्रियाशीलता का उदात्त लक्ष्य उनके विचार में "समाजोद्धार का कार्य ही संन्यासी का आत्मोद्धार हैं। यहीं सक्रिय वेदांत है। इसे ही व्यावहारिक वेदान्त कहा जा सकता है।"[13] जिस प्रकार आद्य शंकराचार्य ने ग्रंथ कीट बनाने का प्रयास नहीं किया, 'शब्द जालम्महारज्यं चित्त विर्भम कारकम्' का उद्घोष कर सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कर अज्ञान का निरसन कर सांस्कृतिक एकता का अथक प्रयास किया था, उसी प्रकार स्वामी जी ने भी वेदान्त के इस परिपाक से उत्पन्न ज्ञान को समाज सेवा में लगाया। उनकी आध्यात्मिकता भौतिक कठिनाइयों के निराकरण, दलितों के लिए संदेह संघर्ष में भगवत्-प्राप्ति का अवलोकन किया, फिर भी इस क्रमिक विकास की जड़ में अभी भी उनका किसान वर्णाधार, जो अपने को श्रेष्ठ मानता है, बना रहा और जातीय उत्थान की ब्रितानी सभ्यता संस्कृति के दबावों तले कमजोर पड़ती जा रही थी और

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उन्मुख हुआ। वहां सनातन वेदान्त, अध्यात्म अभी भी प्रबल था और एक कुंद होती वर्ण-व्यवस्था के ढांचे में उन्होंने जातीय उत्थान के लिए अपने को क्रियाशील किया।

जाति प्रथा के प्रति विचार

वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मणों की सामाजिक वरीयता को स्वामी जी ने न सिर्फ स्वीकारा बल्कि 20 वीं सदी के प्रथम दो दशकों तक उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकारते हुए यह अथक प्रयास किया कि भूमिहारों को भी ब्राह्मणों की श्रेणी में लाकर समाज के सर्वोपरि महत्व के स्थान पर बैठाया जाय। 1907 से 1914-15 तक जिस भारतीय दर्शन और शास्त्रों का गहन अध्ययन उन्होंने किया, उनसे प्राप्त ज्ञान के प्रति उनकी चेतना अभी पुरानपंथी ढंग से विकसित हो रही थी; किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास न हो सका था। इसका मुख्य कारण था कि यूरोप में मार्क्स, ऐन्जिल्स के साथ अराजकतावादी, गिल्डसोशलिस्ट आदि ने वैचारिक स्तर पर जिस सामंतवादी दर्शन का सृजन किया था उसका भारत में आगमन भारत के औपनिवेशिक शासकों का पूंजीवादी दर्शन था और उसके विकल्प में पौराणिक भारतीय सामंती और अर्धसामंती दर्शन खड़ा किया जा रहा था।

भारत जैसे जातीय विभाजित देश में जहां जन्म के आधार पर जाति तथा जाति के आधार पर व्यक्ति का सामाजिक स्तर तय होने की प्रथा चली आ रही थी, उस सामाजिक संरचना में स्वामी जी ने भूमिहारों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त ब्राह्मणों को कोटि में लाने का संघर्ष तेज किया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन का एक शोधपूर्ण कार्य जिसे स्वामी जी ने किया वह था भूमिहारों को ब्राह्मणों की श्रेणी में ला खड़ा करना। कतिमय विद्वान स्वामी जी के इस जातीय संघर्ष को समाज-सुधार की संज्ञा देते हैं, परन्तु जाति प्रथा के प्रति स्वामी जी का ऐसा विचार प्रचलित जाति प्रथा का विरोध न होकर एक विशेष जाति भूमिहारों को जाति प्रथा की सबसे ऊंची मंजिल पर लाने का एक प्रयास था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भूमिहार कहलाने वाले लोग भी ब्राह्मण श्रेणी के अन्तर्गत ही आते हैं। ब्राह्मणतत्व के ठेकेदारों से शास्त्रार्थ करना और उन्हें पछाड़ना, भारतीय समाज में भूमिहार-ब्राह्मणों का स्थान और उनको हीन बनाने में दूसरे ब्राह्मणों की चाल, बस वे सभी बातें स्वामी जी की आंखों में नाचती रहती थीं।

भारत में जाति प्रथा का संस्थागत स्वरूप रहा है और उसमें परिवर्तन लाने के लिए सशक्त जन संगठनों और क्रियाकलापों की जरूरत रही है। इस महत्वपूर्ण कार्य को प्राप्ति के लिए स्वामी जी पूर्णानन्द जी सरस्वती की प्रेरणा से 1913 ई.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दिसम्बर में बलिया में होने वाले अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासभा में सम्मिलित हुए। उसी सम्मेलन में उन्होंने संकल्प किया कि इनमें स्वाभिमान जागृत करूंगा और उनके ब्राह्मणत्व को प्रमाणित करूंगा। स्वामी जी ने भूमिहार-ब्राह्मण-आंदोलन को स्थान-स्थान पर अपने व्याख्यानों द्वारा उत्तम और अंतिम स्तर पर पहुंचाया। महासभा को संबोधित करते हुए संस्कृत भाषा महत्व की चर्चा के क्रम में प्रसिद्ध संस्कृत विद्धान मैक्स मूलर को प्रशंसा की, क्योंकि वे मानते थे कि भूमिहार ब्राह्मण भी ब्राह्मण ही हैं।[14]

हालांकि ब्राह्मणों का सामाजिक वर्चस्व ब्रिटिश शासन काल में पूंजीवादी संस्कृति के प्रभाव से कुछ घटा था फिर भी ब्राह्मण सनातन धार्मिक मान्यताओं को आधार बना अपने सामाजिक वर्चस्व की किसी-न-किसी रूप में कमोवेश बनाये हुए थे। समाज के शीर्षस्थ ब्राह्मण भी संपत्ति के स्वामित्व के ही आधार पर दो दलों में बंटे थे। गरीब ब्राह्मण जो पुरोहिती वृत्ति में लगे थे, गरीब और निर्धन थे और उन्हें 'याचक' कहा जाता था जबकि धनी ब्राह्मण 'अयाचक' कहलाते थे। 'याचक' ब्राह्मणों के पास जीविकोपार्जन के साधनों के अभाव में उन्हें अशिक्षित और अयोग्य बना दिया था। जबकि 'अयाचक' प्रायः सम्पन्नता और शिक्षा में आगे थे। गरीबी, अभाव तथा सम्पन्नता के बीच का अन्तर्द्वन्द्ध ब्राह्मणों को दो परस्पर विरोधी खेमों में खड़ा कर दिया था।

स्वामी जी ने दोनों वर्गों के लोगों को उचित मार्ग पर लाने के लिए सराहनीय प्रयत्न किया।[15] स्वामी जी ने भूमिहार ब्राह्मणों के स्वाभिमान को जगाया और 'ब्रह्मर्षि वंश विस्तार', 'कर्म कलाप', 'ब्राह्मण समाज की स्थिति', 'झूठा भय मिथ्याभिमान' आदि ग्रन्थों की रचना कर ब्राह्मण-वर्ग की मानसिक कुण्ठा के उन्मूलन का प्रयत्न किया। शास्त्रों का प्रमाण देकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि याचक और अयाचक ब्राह्मण सदा से होते आये हैं और भूमिहार ब्राह्मण मुख्यतः अयाचक हैं। स्वामी जी समझते थे कि भूमिहारों के साथ ब्राह्मण शब्द जुड़ा हुआ है। जिस तरह कान्यकुब्ज ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण है उसी तरह भूमिहार ब्राह्मण भी ब्राह्मण है इसे स्वामी जी ने स्पष्ट अपने लेखों में लिखा है। इस संबंध में स्वामी जी के कथन द्वितीय अध्याय में उद्धृत किया गया है।

स्वामी जी ने हीनभावना से ग्रसित एवं समाज में जागृति पैदा करने का कार्य किया लेकिन उन्होंने एक बार चुनाव में अपने ही जाति के हथुआ महाराज का पक्ष नहीं लेकर एक धोबी का समर्थन किया था।[16] इससे स्पष्ट है कि स्वामी जी जाति विशेष के प्रभाव या जातीय राजनीति को प्रबल बनाने में नहीं लगे हुए थे बल्कि एक सामाजिक कुरीति को समाप्त कर समाज में जागृति पैदा करना

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

चाहते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वामी जी जाति-भावना से मुक्त थे। 1915 ई॰ "भूमिहार ब्राह्मण परिचय" नामक चार सौ पृष्ठों का ग्रन्थ लिखकर स्वामीजी ने 1916 में प्रकाशित कराया। अब भूमिहारों को भी ब्राह्मणों जैसा पुरोहिती करने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने इसके लिए दूसरी पुस्तक "ब्राह्मण समाज की स्थिति" लिखी। तीसरी पुस्तक "झूठा भय और मिथ्याभिमान" लिखी। पुरोहितों कार्य में कठिनाई न हो इसके लिए इन्होंने "कर्मकलाप" 12 सौ पृष्ठों की पुस्तक लिखी। जिसमें इन्होंने कर्म काण्ड एवं ज्योतिष सम्बन्धित बातों की चर्चा की है। सभी ब्राह्मणों के साथ भूमिहार ब्राह्मणों का सम्बन्ध पता लगाकर उन्होंने पांचवीं पुस्तक 'ब्रह्मर्षि वंश विस्तर' 1919 ई॰ में लिखी। 'ब्रह्मर्षि वंश विस्तर' एक समाज शास्त्रीय शोध ग्रन्थ है।[17] स्वामी जी ने उत्साह में आकर इन सबकी ब्योरे बार लम्बी सूची तैयार की और अपने ग्रन्थों में प्रतिपादित किया–"दान लेना और पुरोहिती करना ब्राह्मणों के लिए कोई जरूरी नहीं है। परन्तु यदि विरोधी लोग बार-बार यह कहते रहेंगे और पुरोहितों के अभाव में ही भूमिहारों को अब्राह्मण सिद्ध करने की कुचेष्टा से बाज नहीं आयेंगे तो हारकर भूमिहार ब्राह्मणों को भी सामूहिक रूप से पुरोहितों को अपनाना ही पड़ेगा। बाद में स्वामी जी ने भूमिहारों से कहा–आत्मसम्मान की पुकार है कि वे पुरोहिती कर्म को अपनायें।[18] वास्तव में पौराणिक भारतीय समाज में व्याप्त वर्ण-व्यवस्था की ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन पूंजीवादी संस्कृति ने अस्त व्यस्त करना शुरु कर दिया था। ब्रिटानी शासनकाल में जिस नई भूमि व्यवस्था का सृजन किया, जो साम्राज्यवाद के हित को ध्यान में रखकर किया गया था, उसमें भूमिहार जाति के उद्‌भव और विकास एक नये जमींदार वर्ग के रूप में हुआ था। ब्राह्मण समाज की, जो सनातन रूप से कृषि या व्यवसाय तथा उद्योगों से जुड़ा नहीं था, औपनिवेशिक दासता के काल में उसकी आर्थिक स्थिति में प्रायः ह्रास होता गया। जाति प्रथा में आ रहे क्रमिक ह्रास की स्थिति में भी स्वामी जी अपने प्रारम्भिक जीवन काल में उसमें जुड़े रहे। हालांकि पुरोहिती वृत्ति को एक अभिशाप के रूप में देखते थे, फिर भी भूमिहार जाति की गरिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए ही उन्होंने उपर्युक्त आह्वान किया था। हालांकि स्वामी जी का यह जातीय चिन्तन अपने आप में एक प्रतिगामी चिन्तन लगता है, मगर उसकी एक उपलब्धि यह है कि भूमिहारों को ब्राह्मणों की श्रेणी तक लाने के लिए उनके कार्य ने ब्राह्मण को जातीय श्रेष्ठता को समाप्त करने में एक हद तक योगदान किया। फिर भी उसका व्यापक प्रभाव ऐसा नहीं था जो वर्ण-व्यवस्था को ध्वस्त करने में दूरगामी परिणाम ला सके। वास्तव में भारतीय सामंत सामाजिक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

संरचना के ये अवशेष किसी-न-किसी रूप में आज भी वर्तमान हैं और ब्राह्मणों का वर्चस्व आज भी कायम है। 'ब्राह्मण समाज की स्थिति' स्वामी जी ने ब्राह्मणों के प्राचीन निष्ठा को भारतीय वांड्मय, वेदों आदि से उद्धरण प्रस्तुत करते हुए यह निष्पादित किया है कि ब्राह्मण की प्रतिष्ठा का मूल कारण क्या था। स्वामी जी ने उद्धृत किया "ब्राह्मण जन्म मात्र से ही 'नित्य धर्म की मूर्ति है, क्योंकि वह धर्म के लिए ही उत्पन्न हुआ है और उसी के द्वारा ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर सकता है। इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने के साथ ही ब्राह्मण सब प्राणियों का मालिक और धर्म का रक्षक होता है।"[19] स्वामी जी प्रतिष्ठित करते हैं कि ब्राह्मणों को यह उच्च स्थान उनके गुणों के कारण प्राप्त था।

स्वामी जी ने ब्राह्मण समाज की अधोगति का सांगोपांग वर्णन किया है।[20] ब्राह्मणों को अधोगति के कारणों का विवेचन करते समय स्वामी जी ने जिन मूल कारणों का जिक्र किया है उनमें व्यापक वैज्ञानिक दृष्टि का सामंजस्य कम मिलता है, क्योंकि उनके तर्कों में व बाह्य सामाजिक संरचना को ही मूल कारण मानते है। जैसे आपसी भेदभाव, एक दूसरे से सामंजस्य की कमी आदि। अपने तर्कों के समर्थन में स्वामी जी ने बहुत से 'विचारकों, पुस्तकों, सम्मेलनों के प्रस्ताव आदि का जिक्र किया है[21] और यथार्थ प्रमाण प्रस्तुत किया है। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम और 20वीं सदी के प्रथम कई दशकों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा सामंती और पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया के घोल मेल से जन्मे जिस आर्थिक सरंचना का निर्माण किया जा रहा था उससे पौराणिक या ब्रिटिश पूर्व भारत को आर्थिक-सामाजिक संरचना में एक प्रतिगामी बदलाव आ रहा था, जो इंग्लैंड के पक्ष में तथा भारतीय स्वार्थ के खिलाफ था। ऐसी विकृत व्यवस्था के जिस आर्थिक-सामाजिक मान्यताओं को प्रतिष्ठित कर रही थी उसका स्वाभाविक परिणाम था भारतीय समाज में एक बदलाव और स्वामी जो तकरीबन 1915-16 तक इस बदलाव की प्रक्रिया की वैज्ञानिकता को नहीं समझ पाए थे, मात्र जो समझे थे वह था परिवर्तित उत्पादन-प्रक्रिया-द्वारा उत्पन्न किया गया परिणाम, उसका कारण नहीं। यही कारण था कि स्वामी जी अपने जीवन के प्रथम दशकों में जाति प्रथा के उन्मूलन नहीं इसकी शृंखला में भूमिहारों को अग्रणी स्थान दिलाने का संघर्ष कर रहे थे। बाद में यह क्रम इनके जीवन में उलट गया। बाद के वर्षों में उन्होंने शोषण के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया।

एक मध्यमवर्गीय अशिक्षित परिवार का परिवेश, जिसमें वे पले थे, समस्याओं के प्रति किसान मनोवृत्ति को उनमें पैदा किया था। गांवों में जमींदारों का दमन देख चुके थे जो आगे उनके जीवन को जमींदार विरोधी मोड़ देने में योगदान किया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मगर संस्कृत वांड्मय का प्रभाव उन पर इतना न प्रबल था कि पौराणिक धार्मिक आस्थाओं से पूर्णतः मुक्त होने की प्रक्रिया को अति धीमी गति दे रहा था। अपारनाथ मठ के पंडित हरिनारायण त्रिपाठी से सिद्धांत कौमुदी, शंकर भट्टाचार्य से न्याय, नित्यानन्द के मीमांसा, दूसरे से वेदान्त, व्याकरण में मनोरमा, शेखर और महाभाष्य, वात्स्यायन भास्यन्यायवार्त्तिक, तात्पर्य टीका, कुसुमांजलि, आत्मतत्त्व विवेक जैसे ग्रन्थों का प्रभाव तो था ही इसके बाद भी नैयायिक जीवन नाथ मिश्र से पक्षता सामान्य निरुक्ति, सिद्धांत लक्षण, खण्डन खण्डखाद्य, संक्षिप्त शारीरिक अद्वैत सिद्धि आदि का अध्ययन करते हुए ये मीमांसा में न्याय, रत्नमाला तक आ चुके थे। इन वांड्मय का, जो एक ऐसे आर्थिक सामाजिक परिवेश में लिखे गए थे जब समाज का स्वरूप मूलतः संरचना की दृष्टि से धर्म आधारित राज्य और वर्ण-धर्म आधारित समाज था, प्रभाव उन्हें जातीय वरीयता और अवरीयता को मानसिकता बना चुके थे। उनका मूल उद्देश्य बन गया था भूमिहारों की जातीय श्रेष्ठता को ब्राह्मणों के समकक्ष खड़ा करना। चूंकि संस्कृत वांड्मय ब्राह्मणों को उनकी श्रेष्ठता का मुख्य आधार प्रस्तुत करना था, इसलिए भूमिहारों को उन्होंने संस्कृत पठन-पाठन का मशविरा देते हुए अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासभा के मंच से उन्होंने कहा, "सबसे पहले संस्कृत का प्रचार करना चाहिए। यह लज्जा की बात है कि हम उससे उदासीन हैं। जर्मनी जैसा गुण-ग्राहक हमारी विधाओं का पठन-पाठन करे, रक्षा करे। हमें मीमांसा पर प्रभाकर के एक ग्रंथ की आवश्यकता थी–वह हमें जर्मनी में मिला। उसे लिखकर बनारस से लौटाया गया। धिक्कार है तुम लोगों पर। जर्मनी को साधुवाद।"[22]

संस्कृत साहित्य के प्रति स्वामी जी का ऐसा अपनत्व भूमिहार जाति को ब्राहमणत्व प्रदान कराने के लिए तथ्यों और प्रमाणों का संकलन कराना था जिसे उन्होंने स्वयं किया। बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, प्रयाग आदि की यात्रा के प्रसंग में उन्हें ज्ञात हुआ कि भूमिहारों का शादी-ब्याह सरयूपारियों, कान्यकुब्जों और मैथिलों के साथ हुआ है। अपने इस शोध कार्य के ही आधार पर उन्होंने 'भूमिहार ब्राह्मण परिचय' नामक पुस्तक की रचना की थी और कई वर्षों बाद अत्यधिक सामग्री जमा कर उन्होंने इसी पुस्तक का विस्तार कर "ब्रह्मर्षि वंश विस्तार' के नाम से प्रकाशित कराया था। बिहटा, राघवपुर में परमहंस सीताराम जी दास की जमीन पर, सीताराम आश्रम खोलने का लक्ष्य स्वामी जी ने तय किया था, जिसका वर्णन उस पंचायत नामा में है–यहां ब्राह्मचर्याश्रम खोला जाएगा और इसमें केवल भूमिहार ब्राह्मणों के लड़को को स्थान दिया जाएगा, उन्हें व्यय दिया जायेगा और ये ही पढ़ाये जाएंगे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भूमिहार ब्राह्मण सभा से उनका सम्पर्क प्रायः 1913 से लेकर 1929 तक बना रहा और उसी समय के मध्य में उन्होंने 'ब्राह्मण समाज की स्थिति' और 'झूठा भय तथा मिथ्याभिमान' पुस्तकों की रचना की। संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की तथा भूमिहारों द्वारा पुरोहिती किए जाने पर बल दिया। वर्षों उन्होंने स्मृतियों, आचार ग्रथों का अध्ययन किया तथा कर्म काण्ड विषयक ग्रंथों का मनन करते रहे, फलस्वरूप उन्होंने "कर्मकलाप" नामक एक वृहद ग्रंथ लिखा, तथा निर्णय-सिन्धु की टिप्पणियों की समीक्षाएं की।[23] बिहार के बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना कर उसे संस्कृत-अध्ययन का केन्द्र बनाया।

वास्तव में भूमिहार ब्राह्मण सभा से स्वामी जी के लगाव काल को दो भागों में बांटा जाना चाहिए :– प्रथम चरण में उनकी 1920 की गतिविधियां हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य जातीय विभाजित समाज में उन्हें भूमिहारों को तथा कथित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समकक्ष प्रतिष्ठित करने का अथक प्रयास था। निस्संदेह उनका यह कृत्य एक पुरानी रूढ़िवादिता एवं धर्म आधारित शासन-व्यवस्था में उत्पादन के साधनविहीन ब्राह्मणों को अति उच्च स्थान पर बनाये रखने की संस्कृति का यह विरोध था, मगर 20 वीं सदी के भारत में जब पूंजीवादी संस्कृति इस अवधारणा पर चोट कर रही थी, इस तरह के जातीय आन्दोलन के लिए न भौतिक वातावरण था न कोई प्रबल उद्देश्य। स्वामी जी अपने आन्दोलन से किसी भूमिहार का ब्राह्मणत्व तो नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन अपने ऊपर जातीय नेता होने का लेबल जरूर लगा लिए।

कतिपय लेखकों ने लिखा है कि ''अंधविश्वास और रूढ़ियों की शृंखला टूट गई। भूमिहार ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मणों के पाशविक सामाजिक अत्याचार से मुक्ति मिली।" इस प्रकार उक्तियों की निस्सारता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि स्थानीय स्तर पर भूमिहारों को राजसत्ता में बड़ी भागीदारी है, भूस्वामित्व में उनका हिस्सा काफी मजबूत रहा है ऐसी हालत में भूमिहारों के पुरोहिती का अधिकार नहीं था और सभ्रांत भूमिहार उसे प्राप्त करना भी नहीं चाहते थे। आधुनिकता का प्रभाव तो इतना प्रबल था कि 80 प्रतिशत ब्राह्मण पुरोहिती छोड़ चुके थे।''[24]

स्वामी जी ने 'ब्राह्मण समाज की स्थिति' में ब्राह्मणों की 'प्राचीन प्रतिष्ठा' का वर्णन करते हुए प्राचीन भारतीय साहित्य को आधार बनाया और उनकी धार्मिकता की तुलना अगर दक्षिण और पश्चिम के ब्राह्मणवाद विरोधी आन्दोलनों से करें तब वह पुनरुत्थानवादी श्रेणी में ही आ सकता है। क्योंकि वेदों की जिन सूक्तियों[25] का उद्धरण उन्होंने किया है या अन्य संस्कृत वांड्मय को उद्घृत किया है उनमें

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

धार्मिकता का सनातनी स्वरूप ही उजागर होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण समाज के आधुनिक अधःपतन के सम्बन्ध में जिन साक्ष्यों एवं प्रकरणों के उदाहरण पेश किये गये हैं, उनमें भी इन्हीं साहित्य साक्ष्यों को उद्घृत किया है।[26] जो भी हो स्वामी जी के इस जातिगत क्रिया कलापों का अगर एक सकारात्मक पहलू यह था कि सनातनी ब्राह्मणवाद के मिथ्या वर्चस्व को धक्का लगा और एक हद तक पुराने जातिगत स्वाभिमान को मिटाने की कोशिश की गई वहीं दूसरी तरफ इस सामाजिक पृष्ठभूमि के चलते भूमिहारों का एक संभ्रांत तबका स्वामी जी के सिपाहसालारों के साथ मधुर रिश्ता बना उन्हें भ्रष्ट करनेकी चेष्टा में कामयाब रहा। फिर, मझोली जातियों के अनेक नेता स्वामी जी की इस जातिगत संगठन के साथ सम्बद्ध होने के कारण उनके प्रति शंकालु बन गए, उन्हें किसान आंदोलन में नहीं लाया जा सका। जबकि मध्य बिहार में इन संगठनों का खासा प्रभाव था। खुद स्वामीजी ने भूमिहारों को ब्राह्मणों के समकक्ष खड़ा करने के अथक प्रयास का फल क्या पाया? वे लिखते हैं ''आश्रम के प्रति जमींदारों के विद्रोह ने मुझे यह भी प्रत्यक्ष बताया कि जातीय सभायें और जाति व धर्म के नाम पर दिये जाने वाले दान का क्या अर्थ होता है। इन सभाओं को धनिक और चलते-पुर्जे लोग अपने हाथ का खिलौना बना कर रखते हैं और समय-समय पर कुछ पैसे देकर अपनी जमींदारी, अपना व्यापार और अपना प्रभाव दृढ़ कर लेते हैं–न कि परलोक या उपकार के लिए भी करते हैं[27] इस प्रकार स्वामी जी का एक लम्बा समय जिस प्रमाण में लगा उसकी निष्फलता या स्वयं के मोह भंग होने के बाद उनका जीवन राजनीति के प्रति मुखातिब हुआ।

इस प्रकार स्वामी जी की एक यात्रा ''मैं ईश्वर को ढूंढने चला था। मैंने जंगलों एवं पहाड़ों में ढूंढा। ग्रंथों और पुस्तकों में भी कम नहीं ढूंढा, मगर मैं उसे नहीं पा सका,"[28] से चलकर भूमिहारों को ब्राह्मणत्व प्रदान कराने के रास्ते, संस्कृत शिक्षा का प्रचार-प्रसार के लिए परिश्रम के परिणामों तले के अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में अब तमाम पौराणिक मान्यताओं के प्रति मोह के जाल से साम्राज्यवादी उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष की दिशा में संक्रमण कर गया।

राजनीति एवं स्वतंत्रता संग्राम में

स्वामी जी का राजनीतिक जीवनकाल महात्मा गांधी द्वारा संगठित 1920 के असहयोग आन्दोलन से शुरू होता है। संन्यास धर्म नव साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक क्रिया कलाप में संक्रमण कर गया। ऐसा क्यों हुआ? वास्तव में प्रथम विश्व-युद्ध के बाद के वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने आर्थिक एवं राजनीतिक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दोनों ही क्षेत्रों में एक नई और उच्चतर नीतियों का अवलम्बन शुरू किया। आर्थिक क्षेत्र में पुरानी आर्थिक प्रतिरोधात्मक नीतियों को त्याग कर भारत में भी ब्रिटिश पूंजी के नियंत्रण में औद्योगीकरण की नीति अपनाई गई तथा राजनीतिक क्षेत्र में क्रमिक ढंग से भारत को ब्रिटिश शासन के तहत स्वायत्तता बढ़ाने की नीति को अख्तियार की गयी। इस नई नीति ने भारतीय राष्ट्रीय पूंजी और ब्रिटिश साम्रज्यवादी पूंजी के बीच के अन्तर्विरोध को काफी गहरा एवं विस्तृत बना दिया। कतिपय ऐसे कदम उठाए गए, जिन्हें किसानों को अपने बेचने वाले सामानों के मूल्य में काफी ह्रास हुआ, ब्रिटिश मालों के भारत आगमन के लिए कई सुरक्षात्मक कानून बनाए गए आदि। पहले से चला आ रहा स्वदेशी और बहिष्कार आन्दोलनों को कम उपलब्धि भारतीय जनमानस को ज्यादा सशक्त आन्दोलन के लिए प्रेरित कर रहा था, तथा औद्योगिक मजदूर युद्धोत्तर काल की आर्थिक मंदी से त्राण पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संक्षेप में युद्धोत्तर काल का भारत एक ज्यादा सशक्त एवं क्रांतिकारी संघर्ष के लिए परिस्थिति तैयार कर चुका था और उसकी बुनियाद गांधी के चम्पारण आन्दोलन से जुड़ते-जुड़ते असहयोग आन्दोलन शुरू करने तक आ गया था।

स्वामी जी के राजनीति में प्रवेश करने के पूर्व की यही स्थिति भारत में मौजूद थी उसने स्वामीजी के चिन्तन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। किसान और सनातनी मनोवृत्ति वाले स्वामी जी को गांधी जी द्वारा चम्पारण में किसानों को निलहों द्वारा शोषण के खिलाफ का आन्दोलन प्रभावित कर चुका था और बदली भौतिक परिस्थितियों में राष्ट्रवाद का चिन्तन स्वामी जी के लिए अपरिहार्य बन गया था। 5 दिसम्बर, 1920 को पटने में मौलाना मजहरुलहक के मकान पर स्वामी जी को महात्मा गांधी से प्रथम वार्तालाप हुआ। फलतः खिलाफत आन्दोलन में गांधी ने स्वामी जी को राष्ट्रवाद की उफनती लहर में धकेल दिया।[29] महात्मा गांधी, मौलाना आजाद जैसे नेताओं के भाषण से स्वामी जी प्रभावित हुए। स्वामी जी ने निश्चय किया "देश की सेवा बड़ी चीज है, मैं मुल्क की सेवा करूंगा।[30] गांधी जी से बातचीत के बाद स्वामी जी के दिल पर यही प्रभाव पड़ा कि उन्हें राजनीति में फौरन कूद पड़ना चाहिए। देश के उपकार के लिए ही नहीं, इसलिए कि तभी वे सच्चे संन्यासी बन सकेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सृजित नयी आर्थिक नीति से जिसमें किसान मजदूर सब कुप्रभावित हो रहे थे, स्वामी जी ने साम्राज्यवाद विरोधी दार्शनिकता को तो अपनाया, मगर उनकी मनः स्थिति अभी भी संन्यासवाद के ही भंवर में पड़ी थी। इसी विचार से प्रभावित होकर वे 1921 के नागपुर कांग्रेस में शामिल होने के लिए चल पड़े। स्वामी जी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के जीवन के इतिहास-पथ पर नागपुर कांग्रेस ने अपनी अमिट रेखाएं अंकित कर दीं, क्योंकि नागपुर कांग्रेस में पहले पहल "भिक्षां देहि"—और केवल गरमागरम लेक्चर झाड़ने को छोड़ आत्म-सम्मान का मार्ग पकड़ा। भारत के हक के दावे के साथ ही उसके पूर्ण न होने पर सरकार से "युद्धं देहि" का पहली बार निश्चय किया गया। इस प्रकार नागपुर कांग्रेस ने देश में नयी स्फूर्ति भर दी।[31] स्वामी जी कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में भी सहयोग देने लगे। वे एक कट्टर गांधीवादी के रूप में कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में भी सहयोग देने लगे। वे कट्टर गांधीवादी के रूप में कांग्रेस और राजनीति में शामिल हो गये।[32]

1920 के दशकों में स्वामी जी जब साम्राज्यवाद-विरोधी भारतीय मुक्ति संग्राम में पदार्पण किए तो उनका झुकाव किसान-आंदोलन की तुलना में स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ ज्यादा था। स्वतंत्रता-आन्दोलन का, जो कांगेस के नेतृत्व में तमाम साम्राज्यवादी तत्वों का एक संयुक्त मोर्चा के रूप में चल रहा था; अनुभव स्वामी जी का कांगेस भ्रम दूर होने की महागाथा है।

स्वतंत्रता संग्राम में 1920 के दशक में स्वामी जी पहली बार तब जेल गए जब वे गाजीपुर जिला काग्रेंस कमिटी के अध्यक्ष थे[33] ओर कांगेस के अहमदाबाद महाधिवेशन से लौटते समय गाजीपुर में पकड़े गए।[34] 2 जनवरी, 1922 को जेल भेज दिए गए, इसके बाद अपने बिहार कार्य क्षेत्र से क्रमशः 1930 एवं 1940 में जेल गए।[35] सबसे पहले उन्हें काग्रेस के जातिवादी एवं साम्प्रदायिक चरित्र का अनुभव बिहार की जेलों में हुआ। 1920 के जिला परिषदों के चुनावों के वक्त उन्हें परिलक्षित हुआ कि "भीतर ही भीतर गुटबन्दी थी। कांगेस के प्रमुख लोग जाति पाति की बात भीतर ही भीतर करते थे, खुल कर तो कर सकते नहीं थे। वही चुनाव नहीं उसके बाद भी आज तक जितने चुनाव हुए हैं, इन सर्वो के अनुभव से मैं कह सकता हूं, गुस्ताखी माफ हो, कि अधिकांश बिहारी राष्ट्रवादी नेता भीतर ही भीतर जातिवादी भी है .... 'ठग-ठग मौसेरे भाई' के अनुसार प्रायः सबों का अपनी-अपनी जाति के पक्षपात में सट्टा-पट्टा भी लग जाता है। इसलिए कोई किसी को कुछ भी खुल कर कहता नहीं।"[36]

अपने जेल प्रवास में दो दिनों की भूख-हड़ताल, श्रेणी विभाजन के खिलाफ संघर्ष[37] आदि के कारण स्वामी जी को गाजीपुर वालों के साथ फैजाबाद और फिर लखनऊ जेल में भेज दिया गया।[38] एक सम्पूर्ण गांधीवादी दार्शनिकता की मनोवृत्ति लिए स्वामी जी ने जेलों में क्या अनुभव किया? सम्पूर्ण कांग्रेसी नेतागण खाने-पीने तथा रहन-सहन की सुविधा के लिए ही जेलों में अनशन तक करते थे। आचार्य कृपालानी, सम्पूर्णानन्द, बाबा राघव दास का साक्षात्कार उन्हें जेलों में ही हुआ।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

किसान मनोवृत्ति वाले स्वामी जी को, जिन्होंने गांधीवाद को, जो खुद एक पिछड़ी ग्रामीण व्यवस्था का दर्शन था, अपना दर्शन बना लिया था, यह विडम्बना पूर्ण लगा कि राष्ट्रीय मुक्ति-संग्राम के तथाकथित सेनानी कष्ट सहने की गांधीवादी अवधारणा से भिन्न आचरण कर रहे थे।

1930 के नमक सत्याग्रह के गांधी के आह्वान पर स्वामी जी नमक कानून भंग कर जेल गये और छः मास की सजा पाकर बांकीपुर जेल से हजारीबाग सेन्ट्रल जेल जाने पर उन्हें सत्याग्रहियों के प्रति वहीं पुराना कटु अनुभव हुआ। सत्याग्रही भोगवाद में निर्लिप्त थे, और सुविधा प्राप्ति के लिए जेलों में लड़ते रहते थे। स्वामी जी अपने जेल अनुभव को बताते हैः–

"मेरी मानसिक वेदना कभी-कभी इतनी बढ़ जाती की, माफी मांग कर चले जाने को सोचने लगता। वह केवल इसलिए कि मुझे देशद्रोही समझकर फिर ये लोग मेरे पास कांगेस के संबंध में पूछने न आएंगे, और न फिर मैं कभी आगे इस नरक यातना में पहुंचूंगा।[39]

गांधी द्वारा सत्याग्रह वापस लिए जाने के बाद स्वामी जी जेल से रिहा हुए, मगर उनका गांधीवादी रुझान को करारा झटका लग चुका था कि गांधी किसी सशक्त आन्दोलन को उसकी पूर्णाहुति तक नहीं लड़ सकते। हालांकि स्वामी जी के विचारों में क्रान्तिकारी दर्शन का प्रभाव नहीं था, फिर भी वे गांधी को एक आदर्श साम्राज्यवाद विरोधी योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित कर चुके थे मगर अब इस धारणा को झटका लग चुका था। उन्होंने समझा दिया जमकर लड़ते रहना गांधी जी के लिए असंभव है। स्वामी जी की तो यह मान्यता थी कि जो आजादी हम चाहते थे वह तो बिना मुड़े-झुके और समझौता किए ही लड़ाई जारी रखने से मिल सकती है।[40]

1934 के भूकम्प के बाद सहायता कार्य में लगे स्वामी जी को मालूम हुआ कि दरभंगा महाराज राजेन्द्र बाबू से ऊपर-ऊपर बातचीत कर बिहार टिर्नेसी एक्ट को जमींदारों के पक्ष में पास करवा लेना चाहते हैं। जब स्वामी जी को यह पता चला कि जो मदद किसानों को जीने के लिए दी जा रही है उसे जमींदारी लगान में हड़प लेना चाहते हैं तो स्वामी जी ने गांधी जी को इसकी सूचना दी मगर गांधी जी भी इसका उचित निराकरण नहीं किये और परिणामस्वरूप स्वामी जी ने गांधी जी से सदा के लिए अलग हो गये। गांधी जी की उत्तर स्वामी सहजानन्द को इतना असन्तोषजनक लगा कि इन्होंने वहीं गांधी जी के सामने ही गांधीवाद को आखिरी सलाम किया। स्वामी जी को चौदह वर्ष की कांगेसी मान्यता आज सदा के लिए समाप्त हो गयी। फिर भी वे कांगेस में रहे और बाद में कांगेस छोड़ा।[41]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

फैजाबाद जेल में गीता का मूल पाठ, बिना किसी टीका के, स्वामी जी ने जीवन की सम्पूर्ण दार्शनिकता को एक नया आयाम प्रदान किया, जो उच्च से उच्चतर की दिशा में था। स्वामी जी ने लिखा, हमारे जीवन में वह पहला ही अवसर था जब हमने गीता का रहस्य समझा और जीवन की बाधाओं और चिन्ताओं से निश्चिंत हो गया। जीवन भर वेदान्त और अन्य दर्शनों के पढ़ने से शक्ति हमें उपलब्ध न हो सकी वहीं हमें गीता की कृपा से फैजाबाद जेल में प्राप्त हो गई। हमारा जीवन स्थिर हो गया।[42]

लखनऊ जेल में पं. जवाहरलाल नेहरू से, जिनकी देश भक्ति और साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा ने काफी प्रभावित किया, मुलाकात हुई।[43] स्वामी जी का नेहरू के साथ कई पत्राचारों से पता लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया जा रहा भारतीय मुक्ति-आन्दोलन की रणनीति और कार्यनीति के सम्बन्ध में उनका केन्द्रित आन्दोलन की रणनीति नेहरू के विकेन्द्रित आंदोलन की रणनीति के विचारों पर हावी हो गई।[44] मगर असहयोग आन्दोलन की अशर्त वापसी का कुपरिणाम भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन पर गहरा था, क्योंकि आन्दोलन के पूर्व और प्रथम विश्वयुद्ध जनित साम्राज्यवाद के आर्थिक संकट ने संगठित मजदूरों के विद्रोह को काफी बल दिया था, हड़तालों का अविराम सिलसिला जारी था तथा असहयोग आन्दोलन अपने विकास की इस उच्चतर मंजिल को प्राप्त कर लिया था, जहां तमाम साम्राज्यवाद विरोधी ताकतें एक संयुक्त मोर्चा के तहत एक जुट हो गई थी, ऐसी स्थिति में आन्दोलन की वापसी से व्याप्त असंतोष ने वर्गीय ओर साम्प्रदायिक एकता को भी खंडित कर दिया। इस राजनीतिक घटनाक्रम का ही फल था कि बारदोली के बाद दिल्ली में आहूत अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक में गांधी का अहिंसा पर बल देने वाला प्रस्ताव पारित न हो सका और वे कांगेस की सदस्यता तक से त्याग पत्र देने को उतारु हो गए। कांगेस के अन्य नेताओं देशबन्धु, मोहम्मद अली, मोतीलाल नेहरू आदि का गांधी को राजी कराने के प्रयास का, जिसमें मोहम्मद अली ने अपनी टोपी गांधी के पैर पर रखा था, काफी प्रभाव डाला।[45]

असहयोग आन्दोलन के बाद की घटी साम्प्रदायिक वारदातों के प्रति कांगेस के रवैये का वर्णन स्वामी जी करते है "नेताओं ने साम्राज्यशाही से लड़कर आजादी छीन लेने से इनकार किया और ब्रिटिश साम्राज्यशाही से समझौता कर लिया। इसी का नतीजा है कि देश में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए जिसमें लाखों जंनता को भय मुसीबत और बर्बादी का सामना करना पड़ा। मगर लीग के नेता जो सम्प्रदायवाद के समर्थक हैं और कांग्रेस के नेता को राष्ट्रीयता की दुहाई देते हैं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दोनों ही ने साम्प्रदायवाद से लड़ने के बदले साम्प्रदायिक प्रतिगामियों को खुश करने की नीति अपनाई है।[46]

कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों के तहत स्वामी जी ने बिहार के बिहटा आकर जब अध्ययन-अध्यापन शुरू किया तो क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा और जमींदारों के जुल्म, भावली, दानाबंदी, बैठं बेगारी, नजर तहरीर आदि के विरुद्ध किसानों को संगठित करने लगे, तथा पश्चिम पटना किसान सभा का गठन 1926 के अन्तिम दिनों में किया। मगर गांधीवादी दार्शनिकता का प्रभाव उस किसान सभा की एक समझौतावादी किसान संगठन के रूप में ही रहा। गो-हत्या के खिलाफ ब्रह्मपुर मेले के आन्दोलन का अनुभव, जिसमें तमाम निहित स्वार्थ, जमींदार से लेकर मेल के ठेकेदार तक, जो सबके सब हिन्दू थे, स्वामी जी को बड़ा कटु रहा। उन्होंनें 'मेरा जीवन संघर्ष' में 'भारी भूल' के उप शीर्षक में इसकी विस्तार से चर्चा की है।[47] उन्हीं के शब्दों में उन्हीं दिनों ब्रह्मपुर के मेलेमें एक बड़ा ही कटु अनुभव हुआ और हिन्दुओं की गौरक्षा की पोल मैंने बखूबी समझ ली।[48] उन्होंने धर्म की असलियत को समझा तथा निहित स्वार्थों के असली रूप को भी। वे इस संबंध में लिखते हैं कि मैंने सिर्फ इतना ही परिणाम निकाला कि हिन्दुओं का गोरक्षा का प्रश्न ढोंग है, दिखाऊ और बनावटी है।[49] तबसे उन्होंने गोरक्षा के प्रश्न की निरी नादानी माना तथा गोहत्या का दोषी तबसे सोलहो आने हिन्दुओं को ही मानना शुरू कर दिया। वे स्वयं लिखते हैं "हम सबको लाख समझाते रह गए कि आप ही के धर्म की बात है जिसे आप ही पुकारते हैं। मगर सुने कौन?................. ......इसका कारण क्या था? यही न कि धर्म और भगवान उनके सामने आए तो सही-रुपये पैंसे के खिलाफ रुपये पैसे का विरोधी बनकर– इसलिए उनका तिरस्कार हुआ....................अध्यात्मवाद का भौतिकवाद से जमकर भिड़न्त हुई और अध्यात्मवाद बुरी तरह पछाड़ा गया। ....मैंने स्वयं देखा कि धर्म का प्रश्न किस तरह बाहरी और दिखावटी है।[50] वे आगे कहते हैं "मेरी कट्टर धार्मिक भावना को कड़ी ठेस लगी और मैं तिलमिला गया। वर्ग के बारे में भी उन्होंने अपनी पुरानी धारणायें छोड़ीं या यों कहें वे छिन्न या निर्मूल हो गईं।[51] उनको लगा यही ठेस तथा धार्मिकता की आड़ में पनपता दोषयुक्त समाज ने उन्हें वस्तुपरक परिस्थितियों को जिनसे वे अन्ततः भौतिकवाद की वैज्ञानिक पद्धति की ओर मुखातिब हुए।

अध्यात्मवाद से विमुखता हिन्दू कट्टर पंथियों की कायरता, द्वारिका और पुरी के शंकराचार्य भारतीय कृष्ण तीर्थ की नामर्दगी आदि का अनुभव गम्य बोध उन्हें अध्यात्म से भौतिकवाद की तरफ ले आया। यों तो कांगेस से विमुख होने का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कारण और उससे मुक्ति की लम्बी कहानी है मगर मुख्यतः उन्होंने देखा कि कांग्रेस के अन्दर धूर्तता, दो मुद्दापन, अनुशासनहीनता, स्वार्थपरता और घोर अवसरवाद है। गांधी की दार्शनिकता मीमांसा उनके अनुयायियों द्वारा अपनी स्वार्थपरता के लिए अलग-अलग ढंग से की जाती है। धर्म और राजनीति की खिचड़ी ने उसे और बिगाड़ दिया। 1921 के असहयोग आन्दोलनों के अनुभवों का उनका निचोड़ है। "सत्य अहिंसा, सदाचार के नाम पर कांगेस में केवल दम्भ, प्रवंचना, हिंसा और असत्य का बाजार गर्म है। खूबी तो यह है कि जो लोग स्पष्ट वक्ता हैं उनके लिए गांधी के दल में कोई स्थान नहीं......................धर्म के नाम पर ये चीजें होती ही थीं, मगर जब धर्म आ गया राजनीति में तो वहां भी वही बाजार गर्म है।[52]

वास्तव में स्वामी जी का शाही कांग्रेस के वर्ग चरित्र का मूल्यांकन कोई सतही नहीं था, राष्ट्रीय पूंजी और साम्राज्यशाही के अन्तर्गत निर्मित जमींदार वर्ग और इनका वर्ग चेतन हिस्सा ही कांगेस का प्रतिनिधित्व करता था, जिसका साम्राज्यशाही के साथ अपना अन्तर्विरोध तो था ही, भारतीय जनआयाम के शोषित पीड़ित हिस्सा के साथ भी वर्गीय संघर्ष था। जहां कांगेस साम्राज्यशाही के खिलाफ संघर्ष में उक्त प्रथम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी वहीं स्वामी जी दबी-कुचली मानवता के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते थे अतः कांग्रेस के साथ उनका दर्शन सर्वथा टकराता रहा और क्रमशः वामपंथ की तरफ उन्मुख होता गया। इस वैचारिक संक्रमण से स्वामी जी को ग्रामीण सर्वहारा, छोटे मझौले किसानों के संघर्षों के प्रतिरूप में खड़ा किया और कांगेस से ज्यादा नजदीकीपन वामपंथी आन्दोलनों से कटा दिया, जो उनके किसान संघर्षों में और ज्यादा प्रखर होकर निखरा।

किसान-आन्दोलन में स्वामी जी

1929 में बिहार प्रान्तीय किसान सभा के गठन के पूर्व भी साम्राज्यवादी शासन द्वारा निर्मित जमींदार वर्ग और उसके द्वारा किसानों के शोषण का एक लगातार चलनेवाला सिलसिला बन गया था जिसके खिलाफ भारत में किसानों का विद्रोह हुआ था, जिसमें कूका विद्रोह, संथाल विद्रोह, नीलगिरि के किसानों का विद्रोह, मोपला विद्रोह, बिहार के आदिवासियों का विद्रोह प्रमुख था, मगर इन विद्रोहों[53] को सशक्त वाणी और सशक्त संगठनके अभाव में साम्राज्यवाद और उसके द्वारा पोषित देशी प्रतिक्रिया की ताकतों ने सम्मिलित रूप होकर दबा दिया था।[54] 1924 के बाद से, जब शाहाबाद जिले के सिमरी ग्राम को अपना केन्द्र बनाकर स्वामी जी ने चरखा और खादी का प्रचार शुरू किया था उसी वक्त से किसानों की दुर्दशा के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रति उनकी वर्ग-चेतना जागृत होने लगी थीं, और उसकी परिणति हुई सीताराम आश्रम बिहटा के निर्माण के बाद 1928 में एक पैसा सदस्यता शुल्क के आधार पर (किसानों को किसान सभा में संगठित करने में लिए) सदस्य बनाने में। संभवतः यह पटना पश्चिम किसान सभा का संगठन था जिसने आगे चलकर बिहार प्रान्तीय किसान सभा का रूप ग्रहण किया।[55]

1929 में मुजफ्फरपुर में बिहार प्रान्तीय किसान सभा का संगठन श्री कृष्ण सिंह को उसका 'जेनरल सेक्रेट्री बनाकर किया गया और उसके प्रथम सम्मेलन, सोनपुर में, स्वामी सहजानन्द सरस्वती को अध्यक्ष बनाकर सम्पन्न किया गया। सम्मेलन के तुरंत बाद बिहार विधान-सभा में किसान विरोधी जो काश्तकारी बिल पेश और पास किए जाने वाला था,[56] उसका प्रबल विरोध इस किसान सभा ने किया, जिसके फलस्वरूप सरकार को उस काम को वापस लेना पड़ा। यह किसान सभा की पहली विजय थी। मगर विडम्बना यह थी कि रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे समाजवादी विचारक तक इस सभा का विरोध इसलिए कर रहे थे कि, उनकी सम्भावना में, यह कांग्रेस के समानान्तर संगठन का स्वरूप ग्रहण कर भारतीय मुक्ति संग्राम को खंडित करने वाला था।[57] मगर स्वामी जी का किसान संगठन के पीछे जमींदारों के शोषण तथा उस शोषण[58] को गति प्रदान करने में सरकारी भूमिका के खिलाफ एक वर्गीय संघर्ष था, जो अन्ततः मुक्ति-संग्राम का एक पक्ष या अंग ही बन रहा था। स्वराज को परिभाषित करते हुए उसमें स्थापना की गई, "किसानों के स्वराज्य का अर्थ है दलितों का स्वराज्य।[59] स्वामी जी ने कांगेस और किसानों के सम्बंध को भी प्रभावित किया तथा किसान सभा के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए अपनी स्थापना में यह अवधारणा प्रदर्शित की, कि बिना आर्थिक आजादी के राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं। देश के किसान भारत की रीढ़ हैं, उनका वर्चस्व कांग्रेस पर होना चाहिए। कांगेस राजनीतिक संस्था है। किसान-सभा किसानों की वर्ग-संस्था है। जब तक राजनीति और अर्थनीति दो शब्द हैं तब तक ये दोनों संस्थाएं दो हैं.......... ....कांग्रेस मुल्क की आजादी के लिए लड़ती है, किसान सभा आर्थिक अधिकारों के लिए लड़ती है।[60]

उपर्युक्त उद्धरण इस तथ्य का गवाह है कि कांगेस और स्वामी जी की दार्शनिकता का मौलिक भेद यह है कि स्वामी जी आर्थिक आजादी के साथ राजनीतिक स्वाधीनता के पक्षधर थे। साम्राज्यवाद और घरेलू पूंजीवाद और जमींदारवाद की समाप्ति के साथ स्वाधीनता उनका लक्ष्य था, आर्थिक स्वाधीनता शहरी एवं ग्रामीण सर्वहारा को प्रदत्त कराने का उनका लक्ष्य कांग्रेस की अर्थनीति

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

से भिन्न था। मगर वास्तविकता यह है कि कांगेस के अन्दर का एक तबका, जो स्वामी जी के समतामूलक विचारों और अर्थिक स्वाधीनता के पक्ष में न था, जमींदारों का खिलाफत किया, और स्वामी जी की जमींदारी विरोधी नीतियों का समर्थन करता रहा। कांग्रेस संगठन में रूढ़िवादी सुझावों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरदार पटेल ने सीतामढ़ी की एक आम सभा में कहा था–

"बिहार में या हमारे मुल्क में इन जमींदारों की क्या जरूरत है? लोग कौन सा काम हमारे मुल्क के लिए करते हैं? सुना है किसानों को बहुत सताते हैं, और इनसे किसान बहुत डरते हैं, उनसे डरना क्या? ये तो बहुत कमजोर है। यदि हाथ में इनका सिर पकड़कर दबा दिया जाय तो इसका भेजा बाहर निकल आए।[61]

1931 में कांग्रेस और साम्राज्यवाद का समझौता हो गया गांधी इरबिन पैक्ट में, सत्याग्रह स्थगित था मगर डा. राजेन्द्र प्रसाद और श्रीकृष्ण सिंह ने गया और मसौढ़ी के किसानों की हालत की जांच की और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का वादा किया। स्वामी जी गांधीवादी समझौता परस्ती से उदास हो किसान-सभा का कार्य भी प्रायः बन्द कर दिये थे, तभी अखबारों में छपा एक फर्जी किसान-सभा के निर्माण की बात जिसका उद्देश्य पूर्व के काश्तकारी कानून को पास करवाना था जिसका विरोध किसान सभा कर रही थी। इस फरजी किसान सभा का मूल उद्देश्य किसानों के नाम पर कुछ निहित स्वार्थों को जमींदारों के साथ मिलकर किसान-सभा के संघर्ष में प्राप्त उपलब्धि को समाप्त करवा देना था।

पटना में आहूत इस फरजी किसान-सभा की बैठक में जब स्वामी जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां किसानों की सभा में लैण्ड होल्डर्स एसोसियेशन के स्तम्भ श्री सच्चिदानन्द सिंहा और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह उपस्थित हैं। सभा की अध्यक्षता श्री डोमा सिंह कर रहे थे। स्वामी जी ने कहा 'किसानों के बिना सूचना दिये यह सभा कैसी? सभा भंग हो गयी।

इसके बाद बिहार के किसानों में स्वामी जी ने एक चेतना भर दी, यही कारण था कि 1933 में जेल से बाहर आने पर एक सभा में श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि "बिहार प्रान्त के किसान आन्दोलन कर बता दिए हैं कि वह सभी जीवित हैं और सब कुछ कर सकते हैं।"

प्रान्तीय किसान सभा की जो बैठक पटना में हुई, जिसमें सोशलिस्टों ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रस्ताव लाया उसमें स्वामी जी ने इसका विरोध यह कहकर किया कि अभी इसके लिए समय नहीं आया है, और वह प्रस्ताव पारित न हो सका। मगर हाजीपुर में प्रांतीय किसान सम्मेलन[62] में उन्होंने खुद जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रस्ताव रखा और उसे स्वीकृत कराया। 4 मार्च, 1927 को

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पश्चिम पटना किसान सभा की स्थापना, 1929 में उसे बिहार प्रान्तीय किसान-सभा का रूप प्रदान किया जाना, सरकार द्वारा बिहार काश्तकारी अधिनियम में संशोधित प्रस्ताव वापस लिया जाना तथा 1933 को गया रैली स्वामी जी के नेतृत्व में किसान आन्दोलन की सफलताएं थीं जिसने किसान-सभा को मध्य बिहार का सबसे सशक्त वर्ग संगठन तथा राजनीतिक शक्ति के रूप में उभाड़ा था। शुरू में कांग्रेसी जब इसके संरक्षक बने रहे मगर ज्योंही वर्ग-संघर्ष गहराया, वे इसके विरोधी बन गए। बाद में दरभंगा के किसानों की जमींदार विरोधी शिकायतों के प्रति गांधी का रुख और पुनः अमांवा स्टेट के खिलाफ यहां के किसानों की शिकायतों पर गांधी के जमींदार पक्षी रुख जिसमें गांधी ने कहा था, "उनके मैनेजर कांग्रेसी है, इसलिए कष्टों को जरूर हटा देंगे।"[63] पर स्वामी जी का कांग्रेस से भ्रम दूर हो गया। उन्होंने कहा "प्रायः चौदह वर्षों की बनी बनाई गांधी भक्ति आज खत्म हो गई।[64]

स्वामी जी ने सैकड़ों किसान आन्दोलनों का नेतृत्व किया और प्रायः प्रत्येक बार पाया कि जमींदारों के ही साथ लड़ना नहीं, बल्कि कांग्रेस के साथ भी लड़ना पड़ रहा था। कांग्रेस के प्रति अपने मोह-संवरण में स्वामी जी किसानों को समझाते रहे– लेकिन हर किसान-आन्दोलन अनकी आंखे खोलता रहा कि विद्वानों के प्रति कांग्रेस की रामायण कितनी घिनौनी है। इस प्रकार स्वामी जी को पता चल गया कि "बिहार के कांग्रेसी लीडर जमींदार और जमींदार के पक्के आदमी हैं, एक-एक के बारे में गिन-गिन कर कहा जा सकता है।"[65]

सरदार बल्लभ भाई पटेल, जिनके बारे में स्वामी जी की आस्था बड़ी पक्की थी, के बारे में स्वामी जी के गुजरात भ्रमण से उन्हें पता चला कि बारदौली का आन्दोलन महज 10 से 15 फीसदी घनी किसानों का आन्दोलन था जिससे गरीब और मध्यम किसानों को कुछ लेना देना नहीं था। पटेल, जिन्हें लौह-पुरुष कहा जाता था, स्वामी जी की वास्तविकता में महज एक झूठे वादों और गरम भाषणों का मात्र पुलिंदा थे, जो किसानों की प्रायः सब्जबाग दिलाकर कांग्रेस के प्रति सहानुभूति हासिल करते रहे थे।

1935 के चुनावों में किसान. सभा के प्रति कांग्रेस का रुख बड़ा ही विचित्र रहा उम्मीदवारों की चयन समिति ने, जिसमें स्वामी जी एक सदस्य थे, कई बदनाम जमींदारों को अपना उम्मीदवार बनाया, किसान सभाई कोई व्यक्ति उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। स्वामी जी ने जब इस कमिटी से इसके प्रतिरोध में इस्तीफा दिया तो दो किसान सभाइयों को टिकट तो दिया गया, मगर कांग्रेस उन्हें मदद करने के बजाय, अंग्रेज पक्षी करार देकर विरोध किया। फलतः एक की हार हो गई तथा एक जहानाबाद से, जो किसान सभा का गढ़ था, भारी मतों से विजयी हुआ।[66]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें एन.जी.रंगा, इन्दुलाल याज्ञिक, मोहन लाल गौतम आदि पधारे थे, और स्वामी जी ने इसकी अध्यक्षता की,[67] और गया, फैजपुर कोमिल्ला, पलासा, विजयवाड़ा, मखना आदि कि किसानों ने हिस्सा लिया था। अब भारत के विभिन्न प्रान्तों में जो किसान संघर्ष बिखरा पड़ा था उसे एकताबद्ध करने का मौका आया, मगर काल और देश की परिस्थिति के मुताबिक किसान संघर्ष और संगठन का स्वरूप संघीय ही बना रहा। बिहार के किसान आन्दोलन को इससे काफी बल मिला, स्वामी जी को विभिन्न प्रान्तों के दौरे से किसान संघर्ष की विविधता का पता चला। उन्होंने किसान समस्या को समग्रता में समझा।

1937 में फैजपुर (महाराष्ट्र) कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ। एन.जी. रंगा, अध्यक्ष थे। इस सभा में बीस हजार किसानों ने भाग लिया। जिनमें से बहुत से सैकड़ों मील पैदल चलकर आये थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में खेती सम्बन्धित एक कार्यक्रम पास किया और दोनों संगठनों के राजनीतिक भाईचारे की घोषणा भी की गयी।[68]

इस सभा की विशेषता यह रही कि कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी दल सबों का सद्भाव इसे प्राप्त था और स्वामी जी का बहुआयामी व्यक्तित्व सबों के लिए स्वीकार्य नेतृत्व था।[69] इस सभा में स्वामी जी ने किसानों की दशा की जांच कराने के सम्बन्ध में मांग की। यह मांग स्वीकार कर ली गयी। इसके समर्थन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा–

"किसानों की स्थिति की जांच अवश्य होनी चाहिए। हम इसके लिए स्वामी जी को धन्यवाद देते हैं", लखनऊ में ही पहली सितंबर को किसान दिवस मनाने का निश्चय किया गया। पूरे भारत में उसी समय से एक सितम्बर को ही किसान दिवस मनाया जाता है। वास्तव में कांग्रेस द्वारा पारित फैजपुर प्रस्ताव मुख्यतः किसानों की कोरी मांग पर आधारित था और समग्र भूमि सुधार की नीतियों को भविष्य में सूत्रबद्ध करने का मात्र एक आश्वासन भर देता था, फिर भी किसान सभा के लिए यह एक भारी महत्व की घटना थी। अतः यह राष्ट्र की ओर से इस बात की स्वीकृति थी कि किसान भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है और एक जनवादी भारत के निर्माण के लिए किसान समस्या का हल किया जाना, उग्र-भूमि-सुधार आदि आवश्यक कारक है। स्वामी जी की स्पष्ट मान्यता है कि "कोई भी राजनीतिक या आर्थिक कार्यक्रम जो इन किसानों की जरूरतों तथा मांगों

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

को भुलाने की घृष्टता करता है उसे किसी भी ख्याली दौड़ से राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं कहा जा सकता।"[70] इस काल में स्वामी जी वामपंथ की ओर झुके।

1938 में कांग्रेस अधिवेशन से अलग स्वतंत्र रूप में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन आयोजित होने लगा। मई 1938 की स्वामी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का तृतीय सम्मेलन कोमिल्ला (बांगला देश) में सम्पन्न हुआ। 1939 के 9-10 अप्रैल की आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का चतुर्थ अधिवेशन गया में हुआ। पांचवां अधिवेशन 1940 में आन्ध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के पलासा स्टेशन के पास काशी बुग्गा में हुआ। इसके अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह मकना हुए। छट्ठा अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन बिहार में 1942 में हुआ। सांतवां अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 1943 में भकना में हुआ। आठवां सम्मेलन विजयवाड़ा में 1944 में हुआ।

वास्तव में 1930 का दशक बिहार के राजनीतिक इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि इसके दस जिलों में 1933 के नवम्बर एवं 1935 के नवम्बर के बीच अवधि में लगभग 500 किसान सभा की यूनिटें गठित की गईं जो हाजीपुर में हुए किसान सम्मेलन के बाद शुरू की गई थी। पटना में 88, गया में 38, मुंगेर में 57 शाहाबाद में 39, भागलपुर में 22, दरभंगा में 38, मुजफ्फरपुर में 43, सारण में 19, पूर्णिया में 13 तथा चम्पारण में 2 किसान सभाओं को स्वामी जी ने सम्बोधित किया।[71] किसान-सभा की सदस्यता, जो 1935 में 35000 थी। 1937 में बढ़कर 70000 तक पहुंच गई।[72] स्वामी जी अपने भाषणों में एक साल के लगान माफी की मांग उठाते हुए जमींदार एवं उनके अमलों पर तीखा प्रहार करते रहे।[73]

दरभंगा के किसानों को लगान न देने की राय 10 जून, 1934 को किसानों के महाधिकार पत्र[74] की घोषणा तथा बलदेव सहाय के निवास स्थान पर एक किसान-सभा की अध्यक्षता करते हुए "किसान" शब्द की पारिभाषित कर स्वामी जी ने आन्दोलन की तीव्रता दी। सभा में प्रस्तावित हुआ कि अपने जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करने वाला हर व्यक्ति किसान है।[75] इस महाधिकार पत्र में भूमि पर रैयतों के अधिकार एवं लगान सम्बन्धी नियमों की स्पष्ट व्याख्या ने किसानों को संघर्ष के लिए सैद्धान्तिक हथियार से लैस कर दिया। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 29 जनवरी 1935 को आयोजित किसान सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि "वैसा कोई भी काश्तकारी कानून स्वीकार्य नहीं होगा, जो किसानों के मौलिक अधिकारों पर आधारित नहीं है[76] स्वामी जी की मान्यता थी कि जमींदार लगान ले सकते हैं, लेकिन पैदा करने वाले के आहार के लिए भी कुछ छोड़ दें।"[77]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

साम्राज्यशाही की समाप्ति के बाद एक जनवादी सरकार, जो किसानों के जमीन पर मालिकाना हक दे सके– की स्थापना की अवधारणा को1937 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में शामिल न किए जाने के बाद उनका अन्तः विरोध कांगेस से बढ़ गया[78] और गांधी तथा राजेन्द्र प्रसाद से स्वामी जी का मतभेद प्रारम्भ हो गया।

अपने कटु अनुभवों का वर्णन स्वामी जी खुद करते हैं कि जिस ईमानदारी और नेकनीयती के साथ विश्वासपूर्वक मैंने जमींदारी और जमींदारों को सुधारने और किसानों एवं उनके बीच सद्भाव लाने की कोशिश की थी इसका परिणाम सिवाय परेशानी और भयंकर निराशा के दूसरा कुछ न हुआ उल्टे जमींदारों का कुचक्र दिन रात बढ़ता गया। भूकम्प के बाद जिस हृदयहीनता का परिचय उन्होंने दिया, वह मेरी आंखों के सामने आज नाचता है। बिहार में सरकार के ही कथनानुसार गल्ले का दाम साठ फीसदी घट गया। फलतः किसानों की ढाई रुपये की जगह सिर्फ एक रुपया दाम मिलने लगा।[79]

1939 में द्वितीय महायुद्ध के शुरू होने पर किसान आन्दोलन का और ज्यादा राजनीतिकरण हो गया। साम्राज्यवादी ब्रिटेन के साथ किसी प्रकार का समझौता न किये जाने के लिए आन्दोलन गठित करने में स्वामी जी ने सुभाष चन्द्र बोस के साथ रामगढ़ कांग्रेस महाधिवेशन के मौके पर 20 मार्च, 1940 को समझौता विरोधी सम्मेलन किया, जिसमें स्वामी जी स्वागताध्यक्ष तथा सुभाषचन्द्र बोस अध्यक्ष बने थे। यह सम्मेलन कांगेस की उन नीतियों के विरोध में गठित किया गया था जिसके तहत कांग्रेस ब्रिटानी साम्राज्यशाही से समझौता का प्रयास कर रही थी। उनके ऊपर मुकद्दमा चला और जेल जाना पड़ा। मगर किसान-सभा का प्रभाव बढ़ता गया। 1942 की किसान सभा की सदस्यता 25000 से बढ़कर 1944 में यह 550000 तथा 1945 में 825000 हो गई।[80]

द्वितीय महायुद्ध के शुरू होने के पूर्व के किसान आन्दोलनों की संक्षिप्त समीक्षा करते हुए स्वामी जी ने स्थापित किया कि "जब बराबर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्षों में, असहयोग और चुनावों में सरकार पछाड़ पर पछाड़ खाने लगी– वहीं सरकार, जो पशुबल और प्रभुत्व में अपना सानी नहीं रखती थी, सो भी निहत्थी जनता के दृढ़ संकल्प के सामने अपने को बलहीन पाने लगी तथा गांवों की जनता को अनुमान होने लगा कि हममें अपार शक्ति है, जिसे भूल गए थे। 1930-32 के सत्याग्रह और 1934 के केन्द्रीय चुनाव ने इस पर कसकर मुहर भी लगा दी। 1936-39 के चुनाव ने तो स्पष्ट ही बता दिया कि ग्रामीण जनता के पास अपरम्पार शक्ति है, जो किसी को झुका सकती है। इसी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अ0 भा0 समझौता विरोधी सम्मेलन, रामगढ़ (हजारी बाग), बिहार, 20 मार्च, 1940

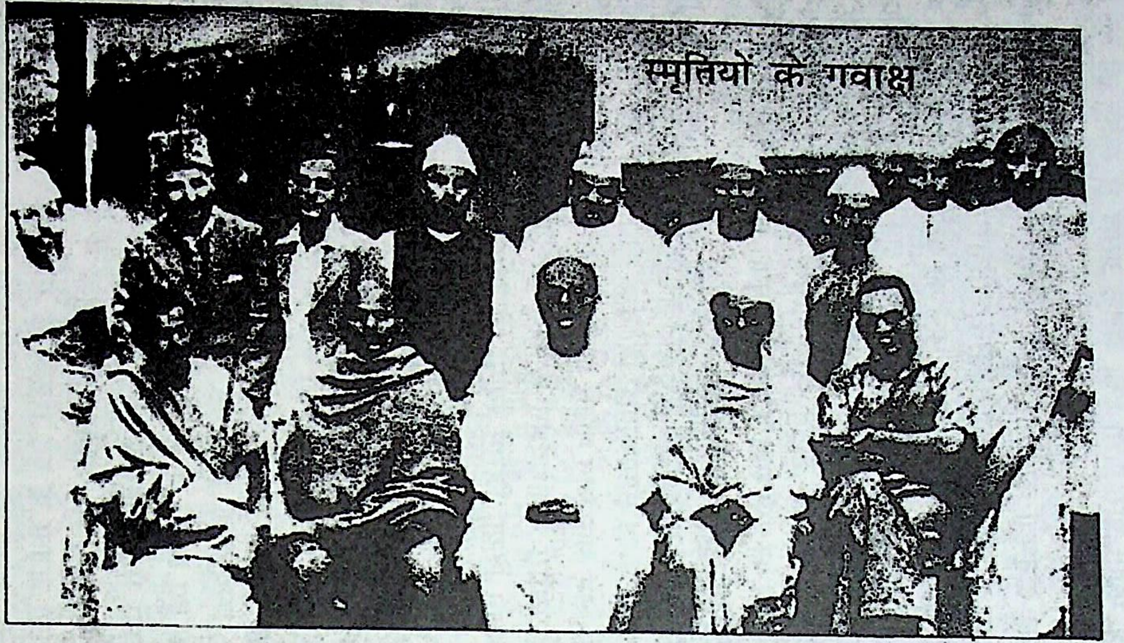

बैठे : बायें से दायें (1) किशोरी प्रसन्न सिंह, (2) स्वामी सहजानन्द सरस्वती (3) देश गौरव सुभाष चन्द्र बोस, (4) प्रोफेसर एन.जी.रंगा, (5) सोली बाटली वाला ।
खड़े : दायें से बायें 1) हरि विष्णु कामथ, 2) पंडित पद्माकान्त मालवीय, 3) शीलभद्र याजिक, 4) श्री अन्न पुनैया, 5) लाला शंकर लाल, 6) रामकृष्ण खत्री, 7) सोमनाथ लाहिड़ी, 8) मियां अकबर शाह, 9) अशरफुद्दीन चौधरी ।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भाव ने, जनशक्ति के इसी ज्ञान ने किसान आन्दोलन को जन्म दिया। जनान्दोलन का मूल तो गांवों में ही था, उसके मूल स्तम्भ किसान ही थे। असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम प्रधानत : उन्हीं को ध्यान में रखकर तैयार हुआ था। अधिकांश वही उस आन्दोलन में खिंचे भी। फलतः अपने अज्ञेय शक्ति का ज्ञान विशेष रूप से उन्हीं को हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर हम अपार बलशाली साम्राज्यशाही को पछाड़ सकते हैं, तो इन जमींदार-मालगुजारों और सूदखोरों को क्या हस्ती? ये तो उसी साम्राज्यवाद के बनाये हुए हैं। ....यदि संगठित जनआंदोलन ने सरकार को समाप्त किया, तो संगठित किसान-आंदोलन ही जमींदारों को करारा पाठ पढ़ायेगा, यह निष्कर्ष किसानों और उनके सेवकों ने स्वभावतः निकाला। 1927-28 से यह आन्दोलन किसान-सभा के रूप में जन्म लेकर क्रमशः पुष्ट और शक्तिशाली होता गया, त्यों-त्यों किसानों को अपनी अपार शक्ति के मान की मजबूती होती गई। 1936-37 के बाद तो 1938-39 में या उससे पूर्व एक बार किसान-सभा ने बिहार में युक्त प्रांत में था अत्यंत सामंतशाही शक्तियों एवं उनके हिमायतियों को जड़ से हिला दिया। आज जमींदारी मिटाने की व्यापक चिल्लाहट उसी का परिणाम है।[81]

स्वामी जी ने किसान-आन्दोलन को कांग्रेस का उत्तराधिकारी बताया और इस स्थापना को पुष्ट किया कि इस किसान-शक्ति के हाथ में राजसत्ता को आए बिना सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। उन्होंने लिखा है, "किसान-सभा प्रभृति को शक्ल में क्रान्तिकारी शक्तियों का यह प्रादुर्भाव ही है। नियमानुसार ये शक्तियां बाबुओं को प्रतिगामी शक्तियों के साथ घोर संघर्ष करती हुई आगे बढ़ती ही जा रही हैं। यदि माता की उत्तराधिकारिणी पुत्री या पिता का उत्तराधिकारी पुत्र होता ही है, तो कांग्रेस और उसके जन-आंदोलन से उत्पन्न किसान-आंदोलन तथा विधान सभा प्रभृति विप्लवाहिनी की अनिवार्य रूप से कांग्रेस का उत्तराधिकारी बन के उसकी गद्दी पर आसीन होना है। उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तभी वास्तविक राष्ट्रीय आजादी की स्थापना भी होगी।"[82]

1927-28 से 1939 तक किसान आन्दोलनों का वर्ग चरित्र मध्यम किसानों का था, जैसा स्वामी जी कहते हैं, "1927-28 से शुरू होकर प्रायः 15 साल तक किसान आन्दोलन सर्वाधिक शोषित-पीड़ित किसान जनता के उच्च स्तर तक ही सीमित था। फलतः यह भी एक प्रकार से मध्यमवर्गीय आन्दोलन हीं था। खाते-पीते या साधारण किसान हीं इसमें भाग लेते थे..............।"[83]

सोवियत सरकार स्वामी जी का एक आदर्श थी, जिसकी वे प्रशंसा करते हुए इस तरह की राज सत्ता की कल्पना आजादी के पश्चात चाहते थे। मझियावां

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(गया) में एक सभा में स्वामी जी ने स्पष्ट कहा था—दुनिया में एक ऐसा देश है जहां जमींदार नहीं है, पूंजीपति नहीं है, कमाने वालों का राज है, उसकी कमाई का कोई शोषण नहीं करता, वह देश है सोवियत रूस।[84]

1941 में सोवियत संघ पर जर्मनी के हमले के बाद स्वामी जी ने इन्दु लाल याज्ञिक के साथ मिलकर एलान किया कि यह युद्ध जनयुद्ध है, हालांकि उनकी जेल में रिहाई के पूर्व ही केन्द्रीय किसान-परिषद अपने नागपुर बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर इस लाइन को हाजिर कर दिया था।[85] स्वामी जी की स्थापना में "पूंजीवाद का आखिरी रूप फासिज्म की शक्ल में नजर आ रहा है और उसके चलते वर्ग शक्तियों का जो नया गंठजोड़ हो रहा है उसे देखकर तो कहा जा सकता है कि कुछ भी होना असम्भव नही।"[86]

1942 से 1945 तक की अवधि में ब्रिटानी शासन ने दमन का रास्ता अपनाया, सभी नेता जेलों में बन्द कर दिए गए तो किसान-सभा ने राष्ट्रीय नेताओं की रिहाई, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए आन्दोलन चलाया, युद्ध के लिए जबरन वसूलों का खिलाफत किया तथा अन्न पैदा करने के लिए एक आम सहायता आन्दोलन गठित किया[87] यह सारा आन्दोलन किसान सभा के मंच से चलाया गया। आन्ध्र में लाखों एकड़ बंजर जमीन की जोता बोया गया, बंगाल के अकाल में मदद दी गई।

1942 को अगस्त क्रान्ति का चरित्र विश्लेषण करते हुए स्वामी जी ने उसे "बबुआवाद" की संज्ञा दी। वे विश्लेषित करते हैं, "प्रश्न तो यह है कि यह क्रान्ति जन शक्ति की उस.... अनियंत्रित जनशक्ति की; जो प्रलयंकर विस्फोट लाती है, महायुद्ध का महाताण्डव करवाती है............ बढ़ानेवाली, पूर्णरूप से पल्लवित-पुष्पित करने वाली थी, या कि बाबूदल की वैधानिक शक्ति की ही? जन शक्ति को भी उसने कुछ बढ़ाया हो, सही; लेकिन उससे भी कई गुणा यदि बाबू शक्ति को, बाबुओं के वैधानिक बल को बढ़ाया हो, तो मानना ही होगा कि जिस अगस्त क्रांति का हमें गौरव है, फक्र है, उससे हम आगे बढ़ने के बजाये सब मिलकर पीछे ही गए।................यह तो माना ही होगा कि बाबुओं की वैधानिक शक्ति इससे इतनी बढ़ी कि साम्राज्यशाही ने घुटने टेक उनके लिए गद्दी खाली करा दी। उन्हीं बाबुओं की संस्था-पार्टी-कांग्रेस के विरोध में खड़े होने की आज हिम्मत किसे है? क्रान्तिकारी शक्तियों को ये बाबू आज फूटी आंखों भी नहीं देख सकते। ये शक्तियां बिखरी हुई हैं, जिनसे इन बाबुओं के दमन-दबाव का जम कर सामना करने में असमर्थ है। चीन, हिन्द-चीन, हिन्द-एशिया, मलाया और वर्मा में तो अगस्त क्रान्ति जैसी कोई चीज हुई नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

और सर्वत्र क्रान्तिकारी जनशक्तियां इन बाबुओं और उनकी सरकारों के छक्के छुड़ा रही है। चीन तो शायद शीघ्र ही इन बाबुओं के शिंकजे से बाहर चला जाएगा। बाकियों में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हां, इसमें कुछ देर हो सकती है। वर्मा आदि देश में बाबू दल विप्लवी शक्तियों को मिलाने के लिए काफी आगे बढ़ा भी है–इतना आगे जिसकी कल्पना भी भारत की राष्ट्रीय सरकार कर नहीं सकती।"[88]

जेल में ही स्वामी जी ने मार्क्सवादी साहित्य का अध्ययन किया और समाजवादियों की अपेक्षा कम्युनिस्टों के सम्पर्क में ज्यादा आए, बिहार में, कम्युनिष्ट पार्टी के निर्माण के बाद उन्हें उसकी सदस्यता के लिए जब आग्रह किया गया तो वे इसे अस्वीकृत कर दिए। ऐसा लगता है कि उस पार्टी की नीतियों के सम्बन्ध में अस्पष्टता, विभिन्न दलों के सम्पर्क के कटु अनुभव, और सबसे बढ़कर एक किसान जनवादी की सीमाबद्धता ने उन्हें उस पार्टी के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी उसमें शामिल होने में रोक रखा। मगर 1942 में किसान सभा का एक मुख्य नारा था कम्युनिस्ट पार्टी पर से प्रतिबंध हटाओ।

1940 के दशक में स्वामी जी के अन्दर एक गतिरोध दृष्टिगोचर होने लगा था। युद्ध के शुरू के दिनों में खेरा, बड़हिया टाल, मंझियावा, पंडौल, सांडा, अमवारी इत्यादि जगहों में किसान संघर्ष हुए मगर बाद में यह आम तौर पर धीमा पड़ता गया। 1935 के कांग्रेसी शासन ने भावली को नगदी बना दिया, जिससे जमींदारों को काफी मुनाफा हुआ मगर युद्ध जनित मंहगाई ने उसे निरर्थक बना दिया। 1944 से ही ऐसा लगंने लगा था कि अब अंग्रेजों को भारत छोडना पड़ेगा। मगर इसके बावजूद किसान जागृत रहे और आन्दोलनों के सिलसिले में कांग्रेसी सरकारी की कई जगह गोलियां चलानी पड़ीं।

स्वामी जी ने चार कांग्रेसी सरकारों को देखा था, 1937, 1943, 1946 और 1947 और इन चारों सरकारों को उन्होंने किसान-विरोधी पाया। स्वामी जी अपना अनुभव बताते हैं "रह गई किसानों और मजदूरों की बात, सो तो बम्बई और कानपुर का गोली और आंसू लाने वाली गैस के प्रयोग आदि ही बताते हैं कि मजदूरों ने क्या पाया। इनकी हड़ताल को तोड़ने में बम्बई में सारी ताकत लगा दी गई। कानून भी ऐसा बना कि मजदूरों को उसका खुलेआम विरोध करना पड़ा और जब उन्होंने उसके विरोध में हड़ताल की तो कांग्रेसी सरकार और कांग्रेस की सारी ताकत उसे तोड़ने लगी। हालांकि फिर भी उनकी हड़ताल सफल होकर ही रही। जमशेदपुर, झरिया, डिहरी, बिहटा, आदि मिलों के मजदूर बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल को क्या कभी भूलेंगे"।[89]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हुआ और उस सरकार के सम्बन्ध में स्वामी जी का मूल्यांकन है, "..............................प्रान्तों एवं केन्द्र में जो कांग्रेसी सरकारें हैं..............................जमींदारी तथा मध्यवर्ती स्वार्थों एवं लगान, मालगुजारी और श्रमदान के सड़े-गले एवं पुराने तरीकों को मिटाने और उनके स्थान पर नई सामयिक प्रणाली को कायम करने को योजनाओं पर उन्होंने पानी फेर दिया है.................."।[90]

स्वामी जी का कम्युनिस्टों से थोड़े दिनों तक झगड़ा भी रहा, जिसके लिए कांग्रेस एवं सोशलिस्ट नेता, जिन्होंने वर्ग-संगठनों को तोड़ने का एक मुहिम-सा चला रहा था, जिम्मेवार थे। लेकिन कम्युनिस्टों को राजनीतिक लाइनें जो कभी दक्षिण पंथ और अतिवामपंथ की रही, भी कम जिम्मेदवार नहीं है। 1947 में ही अपने एक लेख में "अब क्या हो"? के द्वारा समाजवादी एवं वामपंथी ताकतों को एक जुट करने के लिए 1948 के फरवरी माह में कई वामपंथी दलों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए। बैठक भी हुई। सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर 18 दलों के लोग शामिल हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कामरेड सोमनाथ लाहिड़ी इसमें उपस्थित थे। मार्च 1948 में पार्टी की दूसरी कांग्रेस में अपनाई गई नीतियों के कारण वह वामपंथी मोर्चा चल नहीं सका। स्वामी जी का संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास सफल नहीं हो सका। 28,29 और 30 अक्टूबर, 1949 को नेता जी भवन, कलकत्ते में देश के वामपंथियों का एक सम्मेलन फिर बुलाया गया। एक समिति भी बनी। किन्तु राष्ट्रीय जनतांत्रिक वामपंथी शक्तियों को एकबद्ध, संगठित करने और राष्ट्रीय जनवादी क्रान्ति को पूरा करने का कर्तव्य अभी भी अधूरा है।

स्वामी जी के अन्तिम योगदान के रूप में है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, भारतीय संयुक्त किसान सभा, भारतीय संयुक्त समाजवादी सभा और संयुक्त वामपंथी मोर्चा जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो सकी। पटना में आहूत वामपंथी सम्मेलन में 18 वामपंथी दलों[91] ने शामिल होकर वर्ग-संघर्ष के आधार पर आन्दोलन विकसित करने सम्बन्धी सम्मेलन किया, जिसकी अध्यक्षता स्वामी जी ने की। जय प्रकाश नारायण की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इसमें भाग नहीं ले सकी।

स्वामी जी की कृतियां

जिस तरह स्वामी जी के जीवन के कई पक्ष हैं : बचपन, संन्यास-धारण, जातीय उत्थान का जीवन, राष्ट्रीय आन्दोलन, किसान-सभा, साम्यवाद के प्रति झुकाव तथा संयुक्त मोर्चा का प्रयास, उसी प्रकार उनकी कृतियों, साहित्यों और लेखों की श्रेणियां भी हैं, जिन्हें मुख्यतः पांच श्रेणियों में बांटा जा सकता है:[92]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

1. जातिगत, उत्थान एवं सुधार मूलक,
2. किसान आन्दोलन से सम्बन्धित
3. कर्मकाण्ड एवं ज्योतिष विषयक
4. जीवनी विषयक तथा
5. आध्यात्मिक दार्शनिक

उनकी इन कृतियों पर काल एवं परिस्थितियों का, जिसमें उन्होंने कार्य किया, अमिट छाप दिखाई पड़ती है, और यही कारण है कि भगवान-प्राप्ति जैसे घोर अध्यात्मवाद से लेकर उदार पूंजीवादी संस्कृति से होते हुए मार्क्सवाद, लेनिनवाद के भौतिकवादी दर्शन तक की लम्बी यात्रा का वृतान्त उनकी कृतियों की विशेषता है।

अनेकों शुरू की कृतियां संस्कृत वांड़मय के उनके अध्ययन, जिनमें मुख्य हैः मनोरमा, शब्देन्दु और परिभाणेन्दु, शेखर, भूषण, मंजूषा और महाभाष्य, वात्स्यायनभाष्य, न्यायवर्तिक, न्यायकुसुमांजलि, आत्मतत्व विवेक, निरुक्त, सिद्धांत लक्षण, सिद्धांत कौमुदी, खण्डन खण्ड खाद्य, पदार्थ खण्ड, सत्प्रतिपक्ष, बाघ, दुर्गा सप्तशती, देवी सूक्त भागवद्‌गीता, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीय, नैषध के अध्ययन स्वरूप उनका दार्शनिकता के भाव का विस्तार हुआ मगर पौराणिक सामाजिक संरचना के सन्दर्भ में ही। वही कारण है कि उनकी पहले वाली कृतियों में वर्णाश्रम धर्म तथा सनातनी संस्कृति का प्रभाव दीखता है। उनकी प्रमुख कृतियों में है :

1. *भूमिहार ब्राह्मण परिचय*, 2. *ब्रह्मर्षि वंश विस्तर* 3. *ब्राह्मण समाज की स्थिति*, 4. *झूठा भय मिथ्याभिमान*, 5. *मेरा जीवन संघर्ष*, 6. *कर्म कलाप*, 7. *गीता हृदय*, 8. *किसान सभा के संस्मरण*, 9. *क्रान्ति और संयुक्त मोर्चा*, 10. *किसान कैसे लड़ते हैं*, 11. *किसान क्या करें*, 12. *झारखण्ड के किसान*, 13. *खेत मजदूर*, 14. *किसानों को फंसाने की तैयारियां*, 15. *महारुद्र का महाताण्डव*, 16. *जमींदारी प्रथा का खात्मा कैसे हो*, 17. *जमींदारी क्यों उठा दी जाय*, 18. *अब क्या हो?* आदि। अंग्रेजी में भी लिखी दो पुस्तकें हैं 19. *दि अदर साइड आफ दि सिल्ड* तथा 20. *रेन्ट रिडक्शन इन विहार, हाउ इट वर्क्स*।

उनके जातिगत उत्थान एवं सुधार मूलक रचनाओं में प्रमुख स्थान रखता है। ब्रह्मर्षि वंश विस्तर, ब्राह्मण समाज की स्थिति तथा झूठा भय और मिथ्याभिमान वास्तव में स्वामी जी का प्रथम प्रणयन पुस्तक है, जो 1924 में दण्डी स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती-द्वारा हित चिन्तन प्रेस, राजघाट बनारस सिटी से प्रकाशित की गई। जिसका नाम था भूमिहार ब्राह्मण परिचय।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भूमिहार-ब्राह्मण परिचयः चार खण्डों खण्डों में प्रकाशित इस ग्रन्थ में पूर्वार्द्ध, उतरार्द्ध पूर्व परिशिष्ट और उत्तर परिशिष्ट है। पूर्वार्द्ध में विविध ब्राह्मण विचार के अन्तर्गत लक्षण, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणों के भूमिहार, त्यागी आदि विश्लेषण, आचार, व्यवहार, आस्पद, उपाधि या पदवियां, विवाह-सम्बन्ध, अवस्थायें सम्मतियां और पत्र, आइने अकबरी और उपसंहार नाम से 8 उपखण्ड लिए गए हैं। उत्तरार्द्ध को कन्टकोद्वार माना गया है और इसके अन्तर्गत दुरूक्ति दमन, दीनवार आदि शब्दों की मीमांसा तथा वेदेशिक उक्तियां और उपसंहार आदि का उल्लेख हुआ है।

पूर्व परिशिष्ट और उत्तर परिशिष्ट में क्रमशः स्फुट प्रश्न, समालोचना, वंगीय ब्राह्मण-सम्बन्ध, आवश्यक कर्तव्य, धर्मारण्य और वाडय, याचक और अयाचक, अंशीय और उसका शंकर गोत्र, प्रबल और साधारण क्षेत्र, ब्राह्मणों को भी पदवियां तथा चरम उपसंहार और समर्पण आदि अंश अभिलिखित है। 37 पृष्ठों की भूमिका में स्वामी जी ने वर्ण विवेक चन्द्रिका की 'जाति निर्णय', विशेष वंश वाटिका 'जगतराजदिगिवण्वै', 'विहार पंथ' और 'भारत वर्षीय राजवंश दर्पण' में लिखित बातों की डट कर आलोचना करते हुए यह बताया है कि उनमें वर्णित बातें बेसिर-पैर की प्रमाणहीन तथा दोषपूर्ण है।[93]

रजनीकांत शास्त्री ने इस पुस्तक की आलोचना भूमिहार भ्रम-भंजन में हिन्दू जाति का उत्थान-पतन से की है। मगर सरस्वती के सम्पादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मंतव्य है कि 'भूमिहार ब्राह्मण परिचय' में कोई बात छूटने नहीं पाई है। अलग-अलग प्रकरणों में सभी बातों का विस्तृत एवं प्रामाणिक विवेचन है।[94]

जो लोग इसे जातिगत राजनीति की कृति मानते हैं उनकी स्पष्टीकरण देते हुए स्वामी जी ने कहा है कि उन्हें बचपन से ही अपने में दूसरे मनुष्यों के साथ समता का भाव रहा है और जब इन्होंने यह देखा कि एक मनुष्य या मनुष्यों का एक समुदाय दूसरे मनुष्य या मनुष्यों के अन्य समुदाय के साथ तिरस्कार का व्यवहार करता है, और अपने को ऊंचा समझता है, तो उन्हें यह सदा से असह्य रहा है।[95]

ब्राह्मण समाज की स्थितिः जिसे स्वामी जी ने 1916 में ही लिखी थी, ब्रह्मर्षि वंश विस्तर का पूरक माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो बात, ब्रह्मर्षि वंश विस्तर में छूट गई थी उसे ही इसमें जोड़ दिया गया है। इसमें ब्राह्मणों की सही स्थिति की जानकारी अपने अधिकार की सूझ-बूझ तथा सदुपयोग-दुरुपयोग की लाभ-हानि को स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया गया है। ब्राह्मणों के लिए तीन चीजों पर बल दिया गया है—ब्राह्मणोचित स्वाभिमान, कर्तव्य एवं आचरण।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पठन-पाठन से विमुख ब्राह्मण पुआल की आग की भांति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए उसे देव-पितृ कार्य में कुछ नहीं देना चाहिए। पुस्तक में याचक और अयाचक ब्राह्मण के आपसी भेद-भाव को दूर करने का भी सही सुझाव दिया गया है। वास्तव में यह पुस्तक भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की शिक्षा देती है। देश-भक्ति और कर्तव्य-प्रेम को ओर भी अन्यतम संकेत करती है।

ग्रंथ के उत्तरार्द्ध में ब्राह्मणों के आधुनिक पतन की चर्चा है, इसका कारण है, बताया गया है उनकी आपसी फूट तथा शिक्षा एवं एकता का अभाव। इसमें स्वामी जी ने ब्राह्मणों के इतिहास को गोत्रों एवं उपाधियों के साथ पेश किया है। व्युत्पत्यर्थ बतलाते हुए उनके वैवाहिक सम्बन्ध पर भी समुचित प्रकाश डाला है। रचना का सम्बन्ध सामाजिक आन्दोलन से है, जो यह सिद्ध करता है कि लेखक का एतहविषयक गहरा अध्ययन था।

स्वामी जी ने कहा है, " इस पुस्तिका के लिखने का एकमात्र तात्पर्य यही है कि ब्राह्मण मात्र को उनकी सामाजिक स्थिति का यथार्थ ज्ञान कराकर उनके अधिकार उन्हें सुझा दिए जायें और यह भी बता दिया जाए कि उन अधिकारों का सदुपयोग-दुरुपयोग उनको और देश की क्या हानि-लाभ हो रहा है और आगे होगा।"[96] पुस्तक के सारे साक्ष्य पौराणिक संस्कृत साहित्य के श्लोकों को उदृत करके ही स्थापनाओं को सम्पुष्ट किया गया है।

झूठा भय और मिथ्याभिमानः मात्र 32 पृष्ठों को वह कृति स्वामी जी की तीसरी ऐसी रचना है जिसका सम्बन्ध अयाचक ब्राह्मणों से है। इन्होंने इस बात की जबरदस्त वकालत की है कि अयाचक ब्राह्मण को संस्कृत और शास्त्र को भली-भांति अध्ययन कर पौराहित्य कर्म करना चाहिए। जो इसका विरोध करता है उसके पास झूठा भय है तथा अपनी जमीन्दारी की शान रखना मिथ्याभिमान है। इस प्रकार की पुस्तक में एक ओर निर्भीकता की सीख दी गई है तो दूसरी ओर मिथ्याभिमान को त्यागने की सलाह भी दी गयी है।

कर्मकलापः सन् 1928 ई. में ही बी.एस. पावगी द्वारा वाराणसी गाय घाट से प्रकाशित यह स्वामी जी का एक ऐसा विशालकाय ग्रंथ है जिसमें जीवन से मृत्युपर्यन्त तक सभी संस्कारों, ग्रह श्लेषादि शानितयी, देव-प्रतिष्ठा, गृहारम्भ कर्मों, आराम जलाशय आदि उपसर्ग, महामृत्युंजय अनुष्ठान विधि का सामदेव-यजुर्वेद-रीति से विशद संग्रह तथा गृह कार्य पेक्षित सम्पूर्ण ज्योतिष का सविस्तार निरूपण हुआ है। यह तीन भागों में विभक्त है–वैवाहिक प्रकरणान्त, अन्त्येष्टि संस्कार, देव प्रतिष्ठा, उत्सर्ग शान्ति, नित्यकर्म विधि तथा सम्बद्ध वैदिक सूक्त प्रकरणान्त और ज्योतिष प्रकरणान्त।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

यह ग्रन्थ पौराहित्य-कर्म कराने वाले ब्राह्मणों के लिए एक अनुपम एवं बहुमूल्य कृति हैं। इसमें सभी प्रकरणों से सम्बन्ध अंश मूल संस्कृत और उसकी सरल हिन्दी व्याख्या सहित लिखे गए हैं। पौरोहित्य कर्म कराने वालों के लिए सम्भवतः इससे अच्छा और सरल गंथ कोई दूसरा उपलब्ध नहीं है।

किसान सभा के संस्मरणः यह संस्मरण विषयक ग्रंथ है, किन्तु इसमें किसी व्यक्ति विशेष का संस्मरण नहीं लिखा गया है वरन् 1940 से 1942 तक के किसान-आन्दोलनों के संस्मरण लिए गए हैं। यह स्वामी जी के इतिहास विषय ज्ञान को बताता है। उनका कहना था कि किसानों की दशा सर्वत्र एक-सी हो रही है। आज से 50 से 100 साल पूर्व जमींदारों और सूबेदारों ने उन्हें सर्वत्र बुरी तरह सताया है और सरकार भी उन उत्पीड़कों का ही साथ देती रही है। फलतः किसानों के विद्रोह सर्वत्र होते रहे हैं।

उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों के किसान-विद्रोह का उल्लेख करते हुए भारतीय किसान-आन्दोलन की चर्चा की है और बताया है कि हमारे देश के 1936 का मोपला किसान विद्रोह, 1920 में कालीकट में काश्तकारी कानून-संशोधन का आन्दोलन 1845 से 1875 के बीच बम्बई प्रैसीडेन्सी के महाराष्ट्र खानादेश तथा अन्य आन्दोलन इसके ज्वलंत प्रमाण है। सभी आन्दोलनों के कारण रहे हैं आर्थिक एवं सामाजिक उत्पीड़न तथा सूदखोरों एवं जालिमों के अत्याचार।

क्रान्ति एवं संयुक्त मोर्चाः यह स्वामी जी की वह दुर्लभ कृति है जो दलित किसानों को संयुक्त मोर्चा बनाकर क्रान्ति के द्वारा बलपूर्वक सत्ताधारी-वर्ग को हटाने की सीख देता है। किसान नेता ने इसमें बुर्जुआ क्रान्ति, जनवादी क्रान्ति और सर्वहारा क्रान्ति का भेद स्पष्ट किया है तथा क्रान्ति की दिशा और प्रकृति का विश्लेषण किया है और बताया है कि भारत के लिए पूंजीवादी क्रांति घातक हैं।

महारुद्र का महाताण्डवः इसमें बताया गया है कि जनशक्ति जब महारुद्र का महाताण्डव करती है तब बाबू शक्ति को घुटने टेकने पड़ते हैं। जनशक्ति है किसान सभा, किसान आन्दोलन "यह आन्दोलन या किसान सभा उन्हीं विप्लवी विस्फोटकारी शक्तियों का प्रतीक है, जो भीषण भूकम्प लाती है और महारुद्र का महाताण्डव करती है।" आज की भाषा में जिसे क्रान्ति भी कहा जाता है उसे ही किसान नेता ने महारुद्र का महाताण्डव कहा है। पुस्तक में कांग्रेस की कमियों का खुलासा चिट्ठा प्रस्तुत करते हुए ग्रामीण सर्वहारा जागरण का महत्व बतलाया गया है।

"लट्ठ हमारा जिन्दाबाद" या 'डण्डा कल्ट' के समर्थक स्वामी जी की किसान-आन्दोलन से सम्बन्धित जो अन्य शेष रचनाएं हैं उनमें उन्होंने किसानों

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

की सामूहिक शक्ति की महत्ता, उनके दुख-दर्द, मेरे जीवन की कहानियां, उनकी समस्यायें, उन्हें तंग करने के विभिन्न तरीके, लड़ने के रूप, जनवादी क्रान्ति की सीख और पुलिस जुल्म के सजीव चित्र पेश किए हैं। जमींदारी-जुल्म का सजीव चित्र खींचा है, किसान कैसे लड़ते हैं। इसमें उन्होंने जमींदारी को जोंक उनके अमलों को प्लेग के कीटाणु का नाम दिया है।

किसानों का फंसाने की तैयारियां: उन लोगों को अच्छी सीख देती है, जो देहातों में युद्धरत विभिन्न निजी सेनाओं का गठन कर किसानों पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। वहां काम तो ब्रिटिश राज्य में जमींदार करते थे। उनका मानना है कि जातीय संगठन जन संगठनों के लिए जाल है। उनकी सभी कृतियों का मूल है।

जो अन्न वस्त्र उपजायेगा, अब सो कानून बनाएगा।
भारतवर्ष उसी का है, अब शासन वहीं चलाएगा।।

मेरा जीवन संघर्षः यह ग्रन्थ स्वामी जी के संघर्षमय जीवन का वह दर्पण है, जिसमें उनके समग्र जीवन वृत को देखा जा सकता है। इसकी रचना 1940 ई. में सेन्ट्रल जेल हजारीबाग में हुई है। इसके चार भाग है–पूर्व, मध्य, उत्तर और उपशिष्ट। प्रथम में जन्म, बाल्यावस्था और उपनयन संस्कार से लेकर गुरुमंत्र तक के भाग सम्मिलित हैं। पूनः शिक्षा, वैराग्य, विवाह, पत्नी, मृत्यु तथा संन्यास की चर्चा हुई है। मध्य भाग में काशी, नर्मदा, ओंकारेश्वर, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, बदरीनारायण और केदार आदि की यात्राएं वर्णित हैं। शास्त्र, अध्ययन, दण्ड ग्रहण ज्योतिष विद्या, कर्मकाण्ड, मिथिला-यात्रा एवं जातीय सभा आदि के संघर्ष में प्रकाश डाला है। इसका उत्तर खण्ड बतलाता है कि स्वामी जी सामाजिक कामों में क्यों पड़े, उन्होंने जातिगत सुधार मूलक ग्रन्थों की रचना क्यों की और राजनीति में उनका प्रवेश कैसे हुआ। ग्रन्थ के उत्तर भाग का सम्बन्ध गांधी-मिलन, विभिन्न जेल यात्राएं गीता का अर्थ समझना, जल चिकित्सा, छुआछूत-भावना, पुरोहितों प्रश्न, क्रान्ति का प्रतीक श्री सीतारामाश्रम एवं साप्ताहिक पत्र 'लोक संग्रह' प्रकाशन से है। इसी में वे वृतान्त आये हैं जिनका सम्बन्ध किसान सभा, 1930 के आन्दोलन, जीवन की तीन घटनाएं, सरकार से भिड़न्त, असेम्बली चुनाव, बिहटा चीनी मिल की वारदातें, काश्मीर यात्रा, डंडावाद, प्रान्तीय दौरें एवं वाम पक्ष का मेल आदि से है।

अवशिष्ट भाग में पार्टियों में क्यों नहीं, पार्टी की करतूतें, दिनचर्या, रूस पर जर्मनी का हमला, फासिज्म के करिश्में, जान स्ट्रेची की किताब, विरोधियों को मनोवृत्ति और डुमरांव का संघर्ष आदि अंश उल्लिखित है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गीता हृदयः "गीता हृदय" स्वामी जी की हिन्दी जगत् को एक अदभुत देन है। यदि लोकमान्य तिलक का "गीता रहस्य" हीगेल, कान्ट, शोर्पन हाबर, ग्रीन और हाब्स जैसे पश्चात्य विद्वानों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन है तो निष्काम कर्म योगी स्वामी जी का "गीता हृदय" गीता को मार्क्सवादी व्याख्या है। गीता की मार्क्सवाद से तुलना कर यह सिद्ध किया है कि दोनों में अन्तर नहीं है। गीता धर्म की बात मार्क्सवाद में कही गयी है, और मार्क्सवाद के विचार को गीता धर्म में समाहित किया गया है। दोनों एक दूसरे के पोषक हैं। "गीताधर्म का मार्क्सवाद के साथ विरोध नहीं है, किन्तु मेरे ज्ञान से गीता धर्म मार्क्सवाद का पोषक है। मेरे ख्याल से गीता के "सर्वभूतात्म भूतात्मा" और सर्व "भूतहितेरता"; सिवाय सच्चे मार्क्सवादियों के और कौन हो सकते हैं? वहीं तो समस्त मानव-समाज का पुनर्निर्माण इस तरह करना चाहते हैं कि एक भी आदमी दुःखी, पराधीन, समुन्नति के सभी साधनों से वंचित न रहने पाये।"

स्वामी जी का विचार "गीता हृदय" को तीन भागों में करने का था—पूर्व, मध्य और उत्तर, पर दो भागों का ही वह पूरा कर सके। पहला भाग "गीता हृदय" का अन्तरंग है। इसमें गीता का मुख्य मन्तव्य, गीता धर्म और मार्क्सवाद, गीता धर्म की शेष बातें, कर्मवाद और अवतारवाद, गुणवाद और अद्वैतवाद, अपर्याप्त तदस्माकम् जायते वर्ण संकरम्। ब्रह्मसूत्र पदेश्चेव सर्वधर्मान्परित्यज्य और शेष बातें शीर्षक उपखण्ड रखे गये हैं। पुस्तक में पहला भाग का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि इसी में गीता धर्म और मार्क्सवाद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसी में गीता को समझने का सूत्र है। दूसरा भाग अर्थात् गीता-भाग में गीता के मूल श्लोकों का अर्थ दिया गया है।

तीसरा भाग लिखने का अवसर स्वामी जी को नहीं मिला। इसमें वे गीता के मर्म को देशी-विदेशी विचारकों के विचारों से तुलना कर प्रस्तुत करना चाहते थे। हजारीबाग की केन्द्रीय कारा में उन्हें इसके लिए सामग्री नहीं मिली अतः काम अधूरा रह गया।

विवेचन ग्रन्थ के अर्थ निरूपण में स्वामी जी की कारीगरी देखते ही बनती है। पहला अध्याय के 10 वां श्लोक में अपर्याप्त की व्याख्या, इसी अध्याय के 41 वें श्लोक में "जायेतेवर्ण संकर" का अर्थ, तेरहवें अध्याय के चौथे श्लोक में "ब्रह्मम सूत्र पदेरचैव की व्याख्या, अठारहवें अध्याय के 66वें श्लोक में "सर्वधर्मान्परिज्लन" की व्याख्या आदि। इसी तरह ग्यारहवें अध्याय के 46 वें श्लोक में "चतुर्भुजेन" शब्द को एक न मानकर दो मानना और सम्बोधन के रूप में प्रयुक्त करना स्वामी जी की बुद्धि का चमत्कार और उनके मस्तिष्क की तेजी का ही सूचक है। अन्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

टीकाकार तो इसको एक ही शब्द मानकर चतुर्भुज रूप दिखाने का अर्थ कर सकते हैं। स्वामी जी का तर्क है कि यदि यहां अर्थ यह माना जाय तो तुरन्त 51 वें श्लोक में मानुष रूप दिखाने का अर्थ करना खिलवाड़ है। उनके "गीता हृदय" के अर्थों का मनन करने से ऐसा लगता है कि उन्हें महाभारत पर बेजोड़ अधिकार एवं पकड़ है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गीता उनका हृदय था, उनके दिल की बातें उसमें मिलती है। स्वामी जी का ऐसा कहना है कि गीता में वे भी बातें मिलती हैं, जो उपनिषद आदि ग्रंथों में नहीं मिलती हैं। यथा 'अधियज्ञ' गीता की अपनी चीज है। उसकी भली-भांति व्याख्या स्वामी जी ने की है।

अदर साइड आफ दी शिल्डः (1938)–इसमें स्वामी जी ने कुछ महानुभावों द्वारा प्रकाशित लेखों का मूल्यांकन किया है तथा कांग्रेस द्वारा किसानों के हित में किये गये दावे का पर्दाफाश किया है। फैजपुर में कृषि-संबंधी जो प्रोग्राम लिये गये थे उसके द्वारा बिहार के राज्य स्तरीय कांग्रेस नेताओं ने लेखों में किया था। राजेन्द्र प्रसाद ने भी बिहार के कांग्रेस सरकार को कार्य का दावा पेश करते हुए कहा था कि किसानों के हित के लिए अनेक कार्य किये है तथा सरकार द्वारा लगान कमी की सराहना की गई थी। लेकिन स्वामी जी ने इन दावों को खोखला बताते हुए उसका विश्लेषण इस बुकलेट में किया है। अन्त में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख है। उन्होंने निष्कर्ष के रूप में यह कहा है कि फैजपुर में जो भूमि संबंधी कार्यक्रम लिये गये थे उसका मिलान जब राजेन्द्र बाबू के कथन से करें तो बेलाग वे अभी तक अपूरित रहे हैं।

रेन्ट रिडक्शन इन बिहारः हाऊ इट वर्क्सः (1936)–बिहार के कुछ नेताओं ने यह दावा किया था कि बिहार के कांगेस सरकार ने किसानों के हित में कार्य किया है रेन्ट रिडक्शन इसका ज्वलन्त उदाहरण है। स्वामी जी ने 28 पृष्ठों के इस बुकलेट में कई बिन्दुओं पर बिहार टेनेन्सी एक्ट का विश्लेषण प्रस्तुत किया है तथा लगान में कमी किसानों के हित में है, इस दावे को खोखला करार दिया है। स्वामी जी ने बताया है कि रेन्ट रिडक्शन का इस तरह से क्रियान्वयन किया गया है'जो किसान हितों के अनुकूल नहीं था। सरकारी दावा था कि जहां भी भूमिक्षय जलप्लावन से हुआ है बालू, जल जमा होने या अन्य कारण से वहां लगान को कम किया गया है, जहां भूमि कृषि कार्य योग्य नहीं रह गयी है वहां रेन्ट रिडक्शन अधिकारियों के पूरी तरह लगान माफी के अधिकार को कम नहीं किया गया है इत्यादि। जो टेनेन्सी कानून बिहार के तत्कालीन सरकार द्वारा पास किया गया था उसे काश्तकारों के प्रति सही बर्ताव कहा गया लेकिन स्वामी जी ने बताया है कि

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

रेन्ट रिडक्शन का प्रयोग पूरी तरह किसान हित में नहीं हुआ। उन्होंने यह भी बताया है कि किसानों ने जानबूझकर सिंचाई-प्रणाली को बर्बाद होने दिया वह सर्वज्ञात है। साथ ही रेन्ट रिडक्शन अधिकारियों को अधिकार की भी सरकारी आदेश द्वारा कम किया गया। उन्होंने इसमें बताया है कि जमीन्दारों ने सरकार को अपने हित की रक्षा के लिए मना लिया तथा उन्हीं की इच्छा के अनुरूप निदेश तथा सरकुलर भेजे गये जिससे किसानों को उतना लाभ नहीं हुआ।

खेत मजदूरः स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने 'खेत मजदूर' का लेखन कार्य फरवरी 1941 में पूरा किया। जब वे हजारीबाग सेन्ट्रल जेल में थे। इस पुस्तक में उन्होंने खेत मजदूरों–जो सदियों से पद दलित एवं शोषित रहे हैं, उन गरीबों की भयावह स्थिति एवं दुर्दशा का वर्णन किया है। खेत मजदूर खेत में काम करते और मजदूरी करके अपना जीवन बसर करता है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं एवं कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कृषक मजदूरों के जर्जर स्थिति के कारणों की व्याख्या की है, कम मजदूरी तथा उनके कर्ज एवं उसके भार जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सतही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वे अत्यंत गरीब किसान तथा मजदूर की स्थिति को सुधारना चाहते थे तथा कृषि व्यवस्था में परिवर्तन एवं सुधार कैसे लाया जा सकता है इसकी रूपरेखा उन्होंने इस पुस्तक में प्रस्तुत की है। उनके अनुसार अत्यंत गरीब किसानों तथा मजदूरों की स्थिति में बहुत अन्तर नहीं है अतः उन्हें अलग-अलग श्रेणी में बांटकर रखना एवं समस्याओं का समाधान निकालना सही नहीं होगा। स्वाजी जी के अनुसार "जो असल किसान है, जिन्हें गरीब या मध्यम किसान कहते हैं, उनकी हालत और 98 प्रतिशत खेत मजदूरों की दशा में कोई भी महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। जहां तक इन दोनों की आर्थिक दशा और मानसिक हालत का ताल्लुक है खेत मजदूरों और गरीब किसानों में जिनकी संख्या 80 फीसदी से कम नहीं है, कोई भी भेद किया जा नहीं सकता–किसी भेद की गुंजाइश नहीं है।" उन्होंने बाद में कहा है कि "जैसे किसानों की दशा बदतर होते-होते जो उनमें सबसे नीचे आ जाते हैं वही गरीब किसान हैं, ठीक वैसे ही आमतौर से उनकी दशा कुछ और गिर जाने से उन्हें खेत-मजदूर कहने लगते हैं पुनः आगे वे लिखते हैं, " इसीलिये खेत-मजदूरों को, जिनसे आमतौर से हमारा ताल्लुक है, किसान ही मानना उचित है।"

उन्होंने खेत-मजदूरों के प्रश्न को सोलहो आने आर्थिक माना है। इसे धार्मिक रंग देना निहायत ही गलत और खतरनाक बात है।

खेत-मजदूरों की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनमें सबसे अहम मजदूरी का मुद्दा है। खेत-मजदूरों को मिलनेवाला का रोजाना नहीं होता तथा उन्हें काफी कम मजदूरी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मिलती है। साथ ही उनकी सुरक्षा का कोई इन्तजाम एवं गारंटी नहीं होता। उनके लिए भी यह गारंटी चाहिए कि अस्वस्थता, बुढ़ापा, हाथ-पैर आदि खराब हो जाने की दशा में उनकी गुजर होती रहे। दूसरा सवाल मजदूरी कितनी हो इसका है कम से कम वेतन या मजदूरी उतनी हो जो गुजारा के लिए जरूरी हो। मजदूरी का प्रश्न सिर्फ आदर्शवादी न होकर व्यावहारिक बनकर हल किया जाना चाहिए। श्रमिकों को ठीक अन्न मजदूरी में नहीं दिया जाता न ही समान मजदूरी दिया जाता है।

कर्ज का सबसे अगला प्रश्न है जो निहायत ही पेचीदा है। कर्ज के कारण खेत मजदूर किसानों, बनियों का पुश्त दरपुश्त के लिए गुलाम बन जाता है। बंधुआ मजदूर की समस्या पैदा होती है। गलत ढ़ंग से, शराब पिलाकर, फिजूलखर्ची के लिए प्रोत्साहित करके साहूकार उन्हे कर्म के जाल में फंसाते हैं। अनेक प्रकार से उनका शोषण किया जाता है तथा उन्हें दास बना दिया जाता है।

बीमारी की हालत में काम के लिए मजबूर होना भी उनकी एक अहम समस्या है। जमीन प्राप्त करना तथा घर के लिए जमीन हासिल करना भी उनकी एक महत्वपूर्ण समस्या है। अन्तिम समस्या है उनके साथ बर्ताव की, उन्हें उचित सम्मान एवं इज्जत देने की। इन समस्याओं के विस्तार से वर्णन के बाद उन्होंने अनेकों समाधान बताये हैं। स्वामी जी के अनुसार ठंडे दिमाग से उनकी सभी बातों पर विचार करना तथा उनकी समस्याओं को समझना होगा किसान तथा मजदूर एक दूसरे के दुश्मन न समझें बल्कि उनमें आपसी साझेदारी तथा सहयोग की जरूरत है।

श्रमिकों के लिए बिना सूद किसानों के द्वारा कर्ज प्रबंध होना चाहिए। उनके प्रति मनुष्यता के बर्ताव तथा सहृदयतापूर्ण सलूक की जरूरत है। खेत-मजदूरों से समानता और भाईचारा का सलूक बिना विलम्ब करना होगा। उनक साथ मनुष्यता तथा प्रेम का व्यवहार करना जरूरी है। उनकी मां बहनों के साथ आदर का सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। जमीन की चाह तथा मजदूरी का सवाल हल होना चाहिए। एक से अधिक फसल उगाकर तथा खेती को आधुनिक बनाकर किसानों की हालत में सुधार होगा तथा मजदूरी में भी बढ़ोत्तरी होगी। सरकार जमींदारों की सारी जिरात और बकाश्त की जमीनें छीन ले जो खेती से गुजर नहीं करते। जो लोग भावली या नगदी लगान पर गैरों को जमीन देते हैं, उनकी ऐसी जमीनें लेकर उनमें से सबसे पहले उन लोगों को भी दी जाए जो खेत मजदूर या इसी प्रकार के लोग हैं। धनी किसानों से उचित मजदूरी ली जाय लेकिन गरीब किसान के साथ रियायत की जा सकती है। मजदूर तथा गरीब किसान इन ग्रहों (जमींदार बड़े धनी किसानों) के पेट से पैदावार को बचाये। इसके लिए दोनों को

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मिलकर एकमत होकर सम्मिलित रूप से लड़ने की जरूरत है। किसानों तथा मजदूरों में सही समझदारी तथा सदभावना की जरूरत है। मजदूरी का सवाल इसी तरह हल किया जाना चाहिए।

इसके लिए मजबूत संगठन तथा प्रचंड आन्दोलन की जरूरत है। जब किसान तथा मजदूर संगठित तथा सम्मिलित शक्ति से लड़ेंगे तथी यह संभव होगा। इन दोनों का एक संगठन होना चाहिए। धनियों से गरीब किसानों का जुदा संगठन हो, जो अत्यंत गरीब और संपत्तिहीन हैं वही तो खेत-मजदूर हैं। गरीब किसान तथां मजदूर आपस में बातें करके मजदूरी बगैर का मामला तय कर सकते हैं। इन बातों पर अमल करके न सिर्फ खेत-मजदूरों का, बल्कि समूचे किसानों की समस्याएं बखूबी हल हो जायेंगी।

झारखंड के किसानः यह पुस्तक स्वामी सहजानन्द सरस्वती द्वारा नवंबर 1941 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में झारखंड के किसानों के शोषण तथा उनकी पीड़ा का वर्णन स्वामी जी द्वारा किया गया है। झारखंड क्षेत्र उनकी कर्मभूमि नहीं रही थी। लेकिन उन्होंने कुछ समय उस क्षेत्र के लोगों आदिवासियों तथा किसानों के साथ बिताया था तथा वहां के लोगों से उनकी समस्याओं को वहां के किसानों के शब्दों में सुना था। उन्होंने जो स्थिति देखी थी उसको उन्होंने 'खुले लूट' की संज्ञा दी है। बाहर के लोग *डिकुस* जो वहां व्यापार के लिए, धर्म प्रचार एवं विशेष धर्म के विस्तार के लिए आये या फिर सरकार इन सबों ने झारखंड क्षेत्र की भोलेभाले, सरल, अनपढ़ एवं निरीह लोगों का भरपूर शोषण किया। उनकी दुर्दशा एवं शोषण कर उनकी जमीन को हड़प लिया, वहां के प्राकृतिक साधनों का भरपूर शोषण किया तथा वहां की जनता को उन्हें सदियों से प्राप्त होनेवाले प्राकृतिक साधनों पेड़, जंगल, पत्ते लकड़ी, जल इत्यादि से एवं प्राकृतिक वातावरण से उन्हें वंचित किया तथा जिस परिवेश में वे रहते आये थे उसे छीना। बाहरी लोगों ने वहां की स्थानीय जनता का किस तरह, किन तरीकों से शोषण किया तथा उनके सुख चैन एवं सुविधाओं को छीन लिया इसकी एक सटीक तथा सतही जानकारी एवं विश्लेषण इस पुस्तक में विस्तार से मिलता है। बनिये व्यापारी महाजन वर्ग ने सूदखोरी द्वारा अनपढ़ जनता का शोषण किया। ईसाई धर्मावलम्बियों, जैन धर्मावलम्बियों ने भी उनका शोषण किया। सरकार तथा जमींदारों ने उनका शोषण किया तथा कैसे किया इसकी व्याख्या इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है। वहां के साधनों जंगल, पेड़, लाह, लोहा, कोयला, अभ्रक जैसे बहुमूल्य साधनों का अपने हित साधन के लिए विदेशियों, बाहरी लोगों ने तथा सरकार ने प्रयोग किया लेकिन उनके विकास एवं शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया। वहां अशिक्षा एवं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बदहाली का साम्राज्य है। वहां का काश्तकारी कानून भी किसानों के हितों के सुरक्षा में नहीं बनाया गया बल्कि जमींदारों के हितों की रक्षा की गई। महाजनों ने कर्ज देकर उसके लिए सूद एवं फसल के रूप में 20 गुना वसूल किया, जब कर्ज अदायगी नहीं हुई तो उनकी जमीन को बंधक रख लिया तथा किसान बंधुआ मजदूर बन गये। इन सारी घटनाओं तथा प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। टाटा द्वारा शोषण एवं सहकारी समितियों की खमियों का भी जिक्र किया गया है।

अन्त में स्वामी जी ने झारखंड के किसानों की दशा सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मांगों का उल्लेख किया हैः—

1. झारखंड़ी किसानों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि कोड़कर तथा उठकर आदि नामों से जो जमीनें आबाद की जाती हैं या की जा सकती है उनके बारे में जमींदार की हर तरह की रोक, कानून बना कर अविलंब समाप्त की जाए।
2. जंगल से किसानों को घर गृहस्थी एवं जीविका चलाने के लिए पत्थर, बालू, काठ, बांस, फल-फूल इत्यादि बिना रूकावट लेने की छूट हो तथा किसानों के खेतों में लगे पलास, कुसुम और बेर के पेड़ो पर लाह लगाने और लगी हुई को उतारने, बेचने आदि का उन्हें पूरा हक हो।
3. किसानों तथा उनके पशुओं को पीने वगैरह के लिए शुद्ध जल का जरूरत के मुताबिक फौरन इंतजाम किया जाए।
4. झारखंड से कांजीहोस या कैटल पाउंड फौरन हटा लिये, और तोड़ दिये जाए।
5. लगान कम किया जाए।
6. दामिन इलाके के पहाड़ियों लोगों की कुरांव या झूमचास की आजादी पूरी तरह कायम रखी जाए।
7. झारखड के जो आदिवासी या पिछड़े हुए किसान और दल हैं उनके पढ़ने के लिए उन्हीं की भाषा में जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए।
8. आबयाशी का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया जाए और इस ओर मुस्तैदी के साथ फौरन काम शुरू किया जाए।
9. किसान परिवार के साल भर के लिए खड़ी फसल गल्ला बगैर छोड़ कर ही लगान में जब्त भी नीलाम हो।
10. बकाया लगान की नालिश न तो एक साल से कम की हो और न ज्यादे की।
11. झारखंड के सभी जिलों के लिए एक ही तरह की काश्तकारी कानून बने और वह बिहार के काश्तकारी कानून जैसा हो।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

12. सरकार की ओर से अधिक से अधिक तीन रुपया सैकड़ा सलाना सूद की दर पर किसानों को कर्ज देने का इन्तजाम किया जाए।
13. सेपकाई, कमिऔती आदि नाम से प्रचलित गुलामी और कमिया प्रथा को बिल्कुल समाप्त किया जाए।
14. ऐसी व्यवस्था हो जिसमें आदिवासी और पिछड़े किसानों की भाषाओं तथा रस्म रिवाजों को बखूबी जानने-समझने वाले हाकिम इनके मुकद्दमे पर विचार करें।
15. ऐसे कानून बनाये जायें कि उनके केसों में न वकील, मुखतार या कानूनी सलाहकार है वे धोखा न दे सकें।
16. किसान संबंधी कानून के नये बात की जानकारी के लिए किसानों के बीच उसके प्रचार का पक्का इन्तजाम किया जाए।
17. अबरक का जहां-तहां से चुन और निकाल के जो किसान या गरीब गुजर करते हैं चोरी के बहाने उन्हें सताने का जो कानून है वह रद्द हो।
18. कम जुडिसियस कमिश्नर होने के कारण से सेसन्स के केसों में जो बहुत ज्यादा समय लगता है उस समस्या को दूर किया जाए।

पत्रकार एवं सम्पादक

स्वामी जी की पत्रकारिता एवं सम्पादन-कला भी कम सशक्त नहीं है। तीसरे दशक में जो समस्याएं समाज के सामने आईं उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से पेश कर जनता को उचित मार्ग-निर्देश किया। साथ ही जन जागरण का भी काम किया। इसके लिए उनके दो पत्रिकाओं को सदायाद किया जायगा। वे हैं 1911 से 1916 ई. तक निकलने वाला 'भूमिहार ब्राह्मण' और 1922 से 1924 ई. तक प्रकाशित होने वाला 'लोक संग्रह'। जहां प्रथम के माध्यम से उन्होंने जातिगत जागरण को गति तीव्र की और अपने को श्रेष्ठ प्रिय समझने वाला एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को तिरस्कृत करने के व्यवहार की अच्छी खबर ली, वहीं दूसरे के माध्यम से अंग्रेज शासन के छक्के छुड़ाए। उन्होंने जिन अन्य पत्रों में लेख लिखे वे हैं पटना के 'हुंकार' एवं 'जनता' कलकत्ता का 'विशाल भारत' और गोरखपुर का 'कल्याण' के ईश्वरांक और योगांक आदि।

स्वामी जी की सभी कृतियों को देखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि ये साहित्य की विविध विधाओं के साहित्यकार थे। शोधस्तरीय ऐतिहासिक ग्रन्थ 'भूमिहार ब्राह्मण परिचय' के साथ उन्होंने दूसरे दशक में साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश किया और पांचवे दशक के पूर्वार्द्ध तक हिन्दी-गद्य को विविध विधाओं में छा गये।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उन्होंने आत्मकथा, आलोचना, संस्मरण, इतिहास आदि सब कुछ लिखा। अपने को कर्मकाण्ड का विशेषज्ञ भी सिद्ध किया और दार्शनिक, पत्रकार, सम्पादक भी। सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना से उनके देशवासियों की पराधीनता, किसानों की दुर्दशा, जमींदारों की दमन एवं शोषण नीति और वर्ग विशेष के अत्याचार के प्रति आक्रोश व्यक्त करने को बाध्य किया।

इस प्रकार स्वामी जी एक सनातनी साधु की तरह भगवान की खोज करते, राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन से होते हुए किसान-आन्दोलन का नेतृत्व किया और साम्यवाद की मार्क्सवादी-लेनिनवादी अवधारणा के प्रति प्रतिबद्धता लिए 26 जून, 1950 को 2 बजे रात्रि मुजफ्फरपुर में मृत्यु को प्राप्त हो गए।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

संदर्भ

1. "स्वामी जी की कलम से : जन्म और बाल्यावस्था", स्वामी सहजानन्द स्मृति ग्रंथ (ब्रह्मर्षि समाज, कानपुर, मार्च, 1986)–पृ. सं. 43
2. श्री सुरेन्द्रनाथ, दीक्षित, "जीवन गाथा" ज्योति कलश (स्वामी सहजानन्द सरस्वती विकास सेवा संस्थान, मुजफ्फरपुर, 1989) पृ. 4
3. अशोक कुमार, 'सहजानन्द सरस्वती जी की विरासत', नवयुग, 23 फरवरी, 1990 पृ. 24.
4. क्योंकि दण्डी सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकते थे और स्वामी जी का सम्बन्ध भूमिहारों से था।
5. स्वामी जी के बचपन का नाम
6. स्वामी जी के परिवार में उनके पिता बेनी राय, स्वामी जी के चाचा, स्वामी जी की मां, स्वामी जी की चाची जो उनकी मौसी भी लगती थीं, स्वामी जी के चार अन्य भाई, एक चचेरा भाई और एक चचेरी बहन थी। स्वामी जी के एक भाई का देहांत उनकी जानकारी के पूर्व ही हो गया था, एक अन्य भाई श्री राम विलास राय की मृत्यु भी उनके सामने हो गई थी, माता की मृत्यु स्वामी जी के बाल्यकाल में ही हो गई थी। शेष बचे तीन भाइयों में स्वामी जी के अलावा थे जंगबहादुर राय और रामध्यान राय, चचेरे भाई थे सुन्दर राय उनके पिता तथा चाची, मौसा की मुत्यु भी स्वामी जी के संन्यास धारण के कुछ ही दिनों बाद हो गई। उनके चचेरे भाई का वंश नहीं चला, देखें "स्वामी जी की कलम से : जन्म और बाल्यावस्था"। पूर्वोद्धृत
7. अशोक कुमार, पूर्वोद्धृत
8. सुरेन्द्र नाथ दीक्षित, पूर्वोद्धवृत, पृ. 7.
9. उपर्युक्त पृ. 8.
10. आचार्य परमानन्द शर्मा, स्वामी सहजानन्द सरस्वती : जीवन दर्शन और कृतित्व (सहजानन्द सरस्वती ट्रस्ट, गाजीपुर यू.पी., 1974), पृ. 2.
11. वकौल स्वामीजी स्वयं भूमिहार-ब्राह्मण नहीं थे मगर लगता है कि भूमिहारों के साथ उनके खानदान का खान-पान और शादी-ब्याह का सम्बन्ध होने के कारण उनके परिवार को और उन्हें भूमिहार मान लिया जाता है। देखें, अशोक कुमार, पूर्वोद्धृत, पृ. 28.
12. डा. श्याम बिहारी राय "स्वामी सहजानन्द सरस्वती का राष्ट्रीय आंदोलन मे ऐतिहासिक योगदान "निवेदिता", 1987-88 और 88-89, स्वामी सहजानन्द

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सरस्वती जन्मशती विशेषांक स्वामी सहजानन्द-सरस्वती विद्यापीठ मध्य विद्यालय, गाजीपुर, पृ. 6.

13. सुरेन्द्र नाथ दीक्षित, पूर्वोद्धृत, पृ. 17.
14. डा. सुरेन्द्रनाथ दीक्षित, पूर्वोद्धृत, पृ. 17.
15. निवेदिता, स्वामी सहजानन्द सरस्वती, जन्मशती विशेषांक (स्वामी सहजानन्द सरस्वती विद्यापीठ महाविद्यालय, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, 1987-89)
16. आचार्य परमानन्द शर्मा, पूर्वोद्धत.
17. कुलदीप नारायण 'झड़प' वंश परम्परा और व्यक्तित्व स्वामी सहजानन्द सरस्वती ओंकार से हुंकार तक (राहुल प्रेस. सी. 192, पत्रकार नगर, कंकड़बाग, पटना-20, 1990, पृ.20.
18. सुरन्द्रनाथ दीक्षित, पूर्वोद्धृत, पु. 16.
19. उत्पतिरेव विप्रस्य मूर्ति धर्मस्य शाश्वती।
स हि धर्माथमुत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते।।
ब्राह्मणों जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते।
ईश्वरः सर्वभूतानां धर्म कोशस्य गुप्तयो।।

अध्याय 1/98.99

20. सहजानन्द सरस्वती, ब्राह्मण समाज की स्थिति (बिहटा, ब्रह्मर्षि पुस्तकालय ई. आई.आर. बिहार तथा बेनी प्रसाद सिहं, सराय गोवर्द्धन, बनारस सिटी (पृ.-33 से 98 तक)
21. उपरोद्धृत
22. स्वामी सहजानन्द सरस्वती का भूमिहार-ब्राह्मण महासभा में व्याख्यान (बलिया, दिसम्बर, 1913)
23. "ब्रह्मर्षि संदेश" द्वितीय पुष्प, महाशिवरात्रि सं. 2042 मार्च, 1986 स्वामी सहजानन्द सरस्वती स्मृति ग्रंथ (ब्रह्मर्षि समाज, कानपुर) पृ. 23.
24. अशोक कुमार, पूर्वोद्धृत, पृ. 24
25. यजुर्वेद 32/12, 12/44, 12/67 अथर्ववेद 11/35, 2/36, 2/37
शुक्ल याजुर्वेद 12/67, 2/20, 11/31-34 वात्स्यायन 18/82 ऋग्वेद 7-8-13, 8-7-7, 8-7-1.
गौतम (न्याय) सूत्र भास्य अध्याय-1, सूत्र-54

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पांतजलि, महाभाष्य, 5-1-115, 2-157-58, 2-162-64, 4-190-194, 4-198-202.

उद्योग पर्व 179/24,

गोता, 3/14, 15, 18/42

याज्ञवल्क्य-2/110, 1/95-99 अध्याय-124

अथर्ववेद-11/33-34 काण्डिका-3, अनुच्छेद-4

मनुस्मृति-9/327, 1/100, 10/80, 4/4-6, 11/7, 4/25, 26, 76, 186, 128/74-78, 199/39-40, 2/154,

गौतम स्मृति, 2/10/3

पारस्कर गृह सूत्र, कण्डिका-2, कांडिका-13

महामहोपध्याय पार्थसारथि, मीमांसा वर्तिका तंत्र रत्न, पृ. 29-30

कौशिक सूत्र (3-3)

बोधा स्मृति, 5/1/10

26. मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक, 16-17, 2/9-10, 11, 9/317, 320, 9/131-16-241,10/74, 11/4- 6-6-10, 9/300

दुगास्त द्विवेदी, ब्राह्मण भेद विचार पृ. 4-5

भास्कर भ्रमभंजन

27. अशोक कुमार, पूर्वोक्त, पृ. 25-26

28. भोगेन्द्र झा ''किसानों के लोकप्रिय नेता स्वामी सहजानन्द (एक संस्मरण) ब्रह्मर्षि संदेश, (ब्रह्मर्षि समाज कानपुर, मार्च, 1986) पृ. 27.

29. सुरेन्द्रनाथ दोक्षित "ज्योतिर्मय जीवनधारा" स्वामी सहजानन्द सरस्वती-ओंकार से हुंकार तक पूर्वोद्धृत पु. 31.

30. त्रिवेणी शर्मा "सुधाकर" पूर्वोद्धृत, पृ. 3

31. सुरेन्द्र नाथ दीक्षित "जीवन गाथा" पूर्वोद्धृत पृ. 20

32. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष, पृ. 386

33. दण्डी स्वामी विमलानन्द सरस्वती "युग पुरुष स्वामी सहजानन्द सरस्वती" ब्रह्मर्षि सन्देश, पूर्वोद्धृत, पु. 16

34. पूर्वोद्धृत और सुरेन्द्रनाथ दीक्षित, पूर्वोद्धृत पृ. 21,

35. उपरोद्धृत

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

36. अशोक कुमार, पूर्वोद्धृत, पृ. 26
37. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष, पृ. 366
38. सुरेन्द्रनाथ दीक्षित, पूर्वोद्धृत, पृ. 32
39. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, पूर्वोद्धृत, पृ. 366
40. सुरेन्द्रनाथ दीक्षित, पूर्वोद्धृत पृ. 32
41. देखें परिशिष्ट-III
42. उपरोद्धृत, पृ. 22
43. उपरोद्धृत
44. आचार्य परमानन्द शर्मा, पूर्वोद्धृत
45. सुरेन्द्रनाथ दीक्षित, पूर्वोद्धृत पृ. 23
46. संयुक्त वामपक्षी मोर्चा का घोषणा पत्र
47. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष, पृष्ठ, 203-211
48. उपरोद्धृत पृ. 203
49. उपरोद्धृत पु. 209
50. अशोक कुमार पूर्वोद्धृत, पृ. 26
51. उपरोद्धृत
52. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष, पु. 210 देखें।
53. डा. श्याम बिहारी राय, पूर्वोद्धृत, पृ. 61
54. अयोध्या सिंह, भारत का मुक्ति संग्राम (प्रथम तरंग का विवरण)
55. उपरोद्धृत
56. निवेदिता, पूर्वोद्धृत
57. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष (पूर्वोद्धृत) पृ. 342
58. गया के किसानों की करुण कहानी
59. उपरोद्धृत, पृ. 71
60. उपरोद्धृत, पृ. 255
61. सुरेन्द्रनाथ दीक्षित, पूर्वोद्धृत, पृ. 30
62. प्रान्तीय किसान सम्मेलन, हाजीपुर, नवम्बर, 1935
63. अशोक कुमार, पूर्वोद्धृत, पु. 28
64. उपरोद्धृत

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

65. उपरोद्धृत
66. उपरोद्धृत
67. डा. श्याम बिहारी राय, पूर्वोद्धृत, पृ. 62
68. रजनी पाम दत्त, आज का भारत (मैकमिलन इन्डिया लि., नई दिल्ली, 1985, पृ. 208
69. शंकर दयाल सिंह, जो छोड़ गए वे भी रहेंगे। (1980) पृ. 24-25
70. अशोक कुमार, पूर्वोद्धृत, पृ. 29
71. अवधेश प्रसाद सिन्हा, किसान सभा और कास्तकारी कानून संशोधन, पृ. 6 राकेश गुप्ता, बिहार पीजेन्ट्री और किसान सभा, (नई दिल्ली, 1982) पृ. 66
72. अवधेश प्रसाद सिन्हा, बिहार प्रोभिन्सियल किसान सभा, 1936
73. श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, "किसानों के प्राण" स्वामी सहजानन्द सरस्वती, ओंकार से हुंकार तक", पूर्वोद्धृत, पृ. 88
74. इस महाधिकार पत्र को कइयों किसान का मैगनाकार्टा कहा है।
75. होम पोलिटिकल फाइल न. 10/1934, बिहार और उड़ीसा सरकार स्पेशल ब्रांच इंसपेक्टर की रपट 11 जून, 1934
76. होम पोल (स्पेशल) मेमो न. 16/1935 बिहार और उड़ीसा सरकार
77. किसानों के प्राण-उपरोद्धृत, पृ. 87
78. टाइम्स ऑफ इन्डिया, 19 मार्च 1989 (पटना)
79. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, "मेरा जीवन संघर्ष", पूर्वोद्धृत, पृ. 442-443
80. रजनी पान दत्त, पूर्वोद्धृत, पृ. 109
81. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, "महारुद्र का महाताण्डव" पूर्वोद्धृत, पृ. 8-9
82. उपरोद्धृत, पृ. 9
83. उपरोद्धृत
84. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, महारूद्र का महाताण्डव, पृ. 7-8
85. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, "जंग और राष्ट्रीय लड़ाई, पृ. 2-7
86. स्वामी सहजानन्द, क्रान्ति एवं संयुक्त मोर्चा (बांकीपुर, पटना
87. रजनी पाम दत्त, पूर्वोद्धृत, पृ. 109
88. स्वामी सहजानन्द, महारूद्र का महाताण्डव, उपरोद्धृत, पृ. 7-8

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

89. अशोक कुमार, पूर्वोद्धृत, पृ. 30-31
90. उपरोद्धृत, पृ. 31
91. शीलभद्र याजी, वैज्ञानिक समाजवादी स्वामी सहजानन्द, ब्रह्मर्षि संदेश, पूर्वोद्धृत, पृ. 38.
92. प्रो. रामनाथ शर्मा, स्वामी सहजानन्द सरस्वती : साहित्यकार के रूप में 'निवेदिता' स्वामी सहजानन्द सरस्वती जन्मशती विशेषांक (स्वामी सहजानन्द सरस्वती विद्यापीठ महाविद्यालय, गाजीपुर, कल्पना प्रेस, वाराणसी 1980-88, पृ. 35
93. उपरोद्धृत
94. उपरोद्धृत, पृ. 31
95. उपरोद्धृत
96. ब्राह्मण समाज की स्थिति (बेनीप्रसाद सिंह, सराय गोवर्द्धन, बनारस सिटी, 1916), पृ. 3.

नोटः

पटना सम्मेलन में शामिल प्रमुख दल थे–

1 अखिल भारतीय फारवार्ड ब्लॉक
2 अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
3 अखिल भारतीय संयुक्त किसान-सभा
4 अखिल भारतीय किसान-सभा
5 आल इण्डिया ट्रेड युनियन कांग्रेस
6 अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी
7 भारतीय क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी
8 अखिल भारतीय क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टी
9 अखिल भारतीय क्रान्तिकारी वर्कर्स पार्टी
10 वोलशेविक पार्टी ऑफ इण्डिया
11 डेमोक्रेटिक बेनगार्ड
12 कम्युनिस्ट वर्क्स लीग आफ इण्डिया
13 अखिल भारतीय मजदूर सभा
14 सोशलिस्ट युनिटी सेन्टर
15 कम्युनिस्ट वर्क्स आदि,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-2

तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक परिवेश और स्वामी जी का उदय

दार्शनिकता के स्तर पर वैज्ञानिक चिंतन-प्रणाली इस स्थापना को स्वीकार करती है कि मानव-मस्तिष्क या मानवीय चेतना अपने आस-पास वर्तमान भौतिक परिस्थिति के स्वरूप के अनुसार ही निर्मित होती है। इस भौतिकवादी स्थापना की सत्यता, प्रामाणिकता या आकारयता स्वामी सहजानन्द सरस्वती के व्यक्तित्व एवं कृतियों का गवेषणात्मक अध्ययन से प्रामाणित हो जाती है।

स्वामी जी के जन्मकाल से मृत्यु पर्यन्त भारतीय उपमहाद्वीप में बदलती भौतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप निर्मित आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अवस्थाओं ने उनके व्यक्तित्व को निर्मित किया या यों कहें कि स्वामी जी की चेतना का निर्माण भारत की बदलती भौतिक परिस्थितियों का अनुसरण करता रहा।

उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशकों में, जब स्वामी जी का जन्म 1889 की महाशिवरात्रि' के दिन हुआ, भारत में ब्रिटिश सरकार का वर्ग चरित्र औद्योगिक पूंजी के शासन काल से संक्रमण कर वित्तीय पूंजी के शासन काल में प्रवेश कर चुका था और ब्रिटिश शासन साम्राज्यवाद की प्रथम मंजिल पर पहुंच चुका था। 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लोकमान्य तिलक आदि के नेतृत्व में चलाई जा रही लड़ाई का स्वरूप मुख्यतः धार्मिक पुनरुत्थानवादी था और किसी सशक्त जनसंगठन के अभाव में धार्मिक उत्सवों, गौरीपूजा, गणेशपूजा आदि के माध्यमों से साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में जन-एकता कायम करने का अथक प्रयास राष्ट्रीय नेतागण कर रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय पुनर्जागरण के प्रभावों तले भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर कराने का प्रयास भी चल रहा था, जिसके प्रभावस्वरूप बाल-विवाह के खिलाफ 1890 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 'एज आफ कन्सेन्ट बिल' लाया गया था। इस प्रकार धार्मिक पुनरुत्थानवाद और धार्मिक, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष–इन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दो परस्पर विरोधी परिस्थितियों के काल में स्वामीजी का जन्म हुआ। इस कारण उनके व्यक्तित्व पर इन दोनों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

स्वामी जी के 61 वर्षों की जीवन-अवधि को अगर समय सीमा के वर्गीकरण में विभाजित किया जाय तो उसके मुख्य चार खंड हो सकते हैं और प्रत्येक खंड में उनकी चेतना का विकास उस काल विशेष में विद्यमान भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव तले ही हुआ है, अन्यथा नहीं। ये चार खंड इस प्रकार हो सकते हैं :-

1. 1889 से 1907 तक 18 वर्ष परिवार के बीच,
2. 1907 से 1920 तक 13 वर्ष विद्यार्जन में-काशी एवं मिथिला तथा भारत भ्रमण,
3. 1920 से 1934 तक 14 वर्ष स्वतंत्रता-संग्राम में उनका गांधीवादी स्वरूप,
4. 1934 से 1950 तक किसान-आन्दोलन एवं वामपंथी रुझान

एक अन्य प्रकार से-स्वामी जी के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अगर उनके संपूर्ण जीवन काल का वर्गीकरण उपस्थित किया जाय तो उसे मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे :-

1. समाज-सुधारक के रूप में,
2. आजादी की लड़ाई के अग्रिम योद्धा के रूप में, और
3. किसान आन्दोलन के अप्रतिम योद्धा के रूप में।[2]

वर्गीकरण चाहे जिस दृष्टि से हो, उनकी चेतना के निर्माण में भौतिक कारण एक समान ही रहे हैं।

स्वामी जी का ग्रामीण और पारिवारिक परिवेश

स्वामी जी के जन्म के समय में ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा प्रतिपादित आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण सामंती-अर्थव्यवस्था के अस्तित्व का बना रह जाना ग्रामीण और परिवार की आर्थिक दशा को अभावग्रस्त निम्न मध्यमवर्गीय स्वरूप प्रदान कर चुका था। भू-लगान की वसूली में नौकरशाही और साम्राज्यशाही का जोर तो सदा बना रहता था, परन्तु कृषि को स्वावलम्बी बनाने, सिंचाई-प्रबंध को सुव्यवस्थित करने के अनुसार साम्राज्यवादी नीति के कारण, कृषि पर जनसंख्या का भार काफी बोझिल था। इस कारण बेरोजगारी या अर्धबेरोजगारी का प्रभाव प्रबल रूप से गांव को प्रभावित कर रहा था। भारतीय रूढ़िवादी परम्परा में बाल-विवाह को एक स्वीकृत संस्थागत स्वरूप ग्रहण करने के कारण, तथा हिन्दू रूढ़िवादिता के कटु अनुभव-काल में स्वामी जी का जीवन इन्हीं धार्मिक परम्पराओं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

की गिरफ्त में रहा। घर के बगल में एक शिव-मन्दिर था, वहां वे घण्टों शिव की उपासना करते। उपासना करते-करते वे तन्मय हो जाते, साथ ही अपनी सुध-बुध नहीं रहती। दूसरी और उस समय में प्रचलित छुआछूत के भाव से भी वे पीड़ित थे। इस हद तक कि जिस वेष-भूषा में जर्मन मिशन स्कूल में जाते स्कूल में लौटने पर उसे उतार कर ही घर में जाते। इस कपड़े को भी अस्पृश्य मानते और धोखे से कहीं उस वस्त्र को छू लिया तो नहाना पड़ता था।

कुछ दिनों बाद गांव की पुरानी परम्परा के अनुकूल 16 वर्षों में उनका उपनयन संस्कार और विवाह हो गया। शादी के दो वर्षों के भीतर ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। समाज के लोगों ने उस समय उनकी पत्नी की छोटी बहन (साली) से दूसरी शादी करनी चाही, तो स्वामी जी ने इसका विरोध किया।

स्वामी जी के वैयक्तिक और पारिवारिक परिवेश की धर्मान्धता इस ऊंचाई तक पहुंच गई थी कि जिस स्कूल में उनकी पढ़ाई चलरही थी उसमें खुलेआम ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता था। धर्म के द्वारा शिक्षण संस्था का यह शीलहरण स्वामी जी जैसे विचारवान छात्र के लिए इस कारण असह्य था कि वे सर्वधर्म समभाव की कल्पना किए हुए थे। उन्होंने एक दिन इस प्रकार के ईसाई धर्म प्रचार का विरोध करते हुए कहा "यह स्कूल है या धर्मों के खण्डन-मंडन का अखाड़ा।" धर्म के प्रति उनका बचपन का लगाव तथा धार्मिक पारिवारिक परिवेश, जो पैराणिक धार्मिक संस्कृति द्वारा निर्मित था, उन्हें प्रेरित किया कि मुक्ति का मार्ग मात्र संन्यास धर्म की दीक्षा है। इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान वृद्ध संन्यासी श्री अच्युतानन्द महाराज से धर्म की दीक्षा ली और वे सिर मुंडवा, गेरुआ वस्त्र पहन कर संन्यासी हो गये।

पौराणिक संस्कृत वांड्गमय, तथा वर्णाश्रम धर्म पर आधारित भारतीय सामाजिक-आर्थिक परिवेश, जिसे भारत में अबतक बनाये रखा गया था, स्वामी जी को भूमिहार ब्राह्मणों को उनके जातीय गौरव को स्थापित करने के लिए बाध्य किया। वे खुद जुझौतिया ब्राह्मण थे लेकिन उनके वंशवाले जी बुन्देलखण्ड से आये थे, ने शादी ब्याह द्वारा अपने को भूमिहार ब्राह्मणों से संबंधित कर लिया था।[4] स्वामीजी भूमिहार ब्राह्मण को ब्राह्मण मानते थे। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह ब्राह्मण शब्द कान्यकुब्ज ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण आदि में है वैसा ही भूमिहार ब्राह्मण में भी है। लेकिन उनमें उन्हें स्वाभिमान की कमी नजर आई तथा उन्होंने उनको स्वाभिमान के मार्ग पर लाने की कोशिश की।[5] उन्होंने बाद में लिखा है कि मुझमें ब्राह्मणतत्व पूर्णतः भरा था, उनका संस्कार वैसा था तथा उन्हें यह विश्वास था "मेरे पूर्वज इतने मूर्ख न थे कि बुन्देलखंड के अपने

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जुझौतिया ब्राह्मणों को छोड़ भूमिहारों से मिले। यदि उनमें अपनी जैसी ब्राह्मणता और योग्यता इनमें न पायी होती।........इसलिए मेरा अटल विश्वास था कि ये भूमिहार वैसे ही ब्राह्मण हैं, जैसे कि मैथिल, कान्यकुब्ज आदि।[6] उन पर जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता है लेकिन उन्होंने इसका खण्डन किया है। उन्होंने स्पष्टत: यह बताया है कि वे तो जुझौतिया ब्राह्मण थे, उनका संबंध भूमिहार ब्राह्मणों से हुआ जिन्हें वे खुद ब्राह्मण ही स्वीकार करते थे। उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने अवश्य ही उच्च एवं कुलीन ब्राह्मण समाज जो पददलित एवं अपमानित हो रहा था, को उठाने की कोशिश की। यह ठीक इसी तरह का कार्य है जिसके द्वारा अपमानित को ऊपर उठाया जाता है। स्वामी जी ने स्वयं लिखा है "इसमें क्या अपराध हुआ?............आखिर सारे मुल्क को तो ऊंचा उठाना ही है। ....जिसका हक छीना जाय या छिन गया हो उसे तैयार करके उसका हक उसे वापस दिलाना यही तो मेरे विचार से आजादी की लड़ाई तथा असली समाज-सेवा का रहस्य है।[7] इस तरह यह जाहिर है कि भूमिहारों को जागृत करने की स्वामीजी ने उसे बड़े उद्देश्य का एक छोटा अंग माना। भारतीय मुक्ति संग्राम का वह समय खंड, जिसमें धार्मिक उत्सवों का आयोजन स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में संगठित किया जा रहा था, आर्य-संस्कृति की यूरोपीय पूंजीवादी संस्कृति के ऊपर स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी और वर्णाश्रम धर्म जिस संस्कृति का एक संस्थागत रूप था, स्वामी जी को जातीय उत्थान की तरफ प्रेरित किया। इन वस्तुगत परिस्थितियों ने उन्हें धार्मिक-सामाजिक कार्यों की तरफ उन्मुख किया तथा ब्राह्मणों की भांति भूमिहारों को भी पुरोहितों के लिए तैयार कराया और ब्राह्मणों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा "दान लेना एवं पुरोहिती करना ब्राह्मणों के लिए कोई जरूरी नहीं है। परन्तु यदि विरोधी लोग बार-बार कहते रहेंगे और पुरोहितों के अभाव में भूमिहारों को अब्राह्मण करने की कुचेष्टा से बाज नहीं आयेंगे तो हारकर भूमिहार ब्राह्मणों को भी सामूहिक रूप से पुरोहिती को अपनाना ही होगा।" बाद में स्वामी जी ने भूमिहारों को अपनी पुस्तिका 'ब्राह्मण समाज की स्थिति' में स्पष्ट कहा कि "आत्म सम्मान की पुकार है कि भूमिहार लोग पुरोहिती कर्म को अपनायें।[8] भूमिहारों ने धीरे-धीरे पुरोहिती को अपना लिया।

जातीय उत्थान की चर्चा स्वामीजी ने अपनी पुस्तक *"किसानों को फंसाने की तैयारियां"* में की है। इन्होंने जाति विशेष को हक की लड़ाई के लिए अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत एक जातीय सभा से संबंधित होकर की थी। इसी ने 1929 में मुंगेर में उस सभा को विध्वंस करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बाद के वर्षों में स्वामी जी का उद्देश्य जातीय उत्थान कार्यों से आगे ज्यादा उच्च उद्देश्य की तरफ मुखातिब हुआ, मगर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का जो दौर अभी भारत में चल रहा था उसका स्वरूप अभी भी व्यापक धार्मिक पुनरुत्थानवादी था और उसका विकास आन्दोलन की वैज्ञानिक अवधारणाओं से काफी दूर था जिससे स्वामी जी के चितंन की प्रक्रिया को वैज्ञानिक दिशा मिलने में विलम्ब हुआ।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीति और भारतीय परिवेश

स्वामी जी भारतीय मुक्ति-संग्राम में राष्ट्रीय आन्दोलन, जिसका स्वरूप बदलती आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रणनीति और कार्य-नीति निर्धारित करता आगे बढ़ा है, की ही उपज थे अतः उनका जीवन, उनकी कार्य-पद्धति, उनके द्वारा नेतृत्व किए गए आन्दोलनों का स्वरूप कार्य-नीति और रणनीति ठीक उसी तरह निर्धारित हुई, जिस तरह राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन का स्वरूप विशेष आर्थिक-सामाजिक संबंधों के बदलने पर वर्ग-शक्तियों का ध्रुवीकरण करता रहा। सर्व संबंधों का निर्धारण उत्पादन प्रक्रिया में व्यक्ति के स्थान से होता है उसे स्वामी जी स्वयं कबूल करते हैं।

"समाज का आर्थिक ढांचा ही असली नींव है, जिसके ऊपर राजनीति के महल खड़े किये जाते हैं और उसके अनुसार ही विचारों के निश्चित सामाजिक स्वरूप बनते हैं। संक्षेप, में उत्पादन-प्रणाली ही सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक जीवन के स्वरूपों को आमतौर से निर्धारित करती है।"[9]

वास्तव में 19 वीं सदी का उत्तरार्द्ध, खासकर इस्ट इंडिया कम्पनी, जो ब्रिटेन की व्यापारिक पूंजी के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती थी, के हाथ से भारत का शासन-तंत्र ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटेन की औद्योगिक पूंजी का प्रतिनिधित्व करता था, के हाथ में जाने के बाद भारत में तमाम बुनियादी संरचनाओं का नियमन इस तरह किया जा रहा था कि अर्थव्यवथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों को सम्पूर्णता में रक्षित कर सके। इसके लिए जरूरी था कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर भारत को ब्रिटिश औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जाय। इसी नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत की पौराणिक ग्रामीण-व्यवस्था को नष्ट किया, उसकी जगह पर औद्योगिक विकास को रोक रखा, जिससे बर्बाद कारीगरों को अन्य जीविकोपार्जन के साधनों के अभाव में लौट कर खेती पर जाना पड़ा जो पूर्व से ही आबादी के भार से दबा था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दूसरी तरफ ब्रिटिश पूंजीपतियों और भारतीय उद्योगों के बीच का अपना एक अलग अन्तर्विरोध था, जिसके तहत मैनचेस्टर और लंकाशायर के उद्योगपतियों ने भारत में श्रम-कानूनों को लागू करने की मांग कर रहे थे, ताकि भारत में सस्ते श्रम के द्वारा निर्मित मालों की प्रतिस्पर्द्धा में उन्हें अपना मुनाफा बरकरार रह सके।

भारत में श्रमिक वर्ग हालांकि संख्यात्मक दृष्टि से कम तथा सांगठनिक दृष्टि से असंगठित था, फिर भी 1882 और 1890 के 8 वर्षों में वह कई मुख्य श्रम-आन्दोलन कर चुका था।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण के एक वर्ष बाद 1886-87 में जेम्स जोन्स, बाम्बे के प्रथम स्थायी इन्सपेक्टर ने भारतीय मीलों के मजदूरों की दुर्दशा पर एक रपट सरकार को दी थी। 19वीं सदी के अन्तिम दशक में, जिसमें स्वामी जी का जन्म हुआ था (1889) में प्रथम श्रम संगठन बाम्बे मिल हैन्डस एसोसिएशन का निर्माण तथा प्रथम श्रम पत्रिका 'देशबन्धु' का प्रकाशन भी इसी दशक में शुरू हुआ था।[10] 1891 के फैक्ट्री एक्ट को लॉकल सरकार ने भारतीय पूंजी के ऊपर ब्रिटिश पूंजी की सार्वभौमिकता को 1875 और 1884 के फैक्ट्री कमीशन के सुझावों के मुताबिक, स्थापित कर दिया। 1882 में कांग्रेस की स्थापना के मात्र तीन साल पूर्व ब्रिटिश सरकार ने भारत से संबंधित एक बयान जारी किया जिसे वित्त मंत्री, एमेलिनवाटीन और डेविड बारबर ने तैयार किया था, जिसमें कहा गया कि संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय आय 5.25 मिलियन रुपया और प्रति व्यक्ति आय 27 रुपया था। 1901 में जिस बयान को लार्ड कर्जन ने दिया उसमें 1897-98 के वर्ष में भारत में प्रति व्यक्ति आय 30 रुपया आंका गया।[11]

ब्रिटिश शासन काल की 19वीं सदी का अन्त प्रायः ऐसी ही आर्थिक-सामाजिक संरचना को जन्म दे रहा था, जिसमें धन्यधान्य से परिपूर्ण भारत ब्रिटिश वित्तीय पूंजी का दास बन रहा था, मजदूर छिट-पुट आन्दोलन करते थे जबकि किसानों की विशाल आबादी मूक थी, कृषि पर आबादी का भार बढ़ता जा रहा था और आद्योगीकरण का स्थिर अवस्था में पड़ा रहना तथा कृषि का अवरुद्ध विकास ग्रामीण और शहरों दोनों सर्वहाराओं को बड़ी ही धीमी गति से पैदा कर रहा था। 1885 में कांग्रेस का निर्माण स्वामी जी के जन्म के करीब तीन चार साल पूर्व हुआ था और उसका धोषित लक्ष्य रखा गया था (क) जो लोग राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ख्याल रखते हैं उनकी आपस में भेंट मुलाकात और बातचीत को सुनिश्चित करना तथा (ख) और आगे के राजनीतिक मसलों पर एक समझदारी बनाकर उसके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना।[12]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वास्तव में अपने शुरु के दिनों में कांग्रेस ने उच्च मध्यम वर्ग तथा राष्ट्रीय पूंजीगत वर्ग की एक संस्था का स्वरूप ग्रहण किया। 1886 के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरौजी ने की जो एक राष्ट्रीय पूंजीपति थे तथा इसके संपूर्ण प्रतिनिधि मंडल की बनावट थी कि 130 प्रतिनिधि उच्च भूपति के तबके से आए थे तथा जमीन से संबंधित निहित स्वार्थ का प्रतिनिधित्व करते थे, 40 बड़े समाचार पत्रों के सम्पादक थे या मालिक थे, मात्र 5 रैयत थे तथा 4 अन्य ऐसे थे जो रैयत एसोशियेसन से निर्वाचित होकर आए थे।[13] अधिवेशन का क्रिया कलाप कैसा था? जो मजदूर और बरबाद कारीगर, किसान आदि ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा राष्ट्रीय पूंजीपतियों के दमन का प्रतिरोध कर रहे थे, उनके प्रश्नों को कांग्रेस ने तो छुआ ही नहीं, बल्कि साम्राज्शाही द्वारा उनके दमन को सराहा–क्योंकि कांग्रेस प्रतिनिधियों की नजर में सरकार विधि-व्यवस्था कायम कर रही थी।[14]

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ कांग्रेस की एक सहमेलपूर्ण रवैया को प्रमुख अंग्रेजी अखबारों ने *'मद्रास मेल'*, *'बाम्बे गजट'*, *'डेली न्यूज आफ कलकत्ता'* तथा *'स्टेट्स मैन'* ने काफी उछाला।[15] लेकिन अपनी स्थापना के तीन वर्ष के बाद ही कांग्रेस का साम्राज्यवाद विरोधी चरित्र उजागर होने लगा। रानाडे ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही की नीतियों तले भारत, जो एक उद्योग प्रधान देश था, हस्तशिल्प की बर्बादी के कारण पूर्णतः कृषि आधारित मुल्क बन गया है।[16] खुद ह्यूम ने कहा कि बिना भारतीयों के प्रतिनिधि सरकार के भारतीयों की स्थिति में सुधार असंभव है।[17] इस तरह के बयानों के पीछे भारतीय श्रमिक वर्ग की धीरे-धीरे बढ़ती संख्या तथा उसके परिणामस्वरूप उनके बीच ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष का उभरता संकेत था।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अपनी आर्थिक नीति थी जिसके तहत वह काम कर रहा था तथा उद्योगों में पूंजी लगाई जा रही थी। भारतीय उद्योग उनकी नीति के शिकार हुए थे तथा उनका पतन उनकी नीति का परिणाम था। फिर भी उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिक की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही थी। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार के लिए पलायन कर रहे थे। उनकी विकास नीति का फल था कि भारी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह, शिक्षा, रोजगार, व्यापार आदि के लिए जाने लगे थे। इस प्रकार एक विस्तृत श्रम बाजार का निर्माण हो रहा था। 1911 और 1921 की अवधि में इस प्रकार मानव क्रम का पलायन हो रहा था। यह स्पष्ट दिखाता है कि खेती पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया था कि सबों को रोजगार पाना कठिन हो रहा था और लोग दूसरी जगहों में पलायन कर रहे थे।[18]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बंगाल के उद्योगों और चाय बागानों का पलायन करने वाला मुख्य क्षेत्र इस अवधि में था बिहार तथा युक्त प्रांत। 1911 से 1921 तक इन दो प्रांतों से बंगाल की तरफ श्रम-पलायन का आंकड़ा लाखों को पार कर रहा था।[19]

ऊपर वर्णित तथ्य एवं प्रवृतियां 1885 के बाद से 1921 तक की ब्रिटिश साम्राज्वाद की आर्थिक नीतियों का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि किस तरह भारतीय स्वावलम्बी आर्थिक प्रणाली को समाप्त कर एक ऐसी औद्योगिक नीति का सृजन किया गया जो भारतीय हित के विरुद्ध ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करता था। इस नीति के तहत बिहार की खनिज सम्पदा का बेतहर शोषण किया गया।

कृषि की स्थितिः कृषि के क्षेत्र में यह नीति व्यापक परिवर्तन लाई। हस्तशिल्पों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के बाद उनकी जगह पर यूरोपीय ढंग का औद्योगिक विकास रोक रखा गया जिसे बर्बाद कारीगरों का बड़ा हिस्सा पुनः लौट कर अपनी जीविका के लिए कृषि की तरफ ही जाने को मजबूर कर दिया गया ऐसी कृषि जिस पर पहले से ही आबादी का दबाव काफी ज्यादा था। परिणाम हुआ किसानों की आम तबाही।

1873 में लार्ड कार्नवालिस ने जिस भू-व्यवस्था को लागू किया था उसके अन्दर मात्र 46,000 लोगों को ही बिहार और बंगाल में जमींदारियां दी गई थीं, मगर 1940 में इन जमींदारों की संख्या 80,00,000[20] हो गई थी। भारत के चिर स्थायी प्रबन्ध वाले तमाम इलाकों में, जिसमें बिहार भी था, आम तौर पर यही दशा थी। राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि समूचे देश में 1901 और 1921 के बीस वर्षों में लगान वसूलने वालों की तायदाद में 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और निसंदेह बिहार की दशा सबसे बुरी थी।[21] अपने विलासितापूर्ण खर्चों के लिए जमींदार बड़े पैमाने पर नाजायज वसूलियां करते थे और इसके बाद भी वे अपनी जमींदारियों के एक हिस्से को बेच भी दिया करते थे जिससे तथाकथित जमींदारों की एक फौज सी खड़ी हो गई। इस तरह बिहार में जमींदारों, अनुपस्थित जमींदारों उनके अन्य मध्यवर्तियों, कारिन्दों, जो नाममात्र के वेतन पर जमींदारों के पदाधिकारियों के रूप में बहाल किए गए थे और उनका तमाम खर्च किसानों से गैर कानूनी वसूलियों से ही चलता था, कि एक लम्बी सीढ़ी बन गई थी। कहीं-कहीं तो यह बीस स्तरों वाली व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लिया था। हालांकि ये यूरोपीय शैली के मध्यवर्ती नहीं थे। जिस समय स्वामी जी का उदय हुआ था, उस समय देश में सामंती लोगों का काफी बोलबाला था, ये सामंती जमींदारों ने जुल्म की सीमा पार कर ली थी। यहां अलग-अलग क्षेत्रों में सामंती संबंधों के रूप अलग-अलग

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

थे। छोटे-छोटे सामन्ती ठाकुरों तथा स्थानीय जागीरदारों के द्वारा किसान शोषित हो रहे थे। ये छोटे-छोटे ठाकुर तथा जागीरदार स्थानीय राजाओं के समान थे। वे अपने-अपने क्षेत्रों में मनमाने अधिकारों को लागू करते थे। कुछ सामंती भू-स्वामी और ग्रामीण जमींदार जो समान स्वामित्ववाली जमीनों को अपने कब्जे में लेते थे। वे अपने-अपने क्षेत्रों में मनमाने अधिकारों को लागू करते थे। कुछ सामंती भू-स्वामी और ग्रामीण जमींदार जो समान स्वामित्ववाली जमीनों को अपने कब्जे में ले लेते थे। जमीन के एक हिस्से को पट्टे पर उठा देते थे। उसकी उपज का एक हिस्सा वे खुद लेते थे और एक हिस्सा ऊपर के मालिकों को दे दते थे। राजाओं को कर आमतौर से बड़े-बड़े जागीरदार और भूपति दे देते थे। वे भूपति और बड़े जमींदारों जो अपनी सेनाओं द्वारा तथा अन्य प्रकार से राजा की सहायता करते थे, उन्हें कर से प्रायः मुक्त कर दिया जाता था।

उस समय सामंतवादी और सामूहिक भू-स्वामित्व के अलावा स्वयं राज्य भी अपने पूर्ण अधिकारों सहित भू-स्वामी के रूप में मौजूद था। उस समय राजा लोग सबसे बड़े भू-स्वामी थे। उस समय भारतीय सामंतवाद का ढांचा अत्यंत ही जटिल था, जिसमें कितनी ही प्रकार की संबंध व्यवस्थाएं शामिल थीं। सबसे ऊपर राजा था, उसके बाद इसके दरबारी और सामंती जागीरदार और इसके बाद थे जमींदार। सबसे निम्नस्तर के थे बेचारे जमीन जोतने वाले किसान। सामंती जागीरदारों और जमीन को जोतने बोने वाले किसानों के बीच का संबंध प्रायः छत्तीस (36) का सा रहता था। कुछ अन्य समुदायों में मध्यवर्ती सामंती जागीरदार ही लगान वसूल करता था। कुछ स्थानों पर किसान एक निश्चित अवधि के लिए सामंती जागीरदार से पट्टे पर जमीन ले लेते थे। उस समय कुछ ऐसे भी किसान थे, जो स्वयं निजी सम्पति के मालिक थे। किन्तु यहां ध्यान देना है कि आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सामंती आधिपत्य के दौरान भारत में हो रहे इन परिवर्तनों के बावजूद सामंती जागीरदारों और जमींदारों को कर वसूल करने के अलावा, जमीन पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। सामंती काल में ग्रामीण विकास का कार्य ग्राम पंचायत के मुखिया तथा उसकी निगरानी समिति द्वारा चलाया जाता था। सरपंच का यह कर्तव्य होता था कि वह आम समुदाय की आम सभा के निर्णयों को कार्यान्वित करें। स्वामी जी के समय में सामंती ग्राम समुदाय में मुख्यतः चार सामाजिक समूह थे।[22] पहला था शोषण करने वाले उच्च वर्गों का, जिसमें सरकारी अधिकारी, पुरोहित और आम शासक शामिल थे। इनके पास सबसे अच्छी जमीन होती थी। दूसरा समूह, स्वतंत्र किसान समुदायों तथा संयुक्त परिवारों का था। इसके नीचे, जमीन के असली जोतने वाले बोनेवालों का समूह था। सबसे नीचे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बढ़इयों, लुहारों और श्रमिकों का समूह था। अंतिम दो सामाजिक समूह सबसे अधिक शोषित थे। सामंती जागीरदारों के साथ मिलकर उच्च वर्ग के लोग अपनी सामाजिक स्थिति और प्रभाव को, परम्परागत व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस्तेमाल करते थे।

अंग्रेजों के प्रति स्वामी जी की धारणा बिल्कुल पक्की थी कि वे दैत्य होते हैं और खून पीकर ही जिन्दा रहते हैं तथा जमींदार भी वैसे ही घृणात्मक हैं।[23]

जमींदारी के विषय में स्वामी जी स्पष्ट राय रखते थे, उसकी बुराइयों को कितनी गहराई तक देखते हैं। अगर इनकी दृष्टि गहराई तक नहीं पहुंचती तो शायद जमींदारों के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई ठानकर जीतें हासिल नहीं कर पाए होते। स्वामी जी कहते हैं-

"जमींदार की जड़ ही बेईमानी और मुल्क के साथ गद्दारी है। वह कायम ही हुई इसी तरह .... इसलिए किसानों को इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।"

जमींदारों की जाति और धर्म के बारे में स्वामी जी कहते हैं- "जमींदारों की जाति और जुल्म रुपया-पैसा है और यही उनका धर्म है। अर्थात् शोषक वर्ग के आधार पर विभाजित नहीं हो सकते, उनका विभाजन वर्ग चरित्र के आधार पर ही होना चाहिए। शोषकों की जाति और उनका धर्म एक होता है।[24] सामंतवादी जमींदारी कितनी भयानक होती है, स्वामी जी के विचार में स्पष्ट है–

जमींदारी ऐसी जोंक और ऐसी पिशाची है कि किसानों का रक्त बूंद-बूंद करके चूस लेती है, और उसे मरणासन्न छोड़ देती है। जमींदारों के अमले प्लेग के कीटाणुओं की तरह जहां पहुंचे कि इसे उजाड़ छोड़ा। उनके नाम पर किसानों का कलेजा कांपता है।[25]

शोषित किसान सामंती जमींदारों के जुल्म से इतना आतंकित थे कि कोई भला किसान पटने के कुछ खास परगनों में अपनी लड़की ब्याहता तक नहीं था, कि जानबूझ कर अपनी लड़की की इज्जत खतरे में कौन डाले। सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध सफल विश्व व्यापी संघर्ष एवं भारत मे इसके दकियानूसी एवं प्रतिगामी चरित्र ने ही स्वामी जी के अंदर यह विचार पैदा कर दिया कि इस जमींदारी प्रथा का भारत में अन्त सबसे बाद में इसलिए होगा, क्योंकि इसका यहां पर आगमन ही सबसे बाद में हुआ है। इस प्रथा कि अवश्यम्भावी विनाश की प्रक्रिया के असली चरित्र का वर्णन करते हुए स्वामी जी ने लिखा था। "भारत की जमींदारी" यह बड़ी ही दकियानूसी चीज है। अतः यह अपनी हस्ती बनाए रखने के लिए वह जो न करें, थोड़ा है, रोक रखने की नीति मात्र है, इस तरह वे चाहते हैं कि जमींदारी के बदले उन्हें अधिक पैसे मिल जाएं।[26]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जमींदारों द्वारा किसानों के हो रहे विभिन्न प्रकार के शोषणों ने स्वामी जी को किसान आंदोलन की ओर प्रेरित किया। स्वामी जी ने जातीयता की मानसिकता से ऊपर उठकर अपने ही जाति के टिकारी, बेतिया, अमावा, हथुआ, आदि के बड़े-बड़े सामंतों को धराशायी कर दिया।

निश्चित रूप से स्वामी जी के उदय के समय किसानों के हो रहे विभिन्न प्रकार के शोषणों ने उन्हें किसान आंदोलन की ओर प्रेरित किया और जमींदारी प्रथा के तहत भूमि पर स्वामित्व से वंचित किसानों को इनका हक दिलाने तक ही स्वामी जी का आंदोलन सीमित नहीं था, बल्कि जमींदारी प्रथा का समूल नाश करने के बाद किसानों के सर्वागीण विकास-हेतु एक व्या!पक मार्ग प्रस्तुत करना उनका लक्ष्य था।

जब स्वामी जी का जन्म हुआ था उस समय साम्राज्यवादी शोषकों का शोषण चक्र तेजी पर था। जमींदार और साम्राज्यवादियों ने संयुक्त रूप से इस देश के किसानों को शोषण चक्र में फंसाया। परिणामस्वरूप किसानों की स्थिति दयनीय थी। इसका प्रमाण उन्होंने स्पष्ट रूप से दिया है।[27]

बड़े-बड़े विद्वानों ने हमारे शास्त्रों को खोज ढूंढकर यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे देश में पुराने जमाने में, जमींदारों जैसी कोई चीज नहीं थी। मुसलमानों के जमाने में भी आज की तरह जमींदारी का नाम निशान नहीं था। यह तो अंग्रेजी राज्य द्वारा हमारे देश को मिला एक अजीबोगरीब तोहफा है। साम्राज्यवादियों के बारे में स्वामी जी ने कहा है कि-"साम्राज्यवाद तो भले-बुरे कानूनों के बल पर टिका है।"[28] लेकिन जमींदार लोग केवल जोर-जुल्म के सहारे टिके है। कानूनों का गला घोंटकर वे लोग जुल्म करते हैं, किसानों को कष्ट देते हैं। जमींदार और उनके अमले किसानों के छाती पर बचपन से लेकर मरने तक किस प्रकार सवार रहते और रह-रह के कोदों दरते रहते थे।

साम्राज्वादी शोषकों के जुल्म से मुक्ति पाने के लिए 1939 के अक्टूबर महीनों में "साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन" होना तय हुआ। साम्राज्यवादी लोग इस द्वितीय विश्व युद्ध को भारत मुक्त युद्ध में बदल देना चाहते थे।

अगर इतिहास का अध्ययन कोई दिशा दे सकता है तो यह स्पष्ट है कि कृषि पूंजीवाद के विकास की प्रक्रिया शायद ही कभी सीमित अर्थों में कृषि-क्षेत्र के अंदरूनी घटना विकास-क्रम से शुरू होती है। ऐसा लगता है कि इसके लिए किसी बाहरी उत्प्रेरक की जरुरत होती है, जिसमें बाजार का बढ़ना एक महत्वपूर्ण कारण है। ब्रिटेन में 16वीं सदी के ट्यूडट राजाओं के दौर के कृषि बाड़े और फिर 18वीं सदी के और व्यापक बाड़े क्रमशः उनकी बढ़ती निर्यात मांग और खाद्यानों की

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बढ़ती घरेलू मांगों से प्रेरित थे।[29] भारत में आजादी से पूर्व के सात दशकों के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनकी एक गौर तलब बात यह है कि इन दशकों में खाद्यान्नों के घरेलू बाजार में उल्लेखनीय गतिरोध बना रहा था जबकि कृषि उत्पादन में 80 फीसदी इन्हीं खाद्यान्नों का था। प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों के उपभोग में कमी आई थी।[30] कर राजस्व का एक हिस्सा विदेश भेजा जा रहा था और यह तबादला इसके बराबर के मूल्य के मालों के निर्यात से होता था। लिहाजा इसके लिए निर्यातों को बढ़ावा देने की औपनिवेशिक नीतियों के अंतर्गत, सिर्फ निर्यात योग्य प्राथमिक मालों में ठीक-ठाक बढ़ोत्तरी हुई थी और इन मालों में गेंहू भी शामिल था। ओपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत के हितों को ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के अनुकूल बनाने के लिए एक खास ढंग की घरेलू वित्त मुद्रा तथा व्यापार नीतियों का अनुसरण किया जा रहा था। चूंकि हर साल राजस्व का एक हिस्सा विदेश भेज दिया जाता था, सरकार वास्तव में फायदे का बजट चला रही थी, तथा इसका घरेलू-अर्थव्यवस्था पर मंदी का असर पड़ रहा था। खुल्लम खुला औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में आधुनिक उद्योग का विकास धीमी गति से चल रहा था, जिसके चलते श्रम शक्ति का पेशागत वितरण अधिक से अधिक ज्यों का त्यों बना हुआ था या प्राथमिक क्षेत्र पर उसके दबाव में थोड़ी वृद्धि ही हुई थी। जमीन पर अपनी रोजी कमानेवाली जनसंख्या तेजी से बढ़ी थी और भूमि तथा उस पर निर्भर आबादी के अनुपात में गिरावट आई थी। इसके परिणामस्वरूप एक बहुत की कम रोजगार पर निर्भर फालतू आबादी पैदा हो गई जिसने असामियों के रूप में भूमि के लगानों को भुखमरी के लगानों की ऊंचाई तक पहुंचा दिया और मजदूरों के रूप में जैसे-तैसे करके पेट भरने तक सीमित मजदूरी और कर्ज गुलामी को स्वीकार किया। इस प्रकार जमींदार महाजन व्यापारी, त्रिमूर्ति ने किसानों पर अपना शिकंजा कस लिया। इस प्रकार पूंजीवादी राह पर उत्पादक निवेश के लिए एक जबरदस्त अवरोध खड़ा हुआ। पूर्व पंजीवादी भू-लगान यहां पूंजीवादी कृषि की राह रोक रही थी।

थार्नर ने अंतर्निहित अवरोध के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है वह उस स्थिति में इस प्रकार काम करता है। उनके बताए मालिकों या गैर काश्तकार भूस्वामियों के हाथों में मिल्कियत वाली जमीनों का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा आ गया जबकि वे कुल मिलाकर दस-पन्द्रह परिवार नहीं थे। इन जमींदारों को भूमि के भूखे किसानों को जमीनें लगान पर उठाकर सारे पैदावार का औसतन आधा मिल जाता था, जबकि पैदावार की सारी लागत आसामी की होती थी। लगान की यह आय, भूमि की इजारेदारी मात्र की आय थी और उसका न तो उत्पादन की

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रक्रिया में पूंजी लगाने से कुछ लेना-देना था और न श्रम में हिस्सेदारी से। इसके साथ ही ये जमींदार करीब ऐसे अकेले लोग थे जो भूमि से कमा रहे थे, जिनके पास निवेश के लिए नकद पैसा था, जिसे अकसर व्यापार तथा सूदखोरी में और दुर्लभ मिसालों में कृषि–आधारित उद्योगों में लगाया जाता था। इस स्थिति में, अगर इस तरह का जमींदार जमीन को लगान पर उठाने और लगान वसूलने का रास्ता अपनाने के बजाए प्रत्यक्ष पूंजीवादी खेती का रास्ता अपनाए तो उसे खेती के पैदावार में पैसा लगाना पड़ेगा, वहीं पैसा दूसरी जगह से लाभ दे रहा था। इसके अलावा उसे अपने असामियों से जमीनें वापस लेनी पडेंगी।

सही जमीन जो बिना किसी खर्च के ही शुद्ध भूमि लगान के रूप में लाभ दे रही थी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने, अभी पिछले ही दिनों हमें "ज्ञानदान" किया है कि 1891 तक "इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि भारत में आय वितरण में पहले से बिगाड़ आया है, जो साक्ष्य है भी वे कोई बदलाव नहीं दिखाते हैं न तो बेहतरी की दिशा में और न बिगाड़ की ही दिशा में, और अगर ऐसे साक्ष्य हों भी, तब भी इसके तर्कसंगत ढंग से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आय-वितरण में गिरावट आने से औद्योगिक मालों की मांग घटती है। वास्तव में, इससे उल्टी बात भी सही हो सकती है, वास्तव में यह मान्यता कि आय वितरण की स्थिति में पहले से गिरावट नहीं आई है, एक दोषपूर्ण आर्थिक सिद्धांत और उपभोग के व्यावहारवादी आंकड़ों से, जो आजकल गरीबी संबंधी आकलनों का मुख्य आधार बने हुए हैं; आय के बारे में निकाले गए गलत-सलत निष्कर्षों के योग का ही परिणाम। स्थूल अर्थ व्यवस्था में जहां जनसंख्या का छोटा सा हिस्सा भाड़े के श्रम से उत्पादित वस्तुओं का विक्रेता हो और आबादी में विशाल बहुमत असंगठित श्रम शक्ति बेचनेवालों का हो, मालों की कीमतों में होने वाली कोई भी बढ़ोतरी मुनाफा स्फीति के जरिए, विशाल बहुमत के हाथ से आय को निकाल कर आबादी के इस छोटे हिस्से के हाथों में पहुंचाने का ही काम करती है। यूरोप में 16वीं शताब्दी में हुई मूल्य वृद्धि ऐसी मूल्य वृद्धि का पहला उदाहरण है, जिसका काफी हद तक विश्लेषण हुआ है। इस उदाहरण का कीन्स ने अपने "*मुद्रा पर प्रबंध*" में विस्तार से जिक्र किया है और मार्क्स ने "पूंजी" में आदिम संचय के संदर्भ में इसकी चर्चा की है। कीन्स ने, मुनाफा स्फीति के जिस अपेक्षाकृत वाद के उदाहरण का जिक्र किया है, उसका संबंध पहले विश्व-युद्ध से है। यह वह जमाना था जब ब्रिटिश सरकार के लिए यह जरुरी हो गया था कि घरेलू निवेश दर को किसी प्रकार बढ़ाया जाए। विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो यह करीब उसी तरह की समस्या है जैसे समस्या नियोजित विकास की प्रक्रिया में निवेश की दर बढ़ाने की होती है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वास्तव में औपनिवेशिक शासन-काल में भू-प्रबंध की जो व्यवस्था की गई थी उसका निहितार्थ तीन परस्पर सम्बद्ध प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता था। अन्य चीजों के अलावा जाति पर आधारित प्रभुत्व तथा गुलामी के रिश्तों का इस्तेमाल करके अतिरिक्त मूल्य को निचोड़ने का रुझान, जन उपयोग के औद्योगिक मालों के ग्रामीण बाजार के संकुचित होने का रुझान, तथा कृषि की सम्भव तथा वास्तविक उत्पादकता के बीच दूरी बढ़ते जाने का रुझान।

औपनिवेशिक काल में भारत में कृषि संक्रमण के जिस दौर से गुजर रही थी उस पर मार्क्सवादी साहित्य ने जो विचार किया है उसके सार रूप में दो बातें हैं और दोनों भारत के संदर्भ में लागू थीं। इसमें पहली बात यह है कि संक्रमण का यह रास्ता ज्यादा तकलीफदेह है, क्योंकि यह मालिक मजदूर के पूर्व पूंजीवादी संबंधों के दासता के चरित्र को बनाए रखता है या यों कहें कि सामंतवादी उत्पादन की प्रक्रिया को कमोवेश कृषि के उत्पादन संबंधों में बनाए रखता है। दूसरा अपने संकीर्ण सामाजिक आधार के चलते यह संक्रमण कहीं ज्यादा धीमा और लम्बा खिंचनेवाला होता है। यह दोनों ही प्रक्रियायें भारतीय कृषि में और खास कर बिहार के भू-उत्पादन संबंधों में वर्तमान थीं। भू-स्वामी प्रभुत्व तथा गुलामी की जाति पर आधारित परम्परागत रिश्तों को बनाए ही नहीं रखे थे, बल्कि वास्तव में उनका जानबूझकर इस्तेमाल करते थे ताकि श्रम-शक्ति का फालतू रखना निश्चित कर सके और निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के तरीकों से अतिरिक्त मूल्य निचोड़ने की दर बढ़ा सके।

इतिहास में हमें कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि परम्परागत शोषणकारी सामाजिक संबंधों के ऊपर से व्यापारीकरण का बाजार के लिए उत्पादक का थोपा जाना, गुलामी के आधार पर इन संबंधों को मजबूत करने की ओर ही ले गया न कि मजदूर के लिए ज्यादा स्वतंत्रता की दिशा में संक्रमण का द्वार खोला।[31]

पूर्वी यूरोप के संदर्भ में, जहां भूतपूर्व भू-दास के श्रम का उपयोग करके सामंती जमींदारी पूंजीवादी खेती की ओर संक्रमण कर रहे थे, लेकिन वे जब अर्द्ध-सामंती पूंजीवाद की बात कहती थी तो उसका सार सम्भवतः यही था।[32]

सामंतवादी पूंजीवाद के ऐसे ही धारा-तत्व भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में प्रकट हुए, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। अपने दूसरों पहलुओं के अलावा जाति प्रथा परम्परागत रूप से उत्पादन-प्रक्रिया में लगे लोगों को अधिकारों या कर्तव्यों के बारीक श्रेणी क्रम में बांटे गए जो अलग-अलग ग्रूपों में तोड़ने की प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती आई है। इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि ब्रिटिश कालीन भू-स्वामी पूंजीपति दरिद्रीकृत किसानों के मुकाबले में हरिजन मजदूरों के साथ

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कहीं ज्यादा बुरा बर्ताव करता था, जो आज भी देखने को मिलता है। क्योंकि उसका हरिजन होना ही उस पर परम्परागत प्रतिकूलतायें लाद देता है।

स्वामी जी के काल में उद्योग तथा कृषि उत्पादन के इन दोनों स्रोतों को उपनिवेशवादी ढंग से संगठित किया गया था और सम्पूर्ण कृषि पर उसके जमींदार-रैयत संबंधों के ऊपर से व्यापारीकरण की एक ऐसी संरचना को खड़ा किया गया था जो कृषि-योग्य भूमि पर व्यापारिक फसलों को उत्पादित इसलिए करता था कि ब्रिटेन को जरूरत थी। इसका सबसे कडुवा अनुभव बिहार में नील उत्पादन में देखा जा सकता था।

सम्पूर्ण बिहार चिर स्थायी प्रबंध के अधीन था, किसानों से हर प्रकार के उनके परम्परागत अधिकार छीन लिए गए थे। चारागाह तथा जंगल की जमीन, सिंचाई की नहरों, मछली-पालन और बासगीत जमीन के इस्तेमाल का अधिकार एवं विवेकहीन लगान से सुरक्षा का अधिकार–सबों से उन्हें वंचित कर दिया गया था। भू-राजस्व की प्रणाली इतनी दोषमुक्त बनी थी कि जमींदारों को लगान से सुरक्षा का अधिकार सबों से उन्हें वंचित कर दिया गया था। भू-राजस्व की प्रणाली इतनी दोषमुक्त बनी थी कि जमींदारों को लगान का एक निश्चित हिस्सा ही सरकार को देना पड़ता था- मगर किसानों से बेगार लेने, मनमाना गैर कानून वसूली करने, जिसमें से उन्हें सरकार को कुछ नहीं देना पड़ता था–के असीम अधिकार ने जमीन के लगान को कृषि उत्पादकता बढ़ाने में एक अवरोधक बन कर खड़ा हो गया था, क्योंकि भू-स्वामी बिना कुछ खर्च किए या कृषि पर अपने अतिरिक्त धन का व्यय किए, जितना चाहता था उतना दरिद्र किसानों से निचोड़ लेता था।

गैर कानूनी वसूलियों के लिए तथा अनुपस्थित जमींदारों की वसूलियों के लिए ज्यादा से ज्यादा ताकतवर लोगों की जरुरत पड़ने पर ठेके पर लगान वसूलने तथा अन्य इसी तरह के प्रबंधों ने संस्थागत रूप ग्रहण किया। जमींदारियों की बिक्री या उन्हें गिरवी रखने के कारण मध्यवर्ती जमींदारों की एक शृंखला खड़ी हो गई थी। वास्तव में सामाजिक संरचना के अनुकूल दो ही कारक सामाजिक प्रतिष्ठा के मानदण्ड थे-- सरकारी नौकरियां और जमींदारियां। इस कारण शहरी धनी तबका, सम्पन्न व्यापारी, धनी किसानों एवं महाजनी पूंजी स्वेच्छा से जमींदार बन गई थी।

गया जिले में एक सर्वे के आधार पर स्वामी जी ने 45 तरह की गैर कानूनी वसूलियों का पता लगाया था। औपनिवेशिक दासता के काल में जमींदार ही सर्वोच्य वर्ग और औपनिवेशिक शासन के वर्गाधार थे। अतः साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में साम्राज्यवाद के इस आर्थिक आधार पर चोट करना जरुरी था। प्रायः बिहार के समस्त शहर चंद अपवादों को छोड़कर, प्रायः सामंती शहर थे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बिहार में पूंजीवादी संस्कृति का जो असर हुआ उसमें भावली लगान का नगदी में रूपान्तरण हो जाने से परिस्थितियां और भी किसानों के खिलाफ चली गईं। गया जिले के 16 ग्रामों का मुआयना करके स्वामी जी ने बताया कि भावली का नगदी में रूपान्तरण लगान को लगभग डयोढ़ा कर दिया, क्योंकि एक साल लगान के बराबर नजराना भी वसूला जाने लगा, जिसने किसानों को भारी कर्ज गुलामी में धकेल दिया। इस कुप्रबंध का नतीजा मात्र एक उदाहरण ने स्पष्ट हो जाएगा कि कुर्था के मझियावां ग्राम की पहले ही वर्ष लगान और नजराने ने 30,000 रुपए देने पड़े और मात्र चार वर्षों बाद उन पर सरकार और महाजनी कर्जों का बोझ 1,30,000 रुपया हो गया था।[33] 60 वर्ष पूर्व इस गांव का लगान महज 900 रुपया था।

हालांकि किसान नगदी के ही पक्ष में थे मगर कृषि उत्पादकता बढ़ोतरी की एक अनिवार्य शर्त कृषि उत्पादित समानों का घरेलू बाजार में विस्तार न होने से संबद्ध थी लेकिन ऐसा न होने का कारण कृषि सामानों की गिरती कीमतों ने नगदी को एक अभिशाप बना दिया।

बटाई बिहार की एक प्रमुख समस्या थी। फालतू आबादी, जिसका सैद्धान्तिक निरूपण ऊपर किया गया है, ने जमीन के लगान को भुखमरी के लगान तक पहुंचा दिया था लगान न देने पर जमींदार जमीन छीन लेते थे। सरकारी कानून में बटाईदार को बेदखल करने का मात्र रास्ता था कि मालिक स्वयं उसपर खेती करे, मगर या तो कानून का उल्लंघन कर या स्वयं फर्जी खेतिहर बनकर बटाईदारों को बेदखल किया जाता था। 1901 में और 1921 के दौरान बिहार में बटाईदारी में 2800 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस तरह की बेदखली बिहार की प्रमुख समस्या थी।

उत्तर बिहार में प्रायः नकदी लगान प्रचलन में था, करीब 95 प्रतिशत जमीन पर, मगर मध्य बिहार में यह मात्र दश प्रतिशत ही नगदी में वसूला जाता था। इसलिए उत्तर बिहार में लगान का उतना ज्यादा बोझ किसानों पर नहीं पड़ता जितना दक्षिण और मध्य बिहार में पड़ा था। छोटानागपुर कमिश्नरी अपने जंगलों एवं प्राकृतिक साधनों का क्षेत्र था। उत्तर बिहार की उर्वरा भूमि बिना पटवन के भी उत्पादन दे सकती थी और जूट, तम्बाकू, ईख आदि नगदी फसलों की खेती करता था। बिहार की कुल 31 चीनी मिलों में से 28 उत्तर बिहार में ही थी। मगर मध्य बिहार मात्र खाद्य उत्पादन का क्षेत्र था, नकदी फसलों का नहीं, अतः इसी क्षेत्र की समस्या काफी गम्भीर थी।

विश्वव्यापी मंदी ने किसानों को और ज्यादा संकट में डाला। अन्न की कीमतों में भारी गिरावट से किसान तबाह थे। कांग्रेस का जो वर्गाधार था और जिन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

साम्राज्यवाद या ब्रिटिश पक्षी भावना को लेकर 19वीं सदी के अन्तिम दशकों में कांग्रेस चल रही थी उसका परिणाम था कि कांग्रेस के द्वितीय महाधिवेशन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए भारत के एक सबल वक्ता दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटेन भारत को अपने पक्ष में करने की बजाय अपना दुश्मन न बनाए[34] तथा 1890 में ही फिरोजशाह मेहता ने इसी सन्दर्भ में कहा था, उन्हें विश्वास है कि "ब्रिटेन के नेता समय की पुकार को समझेंगे।"[35] तथा कांग्रेस के उस समय के सबल प्रखर नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के उद्देश्यों का प्रतिपादन ही अंग्रेजों को सबल बनाना बताया था।[36] मगर चन्द वर्षों में ही इस अंग्रेज पक्षी की भावना का मोह भंग क्रमशः होने लगा था। इसका आभास तो तभी हो गया जब नरमपंथियों के नेता गोखले ने कहा था "नौकरशाही साफ तौर पर बड़ी तेजी से स्वार्थी होती जा रही है। पहले यह ऐसी नहीं थी।[37]

19वीं सदी का यह वह अन्तिम दशक था जब भारतीय पूंजीपति वर्ग यह समझने लगा था कि वह अंग्रेजों का सबल विरोध नहीं कर सकता। मजदूर वर्ग असंगठित तथा संख्यात्मक दृष्टि से कम था और किसान थे तो करोड़ों में, मगर चुप थे। यह वही काल था जब स्वामी सहजानन्द का बचपन एक सामंती सामाजिक परिवेश तथा अंग्रेज.पक्षी एवं उनके विरोधी खेमों में कांग्रेस दो गुटों में बंटने की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसी स्थिति में एक नई विचार धारा का कांग्रेस में जन्म स्वाभाविक था, जो ऐसे महारथियों की आलोचना करें जों अंग्रेजों से सहयोग पर आन्दोलन करने तथा ब्रिटिश साम्राज्वाद से हर तरह का संबंध विच्छेद करने की मांगों को उठाया।

साम्प्रदायिकता

ब्रिटिश साम्राज्यशाही से एक समझौताविहीन लड़ाई की मांग करने वाले नेतागण प्रगतिशील आचरण के प्रतीक जरूर थे, मगर उनका सम्पर्क ऐसे प्रगतिशील आंदोलनों से न जुटा था और वे स्वयं ऐसे आंदालनों को गठित कर सके थे जो निर्णायक लड़ाई दे सके। नई विचारधारा का राजनीतिक या सामाजिक स्तर पर किसी वैज्ञानिक विचार धारा से कटे रहने के कारण उन्होंने समझा कि पुरानी पीढ़ी के नेताओं में राष्ट्रवादिता का अभाव तथा पाश्चात्य प्रवृत्तियों के प्रति झुकाव था। इसलिए नई विचारधारा वाले नेताओं ने पुरानी पीढ़ी के नेताओं की सैद्धान्तिक या कार्य-पद्धति को उस समय आलोचना का निशाना उन प्रवृत्तियों को बनाया, जिसके प्रसंग में पुराने नेतागण सचमुच प्रगतिशील दृष्टिकोण रखते थे। किसी वैज्ञानिक सामाजिक सिद्धान्त के कटे होने के कारण नए नेतृत्व ने नरमदली

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नेताओं की पूंजीवादी प्रवृतियों के, जो निश्चित तौर पर भारत की पुरानी सामंती आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थाओं और रीतियों की तुलना में प्रगतिशील प्रवृतियां थीं- खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन को सामंती रुढ़िवादी प्रवृतियों को आधार-शिला पर खड़ा करना चाहा, जो भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ के लिए अब भी आबाद की जा रही थी। नऐ नेतागण, जो गरमदली के नाम से जाने जाते थे, राष्ट्रीय आंदोलन के निर्माण के लिए कट्टर हिन्दुत्व का सहारा लेना शुरु किया और इस मान्यता को बल दिया कि आधुनिक "पश्चिमी सभ्यता" की तुलना में प्राचीन हिन्दू "आर्य सभ्यता" आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। उन्होंने भारत के सर्वाधिक प्रगतिशील आंदोलन, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को, जिसका चरित्र साम्राज्वाद विरोधी था, पुरानपंथी तथा धार्मिक अंध विश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहा।

इस तरह का कट्टर हिन्दूवाद की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का एक नापाक गठबंधन की अभिव्यक्ति तो स्वामी जी के जन्म के एक ही साल बाद 1890 में ही 'एज आफ कन्सेंट बिल'[38] के प्रश्न पर उसी समय मुखर होकर सामने आ गई थी जब कांग्रेस के गरमदली नेता तिलक ने इसके खिलाफ अभियान तेज किया था। तिलक ने इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन का नेतृत्व किया तथा हिन्दूवाद की घोर प्रतिक्रयावादी शक्तियों की तरफ से आवाज उठाई। बाद में उन्होंने गो-रक्षा समिति का गठन किया, मराठी के राष्ट्रीय नायक शिवाजी की ही स्मृति में नहीं, बल्कि गजमुखधारी, सूंड़ सम्पन्न देवता गणेश की स्मृति में भी राष्ट्रीय त्यौहारों का आयोजन किया जाने लगा तथा बंगाल के, जो राष्ट्रीय आन्दोलन का एक मुख्य केन्द्र था, कतिपय हिन्दू राष्ट्रवादी धार्मिक कट्टरता वाले लोगों द्वारा काली की पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाने लगी। धार्मिक कृत्यों की आड़ लेकर व्यापक तौर पर धार्मिक सभाओं, धार्मिक अनुष्ठानों आदि के जरिए राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया जा रहा था तथा धार्मिक संस्थाओं का गठन किया जा रहा था।

राष्ट्रीय आंदोलन का ऐसा दौर बिहार को राजनीतिक तौर पर पिछड़ी सामंती व्यवस्था के जातिगत आधारों पर प्रभावित कर रहा था। किसी संगठित जनाधार के अभाव तथा वर्गीय संस्थाओं या संगठनों की अनुपस्थिति में जातीय सभाओं की अविराम लहर पर संगठनों को खड़ा किया जा रहा था, जिनका उद्देश्य तो साम्राज्यवादी शासन के दमन के खिलाफ संगठित होना था, परन्तु इनका चरित्र भी अखिल भारतीय धार्मिक आंदालनों की ही तरह प्रतिक्रयावादी ही था। 1887 में *अखिल भारतीय कायस्थ महासभा,* 1892 में प्रमुख भूमिहार ब्राह्मण महासभा, 1905 में सरयूपारी ब्राह्मण सभा, 1906 में *राजपूत सभा* तथा *रवानी* कहार सभा,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

1907 में मारवाड़ी यंग मैन एशोशिएशन, 1911 में दुसाध सभा, 1912 में गोप महासभा, *केवट महसभा, कुरमी महासभा* तथा *नाई महासभा* के साथ कई अन्य महासभाओं का जन्म आधुनिक बिहार में स्वामी जी के बालिग होते-होते बन चुका था।[39] इसके अतिरिक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज जैसी राजनैतिक एवं धार्मिक संस्थाएं भी बिहार में मौजूद थीं।

इसी आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी का बचपन बीत रहा था और उस काल विशेष की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों ने स्वामी जी के चिंतन को एक ऐसा आकार प्रदान किया जो धार्मिकता एवं जातिगत महत्व को स्थापित करने की ओर उन्मुख हुआ। धार्मिकता और आध्यात्मिकता के स्तर पर स्वामी जी भगवान की प्राप्ति, योग-सिद्धि तथा मोक्ष-प्राप्ति की उन प्रवचन विधाओं की ओर उन्मुख होकर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों का ही नहीं अपितु जंगलों एवं पहाड़ों में मुक्ति और मोक्ष का रास्ता ढूंढते चले।

बिहार की सामाजिक संरचना में सामंती प्रभाव और आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ापन में बंगाली समुदाय और बाह्य जगत में साम्राज्यवाद ऐसे कारकों में थे जिनसे ऐसा लगता था कि ये ही कारक बिहार का शोषण कर रहे हैं। बचपन तथा मोक्ष-प्राप्ति के प्रति मोह भंग होने के बाद स्वामी जी को ऐसा लगा कि बिहार में सामंत, मध्यमवर्ग और बंगाली तत्वों में राजनीतिक चेतना अवश्य थी, परन्तु वे लोग अलग-अलग अपनी आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों को सुरक्षित करने में मस्त थे। सामंती तत्वों का साम्राज्यवाद से गठबन्धन का मुख्य उद्देश्य सामंतवाद तथा साम्राज्यवाद के आर्थिक एवं राजनैतिक महत्व को बरकरार रखना था। इसी गठबंधन के आर्थिक और राजनैतिक शोषणात्मक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कुछ अर्द्ध राजनैतिक दल भी थे- लैंड होल्डर्स एशोसिएशन, विभिन्न जातीय महासभा आदि, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। मध्यम वर्ग अधिक नौकरी पाने के लिए आर्थिक एवं राजनैतिक संघर्ष एवं राजनैतिक संघर्ष में व्यस्त थे। वे लोग इसी उद्देश्य से बिहार को बंगाल से अलग करने की राजनैतिक लड़ाई लड़ रहे थे।[41]

जातिगत एवं सम्प्रदायगत संस्थाएं उन्हीं के निहित स्वार्थ की पूर्ति में लगे थे। उनका नेतृत्व मोटा-मोटी साम्राज्यवाद, सामंतीवादी, रुढ़िवादी तथा सम्प्रदायवादी रुझान से प्रभावित था। और वैसे ही कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में व्यस्त प्रतीत होते थे। आम जनता की समस्या उनके कार्यक्रम का तब तक अंग नहीं बन सकता था, जब तक वह उनकी वर्गीय, जातीय, साम्प्रदायवादी और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का कारक न सिद्ध हो। देश की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी कि

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राजतंत्र और अर्थतंत्र के साथ-साथ विज्ञान भी वर्णित मोर्चे के स्वार्थों का प्रतीक बन गया था। यह सामाजिक आर्थिक संरचना ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा कर रही थी कि सरकारी पक्ष की दृष्टि में भी शोषित जनता और सरकार तथा उसके समर्थक दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाज़ित हो गए थे।

मगर आर्थिक और राजनैतिक गोलबंदियां अकारण या मनोगत परिस्थिति जन्य नहीं थीं, बल्कि 19वीं सदी के अंतिम तथा 20वी सदी के शुरू के दशकों में जिन साम्यवादी विचारों को सिगारा वेलू चेटियार, राम कृष्ण पिल्लई, लाला हरदयाल आदि जैसे मार्क्सवादी विचारक प्रचारित कर रहे थे तथा 1905 से 1909 के वर्षों में हुए आन्दोलनों में मजदूर वर्ग की जिस एकता का परिचय एवं उसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ रहा था, उसके विरोध स्वरूप तमाम निहित स्वार्थों की एकता बन रही थी। साम्यवाद और समाजवाद के प्रादुर्भाव को कुचलने की योजना बनाई जाने लगी थी। सैनिक तानाशाह की तरह इन प्रगतिशील आंदोलनों को कुचलने की योजना बनाई जा रही थी। आम जनता को वर्ग के बदले वर्ण, जाति, सम्प्रदाय और मजहब के आधार पर विभाजित करने की साजिश रची जा रही थी। इसी सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में स्वामी जी का उदय हुआ था।

हालांकि कांग्रेस के ऊपर कट्टर हिन्दू राष्ट्रवाद के चले आ रहे प्रभाव के परिणामस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म हो चुका था, मगर इस काल के आंदोलनों की जो पृष्ठभूमि भारत में तैयार हुई उसके प्रभाव में एक जुट आंदोलन भी हुए। इस अवधि में व्यापक साम्प्रदायिक एकता का इजहार इस तथ्य में हुआ कि मौलाना सिवली नोमानी के अलावा अनेकों मुसलमानों ने, जिनमें मौलाना रसीद अहमद गांगोई, मौलाना मुहम्मद सिराजी के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने कांग्रेस के कार्यों के प्रति अपने को समर्पित किया। बंगभंग के खिलाफ आंदोलन से लेकर 1916 के कांग्रेस-लीग लखनऊ पैक्ट तक जिस गैर साम्प्रदायिकता एकता का इजहार होने लगा था उसमें हिन्दू मुस्लिम एकता की धुरी इतनी मजबूत थी कि उसके खिलाफ आंदोलनों का जो सिलसिला शुरु हुआ उनमें सार्वजनिक सभाओं का आयोजन सिर्फ एक खास क्षेत्र तत्कालीन बंगाल में हुआ जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम नेताओं ने इनमें तकरीरें दी।[42] बारीसाल में मुकुन्ददास अपने देशभक्ति पूर्ण गीतों से अगर आवाम को आंदोलित कर रहे थे तो अश्विनी कुमार दत्त नव युवकों को उत्प्रेरित कर रहे थे। दूसरी जगह मौलवी इस्माईल सिराज अपने औजस्वी भाषणों द्वारा ब्रिटिश राज के सत्यानाश के लिए जनआयाम को उत्तेजित कर रहे थे तो कोरोसिया के चान्द मियां तथा बारीसाल के अबुल रसूल को शारीरिक यातनाओं को भी सहना पड़ रहा था, जो ब्रिटिश राज के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

खिलाफ उनके लिए किए गए वारदातों के लिए दिया जा रहा था। इन आंदोलनों का नतीजा यह था कि 1909 को आते-आते मौर्लोमिन्टो रिफर्म्स लाया गया जिसमें इस हिन्दू मुस्लिम एकता को तहस-नहस करने के लिए कम्यूनल एवार्ड को लाया गया।[43]

1911 में बंगाल विभाजन कानून को लागू किया जाना कांग्रेस के नेतृत्व में गठित इस आंदोलन की हार थी, जिसमें बीसवीं सदी के प्रथम दशक में अन्तर्राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रभाव पड़ा था। ऐसी स्थिति में संकुचित धार्मिक बंधनों से निकालने की एक कोशिश कांग्रेस और नव निर्मित मुस्लिम लीग दोनों करने लगे। 1912-13 में जो इस्लामिक आंदोलन शुरु हुआ था, उसका चरित्र हालांकि साम्प्रदायिक था, फिर भी उसकी कहर मुसलमान साम्प्रदायिक तत्वों को भी एक संकुचित धार्मिकता से ऊपर उठाया। दोनों सम्प्रदायों को नजदीक लाया क्योंकि इसे कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एक-एक कर आगे बढाया। 1915 के आते-आते कांग्रेस-लीग के संबंध में एक नजदीक का संबंध बना। 1916 के आते-आते लखनऊ में कांग्रेस-लीग पैक्ट हो गया।[44] अब राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग, जो कांग्रेस लौटे मुस्लिम लीग के दो खेमों में साम्प्रदायिकता के आधार पर विभाजित होकर अपनी सामूहिक सौदेबाजी की ताकत खो बैठी थी, पुनः एक होकर नये आन्दोलनों की सम्भावनाओं को पैदा कर दिया।

19वीं सदी के इन अन्तिम तथा बीसवीं सदी के शुरू के दशकों में जो साम्प्रदायिक विलगाव की प्रक्रिया शुरु हुई थी और उसके पीछे जो निहित वर्गीय व्यैक्तिक स्वार्थ कार्य कर रहे थे। उन्होंने बिहार के विभिन्न हिस्से और-खासकर स्वामी जी के कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार को प्रभावित किये। उस साम्प्रदायिक तनाव का मुख्य कारण गो-हत्या का प्रश्न था जो इसे उत्प्रेरित कर रहा था निहित आर्थिक स्वार्थ इसे बल दे रहा था।

स्वामी जी तो स्वयं ही गो-रक्षा के प्रबल समर्थक थे, परन्तु शाहाबाद जिला (जहां पर 1917 ई. में गो हत्या के कारण भीषण दंगा हुआ था) के ब्रह्मपुर पशु मेले में गो-हत्या विरोधी पिकेटिंग में जब उन्होंने सक्रिय रूप में भाग लिया, तब धार्मिक आवरण में छिपे क्षणिक आर्थिक लोभ-लालच की वास्तविकता उनके सामने उभर आई। गो हत्या के विरोध में स्वामी जी के पिकेटिंग के अवसर पर वहां के मेले के ठेकेदार पुरोहितों का व्यवहार उनके प्रति इतना कठोर था कि उन पर जान लेवा हमले किए गए।

उपर्युक्त समस्याओं के आधार पर स्वामी जी ने पाया कि पैसे के भगवान के सामने धर्म का भगवान फीका एवं कमजोर पड़ जाता है। इस संदर्भ में स्वामी जी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

द्वारा स्थापित निष्कर्ष अन्य ऐतिहासिक तथ्यों से सम्पुष्ट होते हैं। यह स्पष्ट है कि आर्थिक स्वार्थों की कीमत पर हिन्दू समाज गो-रक्षा के प्रति अपनी धार्मिक प्रविबद्धता के लिए किसी भी रूप में तैयार नहीं था।

इस प्रकार मजदूर आंदोलनों के प्रभाव ने, जिनमें सभी सम्प्रदाय के लोग एक साथ मिलकर संघर्ष कर रहे होते हैं, स्वामी जी को प्रभावित किया। धर्म के इसी दिखावटी रूप के साथ ही स्वामी जी सम्प्रदाय के फैलाव के लिए मध्यमवर्गीय चरित्रों को भी जिम्मेदार मानने लगे थे। वास्तव में साम्राज्यवादी पूंजीवाद के संरक्षण में जनित भारतीय मध्यम वर्ग के उद्‌भव एवं विकास के परिवेश पश्चिमी जगत में सर्वथा भिन्न थे, जहां पर मध्यम वर्ग सामन्तवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के बाद उदित हुआ था।[45] देशी सामंतवाद एवं विदेशी पूंजीवाद के बीच त्रिशंकु की भांति लटका भारतीय मध्यम वर्ग कोई अपनी स्वतंत्र विचार धारा एवं पहचान नहीं बना सका।

सम्प्रदायवाद की मीमांसा स्वामी जी के दर्शन का एक ऐसा पहलू है जिसका प्रतिपादन उन्होंने एक वैज्ञानिक कनवास में रखकर तराशा था। नेहरू के विलम्बित आधुनिकीकरण के सिद्धान्त जिसका नेहरू ने मुस्लिम सम्प्रदाय की प्रक्रिया में मुस्लिम सम्प्रदाय का पिछड़ जाना सम्प्रदायवाद के परिपेक्ष्य में स्थापित करते हुए कहा था कि आधुनिकीकरण के प्रति मुस्लिम आवाम को भौतिक तौर पर साम्प्रदायिक होने को मजबूर किया। वहीं स्वामी जी ऐसी मीमांसात्मक बौद्धिकता के खिलाफ सम्प्रदायवाद को किसी एक सम्प्रदाय के आधुनिकीकरण में पिछड़ जाना नहीं मानते हैं, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय समाज के सम्पूर्ण मध्यम वर्ग के प्रतिक्रियावादी हिस्से की धार्मिकता मानते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में यह वर्ग ने अपनी पहचान बनाने में असमर्थ साबित हुआ है। इसका संबंध आर्थिक राजनीतिक स्वार्थों का टकराव है। उनके विचार यदि एक ओर धार्मिक आवरण में छिपे आर्थिक-राजनीतिक स्वार्थ के कपटी चेहरे को बेनकाब करते हैं तो, दूसरी ओर उनके विवरण वस्तुगत सम्प्रदायवाद से संबंधित वस्तुगत एवं वैज्ञानिक इतिहास लेखन के निष्कर्षों से इस हद तक समानता रखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक नजर आने लगे हैं।

सामाजिक स्थिति

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भारत में जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास हुए, वे पुराने सड़ी-गली धार्मिक मान्यताओं पुरानी रुढ़िग्रस्त रस्म-रिवाजों और भीतर से खोखले धार्मिक संबंधों से कतई मेल नहीं खाते थे। किन्तु गहरी जड़ें जमाऐ बैठी धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक रस्म-रिवाजों ने अलग हटकर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वैज्ञानिक विचार और रहन-सहन के आधुनिक ढंग को आसानी से स्थान नहीं दे दिया। प्रतिक्रियावादी वर्ग अपने निहित स्वार्थों के संरक्षण और सामाजिक असमानताओं को न्याय संगत ठहराने के लिए ही वेदों और शास्त्रों से उद्धरण नहीं देते थे, वरन ऐसा वे ब्रिटिश सरकार के समर्थन के लिए भी करते थे। दूसरी ओर प्रगतिशील वर्ग और समूह उन्हीं धार्मिक ग्रन्थों से उद्धरण देकर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को न्याय संगत ठहराते थे।

भारतीय सामंतवादी धार्मिकता या वंशानुगत गुरुआई की प्रथा में, जहां वंशानुगत श्रेष्ठता के दर्शन का मूल पाठ था कि पारिवारिक गुरुआई एक संस्थागत रूप ग्रहण कर लेती है, स्वामी जी ने विरोध किया। उन्होंने निःसंकोच कहा "इस वंश परम्परागत गुरुआई ने इन गुरुओं को निरक्षर और दुराचारी बना दिया। क्योंकि उनकी पूजा-प्रतिष्ठा और आमदनी तो रुकनेवाली नहीं, फिर भी वे पढ़ने या सच्चरित्रता की परवाह क्यों करें"?

रुढ़िगत परम्पराओं पर चोट करते हुए सहजानन्द कहते हैं- "गुरुजी चाहे जूते पहनकर आयें या नंगे पांव गंदी चीजें तलवे में लगाए हुए आए, मगर यह विधान हर हालत में जरुरी था कि उनके पांव धोकर चेला लोग प्रणाम करते थे। यह कितनी नादानी और गंदी बात है।"

सामाजिक सुधारों की प्रवृत्ति और धार्मिक पुनरुत्थानवाद के अन्तर को समझाते हुए लाला लाजपत राय ने कहा था- "सुधार और पुनरुत्थान" में यदि कोई वास्तविक महत्व है तो वह सामाजिक मामलों में पथ-प्रदर्शन के लिए सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी क्रमशः जिस अधिकार या अधिकारों से प्रेरणा ग्रहण करते है, उसमें या उनमें निहित है। सुधारवादी तर्क और यूरोपीय समाज के अनुभव पर अधिक निर्भर करते हैं, जबकि पुनरुत्थानवादी शास्त्रों, अतीत के इतिहास तथा जनता को इन परम्पराओं और देश की इन संस्थाओं की ओर अधिक उन्मुख है, जो इस समय प्रचलित थी, जब यह राष्ट्र-गौरव के शिखर पर था।[46]

यह सच है कि पुनरुत्थानवादी हिन्दू धर्म के विगत गौरव की दुहाई देकर जनता को उत्तेजित करने का प्रयत्न करते थे। किन्तु यह कहना सही नहीं होगा कि सुधारवादी देश की परम्पराओं की उपेक्षा करते थे, सुधारवादियों का प्रयत्न भी यह था कि अतीत की विरासत में एक नए भविष्य का सृजन करने का प्रयत्न किया जाए। अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्न में वे भी वेदों, उपनिषदों और पुराणों की शिक्षाओं पर निर्भर करते थे।

हालांकि स्वामी जी सामाजिक सुधारों के प्रबल समर्थक थे, परन्तु उनकी दार्शनिकता में निहित जो विडम्बना थी उसकी मूल जड़ें ऐसे चिन्तनों में कुछ हद

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

तक अवैज्ञानिक लगती थीं; क्योंकि वे सामाजिक सुधार कार्य और राजनीति को एक दूसरे से पृथक वस्तु मानते थे। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड परस्पर संबंधित घटना क्रमों का एक भौतिक एकीकरण है और किसी खास देश और काल में प्रचलित उत्पादन-संबंध ही वह कारण है जो मानव जाति के सारे संबंधों को निर्धारित करता है, विश्व परस्पर विरोधी घटना का ही एक सम्यक रूप हैं इसलिए सामाजिक सुधार कार्य परस्पर निर्भरता के वैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित एक भौतिक जगत है, स्वामी जी नहीं मानते, इसलिए कांग्रेस के क्रिया कलापों और सामजिक सुधार कार्य अलग-अलग घटनायें हैं।

स्वामी जी ने सामाजिक सुधार पर काफी बल दिया है। समाज में व्याप्त बुराइयों को तो वे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। स्वामी जी स्वतंत्रता-संग्राम में गरमदल के नेता और सामाजिक सुधार के पक्षधर थे। हालांकि नरमदल के नेता ने भी सामाजिक सुधार के महत्ता को स्वीकारते हुए कहा है: "राष्ट्रीय कांग्रेस सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक मंच नहीं है।" उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा, "अपने आपको इन्हीं, प्रश्नों तक सीमित रखना चाहिए जिनमें समूचे राष्ट्र की सीधी-सीधी रुचि हो और उसे सामाजिक सुधारों के समंजन तथा अन्य वर्ग प्रश्नों को वर्ग कांग्रेसों के लिए छोड़ देना चाहिए।"[47]

स्वामी जी के काल में सामाजिक सुधारों के आन्दोलन ने धीरे-धीरे और अचूक रूप से नीची जातियों के लोगों को भी प्रभावित करना शुरु किया। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में केरल के ईझवों, महाराष्ट्र के महारों, मैसूर के वोफ्फलिगों और बंगाल के नाम शूद्रों में काफी प्रगति आई।[48] इस प्रगति का मुख्य कारण था कि निम्न स्तर के लोग जिसका रहन सहन का स्तर गिरा हुआ था, किसान थे, नेतृत्व स्वामी जी के हाथों में था।

स्वामी सहजानन्द सरस्वती भारत में धार्मिक एवं जातिगत आंदोलक के रूप में उभरे। भारतीय परिवेशों में सामन्तवाद के प्रभुत्व को कमजोर करने में काफी सहायता पहुंचाई। ब्रिटिश साम्राज्यशाही के दमनकारी नीतियों के तहत तथा व्याप्त आर्थिक सामाजिक उत्पीड़न के काल में धार्मिक अन्धविश्वासों को जन्म देने वाले उन कारकों को ढूंढा जिसके कारण उलझी हुई सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के मोहजाल से देश को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिली जो भारतीय किसानों के लिए मौलिक जादूगर के समान थे, जो पलभर में शोषित किसानों से राहत एवं चैन की बंशी बजाई। जिनमें भारतीय किसान आज भी स्वामी जी का गुणगान करते हैं। उपर्युक्त सभी सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश था, जिसने स्वामी जी को प्रभावित किया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी जी के सम्पूर्ण कार्य-काल में जिस सामाजिक-आर्थिक परिवेश का भारत अनुभव कर रहा था या जो भारत में विद्यमान था उसमें आर्थिक-सामाजिक शोषण के अलावा नस्लवादी विभेदीकरण की नीति भी थी जिसे सम्राज्यवाद पूरी तरह पाल पोस रहा था। पौराणिक सामंती अर्थ-व्यवस्था के साथ साम्राज्यवादी शासनतंत्र का जो अपूर्व घोल-मेल किया गया था उसका परिणाम था एक तरफ साम्राज्यवादी प्रभुओं और तमाम भारतीय जन अभाव के बीच नस्लवादी ऊंच-नीच की विभाजक रेखा को बनाए रखता था तथा दूसरी ओर इस वर्ण आधारित समाज में भारतीय जातियों को उनकी परम्परागत विभेदों को ज्यों का त्यों बनाए रखना। सामंतवाद और साम्राज्यवाद की इस अमेल चरित्र का भारत में स्थापित रहना आर्थिक सामाजिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को कुंद कर रहा था तथा पूंजीवादी विकास क्रम में जाति तथा नस्लवाद पर पूंजीवाद के हमले स्वरूप उनके विघटन की प्रक्रिया को रोक रखा गया था, जो यूरोपीय विकास की प्रक्रिया से काफी भिन्न था। भारत में भी दक्षिण अफ्रीका का अन्य अफ्रीकी देशों की ही भांति नस्ल आधारित विभेदीकरण ऐसा खींच दी गई थी। गोरे चमड़े वाले लोगों को अलग से विशेष सुविधायें दी जाती थीं। उन लोगों को विशेष नौकरी पदोन्नति तथा विशेष कानून को व्यवस्था थी। इन लोगों के लिए क्लब, क्रीड़ा-स्थल तथा सड़क कि विशेष व्यवस्था थी जो सामान्यतया भारतवासी को निषिद्ध था।[49] खुद देशी जमींदारों एवं सामन्तों ने विदेशी प्रशासनिक स्तर को इतना बढ़ा दिया था कि ये अपने जुल्म की सीमा को पार कर गए थे।

सामंतवादी प्रथा में दबी सामाजिक संरचना का यह स्वरूप होता है कि सामंत तथाकथित उच्च जातियों की तुलना में पिछड़ी जातियों हरिजनों आदि पर दमनात्मक कार्रवाइयां ज्यादा संगठित करता है। इसका निकृष्ट स्वरूप आज हरिजन दहन में देखने को मिलता है। स्वामी जी के जीवन काल में तथा कथित उच्च जातियों के द्वारा पिछड़ी जातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों का जीवंत प्रमाण मुंगेर के कई क्षेत्रों में देखने को मिला जहां जनेऊ धारण करने के प्रश्न पर लखीसराय के इर्द-गिर्द काफी लोगों को बेघर कर दिया गया। निचली जातियों के द्वारा जनेऊ धारण करने के खिलाफ वहां के सामन्ती तत्वों ने स्पष्ट घोषणा की कि जनेऊ पहनना बंदकर दें अन्यथा इलाके से उन्हें बलपूर्वक बेघर कर दिया जाएगा। ऐसा लखीसराय में किया गया। इन सामंती तत्वों का स्वार्थ यह था कि ये लोग जनेऊ धारण कर लेंगे तो हल चलाना धार्मिक निषेध होगा। क्योंकि जनेऊधारी को हल चलाने से परहेज करना पड़ता था। इस धार्मिक निषेध के कारण हल चलाना छोड़ देंगे। फिर खेती की गृहस्थी की समाप्ति का डर नजर आने लगा। समस्तीपुर के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नजदीक कुछ मुसहरों ने कंठी पहन कर वैष्णव होने का निर्णय लिया। वहां के जमींदार ने फतवा निकाल दिया कि मुसहर वैष्णव हो नहीं सकते। मुजफ्फरपुर जिले के कुछ निम्नवर्गीय लोगों ने जमीन खरीदी, जमींदारों एवं सामंतों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और न इन लोगों ने इन कास्तकारों को बेदखल कर दिया तथा गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया।[50]

किसी सशक्त जन आंदोलन के अभाव में तथा साम्राज्यवादी दमन के खिलाफ इस तरह की अमानुषिक कृत्यों का विरोध संगठित रूप से नहीं किया जा रहा था तथा जन जातीय सभाओं ने रूप ग्रहण कर लिया था इसका संगठन भी इतना सशक्त नहीं था जो विरोध की ऊंचाई तक ले जाए।

भू-स्वामित्व के खिलाफ आंदोलन का परिवेश

जातीयता की मानसिकता से ऊपर उठकर स्वामी जी ने अपनी ही जाति के टिकारी, बेतिया, अमावा, हथुआ आदि के बड़े-बड़े सामन्तों के खिलाफ संघर्ष तेज किया। "*किसानों को फंसाने की तैयारियां*" नामक पुस्तक, जिसे स्वामी जी ही ने लिखी है, यें जातीय सभाओं के विषय में आए हुए विचारों में परिवर्तन की जानकारी दी है। जिसे स्वामी जी ने जाति, विशेष की हक की लड़ाई के लिए अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत एक जातीय सभा से संबंधित होकर की थी, उसी ने सन 1929 में मुंगेर में इस सभा का विध्वंस करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और उसके बाद सहजानन्द लगातार हर तरह की जातीय सभाओं के संगठनकर्ताओं पर प्रहार करते रहे। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है किः

> "बहुत ही अदब पर स्पष्टता के साथ मैं कह देना चाहता हूं कि चाहे पहले कुछ भी स्थिति रही हो और मेरे जानते पहले भी यही थी, आज तो जातीय संस्थायें एकमात्र कुछ इने-गिने प्रतिष्ठित चलते-पुर्जे तथा धनिकों के राजनीतिक स्वार्थ साधन की सामग्री बन गई है और खूबी यह है कि खुल्लम-खुला तो वहां समाज सुधार की बातें की जाती हैं, लेकिन चुपके-चुपके राजनीतिक स्वार्थ-साधन का षडयंत्र किया जाता है। जहां पहले किसी उच्च पदस्थ अफसर की दरबारदारी और स्वागत कर देने एवं राजभक्ति का बाहरी स्वांग भरने से सभाओं के ये चतुर खिलाड़ी अपने नजदीकियों तथा पिट्ठुओं के लिए नौकरियां, ऊंचे पद और दूसरी रियायतें हासिल कर लेते थे, वहीं उनके साथ-साथ ही अब चुनावों के युद्ध में भी सफलता पाते और पाना चाहते हैं।[51]

इन जातीय सभाओं के विषय में स्वामी जी के विचार अनुभव पर आधारित थे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इन्होंने देखा था कि किस तरह कौंसिलों और बोर्डों के चुनाव के समय के आते ही कुछ खास किस्म के लोग जातीय हित की दुहाई देकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करते थे। इन नेताओं में से अधिकांश समाज के उच्च वर्गों से आते थे। इन नेताओं के स्वार्थ पर आधारित जातीय प्रेम पर प्रहार करते हुए स्वामी जी ने लिखा है:

"जातीय प्रेम की भी सीमा है, और जातीय नेता लोग भी इसका अतिक्रमण करने में साफ खतरा देखते हैं। फलतः समाज की आंखें ये खोल नहीं सकते। बलि के बकरे के साथ भी तो मुहब्बत की ही जाती है और उसे खिला-खिलाकर मोटा किया जाता है- इसमें स्वार्थ है, लेकिन उस बकरे को बाघ बनाने की बेवकूफी कौन करेगा सिवाय उस हितोपदेश के ऋषि के जिसने चूहे को बाघ बनाकर अपनी जान खतरे में डाली। यही है जातीय प्रेम और जातीय संस्थाओं की लीडरों का वास्तविक रहस्य। एक स्वार्थ से धनी या गरीब किसान या जमींदार आदि अपनी-अपनी सभायें करें तो यह बात समझ में आ सकती। लेकिन गरीब किसान जमींदार की खिचड़ी सभा का मतलब समझना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है।"[52]

स्वामी जी ने अपनी व्यक्तिगत सूझ-बूझ के आधार पर अपनी पुस्तक "किसानों को फसाने के तैयारियां" *में लिखा है–*

"सभी धर्मों और जातियों के अमीरों का एक ही समाज होता है, और वे एक जगह बैठकर एक ही दृष्टिकोण से सोचते हैं। हमारी मिलों का माल मंहगा हो, हमें मजदूरों को कम मजदूरी देनी पड़ी, हमें सूद भरपूर मिले, हमारी जमींदारी की आमदनी खूब बढ़े, समूची जमीन हमारी बकाश्त और जिरात हो जाए और कोई भी रैयत हमारे सामने सिर न उठा सके, फलतः हम और हमारे अमले उसे जिस घाट पानी पिलावे-पिये इत्यादि। सभी धर्म और जाति के अमीर और धनी जमींदार यही चाहते हैं।"[53]

स्वामी जी ने अन्य विचारकों की तरह समाज में व्याप्त समस्याओं में पहले रोटी की समस्या हल करने की बात की है–

"मेरी पक्की धारणा है कि वर्तमान परिस्थिति में जबकि हर एक जाति और धर्म के अधिकांश लोग यथार्थतः भूखे और नंगे हैं, और आत्म सम्मान रहित जीवन व्यतीत करने को बाध्य किए जा रहे हैं, हर जातीय प्रेमी, धर्म-सेवक समाज सुधारक नेता की हर सभा का और सभी जातीय एवं धार्मिक पत्र-पत्रिकाओं का यह पवित्र कर्तव्य है कि ईमानदारी के साथ इस रोटी, वस्तु और आत्म सम्मान की समस्या को सबसे पहले हल करने के लिए पूरी शक्ति के साथ जुट जाये और

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इसे हल करके ही छोड़ें नहीं तो आज इस प्रश्न को उठाकर धर्म सदाचार, सुधार नैतिकता आदि की बातें करना इस बात का सबूत देना है कि उनमें वस्तु स्थिति का सामना करने की हिम्मत नहीं है।"[54]

जाति और धर्म के प्रचार करने वाले पेशेवर लोगों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए उन्होंने स्पष्टतः कहा है कि–

"इस समय इस प्रश्न को उठाना जनता को गुमराह करने की कोशिश करना है। क्योंकि इन प्रश्नों और बातों को सुनकर भोली जनता धोखे में आ जाती है और रोटी तथा कपड़े के असली प्रश्न की ओर से इसका ध्यान फिर जाता है, और वह नाटक ही समझने लगती है कि धर्म और सदाचार आदि का प्रश्न ही वास्तविक प्रश्न है और रोटी का सवाल गौण है। बहुत दिनों के धर्म के प्रति जो मूक जनता में अत्यधिक सम्मान है, अनुचित लाभ उठाकर जाति और धर्म के पेशेवर लोग इस प्रकार इसे पथभ्रष्ट और गुमराह कर रहे हैं यह उनका अक्षम्य अपराध है।"[55]

जातीय परिस्थिति

1924 में स्वामी जी का ध्यान भूमिहार-ब्राह्मण सभा एवं पुरोहिती के संगठन की ओर पुनः आकृष्ट हुआ। कांग्रेस संघर्ष में पड़ जाने के कारण भूमिहार-ब्राह्मणों के पूर्व आंदोलन के विरोधियों की हिम्मत बढ़ गई। जहां-तहां लोग उन्हें दबाने लगे और पुरोहितों से इनका विवाह-श्राद्ध कराना भी छोड़ दिया। समाज के सामने हाहाकार मच गया और करुण वाणी में लोगों ने स्वामी जी के सामने यह पुरोहिती का प्रस्ताव रखा। स्वामी जी लोगों के पुकार को सुनकर इस प्रस्ताव में कूद पड़े। और चार महीनों में सिमरी में रहकर "*कर्मकलाप*" की रचना की। इस समय समाज में सभी जगह व्याप्त था कि पुरोहिती केवल ब्राह्मण की करा सकते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्मा ही व्यक्ति केवल इसके योग्य है, भले ही वह लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर पंडित हो। स्वामी जी ने इसका जमकर विरोध किया और डंके की चोट पर गांव-गांव घूम-घूम कर इसका विरोध किया और भूमिहार ब्राह्मणों को ललकारा कि खुद पुरोहिती करो।

स्वामी जी.जब भूमिहार ब्राह्मण समाज के आत्म सम्मान की रक्षा के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक कर रहे थे, साथ युवा वर्ग उनके साथ था जो पुरोहिती का समर्थन करता था, लेकिन जमींदार-भूमिहारों ने इस पुरोहिती का विरोध किया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इस पुरोहिती का विरोध करते हुए सर गणेशदत्त ने स्वामी जी से कहा-

"आप तो हमारे समाज को चौपट कर रहे हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह में लड़कों और जवानों का पढ़ना छुड़ाया, जेल भेजवाया और आप भिखमंगी वाला पुरोहिती का काम सिखाकर रहे-सहे को भी चौपट कर रहे हैं। भूमिहार-ब्राह्मण का बच्चा कथा बांचकर पैसा ले और खाए तो यह डूब मरने की बात रहेगी।"

स्वामी जी ने इसका जवाब देते हुए कहा–

"ब्राह्मण का बच्चा यदि कथा बांचकर जीविका करे तो इसके लिए डूब मरने की बजाए गौरव की बात होगी। कथा बांचना तो ब्राह्मण का धर्म है। अगर वो ब्राह्मणत्व का दावा करें, चोगा पहनकर इजलास पर गंगा तुलसी उठाकर झूठी कसम खिलवाए और उसके मिहनताने के पैसे वसूले (वकील के रूप में) उसे चूल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।"[56]

स्वामी जी ने पुरोहिती की वकालत करते हुए स्पष्ट कहा है कि-

"जो यह भय दिखलाया जाता है कि पुरोहिती करने से समाज में गरीबी और भिक्षावृत्ति बढ़ेगी, वह भी निर्मूल ही है। काशी, बेतिया, नरहन, सुरसंड, शिवहर आदि के राजे महाराजे और एकसरिया, जैसरिया, दसवार, गौतम, दोनवार वगैरह वंशों के जितने बबुआन हैं, इनकी वर्तमान सम्पति और महाराज दरभंगा का राज्य भी इसी पुरोहिती, दक्षिणा या प्रतिग्रह वृत्ति के फल हैं।"[57]

इन्होंने पुरोहिती के पक्ष में दूसरी जगह तर्क देते हुए उन्होंने कहा है कि-

"साधारणतया त्यागी, जमींदार, भूमिहार या पश्चिमी नामधारी समाज का इतिहास इस बात का साक्षी है कि पुरोहिती वृत्ति से ही यह समाज बना है या इसकी भू-सम्पति और धन वृद्धि हुई है। फिर कैसे कहें कि जिस रास्ते से, जिस काम से इस उच्च सिंहासन पर आसीन हुए इसी से नीचे गिर जायंगी। यह तो समझ से बाहर की बात है। यह भी समझ में नहीं आता है कि प्रति वर्ष समाज का जो करोड़ों रुपया दूसरे समाज में जा रहा है, और इसके जाने का द्वार यही गुरुवाई और पुरोहिती है, यदि वह समाज में ही उसी के द्वारा रख लिया जाए तो कैसे समाज गरीब और भिक्षुक हो जाएगा? मैं तो सैंकड़ों नहीं हजारों दृष्टांत ऐसे बता सकता हूं, जहां पर इस समाज की पुरोहिती करने वाले दूसरे लोग हावी होकर उन्हीं की भूमि को खरीद रहे हैं और ये लोग गरीब हो रहे हैं। पुरोहिती दल को जो आजकल बड़ा भारी भय है वह यही है कि इस समाज को पुरोहिती और गुरुवाई तो सोने की चिड़िया है, कहीं ऐसा न हो कि हाथ से निकल जाए"[58]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पुरोहिती के पक्ष में इन्होंने कहा-

> "पुरोहिती से आपका और देश का मुख उज्ज्वल होगा, आपकी ब्राह्मणता की रक्षा होगी। उन्हीं के द्वारा आप इन आक्षेपों का सच्चा उत्तर दने में समर्थ होंगे।"[59]

स्वामी जी ने पुरोहिती का समाज में प्रचार कर के समाज को स्वावलम्बी आत्म-गौरव सम्पन्न और जीवित बनाने का संकल्प कर तदनुसार काम करने में लग जाना प्रत्येक समाज का मौलिक कर्तव्य बताया।

दिसम्बर, 1921 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के बाद की राजनीतिक स्थितिः

दिसम्बर, 1921 के पूर्व या 1885 से 1920 के तमाम दशकों में भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति-संग्राम का स्वरूप कांग्रेस जिस राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग और उच्च भारतीय मध्यम वर्ग के सबसे वाचाल तबके का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसकी सांगठनिक शक्ति तथा राजनीतिक रणनीति मात्र आवेदन देने तथा ब्रिटिश शासकों के सामने अपनी मांगों के लिए असहाय शक्ति के रूप में था, अगर कोई अपवाद इन दशकों में था तो मात्र 1905 से 1908 तक का आंदोलन जिसमें भारतीय मजदूर वर्ग ने विश्व प्रगतिशील आंदोलनों से प्रोत्साहित होकर क्रांतिकारी भूमिका अदा की थी। कांग्रेस के वर्ग चरित्र का मूल्यांकन करते हुए स्वामी जी ने स्वयं लिखा है–

> "लेकिन एक तो इनकी बिरादरी छोटी थी, दूसरे दिमागदार और मालदार होने के कारण उनमें दब्बूपन पहले दर्जे का था। स्थिर स्वार्थ वाले सम्भवतः दब्बू और डरपोक होते हैं और विद्या एवं लक्ष्मी गिने-गिनाए स्थायी स्वार्थों में है।"[60]

मध्यम वर्ग के सबसे ऊंचे स्तर या तबके वाले इन लोगों के सीमित आंदोलन के कारण उनसे कुछ ही नीचे और संबद्ध मध्यम वर्ग का दूसरा तबका जाग उठा जिसमें अधिकांशतः सभी तरह के पढ़े-लिखे लोग थे।

कुछ दिनों बाद लगभग पन्द्रह साल पश्चात् इस दूसरे नव जागृत तबके की लखनऊ में कांग्रेस के ऊपर दबदबा जम गया, इसकी जीत हो गई। जिस तरह सामंत वर्ग का नेतृत्व उच्च स्तर ने छीना उसी तरह कांग्रेस की लीडरों उसके निम्न स्तर ने छीन लिया, हालांकि इसका नाम लखनऊ समझौता रखा गया। इस प्रकार फिरोजशाह मेहता के नेतृत्व को बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। कांग्रेस के अन्दर का भौतिक अन्तर्विरोधों के कारण पुनः उच्च वर्ग के हाथों में चला गया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वर्गीय भौतिक स्वार्थों की टकराहट में ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे-जैसे आंदोलन का दौर तेज होता गया वैसे-वैसे कांग्रेस के अन्दर निहित उच्च मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के नेतृत्व का काल भी घटता गया, महात्मा गांधी ने तो 1919 में ही तिलक, मालवीय नेतृत्व के विरुद्ध जंग जारी किया था मगर 1921 में चौरी-चौरा घटना ने गांधी को अहिंसा की अवधारणा को एक निर्जीव चैलेंज दिया जो सम्भवतः टिक न सका। उसे एक क्रियात्मक सूचना या नोटिस कहा जा सकता है 1930-32 में एक विराट रूप धारण करके गांधी जी ने सत्य अहिंसा को दफना दिया।

1905 का आंदोलन हालांकि एक सशक्त आंदोलन था, फिर भी वह अपना ध्येय पूरा न कर सका, जैसा मौंटेग्यू ने लिखा- "ब्रिटिश सरकार का मूलाधार था जनता का सहयोग, फिर वहां स्वेच्छापूर्वक हो या अनिच्छापूर्वक। यह भी एक सर्वमान्य बात है कि जनता के सामूहिक सहयोग बिना कोई भी शासन टिक नहीं सकता, चल नहीं सकता।"[61] वास्तव में गांधी के आंदोलनों का अनुभव बता रहा था कि जन आजमाइश ही वह शक्ति देगा जो स्वराज्य प्राप्त कर सकता है।

नागपुर में जन आंदोलनों की वकालत करने वाले गांधी ने कांग्रेस को गांवों की तरफ मोड़ा और जनता के स्वतंत्र आंदोलन महाकाय बन चल पड़े। 1921 के पूर्व मजदूर आंदोलनों का जो सिलसिला चल पड़ा था तथा चौरी-चौरा की घटना सम्पूर्णता में यह प्रमाणित कर दिया था कि जिस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की गांधी जन आंदोलन बनाना चाहते थे, उसके पीछे मजदूरों और किसानों की जो संगठित शक्ति के संयुक्त कार्रवाई का जो बल दिखाई दिया वह कांग्रेस को उस जनता का, जिनका राजनीतिक संगठन कांग्रेस थी, वर्ग स्वार्थ पर खतरा पैदा करनेवाला था। इस कारण असहयोग आंदोलन को बिना शर्त्त वापस ले लिया गया।[62]

फरवरी, 1922 के बाद, एक ऊंचे आंदोलन को बिना शर्त वापसी का फल था कि साम्राज्यवाद का राजनीतिक-आर्थिक हमला शुरू हो गया तथा विगत आंदोलनों के दबाव तले सहूलियतों को भारतीय पूंजीपति वर्ग हासिल कर चुका था इस पर साम्राज्यवादी हमले शुरु हुए। गिरफ्तारियों[63] को सिलसिला शुरु हुआ और जन आवाम उदासीन होकर देखते रहा।

मगर प्रिंस आफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध[64] में आंदोलनों का सिलसिला जारी हुआ था वह अन्तिम चरण में धीमा पड़ गया तथा 1922 से 1926-27 के काल अवधि राजनीतिक आंदोलनों के लिहाज से मंदी का काल साबित हुआ, साम्राज्यवाद की दमनात्मक कार्रवाई तेज थी, नेतागण या तो जेल में रहे या चुप। ऐसी राजनीतिक गतिरोध काल में स्वामी जी ने बिहार के किसानों की

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्थिति का मूल्यांकन करते हुए कहा था "किसानों को भयंकर गरीबी और तबाही का सवाल ही हमारे देश की एक मात्र विकट राजनीतिक तथा आर्थिक समस्या है"[65] ब्रिटिश शासन-काल के उन वर्षों में देशी और विदेशी पूंजी के हमलों के खिलाफ औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन पुनः 1926 के बाद के वर्षों में जोर पकड़ता जा रहा था। लीग एगेन्स्ट इम्पेरियलिज्म के साथ भारत का सम्पर्क सोवियत रूस के औद्योगिक विकास तथा यूरोप की अन्य घटनाएं ने भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रही थीं। 1928 और 1929 के बीच के मजदूर आंदोलनों तथा एतत संबंधी चलाई गई हड़तालों ने पुनः एक बार साम्राज्यवाद विरोधी भारतीय मुक्ति संग्राम में मजदूरों एवं किसानों की संयुक्त भूमिका को मुख्यधारा के रूप में ला खड़ा किया।[66] साम्राज्यशाही के दमन के कारण भी इन आंदोलनों की गति धीमी नहीं पड़ सकी है, बल्कि और ज्यादा जोर पकड़ती गई।

1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा ऐसी ही उदीयमान संघर्षों की देन थी और उसमें कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए किसान-संगठन को किसानों की दयनीय स्थिति के खिलाफ लड़ाई के एक मंच के रूप में खड़ा किया। "...... ..... राष्ट्रीय कांग्रेस ही ऐसी राजनीतिक संस्था थी जो भारतीय जनता की ओर से बोल सकती है ... ... अगर कांग्रेस किसानों की समस्या को अपने प्रोग्राम का आधार न बनाए तो उसके सार्वजनिक संस्था होने का कोई मतलब नहीं रह जाता।"[67]

किसानों के ऐसे संघर्षों का उठता ज्वार तथा कांग्रेस के भीतर का प्रगतिशील तबका के प्रयासों के फलस्वरूप ही 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन उन लोगों को लेकर किया गया जो किसान संघर्षों से संबंधित थे और जिनमें प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल याज्ञिक, मोहनलाल गौतम आदि थे और जिसकी अध्यक्षता स्वामी जी ने की। फैजपुर, कोमिल्ला, गया, पलासा, मखना, विजयवाड़ा में किसान सम्मेलन किए गए थे तथा कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के समय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी जी थे, जिन्होंने नेहरू और सुभाष बोस आदि के समर्थन से किसान समस्या पर प्रस्ताव पारित कराया।[68]

वास्तव में 1930 के दशक में फासीवाद के उदय तथा उसके खिलाफ किसान मजदूर एकता की धुरी के चारों तरफ अन्य वर्गों को संगठित कर एक फासीवाद विरोधी संघर्ष का जो नारा कमिन्टर्न की सातवीं कांग्रेस ने ज्यार्यी दिमित्रोव के नेतृत्व में 1935 में दिया था।[69] उसका असर भारतीय राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। इसी संदर्भ में स्वामी जी ने बुखारिन की विचार-धारा जिसमें

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्थापित किया था कि किसान प्रतिक्रांतिकारी होते हैं, स्वामी जी ने आलोचना की थी तथा सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर प्रमाणित किया कि पूंजीवाद के इजारेदार स्वरूप के सबसे निकृष्ट अभिव्यक्ति फासीवाद के खिलाफ संघर्ष में क्रांतिकारी भूमिका निरूपित करेगा के चिन्तन पर मार्क्स-लेनिन के विचारों के फलस्वरूप जन्मी क्रांतिकारी भावना[70] ने उन्हें साम्यवादियों के नजदीक ला खड़ा किया और सोवियत यूनियन के सफल वर्ग संचालित राज्य की परिकल्पना उन्हें समाजवादी राज्य के निर्माण को एक व्यावहारिक रूप प्रदान किया। वर्ग संघर्ष की अहमियत को स्वीकारते हुए उन्होंने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के खात्मे की दलील दी।

1939 के दूसरे विश्व युद्ध के भड़कने तथा सोवियत यूनियन पर हिटलर के हमले के बाद उन्होंने युद्ध को लोक युद्ध की संज्ञा दी, क्योंकि पूंजीवाद के साम्राज्यवाद के उच्चतर मंजिल में प्रवेश कर जाने के बाद विश्व बाजार के बंटवारे में शक्ति-प्रयोग का ही कारण था कि युद्ध भड़का था इसे स्वामी जी स्वीकार करते थे।

वामपंथ का प्रभाव

अपने जेल-प्रवास में स्वामी जी ने जिन मार्क्सवादी विचारों का अध्ययन किया जिनमें माओं-त्से-तुंग की किताबों का अध्ययन किया, जिसमें एक कम विख्यात कृति थी *"क्रांति और संयुक्त मोर्चा"* जिसमें मुख्यतः छापामार युद्ध की वकालत की गई थी। कम्युनिस्ट आंदोलन में यह पी.सी. जोशी का युग था तथा कम्युनिस्ट पार्टी एक रचनात्मक कार्यक्रम "अधिक अन्न उपजाओ" का नारा दे रही थीं, जिसके नाम पर किसानों को बड़ी-बड़ी रियायतें दी जा रही थीं। इस काल में स्वामी जी को एक दिशा-हीनता ग्रसित कर रही थी जिसके कारण अपने कार्यक्रमों को अन्जाम देने का प्रयास स्वामी जी नहीं कर रहे थे।

1943 में कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर राजनीतिक लाइन के संबंध में विवाद चल रहे थे, जिसमें बिहार की यूनिट चीनी नीतियों का समर्थन कर रही थी, परन्तु विभिन्न राजनीतिक दलों में कार्य करने के स्वामी जी का कटु अनुभव उन्हें इस पार्टी का सदस्य बनने से रोक रहा था। सर्वोपरि बात यह थी कि एक किसान जनवादी की सीमित चेतना ने उन्हें इस पार्टी में लाने से रोका था। परन्तु 1942 के दिनों में किसान सभा का नारा सी.पी.आई. से प्रतिबंध हटाओ, का समर्थन स्वामी जी कर रहे थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की नीति और कार्यशील, जो 1948 के पूर्व ऐ व्यापक जनवादी मोर्चा गठित कर मजदूर किसान राज्य की स्थापना की नीति चला रही थी, के प्रति स्वामी जी बचनबद्ध रहे मगर बी.टी. रणदिवे के नेतृत्व काल में जिस संकीर्णतावादी राजनीतिक लाइन को ग्रहण किया गया इसमें

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उनका अलगाव कम्युनिस्टों से होता गया। 1947 के बाद के वर्षों में जिस राजनीतिक स्थिति का सामना कांग्रेस कर रही थी वह था वर्गीय मांगों को लागू करने का।

किसान-मजदूरों की मांग कांग्रेस के वर्ग-स्वार्थ के खिलाफ जाती थी, इसलिए कांग्रेस ने सोशलिस्टों के सहमेल से कम्युनिस्टों के जनाधार पर हमला शुरु कर दिया था, और दूसरी तरफ सी.पी.आई. की अति दुस्साहसिकता की संकीर्ण राजनीतिक लाइन ने भविष्य में बनने वाले संयुक्त मोर्चे की संभावनाओं को समाप्त कर दिया और किसान सभा की एक ऐसे समुचित नीति, जो स्वतंत्र भारत में चलाई जा सके, न इजाद हो सकी। स्वामी जी ने कांग्रेस छोड़ दी तथा कम्युनिस्टों से दुराव बढ़ा लिया। मगर देश के भविष्य के लिए वामपंथ की एकता जो प्रयास उन्होंने जीवन के अन्तिम काल में किया भले ही वह असफल रहा था, किंतु बड़ा ही सराहनीय कहा जा सकता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

संदर्भ

1. स्वामी जी इस तिथि का पूर्णतः सही नहीं मानते देखे–"स्वामी जी की कलम सेः– जन्म और वाल्यावस्था" स्वामी सहजानन्द सरस्वती स्मृति ग्रंथ ब्रह्मर्षि समाज, कानपुर, मार्च 1986 पृ. 43
2. नवयुग, मार्च, 1990 पृ. 24
3. सुरेन्द्रनाथ दीक्षित, पूर्वोद्धत, पृ. 6-7
4. स्वामी सहजानन्द सरस्वती–मेरा जीवन संघर्ष, पृष्ठ 136
5. उपरोधृत, पृष्ठ 164
6. उपरोधृत, पृष्ठ 165
7. उपरोधृत पृ. 170
8. देखें, पूर्वोधृत पृ. 175
9. देखें स्वामी सहजानन्द सरस्वती, 'क्रान्ति और संयुक्त मोर्चे के टाइटिल पृष्ठ पर' कार्ल मार्क्स की यह उक्ति इन्डस्ट्रियल बुलेटिन इन इंडिया, न. 43, 1921-28, पृ. 44-45
10. चमन लाल रेड्डी , *दि इन्डियन ट्रेड यूनियन मुवमेन्ट : इन आउट लाइन हिस्ट्री, 1880-1947*, (आरियन्ट लौंग मैन, 1972) पृ. 27-28 तथा भी.वी. कारनिक, *इन्डियन ट्रेड यूनियन : ए सर्वे*, द्वितीय संस्करण (मानक वाला, बाम्बे) पृ. 6-8,
11. विपन चन्द्रा, राइज एंड ग्रोथ आफ इकोनोमिक नेशनालिज्म इन इंडिया (पी.पी. एच., दिल्ली, 1977) पृ. 15-17
12. *कांग्रेस अधिवेशन प्रथम का दस्तावेज*, पृ. 3-4
13. *आफिसियल रिपोर्ट आफ दि कांग्रेस*, 1886, पृ. 5-6.
14. बी.बी. बालबुशेविच और ए.एम. दयाकोव, *कान्टेम्परेरी हिस्ट्री आफ इंडिया* (पी.पी.एच. दिल्ली (1964), पृ. 7-8.
15. *आफिसियल रिपोर्ट आफ दी कांग्रेस*, 1887, पृ. 18.
16. बी.पी. बालाबुशेचिव एंड ए. एम. दयाकोव, पूर्वोद्धृत पृ. 7-8 और देखें दादा भाई नौरोजी, *पोभर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया* (पब्लिकेशन डिविजन, मिनिस्ट्री आफ इनफार्मेशन एंड ब्रोडकास्टिंग, भारत सरकार, भारत सरकार प्रेस, नासिक रोड, जुलाई 1962).

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

17. *ओल्ड मैन्स होप*, ह्यूम द्वारा जारी एक पम्पलेट-1889, देखें- रजनी पाम दत्त *पूर्वोद्धृत* पृ. 323, *ओफिसियल रिपोर्ट आफ दि कांग्रेस*, 1888 तथा सर विलियन बेडर, *एलान ओक्टावियन ह्यूम फादर आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस*, 1913 पृ. 61-62.
18. *रॉयल कमीशन आन लेवर इन इन्डिया*, इभीडेन्स, भाग-V, पार्ट-I
19. उपरोद्धृत, पृ. 7.
20. अशोक कुमार, *पूर्वोद्धृत*, पृ. 27.
21. उपरोद्धृत.
22. के. दामोदरन, *भारतीय चिंतन परम्परा* (हिन्दी), पी.पी.एच. प्रा. लिमिटेड, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-55, पृ. 214.
23. त्रिवेणी शर्मा सुधाकर, *स्वामी सहजानन्द सरस्वती स्मृति-ग्रंथ*, पृ. 62.
24. सुधाकर, *स्मृति ग्रंथ*, पूर्वोद्धृत, पृ. 63.
25. *उपरोद्धृत*.
26. भी.सी.पी. चौधरी, पूर्वोद्धृत, पृ. 42.
27. अस्फाक अन्जुम, पूर्वोद्धृत, पृ. 43 "औद्योगीकरण साम्राज्यवादी सामंती गठजोड़ का शिकार" कोटेड- स्वामी सहजानन्द सरस्वती- जमींदारी क्यों उठाई जाए? से उद्धृत.
28. उपरोद्धृत. पृ. 43.
29. आर.एच. टोली, *एग्रेरियन प्राबलेम्स इन सिक्सटींथ सेन्चुरी*, कार्ल मार्क्स, *कैपिटल* खंड-1, अध्याय-8.

    जे.डी. चैम्बर्स तथा जी.ई. मेंजी, एग्रिकल्चरल रिवोल्यूसन 1750-1880 (लन्दन 1966).
30. देखें, एस. शिवसुब्रमण्यम, "स्टीटमेट्स आफ अन आउटपुट फॉर आनडीवाइडेड इंडिया" जोसिन एग्रीकल्चरल ट्रेन्डस इन इंडिया, पेपर्स आन नेशनल इनकम एंड एलायड टापिक्स खण्ड-1, लन्दन-1960).

    ए.के. बागची, "प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया" (आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस)
31. पूर्वी यूरोप में दूसरी भू-दासता के संदर्भ में मार्क्स और ऐंगिल्स ने दासता के बंधनों को मजबूत करने में व्यापारीकरण की भूमिका की ओर ध्यान खींचा था। इस संदर्भ में यूरोपीय इतिहास से उदाहरण दिए हैं।

    एम. डाब, '*स्टडीज इन डेवलपमेंट आफ कैपिटलिज्म*' (टाटलेज एण्ड के नागपाल,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

लंदन-1959) और देखें- आर हिल्टन सम्पादक दि *ट्रान्जिसन फ्राम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म'* (मोरिस डॉव, एम. स्वीजी, ताकाहासी आदि की बहस)

32. लेनिन, "लैण्ड रिलेसन एण्ड रुरल पुअर" संकलित रचनाएं, खण्ड-19, "एग्रेरियन रिलेसन इन एशिया टुवर्डस द क्लोज आफ नाइन्टीन्थ सेन्चुरी" उपरोद्धृत, "प्रोग्राम आफ सोशल डेमाक्रेसी दे फस्ट रशियन रिवोल्यूसन" उपरोद्धृत, खण्ड-13.
33. अशोक कुमार- पूर्वोद्धृत, पृ. 27.
34. रजनी पाम दत्त, पूर्वोद्धृत, पृ. 33.
35. उपरोद्धृत.
36. देखें, 1892 में कांग्रेस महाअधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का भाषण.
37. रजनी पाम दत्त, पूर्वोद्धृत पृ. 334.
38. एज आफ कन्सेट बिल भारत में चलाए जा रहे पुनर्जागरण के आंदोलनों के दबाव तले बाल विवाह के खिलाफ एक कानून था जिसमें ऐसा प्रावधान था कि लड़की की उम्र 10 साल के बजाय 12 साल हो जाने के बाद ही उसका पति उसके साथ सहवास कर सकता था। ब्रिटिश सम्राज्यवाद के द्वारा उठाया गया यह एक प्रगतिशील कदम था जो इस तरह की सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सुधार का प्रयत्न करता था।
39. चितरंजन शर्मा, राइज एंड ग्रोथ आफ दि मिड्डल क्लास इन बिहार (1858-1905) (पी.एच.डी. थेसिस, पटना यूनिवर्सिटी) अप्रकाशित और सम्पादक भी.सी.पी. चौधरी, पूर्वोद्धृत, पृ. XIV.
40. द हिन्दू पेट्रीयट, 7 अप्रैल, 1879.
41. सम्पादक वी.सी.पी. चौधरी, पूर्वोद्धृत, पृ. XV.
42. प्रभात गंगोपाध्याय- एन्टी पार्टिशन पेपर्स भारतीय राष्ट्रीय इतिहास खासरा, पृ. 44.
43. सी.एफ. वर्क लैण्ड, *बंगाल अन्डर दी लेफिटनेन्ट गवर्नर.*
44. दीनानाथ वर्मा और विरेन्द्र शुक्ल, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और संवैधानिक विकास, (भारती-भवन, 1977), पृ. 151.
45. एन.ए. सिमोनिया, हिस्ट्री आफ दि केपिटालिज्म इन दि ओरियंट (मास्को, 1985), पृ. 7-8. हनुमंता राव और पी.सी. जोशी "पालिटिकल स्टाविलिटी ऐट सेन्टर" मेनस्ट्रीम, 4 अगस्त, 1989.
46. लाला लाजपत राय, राइटिंग्स एंड स्पीचेज खंड-1 (दिल्ली, 1966), पृ. 54.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

47. दादा भाई नौरोजी, प्रेसिडेन्सियल एड्रेस टू दि सेकेन्ड सेसन आफ दि कांग्रेस.
48. के. दामोदरन, भारतीय चिन्तन परम्परा (पी.पी.एच. दिल्ली), पृ. 385.
49. देखें, भी.सी.पी. चौधरी, इम्पेरियल पोलिसी आफ ब्रिटिश इण्डिया 1976-1880.
50. सम्पादक भी.सी.पी. चौधरी, ओंकार से हुंकार तक, पृ. XI.
51. सहजानन्द सरस्वती, 'किसानों को फंसाने की तैयारियां', पृ. 4-5.
52. उपरोद्धृत, पृ. 13.
53. उपरोद्धृत, पृ. 22.
54. उपरोद्धृत, पृ. 38.
55. उपरोद्धृत, पृ. 38.
56. सम्पादक, महाचन्द्र प्रसाद सिंह, *ज्योति कलश*, जीवन गाथा, पेज-24.
57. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, 'झूठा भय मिथ्या अभिमान', हितचिन्तक प्रेस, रामघाट, काशी, पृ. 7.
58. उपरोद्धृत, पृ. 7-8.
59. उपरोद्धृत, पृ. 24.
60. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, 'महारुद्र का महाताण्डव', पृ. 2.
61. उपरोद्धृत, पृ. 5.
62. होरेन मुखर्जी, इंडियन स्ट्रगल फार फ्रीडम (पी.पी.एच., दिल्ली) पृ. 173.
63. *होम डिपार्टमेन्ट, बंगाल न्यूज पेपर्स सलेक्सन, जनवरी* टू *जून*, 1922
अमृत बाजार पत्रिका, (कलकत्ता) 12, मार्च, 1922.
आनन्द बाजार पत्रिका, (कलकत्ता), 13 मार्च, 1922.
हिन्दुस्तान, (कलकत्ता) 13 मार्च, 1922
64. *होम पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट,* फाइल न. 459/1921.
65. बिहार प्रांतीय किसान सभा का घोषणा पत्र, पृ. 5.
66. जवाहरलाल नेहरू, आटोबायोग्राफी, पृ. 166,
सलेक्टेड वर्क्स आफ जवाहरलाल नेहरू, वौल्युम 2, पृ. 272-76.
67. *बिहार प्रांतीय किसान सभा का घोषणा पत्र*, पृ. 4.
68. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, रेन्ट *रिडकसन* इन बिहार : हाउ इट वर्क्स.
69. *दत्त- बेडले थेसिस आन इंडिया,* 1935.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

70. डाक्टर श्याम बिहारी राय, पूर्वोद्धृत, पृ. 60.
सहजानन्द सरस्वती, '*क्रांति और संयुक्त मोर्चा*', (श्रमजीवी पुस्तकमाला, बांकीपुर) अध्याय "किसान और क्रांति".

नोटः

चौरी-चौरा के बाद कांग्रेस कार्य समिति का आन्दोलन वापस लिये जाने के प्रसंग में देखें–

इन्डिया 1921.22, एपेन्डिक्स-XI
दैनिक *बासुमती* (कलकत्ता) 3 और 18 फरवरी, 1922.
अमृत बाजर पत्रिका, (कलकत्ता) 14, फरवरी, 1922.
नांगली, (कलकत्ता), 14, फरवरी, 1922.
बंगाली, (कलकत्ता), 14, फरवरी, 1922.
नायक, (कलकत्ता), 15, फरवरी, 1922.
स्वराज, (कलकत्ता), 15, फरवरी, 1922.
महम्मदी, (कलकत्ता), 16, फरवरी, 1922.
प्रभाकर, (कलकत्ता), 16, फरवरी, 1922.
इन्दु प्रकाश, (बाम्बे), 14, फरवरी, 1922.
सरभेन्ट ऑफ इन्डिया, (पूना) 2, मार्च, 1922.
महाराठा, (पूना), 6 मार्च, 1922 केशरी, (पूना), 28 फरवरी, 1922.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-3

स्वामी जी के आर्थिक दर्शन के आयाम

आर्थिक दर्शन के आधार पर स्वामी सहजानन्द सरस्वती की प्रतिबद्धता अर्थशास्त्र की किस शाखा के प्रति थी- पूंजीवादी या समाजवादी–एक ऐसा प्रश्न है जो स्वामी जी के आर्थिक दर्शन के आयाम को स्पष्ट से स्पष्टतर करता है। दर्शन जिसे एक विश्व दृष्टिकोण के रूप में सभी स्वीकार करता है और मानता है कि उत्पादन की शक्तियों के साथ किसी काल विशेष या देश विशेष में खास किस्म के संबंध की हिमायत करना, किसी दल, व्यक्ति या व्यक्ति समूहों का आर्थिक दर्शन होता है, तो स्वामी सहजानन्द सरस्वती किस तरह के आर्थिक दर्शन की हिमायत करते थे?

वास्तव में दर्शन की जिन मुख्य प्रणालियों या प्रकारों को आज सम्पूर्ण विश्व के अर्थतंत्र में स्वीकारा जा रहा है वे मुख्यतः दो प्रकार की हैः- पूंजीवाद तथा समाजवाद, और किसी समाज, देश या क्षेत्र में, उत्पादन की शक्तियों के साथ सम्पूर्ण समाज के संबंधों को अपनी खास दार्शनिक पद्धति के मुताबिक संगठन करती है। अध्यात्मवादी दर्शन एक पारलौकिक सत्ता द्वारा सृजित इस संसार को अबोधगम्य साबित करते हुए स्थापित करता है कि सम्पूर्ण समाज में उसकी तमाम संस्थागत स्वरूप का निरूपण भी इसी अदृश्य शक्ति का फल है जिसे परिवर्तित करना न तो मनुष्य के वश में है और न उसके लिए उचित ही। सामान्य तौर पर मानवीय समाज की आंतरिक एवं बाध्य सरंचनाओं के स्वरूप में प्रतिबिम्बित होता है।

19वीं सदी के उतरार्द्ध में हुई आर्थिक प्रगति ने जिसने विज्ञान से लेकर तमाम संस्थागत संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर एक नए दर्शन के आविर्भाव किस पृष्ठभूमि का सृजन किया उसके फलस्वरूप हालांकि वर्ग हितों के आपसी टकराव का सिद्धांत सर्वप्रथम रिकार्डो ने दिया था, मगर वर्ग-संघर्षों से उत्पन्न क्रांतियों के विश्लेषण तथा सिद्धांतों के वैज्ञानिक निरूपण का श्रेय मार्क्स, एंजिल्स, लेनिन को जाता है, जिन्होंने स्थापति किया कि वर्गीय समाज में उत्पादन के साधन इस आंतरिक सरंचना को जन्म देते हैं जिनके द्वारा समाज की बाह्य सरंचना का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वरूप निर्धारित होता है। सम्पति या उत्पादनों के साधनों का व्यक्तिगत प्रणाली पूंजीवादी सामाजिक संरचना को जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की मनोगत स्थितियां पैदा करता है- जन्म देता है और सामूहिक स्वामित्व की प्रणाली में मानव श्रम अपनी समस्त अभिव्यक्तियों के साथ शोषण मुक्त रहता है।

आर्थिक दर्शन की पूंजीवादी तथा समाजवादी प्रणालियों में स्वामी सहजानन्द सरस्वती किस दार्शनिक-आर्थिक शाखा का प्रतिनिधित्व करते थे और क्यों, यह प्रश्न उनके जीवन के विविध आयामों से प्रकट हो जाता है। वास्तव में, स्वामी जी मार्क्सवादी दर्शन में प्रदत्त आर्थिक समाज की अवधारणा के एक मूल प्रहरी हैं जिन्हें भौतिक परिस्थितियों के अनुभवजन्य परिणामों के फलस्वरूप यह चिन्तन स्वीकार्य हुआ।

औपनिवेशिक भारत की कृषि

औपनिवेशिक भारत में उद्योग तथा कृषि के संबंध में अपनाई गई साम्राज्यवादी नीतियों का परिणाम था कि पूर्व ब्रिटिश स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिकीकृत साम्राज्यशाही के उत्पादन-संबंधों के साथ प्रतिस्पर्द्धा न कर समाप्त हो गया। मगर आधुनिक उद्योगों के भारत में विस्तार को साम्राज्यवाद द्वारा जान-बूझकर विकसित न होने देने के कारण विकास की गति उन यूरोपीय देशों की तुलना में, जिन्होंने मशीनकृत उत्पादन की प्रणाली को जन्म दिया था, ठीक उल्टा भारत में हुआ। जिस पूंजीवाद ने यूरोपीय मुल्कों में विकास प्रक्रिया को तेज किया, सामंतवाद के खात्मे के बाद औद्योगिकीकरण की प्रणाली विकसित की, वही पूंजीवाद भारत में प्रतिक्रियावादी विकास की गति को जन्म दिया, नये उद्योग खुले नहीं, भारतीय हस्तकरघा चौपट हो गया जिसके कारण खेती पर जन दबाव का बढ़ जाना तथा श्रम शक्ति को पेशागत वितरण अधिक-से-अधिक, ज्यों-का-त्यों बना रह जाना तथा, प्राथमिक क्षेत्र पर इसके बोझ में थोड़ी बढ़ोत्तरी हो जाना स्वाभाविक परिणति थी।[1]

स्वामी जी ने देखा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इस प्रतिक्रियावादी आर्थिक नीति के चलते जमीन से अपनी रोजी कमानेवाली आबादी की संख्या तेजी से बढ़ी थी और भूमि तथा उस पर निर्भर आबादी के अनुपात में गिरावट आई थी।[2] जिसके परिणामस्वरूप एक बहुत ही कम रोजगार पर निर्भर आबादी पैदा हो गई थी, जिसने अप्रवासियों के रूप में भूमि के लगानों को भुखमरी के लगानों की ऊंचाई पर पहुंचा दिया था और कर्ज गुलामी को स्वीकार किया था। विकास की इस शैली ने मजदूरों के रूप में जैसे-तैसे करके पेट भरने तक सीमित मजदूरी एवं कर्ज गुलामी को स्वीकार किया था। आजादी के पहले के दौर की जानी-पहचानी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जमींदार-महाजन-व्यापारी त्रिमूर्ति ने किसानों पर अपना शिकंजा कड़ा कर दिया था जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति की भांति यहां कभी तीनों ग्रूप एक ही मूर्ति में समाहित होते थे, तो कभी गुणों की अलग-अलग मूर्तियां होती थी। इस प्रकार कृषि-विकास में उत्पादक निवेश के लिए एक जबरदस्त अवरोध खड़ा हुआ था तथा पूर्व ब्रिटिश काल का भू-लगान भारत में कृषि विकास के लिए निवेश की राह रोक रहा था।

स्वामी जी अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में कृषि शायद ही कभी अपने अंतर्निहित घटना क्रम से आगे बढ़ती है, बल्कि उसके लिए किसी बाहरी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है जिसमें बाजार का बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। स्वामी जी का ऐसा विश्लेषण इस तथ्य का गवाह है कि स्वयं ब्रिटेन में सोलहवीं सदी में ट्यूडर राजाओं के शासन-काल में कृषि बाड़े और खाद्यान्नों की बढ़ती घरेलू मांगों से प्रेरित थे।[3] आजादी पूर्व भारत के जिन सात दशकों के, जिन दशकों में स्वामी जी आंदालनों की तरफ मुखातिब हुए थे, आंकड़ों की एक गौर तलब बात यह है कि इन दशकों में खाद्यान्नों के लिए घरेलू बाजार में उल्लेखनीय गतिरोध बना रहा था जबकि कृषि उत्पादन में 80 फीसदी हिस्सा इन्हीं खाद्यान्नों का था। कुल मिलाकर खाद्यान्नों का उत्पादन जहां-का-तहां बना रहा था और प्रति व्यक्ति उत्पादकता में कमी आई थी। इसी तरह हर क्षेत्र में यहां तक कि पंजाब जैसे गतिशील इलाकों में भी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में गिरावट आई थी।[4] कर राजस्व का एक हिस्सा विदेश भेजा जा रहा था और तबादला उसके मूल्य के बराबर के मालों के निर्यात के जरिये होता था। इसके लिए निर्यातों को बढ़ावा देने की औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के अंतर्गत, सिर्फ निर्यात योग्य वस्तुओं या प्राथमिक मालों के औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के अंतर्गत, सिर्फ निर्यात योग्य वस्तुओं या प्राथमिक मालों के उत्पादन में बढ़ोतरी ठीक ठाक हुई थी और इन मालों में गेहूं भी शामिल था।[5]

स्वामी जी के काल में खाद्यान्नों के घरेलू बाजार का अवरुद्ध रहना औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत के हितों को ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतों के अधीन रखना, एक खास ढंग की घरेलू वित्त, मुद्रा तथा व्यापार नीतियों को यहां लागू करना था। चूंकि हर साल कर राजस्व का एक खासा हिस्सा विदेश भेज दिया जाता था। सरकार वास्तव में फायदे का बजट चला रही थी और इसका घरेलू बाजार पर या अर्थव्यवस्था पर मंदी का असर पड़ रहा था। यह साल दर साल बढ़ता चला जा रहा था चूंकि ये निर्यात कराधान में से खिराज की अदायगी के रूप में थे, घरेलू

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अर्थव्यवस्था पर उनका शायद ही कोई प्रेरणादायक असर होता था। ऐसा इसलिए और भी था कि निर्यात योग्य व्यापारिक फसलें खाद्यान्नों की पैदावार के ऊपर से पैदा नहीं हो रही थीं, बल्कि खेती की पर्याप्त जमीन के अभाव में बहुत हद तक खाद्यान्नों के बदले में पैदा हो जाती थी।[6]

1793 के स्थायी बंदोबस्त में भी अधिशेष का बड़ा अंश कम्पनी को ही जाता था, शेष का थोड़ा भाग जमींदारों तथा दूसरे बिचौलियों और हस्तांतरित भूमि के धारकों को प्राप्त होता था। अर्थव्यवस्था पर इन बातों का प्रतिकूल असर पड़ा। अधिशेष पर जिनका भरण-पोषण होना था ऐसे अनेक प्रकार के कारीगरों, शिल्पियों, सैनिकों परिचारकों आदि का संकट बढ़ा था तथा सम्पति का स्थानानांतरण भारतीय जिन्सों के रूप में निर्यातित होने लगा था।

स्वामी जी ने किसानों पर पड़ने वाले दबाव को भारतीय ग्राम समुदाय के विनाश के रूप में ठीक वैसे ही देखा था जिस तरह कार्ल मार्क्स ने–ग्रामीण समाज अपने भीतर काफी स्तरीकरण ही खेतिहरों तथा बहुसंख्यक खेत विहीनों और मजदूरों पर उच्च किसानों और छोटे जमींदारों की प्रभुता छिपाये बैठा था। चूंकि ब्रिटिश शासक भू-राजस्व को अधिकतम करना चाहते थे, और ऐसा करने में वे सक्षम भी थे, इसलिए वे गांव की एक राजस्वदाता इकाई के रूप में उपेक्षा नहीं कर सकते थे जो कि पूर्व के शासक नहीं रह सके थे। खेत-मजदूर उच्च किसान वर्ग से प्राप्त मजदूरी पर जीवन-यापन करते थे, अतः उच्च किसान वर्ग अपने ऊपर पड़नेवाले आर्थिक दबाव को और भी तीखेपन से मजदूरों पर टाल रहे थे।

मार्क्स की तरह ही स्वामी जी ने देखा कि भारतीय सामंतवाद की अपनी अलग विशेषता थी, जिसे मार्क्स ने एशियाई उत्पादन प्रणाली की संज्ञा दी थी और इसके कारण पूंजीवादी विकास की ढेर सारी समस्यायें थीं। ब्रिटिश शासन-काल में भू-संबंधों की जो परिणति हुई उसमें जमीन बिकाऊ माल बन गई, लगान वस्तु के बदले मुद्रा लगान का रूप ग्रहण किया तथा मुद्रा आधारित अर्थ व्यवस्था ने पौराणिक आर्थिक संबंधों को बिल्कुल ही बदल दिया।

कृषि क्षेत्र में लागू की गई नई व्यवस्था ने एक नए जागीरदार वर्ग को पैदा किया था जिसे स्वामी जी ने नजदीक से देखा था। इनसे सरकार जितना रेन्ट लेती थी वह तो निश्चित था मगर खेतिहारों से जो भू-राजस्व उन्हें वसूलना था वह निश्चित नहीं था, इसे भू-स्वामियों को तय करना था। अतः फसल मारी जाने पर भी खेतिहारों को राजस्व तो देना ही था। भू-राजस्व की नगदी उगाहियों के कारण तथा मनमाना कराधान की छूट की वजह से किसानों को असह्य भू-राजस्व अदायगी के लिए महाजनों की शरण में जाना पड़ा जो पहले ऐसा नहीं होता था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सूदखोरी की इस प्रथा ने जमींदारों से सहमेल कर ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें किसान उत्तरोत्तर गरीब होते गए।

स्वामी जी के आर्थिक चिन्तन का प्रादुर्भाव

वास्तविकता यह है कि किसान-आंदोलन का एक वर्ग समन्वयवादी आंदोलन गांधी ने 1917 के अपने चम्पारण-आंदोलन से शुरु किया जहां एक व्यावसायिक फसल नील के उत्पादन में साम्राज्यवादी नीतियों के तहत किसानों से कई तरह गुलामी निलहे कोठीदार ले रहे थे। एक उदार पूंजीवादी नेता की तरह गांधी ने जिस संघर्ष का आहवान किया इसमें साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ किसानों को कुछ रियातें प्राप्त हो सकी। किसी मौलिक भू-सम्बन्धों के परिवर्तन की चर्चा गांधी ने नहीं की थी। उसी प्रकार 1918 का खेड़ा किसान आंदोलन चम्पारण के किसान-आंदोलन से थोड़ा प्रगतिशील था, क्योंकि इसमें भू-राजस्व कम कराने की मांग की गई थी, परंतु यह मांग सरकार से की गई थी जो राजस्व का एक हिस्सा लेती थी, जमींदारों के खिलाफ किसी मांग को गांधी ने नहीं उठाया था। फिर भी किसानों के बड़े तबके में भू-राजस्व द्वारा इनके शोषण की जटिल प्रक्रिया का एहसास हुआ और किसानों ने भारतीय मुक्ति का आंदोलन की मुख्य धारा में प्रवेश करने के एक क्रम को शुरु किया। किसानों की बदहाली तथा जमींदारों के शोषण के प्रति गांधी कितने उदास थे, इसका प्रमाण तो उनके एक ही वक्तव्य से मालूम हो जाता है, उन्होंने कहा था "असहयोग आंदोलन से किसान-आंदोलन को उत्साह मिला है। हम किसानों को सरकार को कर नहीं देने का अनुरोध करने में नहीं हिचकिचायेंगे। मगर असहयोग के किसी दौर में जमींदारों को रेन्ट नहीं मिले, इसकी तरफदारी नहीं करेंगे। किसान आंदोलन को किसानों की स्थिति अच्छी करने तथा उनके और जमींदारों के बीच अच्छा रिश्ता रखने तक ही सीमित रखना है।"[7]गांधी का यह असहयोग-आंदोलन उस अवधि का है जब स्वामी जी गांधी-दर्शन से प्रभावित होकर राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन में एक सचेष्ट प्रयास का नेतृत्व कर रहे थे जो साम्राज्यवाद विरोधी था।

किसानों के किसी क्रांति आंदोलन को, जो वर्ग आधारित स्वरूप ग्रहण कर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की एक कड़ी बन सके, गांधी ने हमें हतोत्साहित किया, मगर गांधी के बयान और किसानों के अपने वर्गीय स्वार्थों के बीच पैदा हुआ अंतर्विरोध इन तमाम मान्यताओं का उल्लंघन कर दिया जिनको गांधी ने जमींदारों के हक में प्रतिपादित किया था। वे शोषण और उत्पीड़न के सबसे नजदीकी जिम्मेवार जमींदारों एवं महाजनों के खिलाफ उठ खड़े हुए, तथा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

लगान-बंदी की क्रांतिकारी कार्रवाई तक आगे बढ़ गए। औपनिवेशिक शासन-काल की मुद्रा, वित्त, व्यापार, कर प्रणाली आदि के द्वारा ग्रामीण हलकों के शोषण की निरंतर प्रक्रिया तथा गांधी के विचारों का समन्वयवादी रुख का अंतर्विरोध स्वामी जी के सामने था- प्रश्न था कि वर्ग संघर्ष को आगे बढाया जाय या समन्वयवाद के तले किसानों की जमींदारी तथा सरकार द्वारा अपनाई गई नृशंस शोषण-प्रणाली के तहत पीड़ित छोड़ दिया जाए। इस अन्तर्द्वन्द्व में स्वामी जी का आर्थिक चिंतन वर्षों उलझा रहा, अभी भी वे गांधीवादी थे जिनका उद्देश्य किसान सभा का गठन किसानों के वर्ग संघर्ष को तेज करना नहीं अपितु ग्रामीण इलाके में फैलते तनाव को कम करना था, और वह वर्ग-समन्वय-द्वारा ही हो सकता था। स्वामी जी ने स्वीकार किया है, "किसान-सभा बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल प्रचार एवं आंदोलन के जरिए किसानों का दुख दूर करना था और किसानों तथा जमींदारों के बीच झगड़े खत्म करना था। क्योंकि ये झगड़े भड़क सकते थे और उनसे आजादी की लड़ाई में सभी लोगों की एकता टूटती। इसलिए किसान-सभा का संगठन बनाते समय मैं पूरा समझौतावादी था।"[8] इस तरह प्रारंभ में किसान-आंदोलन का स्वरूप समझौतावादी था। 1922-23 में मुंगेर में जिस किसान-सभा का गठन शाह मुहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किया गया उसका दृष्टिकोण भी वर्ग समन्वयवादी ही था, मुख्यतः बेगार प्रथा के खिलाफ तथा जमींदारों को सिंचाई प्रबंध के लिए बांधों के निर्माण हेतु उत्साहित करना, परंतु इन संगठनों को भी गांधी ने वर्गीय मांगों के लिए संघर्ष करने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि गांधी का उदारवाद तथा कांग्रेस का सत्याग्रह संबंधी राजनीतिक विचार इस तरह के संघर्षों को रोकने में मूल कारक की भूमिका निभा रहे थे। 1921 में ही उत्तर प्रदेश के किसानों को संघर्ष से रोकते हुए गांधी ने कहा था कि "आप सबों को कुछ हद तक जमींदारों की यातना को बर्दाश्त करना चाहिए, हम लोग जमींदारों से संघर्ष नहीं करना चाहते .... जमींदार भी गुलाम है। अतः हम लोग उन्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहते।[9] भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के प्रति कांग्रेस,जिसके नेता गांधी थे, के ऐसे विचार कांग्रेस संगठन की आर्थिक नीतियों को विश्लेषित करते थे जिन्हें आधार बनाकर कांग्रेस एक साम्राज्यवादी विरोधी क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। हालांकि साम्राज्यवाद विरोधी तमाम वर्ग-शक्तियों का एक विस्तृत मोर्चा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था, परंतु ब्रिटिश साम्राज्यशाही के खिलाफ किसानों की विस्तृत और व्यापक आबादी को, जो सम्पूर्ण जनसंख्या का 80 से 90 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता था, वर्ग स्वार्थ को छोड़ साम्राज्यवाद

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के एक विशेष अंग के रूप में कार्यरत जमींदार वर्ग को अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण छूट देने की गांधीवादी नीति के प्रति स्वामी जी संशकित थे।

फिर भी, अन्य कांग्रेस नेताओं की तरह स्वामी जी किसान-सभा के मूल उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट नहीं थे, हालांकि कतिपय वामपंथी नेताओं ने एक संगठन वर्क्स एण्ड पीजेन्ट्स पार्टी का गठन 1923-24 के वर्षों में ही कर एक किसान वर्गीय विचार धारा के प्रतिपादन में योगदान किया था। स्वामी जी का आर्थिक दर्शन शुरु के दिनों में किस तरह समन्वयवादी था इसका उदाहरण बिहार प्रांतीय किसान सभा के, जिसके निर्माण में स्वामी जी की अहम भूमिका रही थी, से विधान के दूसरे अनुच्छेद में किसान-सभा की संगठित शक्ति और अहिंसात्मक विधि द्वारा किसानों पर अत्याचारों और उनकी शिकायतों को दूर करने के संबंध में व्यवस्था कर दी गई थी। किंतु तत्कालीन और दीर्घकालीन किसानों की मांगों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। इसके समय ही भू-राजस्व, ग्रामीण ऋणग्रसतता और जमीन की बेदखली के संबंध में यह अनुच्छेद पूर्णतः मौन था। इस तरह के वर्ग साम्राज्वाद के तहत किसान-सभा बिहार में 1934 तक कार्यरत रही तथा कई बार इसमें संशोधन लाया गया।

कांग्रेस की ऐसी किसान-विरोधी तथा जमींदार-पक्षी आर्थिक नीति के कारण किसान पस्त हिम्मत थे, परंतु स्वामी जी के चिंतन पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा था तथा उनका गांधीवादी दर्शन, जो अहिंसा को मूलभूत अंग मान कर प्रस्थान करता था, अपना प्रभाव खोने लगा। स्वामी जी ने आर्थिक दर्शन में बदलाव उनकी उस अवधारणा पर अंतर्निहित हुई जो दर्शन के मार्क्सवादी विचारों के प्रति कृतकल्प हुआ। अब स्वामी जी के जीवन को हिंसा पर आधारित तथा किसान-सभा को किसानों की भूख, गरीबी और गुलामी के संघर्ष का मंच मानने लगे।

अब स्वामी जी ने दार्शनिक आयाम में हुई प्रगति से वर्ग-युद्ध की हिंसा को हिंसा कहने वालों को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर हिंसा का अर्थ खत्म करना है, जैसा कि कुछ अहिंसावादी पूंजी और जमींदारों के नाश को हिंसा कहते थे, "तो सभी दुर्गुणों का नाश साम्राज्यशाही का अन्त आदि सब हिंसा है। यदि प्राणियों का नाश हिंसा हो तो सत्याग्रह, असहयोग आदि के करते जितने मरते हैं सभी हिंसा के पेट में आकर उसे हिंसामय बना गए"।[10] स्वामी जी ने वर्ग-युद्ध के आर्थिक दर्शन का परिमार्जित अर्थ पेश किया और कहा कि वर्ग युद्धवादी हिंसा नहीं चाहते। वे निरंतर होने वाली हिंसा के आधार पर आधारित आर्थिक-सामाजिक पद्धति को बदलना चाहते हैं। यही वह बिन्दु है जहां दार्शनिकता के आधार पर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी जी गांधीवाद से अलग हो गए क्योंकि गांधीवादी अवधारणा आर्थिक संबंधों की व्याख्या में यथास्थितिवादी था और स्वामी जी इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि यदि गरीब लड़ने की बात छोड़ भी दे तो भी शोषक अपनी क्रिया में आंशिक हत्यायें रोज करेंगे, इसलिए वर्गवाद को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता।

मार्क्सवादी दर्शन के प्रति स्वामी जी का रुझान

कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को स्वामी जी ने स्वीकार किया तथा मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत- वस्तु/मुद्रा=वस्तु[11] के आधार पर स्वामी जी ने स्थापित किया कि प्राचीन भारतीय स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था मुख्यतः इसी सिद्धांत पर चलती थी जहां अतिरिक्त मूल्य उत्पादन का प्रश्न गौण था। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय आर्थिक जीवन ने जब पूंजीवाद को प्रवेश करा दिया तो इस वस्तु विनिमय प्रणाली का स्वरूप मुद्रा/वस्तु=मुद्रा का रूप ग्रहण कर कृषि को भी प्रभावित करने लगा। ऐसी उत्पादन-प्रक्रिया में पूंजी का महत्व इतना बढ़ गया कि आर्थिक क्रिया द्वारा प्राप्त लाभ का वृहत्तर भाग पूंजीपति की मुट्ठी में केंद्रित होने लगा और लघुतर भाग आया मजदूरों के हिस्से, जो उत्पादन का वास्तविक स्रष्टा हैं। उत्पादन के साधनों एवं अन्य बाह्य संरचना में हुए विकास केंद्रित होने लगा और लघुतर भाग मिला श्रमिक समुदाय को जो यथार्थ में असली उत्पादक हैं। इसके फलस्वरूप जो वृहत्तर मानव समाज अर्थात श्रमिक समाज है, वह निरंतर वंचित होने लगा। इस बचना के विरोध में सर्वाधिक सबल आवाज उठी कार्ल मार्क्स के माध्यम से और आर्थिक चिंतन के इस प्रश्न पर कि उत्पादन और लाभ पर स्वामित्व किसका हो, आर्थिक चिंतक वर्ग दो गुटों में बंट गया। एक वर्ग की दृष्टि में इस पर स्वामित्व परम्परागत रूप में व्यक्ति अर्थात पूंजीपति का होना चाहिए। दूसरे वर्ग की दृष्टि में यह स्वामित्व "समाज" को अर्थात् श्रमिक समुदाय को जाना चाहिए।

स्वामी सहजानन्द सरस्वती चिंतन की इस धारा में अपने सर्वहारा दर्शन के साथ उस कतार बंदी में शामिल हो गए, जिसमें मार्क्स-लेनिन की विचारधारा वाले खड़े थे। विचारों के ऐसे संक्रमण के बाद स्वामी जी के सम्पूर्ण साहित्य में इस दृष्टि का प्रतिपादन मिलता है। *मेरा जीवन संघर्ष, किसान कैसे लड़ते हैं, क्रांति और संयुक्त मोर्चा* आदि तो स्पष्टतः किसान-आंदोलन का इतिहास रचते हैं। उनके गहन आध्यात्मिक चिंतन की पुस्तक '*गीता-हृदय*' में भी उनके राजनैतिक-आर्थिक विचारों की गहरी छाप मिलती है। ये सारे तथ्य इस बात का संकेत देते हैं कि स्वामी जी दूसरे वर्ग में आते हैं। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मार्क्सवाद उनके आर्थिक और राजनैतिक चिंतन पर सर्वथा हावी रहा है। इसी आधार पर कुछ लोग इन्हें कम्युनिस्ट भी मानते हैं। हांलाकि वे आजीवन कांग्रेस संगठन के वामपंथी मंच के नेता रहे और औपचारिक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कभी नहीं बने।[12]

मार्क्स के इसके आर्थिक सामाजिक दर्शन से प्रभावित स्वामी जी मार्क्सवाद की रचनात्मकता का विशेषलेषण दिक और काल के प्रसंग में विशेष रूप से भारतीय परिवेश में करते हैं, क्योंकि उनका मार्क्स से एक बड़ा विलक्षण फर्क यह था कि जहां मार्क्स औद्योगिक मजदूरों को सर्वहारा क्रांति का वाहक मानते हैं वही स्वामी जी इसका वाहक किसान और किसान श्रमिक को। मार्क्सवाद में सर्वहारा क्रांति का आधार अर्थात नींव का पत्थर मिल मजदूर है, जो शुद्ध रूप से अपना श्रम बेचता है और उसके पास पूंजी के रूप में निजी स्वामित्व की कोई वस्तु है ही नहीं, केवल इसका श्रम उसका अपना है।

यही कारण है कि 'कम्युनिस्ट घोषणा पत्र' में कहा गया है कि "सर्वहारों के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खाने को कुछ नहीं है, जीतने के लिए उसके पास सारी दुनिया है।" मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा क्रांति केवल संगठित मिल मजदूरों को ही आती है। किसानों का चरित्र द्विमुखी या दुहरा होता है, वह कभी सर्वहारा के साथ तो कभी पूंजीपति और जमींदार के साथ। इसी अर्थ में किसान को भी क्षुद्र बुर्जुवा मानता है। स्वामी जी अपनी भाषा में इसे टुटपुंजिया मानते हैं। राजनैतिक भाषा में इसकी स्थिति प्रतिक्रियावादी है प्रगतिशील नहीं।

मार्क्स का 'किसान' के बारे में यह दृष्टिकोण एक देश विशेष और काल विशेष की उपज थी, और पश्चिमी यूरोप के परिवेश में इसकी इस धारणा का आंकलन करना ठीक होगा। औद्योगिक क्रांति पश्चिमी यूरोप में ही पहले आई। उद्योग के विस्तार के साथ-साथ पूंजीपति का शोषण भी बढ़ा। परिणाम यह हुआ कि लघु और कुटीर उद्योग समाप्त हो गए।

इस श्रम विभाजन का परिणाम था समाज का स्पष्टतः दो वर्गों में विभाजन- सर्वहारा और पूंजीपति। चूंकि पश्चिम यूरोपीय देशों में आर्थिक क्रिया का मूल स्रोत उद्योग तथा व्यापार था, खेती-उत्पादन का छोटा सेक्टर था इसलिए किसानों का स्थान महत्वहीन था। मार्क्स ने अपना आर्थिक और राजनैतिक चिन्तन इन्हीं देशों के परिवेश में, इनकी स्थिति के आधार पर विकसित किया है। अतः क्रांति के दृष्टिकोण से किसान उसे महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं हो सका। इन्हीं कारणों से किसान मार्क्सवादी चिंतन के सर्वहारा दर्शन में खप नहीं पाया, और वह क्रांति की दृष्टि से निर्भर रहने लायक नहीं जंचा। रूसी क्रांति के दौरान पूर्व एक मार्क्सवादी विचारक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बुखारिन ने (जिसे लेनिन के साथ कुछ प्रश्नों पर मतभेद हो जाने के कारण मृत्यु-दण्ड दिया गया था) किसान के बारे में बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है, "वे अपने नन्हे खेतों से आगे देख ही नहीं सकते।"[13] कहने का तात्पर्य यह है कि मार्क्स द्वारा किसान की क्रांतिकारी भूमिका का अवमूल्यन तत्कालीन परिस्थितियों के सामयिक यथार्थ की उपज है।

हालांकि मार्क्सवाद पश्चिम यूरोप के अनुभवों पर आधारित दर्शन था, परंतु उसकी परिणति हुई पूर्वी यूरोप में, चीन में माओ-त्से-तुंग ने मजदूर और किसान दोनों को क्रांति का अगुवा बनाया वैसे ही स्वामी जी की अवधारणा में भारत में, जहां संख्यात्मक दृष्टि से औद्योगिक मजदूर कम किसान और कृषक मजदूर ज्यादा है, क्रांति का स्वरूप अलग होगा, जो देश की परिस्थिति के मुताबिक तय होगा। उनकी मान्यता थी कि भारत में किसी भी प्रकार के आर्थिक ढांचे का आधार सर्वदा किसान ही रहेगा। स्वामी जी के आर्थिक दर्शन की काया वामपंथी है और काया का केन्द्र या उसकी आत्मा किसान है। स्वामी जी के किसान केन्द्रित आर्थिक दर्शन की मूल बात यह है कि पहले आत्मा तब परमात्मा यानी किसान कमाएगा, उत्पादन करेगा, तो वह पहले स्वयं खाएगा, तब समाज को भी खिला सकेगा। मार्क्सवाद में 'ये कमानेवाला खाएगा' है यानी सर्वहारा का एकाधिपत्य होगा-प्रोलिटेरियट डिक्टेटरशिप रहेगी। परंतु स्वामी जी 'किसान डिक्टेटरशिप' जैसी बात नहीं करते हैं, उसमें किसान अपने बाद दूसरों के लिए भी स्थान देता है। मार्क्सवाद 'स्वयं' के बाद 'पर' (दूसरा) को स्वीकार नहीं कर पाता है और वह कट्टर वर्ग-चेतना की उपज है तथा इसी कट्टर वर्ग-चेतना के आधिपत्य पर समाप्त हो जाता है। परंतु स्वामी जी के चिंतन में 'निज' के साथ 'पर' को भी स्वीकार्य माना गया है। यही स्वामी जी की चिन्तन-पद्धति की मौलिकता है जो निश्चय ही मार्क्सवाद से आगे मानववाद तक जाती है। लेकिन उनका मानववाद प्रथम स्तर में ही किसान को ठोक-पीट कर भूखा सुला देनेवाला मानववाद नहीं। स्वामी जी की दृष्टि में किसान जो अन्न पैदा करता है, सबका अन्नदाता है, सबके जीवन का आधार है, सारी संस्कृति और सभ्यता के रथ की धुरी है, वह किसान वस्तुतः 'सर्वभूत हितेरता' है। वह केवल 'निज' से जुड़ा नहीं रह सकता। वह तो एक अर्थ में सारे समाज के लिए भगवान जैसा है और यही कारण है कि स्वामी जी किसान को अपना आराध्य (देवता) मानते हैं।

स्वामी जी की आर्थिक परिकल्पना में साम्राज्वादी शासन काल के आर्थिक संबंधों ने एक विचित्र सामाजिक संरचना को स्वरूप प्रदान करा दिया है, जिसमें भारतीय कृषि-क्षेत्र को जो उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, विदेशी साम्राज्यवाद तथा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

देशी राजे, जमींदार तथा अन्य बिचौलिए खुलकर लूट रहे हैं। मध्यम वर्ग चुप तथा ढुलमुल है और मध्यम वर्ग का सबसे ऊपरी तबका, तथा राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवादियों के सहमेल से एक ही कार्य कर रहे हैं और वह है किसानों का शोषण। मध्यम वर्ग के ढुलमुल स्वभाव के संबंध में स्वामी जी ने लेनिन की उक्तियों को उद्धृत कर उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा।

"अंतिम धावा बोलने का परिपक्व समय हम तभी मान सकते हैं जबकि हमारी विरोधी सभी ताकतें गड़बड़ घोटाले में पड़ी हों, अच्छी तरह परस्पर की ऐसी लड़ाई में पड़ के उसने एक दूसरे को काफी कमजोर कर दिया हो जिसके लिए उनके पास पहले से ही पूरी ताकत न थी।

सभी आगा पीछा करनेवाले, कमजोर और अविश्वसनीय दलों ने, जो पूंजीवादियों और मजदूरों के मध्य में आ जाते हैं, जैसे कि टुटपुंजिये बाबू और पढ़े-लिखे लोग, जनता की नजरों में अपना असली रूप प्रकट न कर दिया हो, और अपने राजनीतिक दिवालिएपन का काफी सबूत दे दिया हो। सर्वहारा वर्ग में पूंजीपतियों के खिलाफ निश्चित रूप से जबर्दस्त और हिम्मत के साथ आखिरी क्रांतिकारी मोर्चा लगाने के पक्ष में जबर्दस्त भावना उपजी और चारों ओर फैल गई हो।"[14]

मध्यम वर्ग की स्थिति के संबंध में स्वामी जी पूर्णतः आश्वस्त हैं कि क्रांतिकारी आंदोलनों में उसका वर्ग चरित्र ढुलमुल रहता है। वे लेनिन को उद्धृत करते हैं:-

> "देखिए न, फटेहाल और पढ़े-लिखे बाबू लोग, जो अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, क्या फर्माते हैं? मजदूर दल का साथ देने की घोषणा तभी करवाना चाहते हैं जबकि व्यक्तिगत सम्पत्ति का बोलबाला ही है। जबतक पूंजीवाद गद्दीनशीन ही है, और जबतक जनता उसी के नीचे पिस रही है तबतक बहुमत अपने हाथ में शासन ले नहीं सकता। यदि मजदूर लोग देशवासियों के बहुमत को अपनी ओर करना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें पूंजीपतियों को शासन से हटाना और उसका सूत्र खुद हथियाना पड़ेगा .... इस तरह पुराने शासन के ढांचे को तोड़ के एक ही धक्के में पूंजीपतियों और वर्ग सामंजस्यवादी फटेहाल बाबुओं के उस प्रभाव को विरुद्ध असर डालना होगा, जिसे वे लोग मजदूरों के सिवाय अन्य कमानेवाले लोगों पर फैलाए रखते हैं। इसके बाद इनके इस प्रभाव को जड़ मूल से सदा के लिए मिटा सकें।"[15]

इस तरह के मध्यम वर्ग की चेतना पर स्वामी जी का विश्लेषण है कि ये प्रतिक्रांतिकारी होते हैं क्योंकि- "किसानों, कलाकारों, दस्तकारीवालों, दुकानदारों या इसी तरह के दूसरे लोगों के पास जो निम्न मध्यम श्रेणीवाली कहाते हैं, थोड़ी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बहुत सम्पति रहती है और नहीं तो एक झोपड़ा और इसके ईर्द-गिर्द की जमीन ही रहती है। इसलिए उन्हें यह सदा डर बना रहता है कि कहीं यही न गायब हो जाए, वे हमेशा अपनी नन्हीं-सी संपति बचाने की फिक्र में रहते हैं। उन्हें वर्तमान की चिंता नहीं है, किन्तु भविष्य की। .... कब वह सम्पति चौपट हो जाए ... . इसलिए वे परेशान रहते हैं। उनके लिए भविष्य अन्धकारमय है, किन्तु वर्तमान ऐसा नहीं है। उन्हें भविष्य की चिंता जितनी है, उतनी वर्तमान की नहीं। इसलिए वे दकियानूसी और क्रांति विरोधी हैं। बल्कि वे तो चाहते हैं कि जो बड़े-बड़े फार्म बन गए हैं और बड़े-बड़े कारखाने खुल गये हैं, वह सब टूट जाये, और उनकी जगह पर छोटे-छोटे खेत और लघु कारखाने बन जायें। वह बीते जमाने को फिर वापस लाना चाहते हैं। इसलिए वे प्रतिक्रांतिवादी है।"[16]

क्रांति के सबल संवाहक के रूप में विभिन्न वर्गों की स्थितियों का विवेचन स्वामी जी करते हुए मार्क्सवादी अवधारणा के तहत मान्य मजदूर वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका को स्वयं स्वीकार करते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो में उद्धृत मार्क्सवादी मान्यता कि-

"पूंजीवादियों के विरोधी जितने वर्ग हैं, उनमें केवल सर्वहारा ही सचमुच क्रांतिकारी वर्ग है। .... निम्न मध्यम श्रेणी वाले छोटे-छोटे कारखानेदार, दुकानदार, हस्तकार, किसान वे सभी पूंजीपतियों से सिर्फ इसलिए लड़ते हैं कि मध्यम वर्ग के अंग की हैसियत से खुद कायम रह जाए और उनकी हस्ती मिट न जाए। इसलिए वे लोग क्रांतिकारी नहीं हैं, किंतु दकियानूसी और पुराणपंथी है। इतना ही नहीं, वे तो क्रांति-विरोधी या प्रतिगामी है क्योंकि वे ऐतिहासिक चक्र को पीछे घसीटना चाहते हैं। और अगर वे संयोग से कभी वे क्रांतिकारी बन जाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें खतरा है कि कहीं वे भी सर्वहारा न बन जाय। .... वे अपने वर्तमान की रक्षा न करके भविष्य की ही करते हैं। और अगर वे अपने को सर्वहारा के स्थान में कभी रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने दृष्टिकोण को छोड़ना पड़ता है।"[17]

स्वामी जी के आर्थिक-दर्शन में वर्ग-संघर्ष की जो अवधारणा विकसित हुई और व्यापक संयुक्त मोर्चे के तहत किसान मजदूर एकता की धुरी तले साम्राज्यवाद विरोधी मुक्ति संघर्ष के संचालन का भाव प्रकट हुआ उसकी संकीर्णतावादी मीमांसा कर कतिपय अर्थशास्त्री, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा राजनीतिक दल भी हिंसावाद से जोड़ देते हैं। वास्तव में ऐसे तत्व अपनी हिंसावादिता या अराजकतावादिता के समर्थन में तर्क जुटाने में स्वामी जी की वर्ग-अवधारणा या वर्गीय अंतर्विरोध के सिद्धांत को विद्रूप कर पेश करते हैं। स्वामी जी जब किसानों के बारे में कहते थे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कि 'हिसाब दो, हिसाब लो', तो वह शुद्ध लोकतांत्रिक और न्याय संगत बात है कि श्रम लो और कीमत दो।

स्वामी जी की ऐसी उक्तियां वर्गीय समाज में शोषण की प्रणाली को समाप्त करने तथा जमींदारों द्वारा किसानों से बेगार आदि लेने जैसी प्रथाओं की समाप्ति के लिए जनतांत्रिक ढंग से समाधान ढूंढने का नारा है न कि एक ही वर्ग-विशेष के विभिन्न तबकों का एक दूसरे के खिलाफ हत्या की राजनीति वे किसान और कृषि-मजदूरों की एकता के प्रबल समर्थक हैं, क्योंकि उनकी धारणा है, कृषि मजदूर और छोटे-छोटे किसान जो खेती में स्वयं अपना श्रम भी लगाते हैं और अपनी जीविका के लिए मुख्यतया कृषि पर आश्रित हैं।[18] इस प्रकार कृषक तथा कृषक मजदूरों की एकता स्वामी जी का लक्ष्य है जो जमींदारी-जुल्म के खिलाफ एक सबल हथियार है।

स्वामी जी की क्रांति विषयक अवधारणा

स्वामी जी के आर्थिक चिंतन में सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात है वह है उनकी क्रांति विषयक अवधारणा, जिसमें मार्क्स तथा लेनिन के द्वारा प्रतिपादित राजसत्ता के स्वरूप से आर्थिक संबंधों को जोड़ा गया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की परिकल्पना में राजसत्ता के स्वरूप का निर्धारण इस तथ्य में अंतर्निहित रहता है कि किसी खास शासन प्रणाली में सम्पति के संबंधों का स्वरूप क्या है—वह संबंध व्यक्तिगत स्वामित्व वाला है कि सामूहिक स्वामित्व वाला। जब राजसत्ता एक वर्ग के हाथ से निकलकर दूसरे वर्ग के हाथों में चली जाती है तो उस परिवर्तन को मार्क्सवादी भाषा में क्रांति कहते हैं। इस परिवर्तन का मूल मंत्र है कि क्रांति के बाद निर्मित अर्थव्यवस्था को अपने स्वभाव में पिछली अर्थव्यवस्था से बिल्कुल भिन्न होता है। उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के बदल जाने पर राजसत्ता का चरित्र तथा अन्य तमाम बाह्य सरंचनायें बदल जाती हैं। उस प्रकार अर्थतंत्र और राजतंत्र का स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के औजारों और वितरण की प्रणाली के स्वरूप के मुताबिक तय होता है।

स्वामी जी इस मार्क्सवादी भौतिकवाद को स्वीकार करते हैं और क्रांति को उसकी व्यापक अर्थवत्ता में स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि क्रांति कोई सुधार कार्य नहीं है बल्कि परिवर्तन का वह क्रम है जिसके द्वारा राजसत्ता सम्पूर्णता में आर्थिक, सामाजिक और यहां तक कि सांस्कृतिक में भी बदल जाती है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एक दूसरे वर्ग के हाथों में चला जाता है।

स्वामी जी ने अपनी पुस्तक '*क्रांति एवं संयुक्त मोर्चा*' में विश्व क्रांति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय क्रांति और यहां के परिवेश का विश्लेषण किया है। इस संबंध

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में मार्क्स, लेनिन और एंजेल्स के विचारों से बहुत दूर तक सहमत हैं। उन्होंने विप्लव और राज्य क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी रेवोल्यूशन और फारसी इन्किलाब के अर्थ में किया है। क्रांति के अन्दर वे राजनीतिक और आर्थिक मसलों को ही मानते हैं, धार्मिक मसलों को नहीं।[19]

रेवोल्यूशन का अर्थ है– "हालात को उलट देना, बुनियादी रद्दोबदल करना अथवा प्रजा के द्वारा पुरानी सरकार का नये शासन कायम करना" आदि से है।[20] स्वामी जी का विचार है कि, "क्रांति नाम तभी दिया जाएगा जब पहली सरकार के ढांचे या शासन प्रणाली को उलट के इसकी जगह एकदम नईं बनाई जाये। पहली हुकूमत का नामोनिशान् रहने पर यह कहना की क्रांति हो गई, सरासर झूठ है।[21]

लेनिन की अवधारणा में क्रांति तभी जन-क्रांति का रूप ग्रहण कर सकती है जब उसका स्वरूप पूर्ण जनवादी तथा जनता के बहुमत हिस्से-किसान मजदूरों को अपने साथ लेकर चले। मार्क्स लेनिन ने क्रांति में बाहरी उलटफेर पर ज्यादा जोर दिया है, जबकि स्वामी जी ने क्रांति में आंतरिक रद्दोबदल या उलटफेर पर ज्यादा जोर दिया है। लेनिन ने क्रांति को पारिभाषित करते हुए कहा है कि:-

> "क्रांति उस वर्ग-युद्ध को कहते हैं जो उबलता हुआ और बहुत कड़वा होता है, क्रांति कहते हैं शासकों के द्वारा पुरानी शासन प्रणाली की जगह पर बल पूर्वक सोलहों आना नयी शासन व्यवस्था का कायम किया जाना।"

स्वामी जी ने क्रांति के इसी स्वरूप के भीतर भारतीय मुक्ति संग्राम में कांग्रेस द्वारा प्रयुक्त शब्दावलियों, आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता आदि को क्रांति मूलक नहीं माना है, क्योंकि इसमें मात्र सत्ता के हस्तांतरण की बाते हैं बुनियादी आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की नहीं। आजादी की वर्गीय परिभाषा पेश करते हुए स्वामी जी ने कहा है कि जमींदारों के स्वराज्य और किसानों के स्वराज्य में बहुत अन्तर है, फिर दोनों को साथ-साथ स्वराज्य कैसे मिल सकता है। उन्होंने लिखा है-

> "स्वराज्य के बदले क्रांति का प्रयोग हमारी दृष्टि से शोषितों और पीड़ितों की नज़र में ज्यादा महत्व रखता है। इस महत्व को न जानने के कारण ही पुराने समय के फ्रान्स, इंग्लैण्ड, अमेरिका, इटली आदि राष्ट्र विप्लव विफल हो गए हैं, वहां की कमाने वाली जनता वैसे की वैसे ही दुखिया आज भी बनी है।[22] स्वामी जी ने स्वराज्य और आजादी का अर्थ विदेशी शासन के स्थान पर अपना शासन कायम करने को गलत माना है। एंजेल्स ने भी रूस की क्रांति को छोड़कर अन्य क्रांतियों को अल्पमत की क्रांति बतलाया है, क्योंकि सत्ता फिर अल्प मतों के हाथ में चली गई।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अल्पमत एवं बहुमत की क्रांति[23] को परिभाषित करते हुए स्वामी जी ने इसे शोषक और शोषित के संबंधों पर आधारित बताया। आर्थिक तौर पर शोषण हर शासन-व्यवस्था का एक अंग है, क्योंकि आर्थिक संबंध इसी प्रकार के बनते हैं, परंतु सर्वहारा और पूंजीवादी अर्थतंत्र का स्वरूप एक दूसरे से एकदम भिन्न होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में प्रजातंत्र शासन सिर्फ मुट्ठी भर शोषकों और पूंजीपतियों का प्रजातंत्र होता है। उसमें बहुसंख्यक शोषितों के अधिकार संकुचित कर दिए जाते हैं। ऐसी क्रांति और शासन-व्यवस्था बहुमत के शोषितों को दवाने के लिए होती है। इस क्रांति को इन्होंने अल्पमत क्रांति कहा है। इसके विपरीत श्रमजीवियों के जनतंत्र शासन में पीड़ित और शोषित जनता की भागीदारी अधिक होती है। उसमें शोषकों के अधिकार संकुचित कर दिये जाते हैं। लेनिन ने इसको सर्वहारा (मजदूर) वर्ग का एक तंत्र शासन कहा है।[24]

स्वामी जी ने क्रांति के विभिन्न चरणों का उल्लेख किया है, जिसमें सर्वहारा राजसत्ता को हथियाकर अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन ला सकता है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था का सृजन कर सकता है जिसमें मानव द्वारा मानव के शोषण को सदा के लिए समाप्त किया जा सके। इस आर्थिक परिवर्तन का मूल है सत्ताप्राप्ति। यही क्रांति का पहला चरण है। फिर इन्हें पंचायत-द्वारा बहुमत का शासन स्थापित कर जनता पर विरोधियों के स्तर को समाप्त करने के लिए वातावरण उत्पन्न करना होगा। इसे ही बहुमत क्रांति कहा गया है। अल्पमत क्रांति को ही पूंजीवादी क्रांति, जनतंत्र वादी क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। बहुमत क्रांति को पोल्टारियन क्रांति या शोशलिस्ट रेवोल्यूशन कहा जाता है। सर्वहारा वह है जिसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्वामी जी ने इन प्रक्रियाओं के साथ संलग्न अर्थतंत्र के स्वरूप का विवेचन भी किया है। इस संबंध में मार्क्स और एंजेल्स के निम्नलिखित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने कहा है "समाज का आर्थिक ढांचा की असली नींव है, जिसके ऊपर राजनीति के महल खड़े किए जाते हैं और जिसके अनुसार ही विचारों के निश्चित सामाजिक रूप बनते हैं। संक्षेप में उत्पादन प्रणाली ही सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक जीवन के स्वरूप को आम तौर से निर्धारित करती है।[25]

सर्वहारा के नेतृत्व के विषय में स्वामी जी का कहना है कि पूंजीवादी क्रांति के बिना सर्वहारा क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई के पहले चरण में सर्वहारा उतना संगठित नहीं रहता है। भूमि एवं अन्य वस्तुएं, सामंती और जमींदारों से छीनकर, किसानों के हाथ में आती है। दूसरे चरण में मजदूर वर्ग संगठित होकर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

शासन एवं भूमि को हथिया लेता है। क्रांति का काम केवल नाश करना न होकर संगठन कायम करके नई व्यवस्था देना भी है।

उपर्युक्त सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में स्वामी जी ने कुछ अवरोधों की ओर संकेत करते हुए कहा है-

"जो लोग समझते हैं कि पूंजीवादी बिना सारी शक्ति लगा के लड़े ही शासन-सूत्र छोड़ देंगे वे संसार के शब्दों को उलट फेर और खासकर क्रांति का इतिहास जानते ही नहीं, पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ी जानेवाली लड़ाई भीषण और खूनी होती है। सुधार की तरह किस्त-किस्त पर क्रांति नहीं होती।[26]

पूंजीवादी क्रांति-व्यवस्था पर केवल कब्जा करती है, जबकि सर्वहारा क्रांति-व्यवस्था हथियाने के साथ ही साथ नई सामाजिक अर्थव्यवस्था तैयार करती है। पूंजीवादी क्रांति को अधिक समय तक श्रमिकों और शोषित की सहायता नहीं मिल सकती है। दूसरी ओर सर्वहारा क्रांति को उनका समर्थन बराबर मिलता है, क्योंकि वह उनकी बराबर सुनती और सर्वहारा और सहानुभूति लेकर चलती है। इस विवेचन के अनुसार भारत में अंग्रेजों से कांग्रेस को सत्ता हस्तांतरण भी वस्तुतः पूंजीवादी क्रांति बनकर रह गया।

सर्वहारा क्रांति समाजवाद का निर्माण करती है। स्वामी जी के अनुसार समाजवाद का अर्थ है, जो जितना काम करे उसके हिसाब से इसे जीवन के लिए जरूरी सभी सामान मिले।[27]

सर्वहारा क्रांति के असली रूप को समझने के लिए स्वामी जी का ऐतिहासिक विकास का निम्नलिखित तर्क महत्वपूर्ण है– आखिर समाजवादी या सर्वहारा क्रांति का काम तो यही है कि नई सामाजिक व्यवस्था बनाए। यह करने में उसे पूंजीवादी प्रणाली को मिटाना पड़ता है। मगर जब तक पूंजीवादी प्रणाली कायम हुई ही नहीं तभी तक उसके नाश या इसे हटा के नई व्यवस्था कायम करने का प्रश्न उठ सकता है? सामन्तशाही व्यवस्था में तो पूंजीवाद का गर्भ मात्र रहता है तब तो वह विकसित भी नहीं हो पाती, पूर्ण विकास की बात जुदी है। लेकिन गर्भपात करवाकर और बनी बनाई चीज का नाश करना दोनों एक बात है ही नहीं। पूंजीवादी व्यवस्था के नाश करने पर उसकी हड्डियों और राख मांस से नई सामाजिक व्यवस्था की नींव बनती है, ईंट बनती है, गारा-सुर्खी बनती है। गर्भपात करने से तो यह होने का नहीं यद्यपि की हड्डी की जरुरत थी वृत्रासुर के संहार के लिए या बज्र बनाने के लिए ताकि असुरों से देवताओं की रक्षा हो। लेकिन दधीचि को गर्भ में ही मार देने से वह हड्डी कैसे मिलती?[28]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इस क्रांति की सफलता के लिए अस्त्र उठाना और हड़ताल अनिवार्य है। इसका लक्ष्य होता है मजदूरों को आराम पहुंचाना, काम के घण्टे कम करना, इनकी आर्थिक जिन्दगी सुधारना और संगठन को शिक्षा देना। इस क्रांति की सफलता के लिए आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की हड़ताल होनी आवश्यक है। अर्थात कल-कारखाना से लेकर खेत का उत्पादन ठप्प करना और मालगुजारी तथा कर की अदायगी रोकना। सर्वहारा नेतृत्व की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए स्वामी जी ने लिखा कि दूसरे नेता जहां स्व विवेक से जनता के भले-बुरे का निर्णय करते हैं वहां सर्वहारा नेतृत्व जनता की इच्छाओं के अनुरूप पलता है। वह अपनी प्रतिष्ठा या जिद कायम करता। इस संबंध में लेनिन का मत है कि अग्रदूत या नेता को ऐसा करना चाहिए कि लोग इसके पीछे चले। ऐसा न हो कि वह जनता से अलग हो जाए। इसमें धैर्य के साथ ही साथ अनुशासन की आवश्यकता है।

मार्क्स के वर्गहीन समाज की कल्पना के बारे में स्वामी जी का कहना है कि जनता स्वयं इतनी शिक्षित और जानकार हो जाएगी कि सरकार एक दिन खुद खत्म हो जाएगी। पुलिस और फौज का काम जनता करती ही है। एंजेल्स ने सरकार से तात्पर्य सम्पति वाले जमींदारों और पूंजीपति वर्ग की एक सम्मिलित और सुसंगठित ताकत बतलाया है। जिसका काम शोषितों जैसे किसानों और मजदूरों को दबाना है। जनता में जागृति आने पर जब ऐसी सरकार मिट जाती है तो उसे श्रेणीहीन समाज या वर्ग-हीन समाज की संज्ञा दी जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संघर्ष समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को लेकर होता है, जबकि राजनीतिक संघर्ष सरकारों की स्वेच्छाचारिता, अफसरों के पतन, सर्वसाधारण के साथ उनके दुर्व्यवहार, आंदोलन पर रोक और पुलिस ज्यादती के विरुद्ध होता है। इस संबंध में लेनिन का कहना है कि "श्रमजीवी वर्ग को सोशल डेमोक्रेट बनने के लिए यह निहायत जरूरी है कि वह अपने दिमाग में जमींदारों, पुरोहितों, बड़े अफसरों, किसानों, विद्यार्थियों और अवारागर्दों के सामाजिक तथा राजनीतिक पहलुओं के आर्थिक रूप से पूरी तस्वीर बना लें।

'किसान और क्रांति' शीर्षक में स्वामी जी ने किसानों और मजदूरों पर विचार किया है। लेनिन ने किसानों को क्रांतिकारी नहीं माना है। उनका कहना है कि किसान जमीन का भूखा होता है। उसे केवल जमीन और जमींदार के अत्याचार से मुक्ति चाहिए। वह अपने नन्हे खेत से आगे नहीं देख पाता। साम्यवाद, समाजवाद, व्यक्तिगत सम्पति का नाश सम्मिलित सम्पत्ति, सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण आदि कार्य सर्वहारा ही करता है। खेती मारे जाने पर सरकार द्वारा जब लगान वसूली के लिये किसान का खेत नीलाम होने को होता है, तब वह जाकर सर्वहारा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के साथ होता है। सर्वहारा क्रांति की सफलता के लिए छोटे-छोटे किसानों को अपना सहायक मानकर उन्हें बढ़ाना और उनकी सहायता करना मजदूर वर्ग के लिए अनिवार्य है। उन्हें दबरदस्ती दबाकर पंचायती खेती में लगाना ठीक नहीं है। इस संबंध में स्वामी जी का विचार है कि किसानों को मौका दिया जाना चाहिए कि वे अपनी छोटी खेती और पंचायती खेती का हानि-लाभ सोचकर तदनुरूप निर्णय ले सकें।

किसानों और मजदूरों की टक्कर की संभावना पर विचार करते हुए स्वामी जी ने लिखा है कि उनके स्वार्थ परस्पर विरोधी है। मजदूर मिल का सामान मंहगा करना चाहता है ताकि उसका वेतन बढ़े, जबकि किसान खेते में पैदा हुई वस्तु को महंगा बेचना चाहता है ताकि उसे अधिक लाभ मिले। पूंजीपति एवं जमींदार इन्ही दोनों को लड़ाकर मौज करता है। लेनिन का मत है कि सर्वहारा का उचित दर्जे का दोस्त तो अर्द्ध-सर्वहारा लोगों का विशाल समूह है, और उनके आंशिक मित्र है छोटे किसान। किसानों को साथ लेने के लिए आवश्यक है जमींदारों का नाश करके सारी जमीन छोटे किसानों में बांटी जाए। इन्हें सामूहिक खेती की अच्छाई समझाकर उसे अपनी ओर आकृष्ट करना होगा। थोड़े बहुत किसान जो नहीं आते है, उन्हें जबरदस्ती उसमें लेना होगा, क्योंकि पूंजीवादी अपने विकास के लिए जमीन को सामंती दृष्टिकोण से हटाकर पूंजी से जोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में किसान भी जमीन से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। वे भरसक पंचायती खेती में आना नहीं चाहते। इसी कारण लेनिन ने किसान की गणना बुर्जुवा वर्ग में ही की है। उसका कहना है कि किसान सर्वहारा की तरह जन्मजात या स्वभाव से क्रांतिकारी न होकर परिस्थितिवश ही क्रांतिकारी बनता है। इसी कारण क्रांति का नेतृत्व मार्क्स ने सर्वहारा को ही दिया है।

क्रांति के दुश्मन के संबंध में स्वामी जी ने निम्नलिखित शब्दों में सतर्क किया है।[29]

> "उथल-पुथल और क्रांति के समय में पुराने शासक और शोषक काफी सजग हो जाते हैं। वह भरसक इस बात की कोशिश करते हैं कि जनता उन्हें परख न पाए .... वे पूरे बगुला भगत बैठते हैं।" ताकि जनसाधारण उनकी ओर से चिहुंक न सके वे समझ जाए कि वे अब पूरे महात्मा बन गए। ऐसा भी होता है कि जो लोग क्रांति का नेतृत्व करते हैं वे सब के सब शोसित जनता के पक्के आदमी होते ही नहीं। इसके उलटा उनमें शायद ही कोई इक्के-दुक्के ऐसे होते हैं। बाकी लोग तो मध्यम श्रेणी या पूंजीवादी मनोवृत्ति के या इसी प्रकार के होते हैं। हां, क्रांति की लड़ाई में जूझने वाली जनता खुद शोषित एवं पीड़ित होती है शोषितों तथा पीड़ितों के लिए मर मिटने वाली होती है। मगर नेतृत्व से ही उसका मनोरथ पूरा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हो पाता ही नहीं। शोषण और लूट खसोट को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का प्रण करके भी वह जनता नेताओं की धोखेबाजी में पड़ जाती है क्योंकि नेता लोग अपनी बाघ की शक्ल छुपा कर गधे की खाल ओढ़ लेते हैं"

सर्वहारा के एकतंत्र और जनतंत्र पर विचार करते हुए स्वामी जी ने पोलेटारियन डिक्टेटरशिप का अर्थ सर्वहारा के द्वारा समस्त समाज पर एकतंत्र शासन बतलाया है। सर्वहारा के एकतंत्र का आशय है कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों द्वारा सत्ता पर किसी तरह कब्जा करके पूंजीवादियों के विद्रोह को निर्ममतापूर्वक कुचलना। लेनिन के अनुसार "एकतंत्र का लक्ष्य है, समाजवाद की स्थापना, समाज के वर्ग विभेद को मिटाना, समाज के सभी आदमियों से काम करवाना और एक आदमी के हाथों दूसरे के शोषण को असंभव कर देना।"[30] एकतंत्र का निचोड़ वस्तुतः सर्वहारा का सुन्दर संगठन और अनुशासन है। इस क्रांति को सार्वत्रिक क्रांति की संज्ञा दी गई है, अर्थात् यह क्रांति समाप्त न होकर बराबर चलती रहती है।

स्वामी जी ने क्रांति की सफलता के लिए सर्वहारा और किसानों का संयुक्त मोर्चा बनाने पर बल दिया है। दोनों का साथ हुए बिना पूंजीवाद का सफाया संभव नहीं है। इन दोनों वर्गों के अभिन्न रूप से जुड़े होने के कारण भारतीय परिवेश में स्वामी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। यहां केवल सर्वहारा की क्रांति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। भारत की स्वतंत्रता तभी मिली जब गांव के किसानों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया।

1937 ई. में बने कांग्रेसी मंत्रिमंडल को स्वामी जी ने पूंजीपत्तियों की सरकार कहा क्योंकि सरकार फैजपुर कांग्रेस के प्रस्तावों को लागू नहीं कर रही थी। उनका ध्यान खींचने के लिए जब किसानों और मजदूरों ने स्वामी जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया तो उसे देशद्रोह की संज्ञा दी गई, क्योंकि सबको मिलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। दूसरी ओर सरकार ने बिहार में जमींदारों और बम्बई में मिल मालिकों के साथ समझौता किया जो किसानों और मजदूरों के हित के विपरीत था। स्वामी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि कांग्रेस ने किसानों और मजदूरों की सीधी लड़ाई को बन्द कर दिया था। संघर्ष करनेवालों के लिए कांग्रेस में जगह नहीं रह गई थी। ऐसे लोगों को बागी और दुश्मन करार देकर उनपर अनुशासन की कार्यवाही की गई। जिस ताकत को कांग्रेस ने पैदा किया उसके उभड़ते ही वह इससे डरने लगे। पूंजीपतियों की तरह कांग्रेस ने भी अपना नेतृत्व को बनाए रखने के लिए किसानों और मजदूरों को पीछे ढकेल दिया। चूंकि व्यक्तिगत पूंजी को कांग्रेस समाप्त नहीं करना चाहती थी। अतः इसने जमींदारों और पूंजीपतियों से मेल कर लिया। 1935 ई. में किसान सभा ने कांग्रेस में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

फंक्शनल रेप्रेजेन्टेशन का काम तथा पेशा के अनुसार सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की मांग की तो उसे स्पष्ट नकार दिया गया। यह दलील दी गई कि ऐसा करने पर किसान और मजदूर संगठन कांग्रेस पर कब्जा कर लेंगे। कांग्रेसी नेता चवनियां मेम्बरों का नकली प्रतिनिधित्व चाहते थे। इस स्थिति में कांग्रेस आम जनता का प्रतिनिधि संस्था आजादी के पहले भी नहीं बन सकी। उस समय भी उसका आधार व्यक्तिगत सदस्यता थी, जिसके चलते आरम्भ से ही इसमें फर्जी और बोगस लोग भरे हैं। यह देश और जनता के साथ धोखा है। 1936 में देश क्रांति के दूसरे दौर से गुजरा था, किंतु कांग्रेस ने वास्तविक प्रतिनिधित्व की बात दबा दी जिससे क्रांति आगे नहीं बढ़ सकी। यही स्थिति बदतर रूप में आज भी मौजूद है।

पुनः स्वामी जी कहते हैं कि "यदि अल्पमत क्रांति पर सवाल होता तो अधिकांश देशों में गुप्त षड्यंत्र के जरिये यह सफल हो सकती थी। मगर बहुमत क्रांति में तो देश की अधिकांश जनता को पहले से इसके लिए तैयार करना होगा। तभी बाहरी मदद से कुछ हो सकता है। जो मुल्क खुद तैयार नहीं है उसे बाहरी मदद क्या मिलेगी और कैसे? इससे होना ही क्या? ऐसी दशा में क्रांति कराने का ठेका लेना बेकार और नादानी है"।[31]

स्वामी जी सारी त्रुटियों और कठिनाइयों के बावजूद किसान और मध्यम वर्ग के संयुक्त मोर्चा के पक्ष में थे ताकि वे विरोधी खेमे में न जा मिले। इसका नमूना इन्होंने रूस में पाया। जहां समझौता होने पर यह बात नहीं होती और क्रांति की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती। इसलिए यह संयुक्त मोर्चा कहा जाता था। किसानों और मजदूरों को हड़ताल वगैरह करने की पूरी आजादी इसमें थी और यही तो ठीक था-किसान जबर्दस्ती जमीन छीनते थे और उसमें उन्हें रोकने के बजाय प्रोत्साहन मिलता था। मगर हमारे यहां तो अजीब बात है मजदूरों और किसानों को अपने हक के लिए हड़ताल, बकाश्त संघर्ष आदि के जरिए सीधी लड़ाई से रोक के ही कांग्रेस के लीडर और उनके निराले क्रांतिकारी लोग संयुक्त मोर्चा कायम करना चाहते हैं। यह तो गुलामी है और क्रांति की गाड़ी कीचड़ में फंसाना है। इसे संयुक्त मोर्चा क्यों कर कहा जाए।

स्वामी जी की आर्थिक रणनीति और कार्यनीति

स्वामी जी के आर्थिक दर्शन में मुख्य तथ्य यह था कि वे किसानों को एक ऐसा वर्ग समझते थे जो भारतीय समाज में क्रांतिकारी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता था और उसे एक वर्गहीन समाजवादी अर्थतंत्र की पूर्णाहुति तक ले जा सकता था। परन्तु उस आर्थिक सामाजिक संक्रमण में क्रांतिकारी भूमिका के समापन के लिए उसे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अन्य सहयोगी वर्गों के साथ संयुक्त मोर्चा की आवश्यकता थी। अपने मुख्य कार्य क्षेत्र-बिहार के किसानों की आर्थिक दशा के संबंध में उनका मूल्यांकन था कि बिहार अन्य प्रांतों की अपेक्षा ज्यादा कृषि-प्रधान होते हुए भी अपनी आर्थिक दशा में सबसे ज्यादा दयनीय था, और इस दरिद्रता के मुख्य दो प्रभाव सामने आएः (1) किसान उन छोटी-मोटी सुविधाओं में भी वंचित रह गए जो कानून-द्वारा प्राप्त थी, और जिनका लाभ उन्हें मिलना चाहिए था और (2) इस प्रांत का राजनैतिक आंदोलन किसानों की मौलिक मांगों के प्रति उदासीन रहा।[32] अतः दोनों त्रुटियों का निदान अविलम्ब हाने के लिए स्वामी जी ने एक कार्य-नीति का निरूपण किया कि तत्कालीन आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में किसानों को उनके कानून प्रदत्त मांगे मिल जानी चाहिए तथा किसानों को स्वयं अपने हकों की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

इन दोनों मांगों की पूर्त्ति के लिए स्वामी जी की रणनीति रही कांग्रेस के साथ मिलकर इसके लिए आंदोलन गठित करना; क्योंकि साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन में इसी तरीके से कांग्रेस किसानों के साथ घनिष्ठ संबंध कायम कर सकती है। इन मांगों की प्राप्ति के लिए संगठित वर्गीय आंदोलन को गठित करने का कार्य किसान सभा करेगी, जो आंदोलन का केन्द्र बिन्दु होगी। स्वामी जी की परिकल्पना में "संघ शक्ति"[33] या किसान आंदोलन में किसानों की व्यापक भागीदारी के साथ-साथ उन तमाम तत्त्वों, कारकों एवं शक्तियों का संगठित मोर्चा जो मुख्यतः खेती के कार्यों से जीविकोपार्जन करते हैं। किसान-सभा के नेतृत्व में स्वामी जी ने उन तमाम वर्गों, रैयतों, छोटे जमींदारों और मजदूरों को संगठित करने की रणनीति का आश्रय लिया जो व्यापक पैमाने पर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा निर्मित भारतीय अर्थतंत्र में शोषण का शिकार हो रहे थे, क्योंकि भू-राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेज कर वहां की औद्योगिक क्रांति को संचालित किया जा रहा था और सर्व सम्पदा सम्पन्न भारत गरीबी की वैसे कगार पर था जहां सिंचाई की न्यूनत्तम सुविधाएं भी किसानों को प्राप्त नहीं थीं।

भारत में, और खास कर बिहार में भू-संबंधों की जो व्यवस्था सरकार ने की थी, लगान की बंदोबस्ती और वसूली का जो तरीका अपनाया था, कर्ज के लेन-देन की जो प्रणाली चालू की गई थी उसमें साम्राज्यशाही के हितों को सर्वोपरि रखते हुए मध्यवर्ती शोषकों के स्वार्थों को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास भी शामिल था। इस कारण किसान-सभा जिसे क्रांति का वाहक माना गया था, आंदोलनों के द्वारा जमीन बंदोबस्ती, लगान वसूली, कर्ज गुलामी की दकियानूसी नीति आदि का समूल नाश नहीं करती तब तक किसानों की सर्वमान्य गुलामी को नष्ट नहीं किया

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जा सकता। स्वामी जी के कार्यक्रम में किसान-संगठन की संयुक्त रणनीति के द्वारा भू-संबंधों में व्यापक परिवर्तन करने के लिए आंदोलनों की कार्यनीति का आश्रय लिया गया था। इस क्रार्यक्रम के अन्दर किसानों की मौलिक एवं तात्कालिक मांगों का समावेश किया गया।

स्वामी जी ने आर्थिक दर्शन की सबसे बड़ी विडम्बना, जो उनकी कार्यनीति एवं रणनीति को प्रभावित करता रहा, वह था आर्थिक क्षेत्र में उनके विचार मार्क्सवादी थे, परन्तु राजनैतिक क्षेत्र में तकरीबन 1934 तक गांधीवादी–एक ऐसे दर्शन के हिमायती जो स्वभाव में जमींदार-पक्षी और बातों में किसान-पक्षी था। अपने अनुभवों के सारगम्य तथ्यों के आधार पर किए गए वैचारिक अनुभवों में, जिसमें जमींदारी उन्मूलन के प्रति स्वामी जी आश्वस्त हो चुके थे, इन्होंने पाया कि गांधी जमींदारी मिटाने के पक्ष में नहीं थे।[34] स्वामी जी की ही रणनीति के तहत 1936 में जब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया तो उसकी मूल नीतियों के रूप में आर्थिक आजादी को विशेष महत्व दिया गया।

अखिल भारतीय किसान सभा की आर्थिक नीति तथा स्वामी जी

1936 के लखनऊ कांग्रेस महाधिवेशन के वक्त जिस अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानन्द सरस्वती बनाये गए थे। उनकी मूल आर्थिक नीतियां बिहार किसान-सभा की नीतियों से प्रेरित थीं और इसीलिए उनमें किसान-आंदोलन का लक्ष्य "आर्थिक शोषण से पूरी तरह मुक्ति तथा किसानों, मजदूरों और अन्य शोषित वर्गों द्वारा मुकम्मिल रूप से आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति हासिल करना"[35] स्थिर किया गया। इसमें कहा गया "जनता को आर्थिक और राजनीतिक शोषण से हर तरह का छुटकारा मिलने के साथ ही इसके हाथों में पूर्णरूप से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति आ जाए।"[36]

इस प्रकार किसान-सभा ने किसानों एवं अन्य शोषित वर्गों की आर्थिक मुक्ति के प्रश्न को राजनीतिक सत्ता के साथ संबंद्ध कर देखा और अर्थतंत्र में बुनियादी परिवर्तन के लिए राजतंत्र पर वर्गीय अधिकार के सिद्धांत को स्थापित किया।

अपने आखिरी लक्ष्य, राजसत्ता पर कब्जा को सुनिश्चित बनाने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा ने उद्घोषित किया "इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसान सभा किसानों को उनकी तात्कालिक मांगों के आधार पर संगठित करेगी और उनकी प्रतिदिन की लड़ाइयों को चलाएगी ताकि अन्य शोषित और पीड़ित दलों के साथ मिलकर किसान पूर्ण स्वतंत्रता के राष्ट्रीय युद्ध में भाग लें और

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जबरदस्त बनायें।[37] अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यक्रमों की विशेषता उसके लक्ष्य में प्रतिवादिता की गई थी जिसमें किसानों एवं मजदूरों के आपसी सहयोग की बातें पूरी तरह स्पष्ट होकर आई थीं। विश्व प्रगतिशील आंदोलनों के, जिसमें शोषण रहित समाज निर्माण की एक परिकल्पना छिपी थीं, साथ किसान सभा ने अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की, और 1936 में ही उन मजदूरों की याद में, जिन्होंने शिकागो में मजदूर-आंदोलनों का नेतृत्व करते हुए पुलिस की गोली से शहीद हुए थे, पहली बार मई-दिवस मनाया तथा पहली सितम्बर 1936 को किसान-दिवस में भाग लिया। किसान-सभा का यह कृत्य विश्व प्रगतिशील आंदालनों के, जो समाजवादी नारों के साथ साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों को चलाया जा रहा था, अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करता था।

किसानों एवं सरकार के मध्य भू-प्रबंध में रह रहे बिचौलियों को समाप्त करने के अपने कार्यक्रम के दौरान किसान-सभा को पहली सफलता फैजपुर में कांग्रेस द्वारा पारित "खेतिहर प्रोग्राम" के रूप में मिली और 1939 में गया में हुए चतुर्थ सम्मेलन में ज्यादा क्रांतिकारी कार्यक्रम को अपनाया गया जिसमें लाल झंडा हंसिया हथोड़ा के साथ किसान-सभा का झंडा स्वीकार कर सभा को विश्व क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ जोड़ दिया गया।

एक ऐसे समाज में जहां एक ही वर्ग के अन्दर आर्थिक तौर पर कई स्तर बने हुए थे, किसान-सभा के लिए जरूरी था कि वह अपनी मुक्ति-संघर्ष में अपने वास्तविक दुश्मनों की स्पष्ट पहचान कायम करे। प्रारम्भिक दिनों में किसान-सभा ने किसानों के भीतरी स्तरीकरण पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, यही कारण था कि उसका संगठन उच्च तथा उच्च मध्यमवर्गीय किसानों के संगठन के रूप में विकसित हो गया था जहां कई आर्थिक मांगों के ऊपर इसके अन्दर वर्गीय स्वार्थों को लेकर मतभेद पैदा हुआ करता था। स्वामी जी ने 1944 में अखिल भारतीय किसान-सभा के विजयवाड़ा सम्मेलन को संबोधित करते किसानों को उनके आर्थिक आधार पर वर्गीकृत किया था और कहा था "वे किसान कौन हैं जिनके नाम पर तथा जिनकी तरफ से हम बोलते हैं और काम करते हैं, और जिन्हें हम पूरे क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं? इस समय तो मंझौले और बड़े-बड़े खेतिहर ही अधिकांशतः किसान-सभा और उसके काम के साथी हैं और अभी सभा के वर्तमान दशा में दूसरी बात तो हो भी नहीं सकती। साफ तौर पर कह सकते हैं कि वही दोनों तरह के खेतिहर किसान सभा का उपयोग अपने हित और लाभ के लिए कर रहे हैं। साथ ही हम भी सभा को मजबूत करने के लिए या तो उन दोनों का उपयोग तबतक करते या करने की कोशिश करते हैं जबतक खेतिहारों में सबसे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नीचे दर्जे वालों तथा ऊपर वालों में अपने राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों और जरूरतों की पूरी जानकारी नहीं हो जाती और उनमें वर्ग-चेतना नहीं आ जाती। लेकिन सच पूछिये तो अर्ध सर्वहारा या खेत-मजदूर ही जिसके पास या तो कुछ भी जमीन नहीं है या बहुत ही थोड़ी है और टुटपुंजिये खेतिहर को अपनी जमीन से किसी प्रकार काम चलाने और गुजर बसर करते हैं यही दो दल हैं जिन्हें हम किसान कहते हैं।"[38] इस प्रकार आर्थिक आधार पर स्वामी जी ने किसानों का स्तरीकरण बड़े किसान, मंझौले किसान, खेत मजदूर और टुटपुंजिये किसानों की श्रेणियों उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर किया और उत्पादन के साधनों भूमि पर उनके स्वामित्व के हिस्से के आधार पर किया।

स्वामी जी किसानों के इस वर्ग विभेदीकरण को आगे बढ़ाते हुए पुनः कहते हैं "........... अन्ततोगत्वा वही लोग किसान सभा बनाएंगे, उन्हें ही ऐसा करना होगा। जबकि दूसरे लोग किसान-सभा में रहते हुए भी किसान-सभा के नहीं हैं, ये दोनों सभा में है, और सभा के हैं। फलतः हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके पास पहुंचे, उन्हें उत्साहित करें, और किसान-सभा में उन्हें लाएं। जबतक हम इस यत्न में सफल नहीं हो जाते तब तक हमारा काम बराबर अधूरा और अपूर्ण ही रहेगा। समाज के जो स्तर और दल जितने ही गरीब और नीचे हैं उतने ही वे हमारे निकट हैं। इसलिए जो सबसे नीचे के या खेत मजदूर है और हरिजन हैं उतने ही वे हमारे निकट हैं। उनके बाद टुटपुंजिये खेतिहर आते हैं और बस वहीं पर किसानों का वर्ग खत्म हो जाता है। हम मझौले खेतिहारों को सिर्फ तटस्थ बना सकते हैं बस ताकि वे शत्रु का पक्ष न लें। लेकिन आखिरी लड़ाई में वे साथ देंगे यह आशा हम नहीं कर सकते।[39] वे पुनः कहते हैं, "लेकिन अफसोस है कि ये असली किसान समाज के ऊपरी तबके वाले हमलोगों में विश्वास नहीं करते" उन्हीं में से हमलोगों में जो किसान-सभा के विकास की वर्तमान दशा में अधिकांशतः उसमें काम करते हैं और चलाते हैं। यह है भी ठीक ही। इसीलिए हमारा अनिवार्य कर्तव्य है कि हम अपने अकल और बर्ताव के द्वारा उनके प्रति अपनी नेकनीयती का सबूत दें और इस तरह अपने को उनका प्रिय पात्र बनावें।"[40]

इस तरह का किसान वर्ग के प्रति एक वैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि, जो आंदोलन और संगठन में आर्थिक एकात्मकता स्थापित कर सके, इसका प्रमाण है कि स्वामी जी का दृष्टिकोण गांधी के ट्रस्टीशिप के आर्थिक सिद्धांतों से सर्वथा भिन्न था, इसमें ग्रामीण सर्वहारा, शहरी गरीब तबका तथा टुटपुंजिए किसानों के वर्गों के एक संयुक्त मोर्चा की परिकल्पना साम्राज्यवाद तथा देशी रजवाड़ों बड़े भूपतियों एवं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जमींदारों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान था। आर्थिक आजादी के जिसका मतलब स्वामी जी के लिए शोषणमुक्त समाज की कल्पना थी, बिना किसी अन्य तरह की सभी आजादियां भ्रामक तथा पूंजीवाद की पोषक कल्पनायें थीं जिन्हें स्वामी जी पूंजीवादी प्रजातंत्र कहते थे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जमींदार, जो साम्राज्यशाही तथा किसानों के बीच मध्यवर्ती वर्ग थे, तथा शहरी अर्थ-व्यवस्था में पूंजीपति शोषक वर्ग थे जिनके खिलाफ स्वामी जी का संघर्ष अविराम चलता था। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में जमींदारी प्रथा तथा भू-लगान की प्रथा एक अवरोधक का कार्य करती थी, क्योंकि जमींदार मनमाना भू-राजस्व वसूल सकता था तथा बड़ा जमीन मालिक कृषि पर बिना कुछ खर्च किए कम से कम उसकी उपज का आधा भाग तो पा ही सकता था, इस कारण अपने अतिरिक्त धन का उपयोग वह अन्यथा कामों में लगाया करता जैसे कर्ज लगाने या व्यापार में साम्राज्यवादी आर्थिक नीति के चलते जिस अतिरिक्त श्रम का सृजन हुआ था वह जमीन के लगान को भुखमरी के लगान तक ला दिया था। इस कारण मध्यवर्ती जमींदारों को समाप्त करने के लिए 1934 में ही बिहार प्रांतीय किसान सभा के द्वितीय सम्मेलन में ही, जिसका सभापतित्व करने टण्डन जी आये थे, जमींदारी उन्मूलन का एक प्रस्ताव आया, जिसमें मुआवजा देकर जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान रखा गया था, तो उसका विरोध हुआ और इस विरोध में सोशलिस्ट भी शामिल हो गए।

स्वामी जी का प्रचलित नारा था "जमीन जोतने वाले की" और इसी आर्थिक नारे के तहत 1936-37 के चुनावों में शामिल होने के पहले कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में एक किसान प्रस्ताव तो जरूर पास किया मगर चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जब इस प्रस्ताव को लागू करने के बदले इसके प्रति किसी राजनीतिक इच्छा-शक्ति का प्रदर्शन ही कांग्रेस ने नहीं किया। युक्त प्रांत में एक ऐसा काश्तकारी कानून बनाया गया जिसकी वजह से हजारों एकड़ किसानों की जमीन को जमींदार हड़प गए। इस तरह का ही बिहार काश्तकारी कानून बनाने के लिए जब बिहार एसेम्बली में एक बिल आया तो किसान सभा के प्रबल विरोध के कारण उसे वापस लेना पड़ा था।

यों हम जानते हैं कि प्रारंभिक काल में स्वामी जी समझौतावादी थे। जमींदार तथा किसानों में टकराव को बहुत आगे नहीं बढाना चाहते थे क्योंकि इसका बुरा असर बड़ी लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ता। उन्होंने खुद लिखा है "शुरू में जब हमने किसान सभा को जन्म दिया तो किसानों तथा जमींदारों के समझौते तथा उनके हकों के सामंजस्य को सामने रखकर ही यह काम किया।[41] यह उस समय

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कांग्रेस के सिद्धांत के अनुरूप था। उन्होंने बाद में भी कहा है "मेरे मन में जो पहले पहल किसान-आंदोलन और किसान-सभा का ख्याल आया वह पक्के और कट्टर सुधारक या सुधारवादी की हैसियत से ही न कि सपने ये भी क्रांतिकारी की हैसियत से।"[42] लेकिन उनके अनुभवों ने उन्हें पूरी तरह विश्वस्त कर दिया कि जमींदार सुधरनेवाले नहीं हैं अतः उनका अंत होना ही चाहिए।

इस तरह के बिचौलियों की समाप्ति पर तथा उनके प्रति गांधी के समझौतावादी रुख के सबंध में स्वामी जी ने अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति करते हुए गांधी के हृदय-परिवर्तन को उनकी मान्य धारणा के संबंध में स्वामी जी ने कहा, कि अर्थ का संबंध सारी मान्यताओं को समाप्त कर देता है, अर्थ संबंध ही वह मौलिक संबंध है जो समाज के तमाम अन्य संबंधों को निर्धारित करता है। इस संदर्भ में स्वामी जी पूर्ण मार्क्सवादी हैं। उनके निजी अनुभवों ने उन्हें बताया और उन्होंने स्वयं कहा है कि "मेरे दिल में जो यह ख्याल कभी-कभी ही आता था कि शायद गांधी जी की बातें सही हो और जमींदार सुधर जायें, वह अमावा-टेकारी के जमींदारों की जमींदारी में जांच करते समय (किसान जांच समिति की ओर से) समूची घटना ने मेरे दिल पर अमिट छाप लगा दी कि जमींदारी मिटाने के सिवाय किसानों को अत्याचार और मुसीबतों से उबारने का कोई रास्ता है ही नहीं। मैंने दिल से मान लिया कि जमींदार ला-इलाज मर्ज है।"[43] उन्होंने अमावा, टेकारी आदि के इलाकों में जांच करने के दरम्यान यह समझ लिया कि ये जमींदार बड़े ही "बेशर्म और पक्के है। जरा भी टस से मस होने को तैयार नहीं। उल्टा मुझे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी आंखों का पर्दा खुल गया। सारी आशाओं पर पानी फिर गया। मुझे साफ दिखा कि ये लोग लाइलाज मर्ज में फंसे हैं, अब समझौता से शायद काम न चले।[44] वर्ग संघर्ष तथा वर्ग दुश्मन के प्रति स्वामी जी का यह दृष्टिकोण असमझौतावादी रुख का परिचायक है।

मुआवजा के साथ जमींदारी उन्मूलन के प्रश्न को स्वामी जी शोषण की प्रक्रिया को मान्यता प्रदान करने के बराबर मानते हैं; क्योंकि भूमि का एक उत्पादन के साधन के रूप में इस्तेमाल करनेवाले जमींदारों को मुआवजा देना उनके शोषण को मान्य करार देकर उन्हें पुरस्कृत करने या जमीन उनसे खरीदने के बराबर है, ऐसी धारणा स्वामी जी की थी।

किसान-सभा के माध्यम से स्वामी जी अर्थनीति और आर्थिक कार्यक्रम को राजनीति द्वारा देखते हुए उसे साधन तथा साध्य मानते हैं और इसलिए राजनीतिक हारजीत की परवाह किए बिना सदा किसानों के आर्थिक हित को ही देखते हैं और वैसा की कार्यक्रम चलाते रहते हैं। फलतः उनके लिए आर्थिक बातें तथा प्रोग्राम

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

साधन है, और राजनीतिक साध्य या लक्ष्य। यही वजह है कि 1936-37 में मामूली आर्थिक प्रोग्राम से ही उन्हें राजनीतिक स्रोत संभव था तो उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया, लेकिन 10-12 साल के बाद वैसा न देख उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का कार्यक्रम बना।

उक्त साध्य और साधन का संबंध स्वामी जी को किसान-सभा को मात्र अर्थवाद में डालने से ऊपर एक ज्यादा उच्च लक्ष्य, जो राजनीतिक लक्ष्य है किसान मजदूर राज्य की परिकल्पना की तरफ ले गया। स्वामी जी का यही लक्ष्य बुनियादी तौर पर उन्हें कांग्रेस से, जो राजनीति के आइने में अर्थनीति का अवलोकन करती है, भिन्न स्थान पर खड़ा कर देता है, क्योंकि किसान सभा अर्थनीति के आईने में राजनीति को देखती है।

कांग्रेस और किसान सभा अर्थनीति के संबंध में

अखिल भारतीय किसान-सभा के चतुर्थ अधिवेशन जो गया में सम्पन्न हुआ, के दस्तावेज कांग्रेस और किसान-सभा के आर्थिक वर्गाधार, स्वार्थ और वर्गीय राजनीति का खुलासा करता है और परिणाम निकलता है कि किसान सभा का एक जन-संगठन के रूप में स्वतंत्र भूमिका की जरुरत है, क्योंकि किसान-सभा का आर्थिक वर्गीय टकराव कांग्रेस से शुरु हो गया था। जमींदारों का सहयोग किसान सभा को एक खास कालक्षेप में मिला, जब उसका लक्ष्य, उसकी कार्यनीति और रणनीति वर्ग समन्वयवादी गांधीवाद के पीछे चलता रहा। मगर साम्राज्यवाद के खिलाफ के किसान आंदोलनों में आए निखार ने वर्गीय ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को तेज किया और सामंती तत्व, जमींदार तथा बड़े किसान क्रमशः उससे अलग होते गए। हालांकि चुनावों में किसान-सभा ने कांग्रेस का साथ दिया था। गया में आहूत चतुर्थ अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष[45] ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा, "मैं शुरू में चाहे कुछ भी रहा हूं, लेकिन साम्राज्यशाही के साथ ज्यों-ज्यों हमारा संघर्ष जोरदार होता गया त्यों-त्यों जमींदार और मालदार उससे खिसकते गए और किसान तथा दूसरी पीड़ित जनता उसमें उत्तरोत्तर जम कर भाग लेने लगी।"[46] उक्त उद्धरण साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में विभिन्न वर्गों की स्थितियों का एक उदाहरण प्रस्तुत करता तथा साम्राज्यवाद के साथ जमींदारों और मालदारों को एक ऐसी एकता को स्पष्ट करता है जिसका मूल स्वरूप अवाम की लूट की गारंटी करनेवाला है।

कांग्रेस जिन निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व कर रही थी उनकी स्थिति के संबंध में महाधिवेशन में स्वागताध्यक्ष की, जो किसान-सभा की नीतियों को ही

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अपने भाषण में उल्लिखित कर रहे थे, राय या अवधारणा क्या थी–वह थी निहित स्वार्थों की रक्षा, हालांकि चुनावों में "......... आम तौर से धनिक वर्ग ने .... कांग्रेस का संगठित विरोध किया, वहां किसानों और अन्य पीड़ित लोगों ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पर, स्वाभाविक तौर पर इसलिए यकीन किया कि कांग्रेस के सत्याग्रह-संग्राम में उन लोगों ने ही उसे ताकत दी थी"।[47] लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के बाद कांग्रेस ने उन लोगों के स्वार्थों को छिपा दिया, जिन्होंने उसे चुनावी आंदोलनों में सफलता हासिल कराई थी और उन्हीं का स्वार्थ सर्वोपरि हो गया जो चुनावी राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ थे। "उनके और कांग्रेस के दुश्मन एकाएक कांग्रेस के नेता और मददगार बनकर[48] किसानों को ही कुचलने का चक्र चला रहे थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने निहित वर्गीय स्वार्थ में बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास आदि प्रांतों में जो कुछ किया बिहार इनमें सबसे आगे , इस अर्थ में रहा कि यहां निहित स्वार्थों का दबाव और ज्यादा था। अगर कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कुछ जनहित का कार्य किया भी तो चुनाव घोषणा-पत्र में उनके उल्लेख किए जाने के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि जमींदारों की ऐंठन और ऐन मौके की भूल के साथ ही एसेम्बली के कांग्रेसी मेम्बरों के बहुमत ने उनके लिए दूसरा चारा ही नहीं छोड़ा था"।[49] स्वागताध्यक्ष का भाषण कांग्रेस के वर्ग चरित्र को उजागर करता है तथा स्पष्ट करता है कि साम्राज्यवाद विरोध के संघर्ष में कांग्रेस विभिन्न आर्थिक स्वार्थों का एक प्लेटफार्म बन जाती है और राजनीतिक मांगों की पूर्ति के बाद अपने निहित स्वार्थों के लिए साम्राज्यवादमुखी शक्तियों के साथ भी मोर्चा करने तथा किसानों और मजदूरों के स्वार्थों पर हमला करती है– यही इसका दोहरा चरित्र अर्थतंत्र में देशी पूंजी का विदेशी वित्तीय पूंजी के विरोध में ला खड़ा कर देता है। कांग्रेस के नेता इसी कारण कांग्रेस को विभिन्न वर्ग शक्तियों का संयुक्त मोर्चा न बता कर एक राजनीतिक पार्टी के रूप में ज्यादा गठित करते हैं जो उच्च मध्यम वर्ग तथा देशी पूंजी की रक्षा में हमेशा खड़ी रहे, किसानों-मजदूरों की मांगों से मुंह मोड़कर।

किसान-सभा की स्वतंत्र भूमिका का प्रदर्शन कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन के बाद उसके द्वारा किए गए चुनावी वादों की तरफ लगातार ध्यान आकृष्ट कराने के बाद भी जब मंत्रिमंडल निहित स्वार्थों की भरपाई में लगा रहा तब बिहार में किसान-सभा को सत्याग्रह पर जाना पड़ा। इस दरम्यानी दौर में कांग्रेस और जमींदारों का अभूतपूर्व मोर्चा लगा तथा निहित स्वार्थों की रक्षा के रूप में राजसत्ता सामने आया, किसानों को दबाने के लिए वे सिर्फ गुंर्खे और घुड़सवार भेजे गए, बल्कि ऐसे स्पेशल ऑफिसर भेजे गए जिन्होंने खुले आम जमींदारों की

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

तरफदारी की और किसानों को हर तरह से पामाल किया"[50] इसका नतीजा जमींदारों का खुला दमन किसानों के खिलाफ फसल लूट, बेदखली, मार-पीट आदि में परिणत होता गया।

ऊपर के तथ्य राजसत्ता के उस स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं, जिसे मार्क्स, एंजिल्स तथा लेनिन ने स्थापित किया कि राजसत्ता के साधनों के स्वामियों की रक्षा का संगठित गुण्डा-गिरोह है।[51] स्वागत-भाषण में कहा गया, "जमींदारों का दारोमदार और पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व संगठित हिंसा पर है।"[52]

खेत-मजदूरों को जीवनोपयोगी मजदूरी देने, बेगार आदि के खिलाफ संघर्ष करने की किसान-सभा की कार्रवाइयों को नकारने वाले एक अलग मजदूर-संगठन की बातें करते हैं। किसान-सभा के मूल उद्देश्यों का विश्लेषण करते हुए स्वीकार किया गया कि यह कांग्रेस का अंग नहीं, वरन एक स्वतंत्र राजनीतिक वर्ग संस्था है, जिसका उद्देश्य है "कांग्रेस को पूर्णरूपेण से जनतंत्रीय संस्था बनाना और स्थित स्वार्थों के प्रभुत्व से उसे बचाना और अलग रखना। हर हालत में जनता की वास्तविक आजादी के लिए किसानों, मजदूरों, विधार्थियों, नवजवानों और निम्न मध्यम श्रेणी के अन्य शोषितों का एक संयुक्त मोर्चा बनाना इसका काम है।[53] इस प्रकार किसान-सभा को एक वर्गीय संगठन के रूप में इसे आगे लाने के प्रयास में इसे साम्राज्यवाद-विरोधी तमाम ताकतों को एक जुट करने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि यही शोषण की अर्थ-व्यवस्था का मूल धारक और पोषक था। इस प्रकार यह कांग्रेस की प्रतिद्वन्द्वी संस्था न होकर किसानों का एक ऐसा संगठन बना जो हर तरह के दमन का विरोध करता रहा।

कांग्रेस के संबंध में लिखते हुए स्वामी जी ने कहा कि यह जमींदारों एवं धनियों का संगठन बन गया तथा स्वार्थी तत्त्व उस पर हावी हो गये। 1934 के बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के बाद कांग्रेस चरित्र पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है "इस प्रकार स्थिर स्वार्थ वाले जमींदारों और पूंजीपतियों की जड़ कांग्रेस में जमाने का सूत्रपात वहीं हुआ।"[54] उन्होंने अपना विरोध चवनिया मेम्बरों पर भी किया था क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा होने पर उसमें गरीब की गुंजाइश न होगी तथा धनी पैसे के बल पर नकली मेम्बर बना कर कांग्रेस पर कब्जा कर लेंगे[55] इस तरह कांग्रेस के बारे में उनकी राय बनी कि यह आम जनता एवं किसानों के हितों का रक्षा सही ढंग से नहीं कर सकती।

एक वर्गीय संस्था के रूप में किसान-सभा की स्वतंत्र भूमिका पर स्वामी जी ने जोर देते हुए कहा था "कांग्रेसी प्रगतिशीलता एवं लक्ष्य की सफलता के लिए भी जिस किसान दबाव की सख्त जरुरत है, उसके लिए स्वतंत्र किसान-सभा का होना नितांत आवश्यक है"।[56]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

1940 के बाद के वर्षों में कांग्रेस तथा स्वामी जी के विचारों में जो वर्गीय कटुता थी उसने एक तीखापन को जन्म दिया जिसने आगे चलकर उन्हें कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया।

वर्ग-संघर्ष और राष्ट्रीयता

किसान-सभा को स्वामी जी एक वर्ग-संस्था मानते हैं, जिसका उद्देश्य किसानों के शत्रुओं जमींदारों एवं मालदारों के खिलाफ संघर्ष कर आर्थिक एवं राजनैतिक आजादी हासिल करना है इसीलिए सभी जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदि के उन लोगों की संस्था किसान-सभा है, जिन्हें खेती करनी पड़ती है। प्रति वर्ष नौ लाख से ज्यादा किसान आर्थिक शोषण के कारण अपनी भूमि गंवाकर मजदूर बनते जा रहे हैं। इस तरह हक की लड़ाई ही चिन्हित होती है, क्योंकि जाति, धर्म या सम्प्रदाय के आधार पर किया गया वर्गीकरण एक धोखा है। स्वामी जी राष्ट्रीयता को भी वर्ग-हित के आर्थिक मुद्दों से जोड़कर देखते हैं जैसा कोई मार्क्सवाद देखता है। स्वामी जी की विशिष्ट धारणा है कि राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता को भी वर्गीय परिभाषायें की जाती है, क्योंकि किसान-मजदूर एकता जो आर्थिक-राजनीतिक मुद्दों पर समान शत्रु पूंजीपति वर्ग के खिलाफ बनता है, को मालिक वर्ग पूंजीवादी अर्धराष्ट्रीयता को सामने रख वर्ग चेतना के उभार को ढंकने, उसे कुन्द करने के लिए सामने लाते हैं। स्वामी जी सर्वहारा के अन्तर्राष्ट्रीयतावाद को मजदूर वर्ग के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में मानते हैं, और पूंजीवादी के जिसका स्वरूप अन्तरराष्ट्रीय रूप ग्रहण कर चुका है, खिलाफ मुक्ति-आंदोलन में एक ऐसा हथियार मानते हैं जो सर्वहारा के विश्वबन्धुत्व को सबल बना उसे भविष्य के संघर्षों के प्रति शोषण के खिलाफ प्रतिबद्ध योद्धा को भांति अडिग रखता है। राष्ट्रीयता वर्ग से परे कोई चीज नहीं है, उनका कहना था, "राष्ट्रीयता सुन्दर और उपयोगी होने" के बावजूद भावुकता की वस्तु है। भावना और दिमाग की चीज है, महज ख्याली पदार्थ है। वह कोई ठोस और भौतिक वस्तु नहीं है, ठीक उसी प्रकार जैसे धर्म, ईश्वर, स्वर्ग, नरक आदि है। इसीलिए समय-समय पर जर, जोरु, जमीन के सामने टिक नहीं सकते। इनकी अवहेलना होती है और लोग जमीन जायदाद के लिए गंगा-तुलसी, कुरान-पुरान की झूठी कसमें खाते हैं। इस प्रकार भौतिक हितों के अन्तर्विरोध में यह राष्ट्रीयता टिक नहीं सकती। इसे मिट जाना होगा। इसीलिए नेता लोग किसानों के भौतिक स्वार्थों की बातें कभी-कभी किया करते हैं। भावनामय राष्ट्रीयता भौतिक स्वार्थों को ही लेकर टिक सकती

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है, लक्ष्य-सिद्धि में कामयाब हो सकती है। यदि हम भौतिक स्वार्थों को वह छोड़ दें या इससे टकरा जाए तो उनके लिए बेशक खतरा पैदा हो जाएगा।"[57]

स्वामी जी की स्पष्ट धारणा थी कि जबतक शोषित वर्ग समूह अपने हितों के प्रति जागरुक नहीं होगा, उसके लिए संघर्ष नहीं करेगा, संघर्ष में आवश्यकतानुसार आदमी, धन, समाज आदि मुहैया नहीं कराएगा तब तक शोषण में नाम मात्र भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि शासक और शोषक वर्ग का कोई आदमी अपने वर्ग हित के खिलाफ नहीं जाएगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो वह अपने सम्पूर्ण अस्तित्व में उस वर्ग से अलग हो जाएगा। इस प्रकार व्यक्ति का स्थान, जैसा स्वामी जी आंकते हैं, इसके वर्गीय दृष्टिकोण से होता है। गांधी को विडम्बना, ऐसा स्वामी कहते हैं, यह थी कि हृदय-परिवर्त्तन से आदमी को बदलना था, मगर भौतिक स्वार्थों की पूर्त्ति में इस तरह काल्पनिक दर्शन का कोई महत्व नहीं रह जाता।

किसान अपनी बदहाली के खिलाफ जंग में एकजुट होकर लड़े या इस कारण भी जरूरी बन जाता है कि जमींदार पूंजीपति जमींदारी तथा पूंजी की शक्ति को बरकरार रखने के लिए किसानों की गरीबी, भुखमरी को यथास्थिति रखना चाहते हैं। मगर जमींदारी या पूंजीपतियों को खत्म करने से पूंजीवादी या जमींदारी-शोषण खत्म नहीं होगा, बल्कि इसके लिए इनकी आर्थिक शक्तियों को क्रांतिकारी ढंग से खत्म करने के लिए किसानों-मजदूरों को वर्ग-संघर्ष करना होगा। गांधीवाद इस कारण असफल हो गया कि एक भला जमींदार चाहकर भी किसानों की खुशहाली नहीं लौटा सकता जबतक पूंजी और भू-स्वामित्व में परिवर्तन लाकर उनकी आर्थिक शक्ति को क्षय न कर दिया जाता। इस संबंध में स्वामी जी लेनिन को हमेशा उद्धृत करते थे कि "हमें धैर्यपूर्वक जनता को जगाने में लगाना चाहिए। अपना कार्यक्रम जनता पर न लादकर उन्हें इस तरह तैयार किया जाए कि वह कार्यक्रम स्वयं बनाकर इस पर अमल करे। ये बातें मुक़म्मिल करती है कि अधिक जागृत जमात जब क्रांति करता है तो कम-से-कम नुकसान के साथ सफलता मिलती है।[58]

सर्वहारा की अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रति स्वामी जी की प्रतिबद्धता का प्रमाण उनके विजयवाड़ा में किसान-सभा के 8वें अधिवेशन के मौके पर दिए गए अध्यक्षीय भाषणों में मिलता है जब वे कहते हैं किसान-मजदूरों को तंगहाली को दूर करने के बुनियादी उद्देश्यों के तहत सम्पूर्ण विश्व को मौलिक रूप से बदलना होगा, उसमें कोई सुधार कार्य, जो फटे कपड़े में पेबंद की तरह का है इस उद्देश्य की पूर्ति, नहीं कर सकता, इस तरह के मौलिक परिवर्तनों के लिए दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन की जरुरत है।[59]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

व्यापारिक फसलों के संबंध में स्वामी जी की अर्थनीति

1940 के दशक में युद्ध-जनित परिस्थितियों के कारण वस्तुओं की कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी पूंजी तथा भारतीय पूंजी को एक मौका दिया कि युद्ध की अर्थ-व्यवस्था में वे किसानों-मजदूरों का शोषण और ज्यादा करें। खास कर ईख और जूट ऐसी फसलें थी जिनके उत्पादकों को भारी संकट का सामना इस कारण करना पड़ रहा था कि इन फसलों की कीमतें बढ़े उत्पादन खर्चों की तुलना में काफी कम थी और इसी के साथ गांवों में उत्पादित होनेवाली गुड़ की स्थिति थी। जूट और ईख की कीमतों का निर्धारण पूंजीवादी बाजार-प्रणाली में लागू मांग और पूर्त्ति के नियमों पर आधारित था और इन फसलों की सबसे ऊंची कीमतें भी किसानों के लागत खर्चे के बराबर सम्भवतः कभी-कभी ही आता था। किसान-सभा अपने जन्मकाल से ही इस मांग को उठाती आ रही थी कि इन उत्पादकों को पूर्णतः बाजार के यांत्रिकी पर न छोड़कर इन्हें कुल लागत के साथ थोड़ा मुनाफा की गारंटी कराई जाए और उत्पादन लागत का आकलन करते समय जमीन की कीमत और उस पर आनेवाले ब्याज की रकम को भी उत्पादन लागत का अंत माना जाए। जूट तथा चीनी मिल मालिक अपने तमाम लागत खर्चों को शामिल कर उस पर अपना मुनाफा समेत चीनी की कीमत तथा जूट मालों का दाम रखते हैं तो किसान ऐसा न करें, इसके पीछे कोई तर्क नहीं आता। सरकार ईख की कीमत तय करने में मालिक पक्षी नीतियों को अवलम्बन करती है।

बिहार, बंगाल, यू.पी., आन्ध्र प्रदेश आदि का हवाला देकर स्वामी जी ने पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत किसानों की लूट में सरकार तंत्र तथा जमींदारों की सहभागिता का पर्दाफाश किया। इस प्रकार सरकार की बजट नीति, कराधान की नीति, बाजार अर्थव्यवस्था का एक खास किस्म से गठित कर श्रमजीवी जनता के शोषण का एक माध्यम बनाए रखने के इस तरीके का विरोध करते हुए कृषि तथा उद्योग को एक समान धरातल पर लाने की नीति के लिए संघर्ष किया।

गुड़ उद्योग, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का एक मुख्य उद्योग है, के प्रति सरकार की नीति काफी हिंसात्मक है, क्योंकि मूल्य-निर्धारण में एकरूपता का अभाव तथा प्रदेश से इसे बाहर ले जाने संबंधी सरकार की नीति रही है कि उत्पादक काफी हानि उठा रहे हैं। हालांकि सरकार ने प्रति मन गुड़ की कीमत 8 रुपया रखा है परन्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की उसकी परमिट नीति ने, जिसे प्राप्त करना प्रायः असंभव है, गुड़ की कीमत प्रतिमन गिराकर 5 रुपया तक ला दी है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी जी ने यह बताया है कि पूंजीपति कैसे अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए जाल बनाकर किसानों को ठगता है। बिहटा चीनी मिल का उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे कितने स्वार्थी होते हैं तथा इसकी पूर्त्ति के लिए पैसे, भुलावा तथा नेताओं को मिलाने तक के अनेक हथकंडे के प्रयोग में लाते हैं। मिल के संचालक श्री रामकृष्ण डालमियां का उदाहरण उन्होंने दिया है तथा कहा है "वहीं मैंने सीखा है कि मालदार और स्थिर स्वार्थ वाले पूंजीपति किस प्रकार से जनता को शोषण करते हैं।"[60] बड़े-बड़े नेता और महात्मा उनके शिकंजे में किस प्रकार फंसके उनकी मदद भी इस शोषण में करते हैं। उन्होंने बाद में लिखा है कि पूंजीपति अपने स्वार्थसिद्धि के लिए नेताओं या किसानों के रहनुमा को पैसे देकर उन्हें चुप कराना चाहते हैं। जिस तरह चोर गुड़ देकर कुत्ते को फंसाता है कि वह न भूंके ठीक कुछ वैसा ही पूंजीपति भी करता है। उन्हीं के शब्दों में "ठीक यही बात पूंजीपति करते हैं। ये हमें भूंकनेवाले समझ पहले से ही गुड़ डालते हैं।"[61] वे ऐसा करके सफल नहीं होते तो दुष्प्रचार तक शुरु करते हैं ताकि किसान नेता लज्जित हो, बदनामी के डर से किसानों को संगठित करना या उनके हित की बात छोड़ दें। उन्होंने चीनी मिल के मालिक के असली रूप को भांप लिया था अतः उन्होंने किसानों को आगाह किया कि वे गुड़ बनाना न छोड़े अन्यथा वे मिल के गुलाम हो जायेंगे तो उनके विरुद्ध मिलवालों ने जो दुष्प्रचार किया तथा अपना रूप दिखाया उसके बारे में स्वामी जी ने लिखा है "मैंने पूंजीवाद का नग्न रूप वहां देखा। ऐसे-ऐसे गंदे और झूठे प्रचार किसानों को धोखा देने के लिए किए गए कि मैं दंग रह गया। अन्त में यह प्रचार भी हुआ कि मैं मिल से दो हजार रुपए मांगता था और न मिलने पर ही विरोधी बन गया। .... किसान मुझे खूब जानते हैं। फलतः उनकी एक न चली और गुड़ बनाना जारी रहा।[62] इस तरह स्वामी जी ने पूंजीवाद के नग्न रूप का वर्णन किया है तथा बताया है कि वैसे जनहित-विरोधी होते हैं तथा अपने स्वार्थ की पूर्त्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं।

औपनिवेशिक दासता की इस बाजार-व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना स्वामी जी की आर्थिक नीतियों का एक प्रमुख भाग रहा, जिसका विशद विवेचन उन्होंने किया।[63]

झारखण्डी किसानों के लिए स्वामी जी की मांगें

1946 के बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने पूंजीवाद बाजार-संकट तथा उसके अन्दर हो रहे ईख-उत्पादकों को पुनः पटल पर लाया और सरकार की नीतियों को जिसमें ईख की कीमत कम तय की और प्रति मन दो

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आने की कटौती रखी, जिम्मेदार ठहराया और इसी को मुख्य कारण माना जिनकी वजह से बिहार की चीनी मिलें बंद हो रही हैं। उनकी राय में इस संकट का निदान सरकारी कमिटी का गठन, जो उचित मूल्य-निर्धारण की सिफारिश करें तथा उसमें किसान-सभा के प्रतिनिधि भी हों।[64]

बिहार कई खास समस्याओं के, जो बिहार के औपनिवेशिक शासन-काल में हुई असंतुलित आर्थिक विकास का फल थी, और जिसमें झारखण्ड समस्या, उनके गहरे शोषण की समस्या, जंगलों से संबंधित समस्यायें, बकाश्त की समस्या आदि के प्रति एकीकृत हल का प्रश्न रखा। झारखंड के किसान में स्वामी जी ने झारखंड क्षेत्र में रहनेवाले किसानों के शोषण तथा खुले लूट की एक सतही (प्रथम स्तरीय) विश्लेषण प्रस्तुत किया है। बाहर के लोग, जिन्हें वे डिकूस कहते हैं, वहां आकर उस क्षेत्र की भूमि, जनता तथा प्रचुर साधनों का किस तरह शोषण किया है उसकी विस्तृत विश्लेषण इस पुस्तक में मिलता है। उन्होंने लूट के तरीकों तथा प्रकृति की जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। उन्हीं के शब्दों में "जैसे अथाह और अतल सागर के गर्भ में क्रीड़ा करनेवाले जीव-जंतुओं को फंसाने के लिए मनुष्य के दिमाग ने महाजाल तैयार किया है ...., ठीक उसी प्रकार इन झारखण्ड वासियों को फंसाने और इनका रक्तमांस बगैर सभी कुछ चाट जाने के लिए चतुर खिलाड़ियों और काइयां यारों ने ढूंढ़ निकाले हैं। ऐसे जाल बिछाए गए हैं कि यदि एक से बचे तो दूसरे, नहीं तो तीसरे, चौथे में तो खामखाह फंसेंगे ही।"[65] ये बेचारे सीधे-साधे लोग फंस के छट्टपट्ट करते और तिलमिला के मरते रहते हैं। बनिये, महाजन, सूदखोर व्यापारी, जमींदार, सरकार, सरकारी अधिकारी तथा जंगल अधिकारी, ईसाई तथा जैन धर्मावलम्बी टाटा इत्यादि सभी झारखण्ड क्षेत्र में घुस गए हैं और इन भोले लोगों को हर तरह लूटते हैं। स्वामी जी कहते हैं "इस प्रकार चारों ओर से जमीनें और कमाई लुट रही है और वे तबाह हो रहे हैं।"[66] सर्वे तथा उसी केवल कानून की छत्रछाया में लोग पानी, घास-पात, लकड़ी, जलावन, फल-फूल आदि वहां के सब पदार्थों से बुरी तरह वंचित कर दिए गये हैं उनकी दुर्दशा ऐसी है कि उनकी खबर लेने वाला कोई दिखता नहीं। ऐसा उद्गार स्वामी जी ने व्यक्त किया है। उनके अनुसार "झारखण्ड की भूमि तो, सोना पैदा करती है, अपार सम्पति देती है। इसका अबरक, इसका कोयला, इसका लोहा, इसकी कीमती लकड़ियां और इसके रंग बिरंगे पत्थरों के चलते देश-विदेश के लोग करोड़पति बन बैठे हैं, बनते चले जा रहे हैं। .... बम्बई से टाटा ने असंख्य धन कमाया है-लूटा है। मगर पांव तले अन्धेरा है। खुद इसी इलाके के लोग दरिद्र के दरिद्र है।"[67] झारखण्डी खुद गरीब हैं लेकिन गैरों को मालामाल बना दिया है। इस

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रकार स्वामी जी ने झारखण्डवासियों के दुर्दशा, उनके शोषण तथा गरीबी का चित्रण प्रस्तुत किया है जो दर्दनाक है। झारखण्ड क्षेत्र की जनता अशिक्षित एवं अनपढ़ है जिसके कारण भी आसानी से शोषण का शिकार बनती है। काश्तकारी कानून भी जमींदारों के हक में बना है। किसान की जमीन पर लगी पलास, कुसुम इत्यादि वृक्ष जिस पर लगी लाह बेचकर वे पैसे इत्यादि कमा लेते थे, उसे भी गुरुघंटाल जमींदारों ने अपने नाम कब्जा लिखवा लिया है। इस तरह जंगल एवं उसके पेड़ों का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। जंगल के अधिकारी तथा गार्ड भी उन पर कहर ढाते हैं। किसान ऊंची लगान वसूलते हैं लेकिन न तो पीने के पानी के लिए पर्याप्त कुंए हैं और न सिंचाई के लिए आहर नहर। साथ ही किसानों को कानूनी मदद मिलने की भी काफी दिक्कत है। झारखण्डी किसानों की मांगों की एक फेहरिश्त प्रस्तुत करते हुए उनको सर्वांगीण उन्नयन के लिए स्वामी जी ने मांगे रखीं जो उनकी पुस्तक 'झारखण्ड के किसान' के अन्तिम तेरहवें अध्याय के रूप में हैं। उनकी मुख्य मांगे, जिसे स्वामी जी उनकी उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे, ये हैं:[68]

(क) किसानों के खेतों या उनकी सीमा पर लगे कुसुम, बेर, पलास वगैरह पर लाह लगाने और चुनने का पूरा हक बिना कुछ दिये किसानों को हो और इसके विपरीत सर्वे आदि में लिखित बातें रद्द की दी जाए।

(ख) घर-गृहस्थी तथा जीविका चलाने के लिए उन्हें जंगलों और पहाड़ी से फल-फूल, कंद-मूल, साग-तरकारी, शहद वगैरह, पत्थर, बालू, लकड़ी, बांस, कांट-कुश, जलावन, पत्ते, घास वगैरह लाने का पूरा अधिकार हो और उसमें कोई रोक-टोक ने कर सके। खेतों या जंगलों में लगे महुआ के फूल और फल बेटोक चुनने का उन्हें हक हो और एतदर्थ उन्हें कुछ भी देना न पड़े।

(ग) टंगकर, बनकर, पतकर, चुल्हकर, खरचरी, भसौंघा आदि के नामों से लगे कर या हानेवाली वसूलियां नाजायज करार दे दी जायं।

(घ) किसानों और उनके पशुओं के पीने वगैरह के लिए शुद्ध जल की जरुरत के अनुसार स्थान-स्थान पर कुंए आदि के जरिए पूरा प्रबंध किया जाए। सोते, झरने आदि जहां कहीं भी हो वहां उन्हें और उनके पशुओं को बेखटके आने-जाने की पूरी व्यवस्था कर दी जाए और रास्ता बना दिया जाए।

(ङ) एकाएक करके सभी काजीहौस, अड़गड़े या कैट्ल बाउण्ड जल्द हटा दिया जाए।

(च) कोड़कर और उलटकर जमीन तैयार करने का निर्बाध हक किसानों को रहे और इस बारे में जो भी शर्तें या रोक अब तक हो सभी रद्द कर दी जायं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(छ) संथाल परगने के दामिन कोह इलाके के पहाड़िया किसानों के लिए कुरांव या झूमचास की पूरी आजादी बराबर कायम रहे और उसमें जो भी रुकावटें हों वे फौरन उठा ली जायं।

(ज) कोड़कर या उलटकर जमीनों के तैयार हो जाने के कम-से-कम पांच साल बाद ही उनका लगान तय हो और वह आस-पास की सबसे कमजोर जमीनों के लगान से हर्गिज ज्यादा न हो। आमतौर से वह आधा ही हो।

(झ) यहां का लगान सरकारी मालगुजारी से 30-40 गुणा होने के कारण बहुत ही कम कर दी जाय।

(ञ) यहां का काश्तकारी कानून बिहार काश्तकारी कानून जैसा ही हो और उसमें आदिवासियों के खास लाभ की ही बातें विशेष रूप से जोड़ी जायं। मगर जमींदारों के लिए कोई खास अधिकार न रहे।

(ट) सेवकाई, कमिऔती, कमिया आदि नामों से प्रचलित गुलामी प्रथा का नामोनिशान सख्ती के साथ मिटा दिया जाय।

(ठ) आदिवासियों एवं पिछड़े लोगों को अपनी भाषा मे उनकी शिक्षित करने के लिए स्कूल वगैरह खोले जायं और हर तरह की ऊंची शिक्षा मुफ्त देने का प्रबन्ध किया जाय।

(ड) आदिवासियों एवं पिछड़े लोगों की भाषा एवं रस्म रिवाजों के जानकार हाकिम हो, उनके केशों का फैसला करें ऐसी व्यवस्था की जाए और कचहरियों में काम करने वाले वकील-मुखतार आदि पर ऐसा नियंत्रण रखा जाए कि वे उन्हें किसी तरह की गड़बड़ी में न डाल सकें।

(ढ़) इनके लिए जो कानून या व्यवस्था बने उसका मुस्तैदी के साथ उनमें बखूबी प्रचार करके उन्हें अच्छी तरह समझाने का प्रबंध हो।

(ण) अबरख का चून तथा खोद निकाल कर जीविका करने वाले ग्रामवासियों के रास्ते की सभी रुकावटें फौरन हटा ली जाएं और कोयले की खानों के ऊपर की जमीनों को खेती-बाड़ी में होने वाली किसानों की सभी दिक्कतें पूरी कर दी जाए।

(त) एक से ज्यादा जुडिसियल कमिश्नर मुकर्रर किए जाएं ताकि मुकदमों के फैसले में ज्यादा देर न हो।[69]

आदिवासी किसानों के सर्वतोमुखी आर्थिक मांगों को उठाते हुए स्वामी जी ने ब्रिटिश शासन काल की उपेक्षा नीति और असंतुलित आर्थिक विकास के कुपरिणामों के विकल्प में इन मांगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। स्वामी जी द्वारा निर्देशित इन आर्थिक असंतुलन के प्रति उदासीनता की नीति के कारण ही सम्पूर्ण झारखण्ड

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

क्षेत्र आज पृथकवादी आंदोलन को चला एक अलग राज्य की मांग कर रहा है और शासक वर्ग को उसके प्रति अभी सही रुख अपनाने में संकोच सा प्रतीत होता है।

झारखण्डी किसानों की स्थिति इस बात का सूचक है कि विकास की पूंजीवादी नीति एक सार्वभौम राजसत्ता के अन्दर ही विकास की असंतुलित प्रक्रिया के जरिए एक क्षेत्र का शोषण दूसरे तथा पिछड़ी जातियों का शोषण विकसित जातियों द्वारा किए जाने की संभावना प्रस्तुत करती है, जिसका राजनीतिक प्रस्फुटन अलगाववादी आंदालनों को जन्म देता है जिस प्रक्रिया में विकसित तथा अविकसित दोनों ही क्षेत्र अपनी स्वतंत्र स्थितियों के लिए मुख्य इकाई से अलग होने का आंदोलन, तेज करते हैं- जैसा आज बिहार में झारखंड कर रहा है तथा पंजाब कर रहा है तथा पंजाब में खालिस्तान आंदोलन, असम में बोडो तथा दक्षिण भारत में प्रविडिस्वस का नारा लगाया जाता है। इन आंदालनों के स्वभाव में जो भी तत्व या कारक कार्य करते हों कारण सबका एक है- विकास का असंतुलित होना।

अपने झारखंडी आर्थिक दर्शन में स्वामी जी किसी क्षेत्रवाद या समुदायवाद के पिष्टपोषक नहीं है, बल्कि विकास की इस प्रक्रिया के विरोधी हैं जो आर्थिक असंतुलन को पनपाती है, बढ़ाती है तथा पुष्ट करती है। इस क्षेत्र के गैर आदिवासी मजदूरों की चिन्ता भी बराबर हैं गिरिडीह, बरमों, टाटानगर, झरिया आदि के मजदूरों का ठेकेदारों द्वारा शोषण अफसरशाही का वेमरौवतपूर्ण व्यवहार, भुखमरी की तनखाह, और अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की किल्लत उन्हें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि "मजदूरों की यूनियनें स्थान-स्थान पर बने, उसमें हर एक मजदूर अवश्य शरीक हो और मेम्बर बने और इस तरह यूनियनें खूब मजबूत बनाई जाए।.............."[70]

झारखण्डी किसानों के साथ-साथ स्वामी जी अन्य किसानों की दिक्कतों को भी जमींदारों की उत्पीड़क नीति का एक अंग मानते हैं, तथा इसे एक उपाय के रूप में जमींदारों का खात्मा एक आवश्यक शर्तें मानते हैं। जमींदार उनकी नजर में "सर्व सोखन सिंह[71] है जो 24 हजार वर्गमील पर कब्जा जमा, अबरख, कोयला, लोहा, जंगल आदि से करोड़ो रुपया तो प्रतिवर्ष वसूलता है, मगर सरकार को देता है मात्र एक से डेढ़ लाख रुपया।[72] इस कारण जमींदारी उन्मूलन बिना किसी मुआवजा के हो ऐसा स्वामी जी ने कहा- "लार्ड कार्नवालिस ने ब्रिटिश सत्ता और कारोबार को मजबूत करने के लिए जमींदारों का वर्ग पैदा किया और किसानों की जमीनें बेरहमी से छीनकर उन्हें दे दी। न्याय का तकाजा है कि हम भी मौका पाते हुए छीन लें।[73]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वकाश्त और कास्तकारी कानून के प्रति रुख

बिहार के भू-प्रबंध में बकाश्त जमीनों का प्रश्न तब बन गया जब जमींदारी उन्मूलन का आंदोलन तेजी से चला। चूंकि भारतीय कृषि-क्षेत्र में अंग्रेजों ने सामंती उत्पादन संबंधों कृषि का उदय नहीं हो पाया था। इस प्रकार के कृषि उत्पादन संबंधों की यह विशेषता होती है कि अनुपस्थित जमींदारियों का एक सिलसिला इस कारण बन जाता है क्योंकि जमीन पर आबादी का ज्यादा बोझ जमीन के लगान को भुखमरी के लगान की सीमा तक पहुंचा देता है। यही स्थिति बिहार की थी। जमींदारी उन्मूलन के लिए बढ़ रहे किसान संघर्षों ये घबराया जमींदार वर्ग वैसी जमीनों को, जिसका कोई दस्तावेजी सबूत किसानों के पास नहीं था, जमींदारों ने बड़ी तेजी से बदलनी शुरु की। बकाश्त आंदोलन के प्रति कांग्रेस का रुख जमींदार पक्षी होने के कारण किसान सभा के, जो इस वकाश्त आंदोलन को चला रही थी, कार्यों को बदनाम करने का एक सिलसिला सा चल पड़ा। कांग्रेस के चाल के प्रति स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, "किसान सभा ..... लुक्का चोरी खेलना नहीं जानती .... आज जो कुछ जमींदार कर रहे हैं, यदि वह रोका न गया तो हमें और सभा को इसमें मजबूरन पड़ना ही होगा।[74]

कांग्रेस मत्रिमंडल में जिस काश्तकारी कानून को संशोधित करने का प्रयास किया जा रहा था उसका स्वभाव ही किसान-विरोधी था। वास्तव में, यह कानून संशोधन कांग्रेस संगठन के चरित्र का परिचायक था जो बड़े जमीन मालिकों एवं जमींदारों की स्वार्थ-पटुता को खुली तरह दे रहा था। काश्तकारी का कानून भी दफा 69 से भावली वालों की जरा भी रक्षा नहीं हो रही थी तथा दफा 171 से जमींदारों को अधिकार मिल जाता था कि वह जमीन की पैदावार भी खाद तथा उसका पावना सूद समेत किसानों के मत्थे मढ़ दें। इस जन विरोधी कानून के खिलाफ स्वामी जी की मांग थी कि उसका न्याय मशविरा ऐसे वकीलों की एक कमिटी को भेजा जाय जिन वकीलों ने किसानों की कठिनाइयों को नजदीक से देखा है।

आर्थिक संघर्षों के एक रूप कानून के तहत लड़ते हुए उसकी खामियों का निराकरण किसान सभा की एक रणनीति के रूप में विकसित करने का श्रेय स्वामी जी के नेतृत्व में किसान सभा को जाता है।

किसानों की आर्थिक लड़ाइयों का राजनीतिक स्वरूप कैबिनेट मिशन के प्रश्न पर निखरकर सामने तक आया जब किसान सभा ने तत्काल उसे अस्वीकार करते हुए उसके 16 जून की घोषणा को "कांग्रेस की फांसी और मिस्टर जिन्ना की गद्दी"–[75] के संबंधों से संबोधित किया। किसान यात्रा की दृष्टि में आजादी के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

संघर्ष में अब समझौता की सारी गुंजायश समाप्त हो चुकी थी और जो कुछ बचा था वह था–साम्राज्यवाद के साथ अन्तिम लड़ाई।

स्वामी जी की कृषि नीति

अर्थशास्त्र की एक प्रमुख विद्या के रूप में, जो संसाधनों को राज्य के लिए जुटाता है, कर नीति आती है, ऐसे नीतियों के संबंध में स्वामी जी की एक मूल धारणा थी कि कराधान का सीधा संबंध करदाता की देय क्षमता से होनी चाहिए ताकि संसाधनों को जुटाने में करदाता की स्थिति, कर का प्रकार आदि की तरफ से ध्यान हटाना। इस तरह टैक्स नीति का खुलासा स्वामी जी नें केन ग्रोवर्स कोओपरेटीव कांफ्रेंस पटना[76] के अवसर पर किया था जिसमें उनकी स्थापना थी कि कृषि उत्पादन की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करते समय किसानों के हितों को सर्वोपरि महत्व देना होगा न कि उनको या उन एजेन्सियों को जो कृषि उत्पादित वस्तुओं को खरीदती है। स्वामी जी का यह विचार कृषि के उन्नयन के लिए महत्त्व रखता है क्योंकि जहां बाजार का स्वरूप पूंजीवादी हो और कृषि उत्पादन में सामंती अवशेष जड़ जमाए हो, जैसा बिहार में था, तो किसानों के शोषण की प्रक्रिया दुगुनी रफ्तार पकड़ लेती है। इसी परिप्रेक्ष्य में किसानों का हित सर्वप्रथम आता है, क्योंकि मूल्य-निर्धारण की पूंजीवादी पद्धति मांग और आूपर्त्ति को खुले रूप में छोड़ने का मतलब होता है किसानों की लूट को तरजीह देना। "हमारे सामने प्रधान समस्या है खेती से संबंध रखनेवाली और हमें सबसे पहले किसानों के स्वार्थों की रक्षा करती है,"[77] की थी। ऐसी ही अवधारणा स्वामी जी ने की थी। ईख-उत्पादन तथा किसान और मिल-मालिकों के परस्पर संबंध के बारे में स्वामी जी की यही धारणा थी।

वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य निर्धारण की नीति के तहत, जैसी स्वामी जी की राय है, कृषि उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण ठीक उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार करखनिया मालों की कीमत निर्धारित की जाती है- छोटे-छोटे तमाम खर्चों और उनके लिए मुनासिब सूद के अलावे उचित मुनाफा को शामिल करके ही मूल्यों का निर्धारण हो, यही कारखानेदार करते हैं और ऐसा ही कृषि में भी होना आवश्यक है। ईख के प्रतिमन दो आने की कटौती, जो उस समय की जाती थी, का स्वामी जी विरोध किए। उत्पादित वस्तुओं की कीमत निर्धारण में उत्पादक की महत्वपूर्ण भूमिका पर स्वामी जी कहते हैं, "........ मिलों की जरूरत के मुताबिक बराबर काफी ईख वह (किसान) बोएगा तभी, जब उसके ही हिसाब के मुताबिक उसे ईख की कीमत मिलेगी।"[78]

कृषि आधारित उद्योगों के सफल संचालन तथा विश्व बाजार में हो रही

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखकर सस्ता उत्पादन के तरीकों के लिए स्वामी जी का अलग सिद्धांत है और वह है सघन कृषि का तरीका जिससे कम-से-कम जमीन में ज्यादा-से-ज्यादा उत्पादन किया जा सके। उत्पादन की इस विधि के लिए स्वामी जी मिल मालिकों तथा किसानों के बीच उत्पादकता बढ़ाने का परस्पर सहयोगी संबंध हो। मीलें किसानों से समझौता कर मूल्य तय करें, किसानों को नये किस्म के बीज एवं खाद उपलब्ध करावें तथा किसान उनके बतायें तरीकों से खेती करें इसमें दूसरा रास्ता जो स्वामी जी दर्शाते हैं वह यह है कि मिल मालिकों द्वारा इस तरह मुफ्त खाद-बीज उपलब्ध कराने पर जो अतिरिक्त उत्पादन हो उसका आधा मीलों का और आधा किसानों का हो। बटाईदारी का यह नया तरीका मीलों एवं ईख उत्पादकों के परस्पर सहयोग का आकांक्षी होगा।

एक अन्य तरीका का जिक्र करते हुए स्वामी जी का कहना है कि किसानों को पूरा मूल्य देने के वादे के साथ मिलों और किसानों के बीच समझौता कि किस भूमि पर कौन-सा ईख रोपा जाए और किस तरह जिससे ज्यादा ईख उपयाया जा सके।

उत्पादन खर्च में कमी लाने का उपाय यह भी है कि मीलों में उत्पादित हानेवाले सामानों के कचरों का वैज्ञानिक ढंग से इस्तेमाल कर उससे अन्य चीजों का उत्पादन किया जाना जैसे ईख के कचरे से मोटा कागज, *मोलासेस* से स्प्रीट बनाना आदि। उत्पादन की ऐसी प्रक्रिया में कृषि आधारित उद्योग कई तरह के अन्य उद्योगों की भी जन्म देंगे और सर्वमुखी विकास के क्रम में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था शहरों से जुड़ जाएगी।

विदेशी चीनी पर भारी ड्यूटी लगा कर उसकी भारतीय बाजार में प्रवेश न करने देने की नीति के तहत भारत में स्वयं चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में अगर मिलें स्वयं ईख की खेती करनी चाहें तो उन्हें जमीन नहीं मिलेगी तथा टैरिफ बोर्ड की सिफारिशों कि किसानों के हितों की रक्षा को लागू नहीं होगा। टी.एस. वेंकटरमण ने भी अपनी रिपोर्ट में किसान हित का महत्व स्वीकार करते आए हैं और अभी बहुत दिनों तक कायम रहेंगे। इसलिए उन्हीं की दृष्टि से काम करने के लिए मुनासिब तरीका ढूंढ निकाला एवं ऐसा ही अमल करना पड़ेगा।"[79]

छोटे किसानों एवं बड़े कृषि फार्मों के उत्पादन-संबंधी अंतर्विरोध को स्वामी जी स्पष्ट देखते हैं तथा मानते हैं कि कृषि-संबंधी प्रयोग छोटे किसानों के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हीं की संख्या ज्यादा है। मगर व्यवहार में इसका उल्टा होना हानिकारक है, जैसा 453 नम्बर ईख के संबंध में कहा जा सकता है। यह किसानों के हित में नहीं होता है, मगर चीनी ज्यादा देता है। इसे मात्र मिल मालिकों की भलाई है जिसे रोका जाना जरुरी है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उत्पादन पर इजारेदारियों का विरोध और लाभप्रद घरेलू उत्पादन के पक्ष में स्वामी जी का अनुभव इसे सिद्ध कर दिया कि चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा गुड़ बनाने के कार्यों पर रोक लगाना घातक था। 1939-40 में चीनी उत्पादन करीब साढ़े बारह लाख टन हुई थी, मगर 1946-47 में यह एकतिहाई ही रही। 1939-40 में मिलों ने 33,31,500 टन ईख पेरा था, यह 1937-38 में 35,79,520 टन था मगर 1946-47 मं इसकी आधी भी मिलों को न प्राप्त हो सका। जहां 1944-45 में कुल चीनी उत्पादन 177052 टन पैदा हुई थी तो 1946-47 में मात्र 1,38,000 टन ही होने का अंदाज था। इन आंकड़ों को देखा जाए तो 1946-47 के उत्पादन में आई गिरावट का अंदाजा लगाया जा सकता है।

उत्पादकता बढ़ाने में को-ओपरेटिवों की भूमिका बढ़ाना, अफसरशाही की दखलअंदाजी को समाप्त कराना जरूरी है। इस तरह कृषि प्रबंध में कृषकों को महत्व देना, उत्पादन की नई प्रणालियों को विकसित करना मिलों के समानान्तर कृषि उत्पादकों की कीमतें रखना आदि को स्वामी जी ने बहुत महत्व दिया।

ईख की कीमत के प्रश्न पर विचार

ईख-उत्पादन करने वाले किसानों की समस्याओं को स्वामी जी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य में हो रहे प्रतिस्पर्द्धा के परिप्रेक्ष्य में आंकते हैं, और उस प्रतिस्पर्द्धा में किसानों को ईख की उचित कीमत और सस्ती चीनी के उत्पादन के लिए कई सुझाव देते हैं।

प्रथम टेरिफ बोर्ड की अनुशंसा[80] में किसानों के स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए सरकार और मिल-मालिकों किसानों के स्वार्थों की अनदेखी कर रहे हैं। उत्पादन तथा उत्पादित माल-चीनी का मूल्य निर्धारण जिस प्रकार होता है- तमाम छोटे-मोटे खर्चों उनपर आने वाला सूद तथा मुनाफा आदि का कुल योग इसी तरह किसानों की उपज का मूल्य निर्धारण भी किया जाए ताकि उत्पादन और वितरण की पूंजीवादी बाजार प्रणाली में किसान भी अपनी उपज का लाभकारी मूल्य पा सके। पूंजीवादी गणित का हिसाब और उसका उत्तर किसानों को भ्रमित करने वाला है, क्योंकि वह किसानों के हानि-लाभ का आंकलन ही नहीं करता। ईख की कीमत को कम करके तय करना प्रतिमन दो आने की कटौती करना आदि ऐसे सरकारी कदम है जिन्हें ईख उत्पादन में बाधा के रूप में किसान मानता है।

स्वामी जी ईख-उत्पादन के लिए तथा उसकी उचित कीमत प्राप्ति और चीनी उद्योगों की तरक्की के रास्ते भी सुझाते हैं, उनका तर्क एकतरफा नहीं है, बल्कि उत्पादन के औजारों में आई तरक्की के साथ खेती के संबंध को स्थापित करते हुए

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी जी मानते हैं कि "ईख की उपज की तरक्की के माने है उसकी सघन खेती"[81] जिससे कम-से-कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा तौल में ईख पैदा हो, साथ ही उसमें चीनी भी अधिक-से-अधिक निकले। इस तरह की खेती के लिए स्वामी जी की दो शर्तें हैं: पहली, मिलवाले किसानों से सौदा करें और कहें कि हम तुम्हें नया बीज और उसके लिए जरुरी खाद मुफ्त ही देंगे, बशर्ते तुम हमारे बताए ढंग से खेती करो। इस तरह की खेती पर मामूली उपज से जितनी अधिक उपज होगी, उसकी आधी तुम्हारी और आधी हमारी। दूसरी, अगर तुम अपने ही पैसों से खाद और बीज लो, तो सभी तुम्हारी।[82] इस तरह की खेती में स्वामी जी किसानों के इस हक की हिमायत करते हैं जहां वह मिल मालिकों के समकक्ष खड़ा होकर अपनी उपज की कीमत ले सकता है यही स्वामी जी का जनवादी कृषि तरीका है।

एक अन्य उपाय के तहत स्वामी जी की मान्यता है किसानों को ज्यादा और पूरी कीमत देने की शर्त करके कि वह किस खेत में कौन सा ईख बोएगा। ज्यादा दाम पाने पर किसान ईख की खेती मनचाही और ज्यादा मेहनत से कर सकता है। मिल मालिकों की तरफ से उत्पादन का ऐसा तरीका अपनाया होगा जिसे लागत खर्च कम आए और यह लागत की कमी बरबाद होने वाली चीजों से- जैसे खोइया, *मोलेसेस* आदि से मोटा कागज तथा अलकोहल आदि का निर्माण कर किया जा सकता है। इस स्थापना का सार है कि उत्पादन प्रक्रिया में मालिकों, कच्चा माल उत्पादकों तथा मजदूरों को साझीदारी के आधार पर उत्पादन को संगठित करना और सबों के हितों का ध्यान रखना। स्वामी जी का यह अर्थशास्त्र उत्पादन प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करने का मूल मंत्र ही नहीं, किसानों, मजदूरों के हितों की रक्षा का व्यापक आधार प्रदान करने वाला भी है।

स्वतंत्रता के बाद की देशी अर्थनीति और स्वामी जी

भारतीय आजादी को स्वामी जी ने "खोटा सिक्का"[83] की उपाधि दी क्योंकि आजादी के पश्चात की अर्थव्यवस्था में जरुरी सामानों का अभाव, साम्प्रदायिक दंगे, सभा जुलूस पर रोक आदि अर्थव्यवस्था के खिलाफ जन असंतोष के परिणाम थे, ऐसा स्वामी जी समझते थे। नेहरू सरकार के वर्ग चरित्र का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा "नेहरू सरकार बेशक पूंजीपति की है।[84] आजादी के बाद गांधीवाद के नाम पर चलाए जा रहे प्रचार को पूंजीपतियों की सरकार की राजनीतिक पंडागिरि का नाम दिया और इसे "निर मक्कारी"[85] कहा गया, क्योंकि अन्य बातों के अलावा मठ-मंदिरों के नाम पर बिहार में धर्मादाय सम्पति बिल बनाने का प्रयास कांग्रेस ने किया जिसका स्पष्ट मतलब था कि स्वतंत्रोत्तर भारत में भी किसानों के प्रति वही नीति रहेगी जो

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वतंत्रतापूर्व साम्राज्यवादियों की थी। मार्क्स की उक्ति की पूंजीवाद सबका यहां तक कि पशु-पक्षियों तक का शोषण करता है, का स्पष्ट स्थापना स्वामी जी ने अपने एक भाषण में किया और बताया कि स्वतंत्र भारत में लाया गया शासन का पूंजीवादी तरीका किस तरह मठ-मंदिरों संस्कृत शिक्षा, बेसिक शिक्षा की दुर्दशा कर रहा है तथा शिक्षकों, पुलिस के सिपाहियों, होमगार्डों, रक्षा-वाहिनियों, छात्रों आदि का शोषण करना अपना धर्म बना लिया है।

स्वामी जी इस स्थापना से प्रस्थान करते हैं कि साम्राज्यवादी युद्ध के बाद का दौर क्रांतिकारी होता है। स्वामी जी ने रेल, डाकतार, खान, कारखाने आदि की हड़तालों का जिक्र करते हुए इस क्रांतिकारी उभार को तथ्यगत आधारों पर प्रमाणित किए। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के आर्थिक संकट ही ऐसी मजदूर कार्रवाईयों के लिए जिम्मेदार था यह स्थापना स्वामी जी की थी। बढ़ती कीमतें, कराधान की ऐसी नीति जिसने अप्रत्यक्ष करों द्वारा आयाम की बदहाली को निरंतर बढ़ा दिया, मुद्रास्फीति तथा घाटे की बजट व्यवस्था ने ऐसी आर्थिक प्रक्रिया चालू की जिससे राष्ट्रीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा बड़ी पूंजी एवं बड़े भूपतियों के हाथों में चला गया। ऐसी आर्थिक नीति का विरोध करते हुए स्वामी जी ने कहा "एक ओर मजदूरों को वेतन बढ़ाते हैं, दूसरी ओर जरुरी चीजों पर कर बढ़ा कर उन्हें मंहगी करते हैं, फिर वेतन बढ़ाना भी बेकार होता है।[86]

पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी कराधान नीति मजदूर नीति आम लोगों के लिए किस प्रकार घातक सिद्ध हो रही थी उसका खुलासा स्वामी जी ने किया।

सारांशतः हम कह सकते हैं कि स्वामी जी ने आम जनता के हितों के लिए अनेक उपाय सुझाए। जन उपयोग की चीजों पर सेल्स टैक्स का स्वामी जी ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि सरकार के संसाधनों के जुटाने का उपाय बताते हुए बिहार की खनिज सम्पदा का राष्ट्रीयकरण का नाम दिया और बताया कि इससे 24 करोड़ रुपए की आय का सृजन किया जा सकता है। भूमि-सुधार के लिए जमींदारी का उन्मूलन, किसानों की जमीन से बेदखल करने की साजिशों की समाप्ति, सिंचाई-प्रबंध और बाढ़-नियंत्रण, ईख का लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाने का प्रबंध तथा भावली मुकदमों का किसानों हक में फैसला आदि ऐसी मांगे थी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकती थी, किसानों की कठिनाइयां दूर कर सकती थीं तथा सरकार का राजस्व भी बढ़ा सकता था।

आजादी के बाद आर्थिक लड़ाई का स्वरूप वैधानिक तथा अवैधानिक दोनों ही का स्वरूप ग्रहण करेगा, स्वामी जी की मान्यता थी। स्वामी जी कहते हैं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

"आजादी मिलने के बाद .... वैधानिकता का मोह सभी देशों के सर पर सवार हुआ और किसान मजदूर इसी मृगमरीचिका के पीछे मारे गए"।[87] ऐसी भ्रामक भावना का त्याग किसान मजदूरों को कर अपनी मुक्ति के संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा।

आर्थिक सामाजिक दर्शन की दो विचार धाराओं, पूंजीवाद एवं समाजवाद में स्वामी जी समाजवादी अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे और समाजवाद की अन्ततः विजय के प्रति आशावान थे।

आजादी के बाद के शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण था कि इसने साम्राज्यवाद के साथ नापाक गठबंधन कर रखा है तथा जिस साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के दबाव के तहत आजादी प्राप्ति की गई उसी के साथ धोखा भारत सरकार कर रही है। कम्युनिस्ट विरोधी साम्राज्यवादी प्रचार को तरजीह देकर ऐसा हौवा खड़ा किया जा रहा है कि अवाम गुमराह हो रहा है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश की तरक्की का रास्ता सघन खेती ही हो सकती है। इस कारण जमीन पर ये सभी बिचौलियों को हटाकर उसे सीधे किसानों के स्वामित्व में ला सघन खेती का प्रबंध सरकार का निश्चित कर्तव्य होना चाहिए। किसानों को लाभकारी मूल्य तथा खेत-मजदूरों को जीवनोपयोगी मजदूरी कृषि-विकास की कुंजी है।

वर्ग-संघर्ष की अवधारणा में स्वामी जी किसान-मजदूर-एकता की धुरी के चारों तरफ अन्य पूंजीवाद विरोधी वर्गों की एकता के आधार पर कृषि के क्षेत्र में व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तनों के वाहक थे। कुछ लोगों ने स्वामी जी पर हिंसा का आरोप लगाया कि उन्होंने 'डण्डा कल्ट' को बढ़ाया है। लेकिन स्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि 'लट्ठ हमारा जिंदाबाद' का नारा जमींदारों के विरुद्ध किसानों को भड़काने के लिए नहीं था, बल्कि जमींदारों के ज्यादतियों के खिलाफ आत्म रक्षा के लिए था। उन्हीं के शब्दों में "लेकिन यह जरूर है कि मैं किसानों को आत्मरक्षार्थ लाठी या डंडा चलाने को कहता था।[88] जब जमींदार के अमले किसानों को जूतों तथा डंडों से दुरुस्त करते तो उसे कब तक सहा जा सकता था। वे अपनी ज्यादतियों से बाज नहीं आते थे।" तब मैंने आत्मरक्षार्थ डंडे आदि का प्रयोग किसानों को खुलेआम बताना शुरु किया। .... फलतः वह शैतानियत वह आतंक राज्य सदा के लिए खत्म हुआ।"[89] यही है मेरा डंडावाद या डंडाकल्ट।

अपने सम्पूर्ण आर्थिक दर्शन में स्वामी जी भू-संबंधों में व्यापक क्रांतिकारी परिवर्तनों के पक्ष में थे। यह परिवर्तन एक निश्चित कार्यक्रम के आधार था जिसका सम्पादन उन्होंने किसान के दावे और कार्यक्रम का खरीता[90] में सम्पादित

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

किया। इस तरह स्वामी जी का आर्थिक दर्शन दबी, पीड़ित आम जनता के हित का साधन का था तथा वे मार्क्सवादी विचारों को भारतीय संदर्भ में लागू करने के पक्षधर थे। उनका स्पष्ट मत था कि कमानेवाली जनता के हाथों में शासन-सूत्र होना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो उसे छीनकर भी किया जाना चाहिए। इस तरह स्वामी जी क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्षधर थे जिसमें गरीब आम जनता के हितों की रक्षा संभव हो। उन्होंने लिखा है "मैं कमानेवाली जनता के हाथ में ही, सारा शासन-सूत्र औरों से छीनकर, देने का पक्षपाती हूं। उनसे लेकर या उनपर दबाव डालकर देने दिलवाने की बात में गलत मानता हूं। हमें लड़कर छीनना होगा"।[91] उन्होंने वैसे नेता तथा कार्यकर्ताओं के दल को तैयार करने की बात की जो किसानों एवं मजदूरों के आर्थिक प्रोग्राम से संबंद्ध हों। उन्होंने स्पष्टतः एक क्रांतिकारी लड़ाई एवं परिवर्तन का सपना देखा था, जो इस कथन से स्पष्ट है, "मैं आर्थिक लड़ाई को छोड़कर आजादी की लड़ाई का विरोधी हूं। मैं आर्थिक युद्ध को ही आजादी से युद्ध में परिणत करना चाहता हूं। मैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति चाहता हूं और यह दूसरी तरह से नहीं आ सकती"।[92] इस तरह हम पाते हैं कि स्वामी जी एक ऐसे चिंतक थे जो शोषकविहीन समता पर आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना चाहते थे। उन्होंने किसानों एवं मजदूरों के हित की रक्षा के लिए जीवनपर्यन्त काम किया। ये दया की भीख नहीं बल्कि छीन कर अधिकार एवं शासन-सूत्र हाथ में लेने के पक्षधर थे जिसके द्वारा गरीबों, पीड़ितों के हितों की रक्षा भलीभांति की जा सके।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सन्दर्भ

1. देखें, ए.थार्नर और डी. थार्नर, *लैण्ड एण्ड लेबर इन इन्डिया,* (बम्बई, 1965).
2. उपरोद्धृत
3. आर.एच. टोली *"एग्रेरियन प्राबलम्स इन सिक्सटीन्थ सेन्चुरी"*, कार्ल मार्क्स, कैपिटल खण्ड-1, अध्याय-8
   जे.डी. चैम्बर्स तथा जी.ई. मेजी *'एग्रीकल्चरल रिवोल्यूसन' 1750-1880,* (लंदन, 1966).
4. एस. शिवसुब्रमण्यम, "एस्टीमेट्स आफ आउट पुट फांर अनडिवाइडेट इंडिया" *पेपर्स आन नेशनल इनकम एण्ड एलाइड टापिक्स,* खण्ड-1, (लंदन, 1960),
   जीसन *एग्रीकल्चर्स ट्रेन्डस इन इन्डिया 1891-1947,*
   ए.के. बागची, *'प्राइवेट इन्भेस्टमेन्ट इन इंडिया' 1900-1939* (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1972).
5. जिनका अनुमान है कि खाद्यान्नों का उत्पादन सिर्फ 0.11 प्रतिशत सालाना की रुझान वृद्धि दर से बढ़ रहा था। जबकि व्यापारिक फसलों का उत्पादन 1.31 प्रतिशत सालाना दर से बढ़ रहा था। अगर निर्यात होनेवाले खाद्यान्नों को प्रथम श्रेणी से निकाल कर दूसरी श्रेणी में रख दिया जाए तो यह अन्तर और भी बढ़ जाता है।.
6. *सोशल साइन्टिस, न. 188,* (दिसम्बर, 1984).
7. शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, "वर्ग समझौते से वर्ग संघर्ष तक" *स्वामी सहजानन्द सरस्वती, ज्योति कलश* (स्वामी सहजानन्द सरस्वती विकास सेवा संस्थान मुजफ्फरपुर, 1989), पृ. 141.
8. शेलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव-पूर्वोद्धृत, पृ. 143.
9. विपिन चन्द्रा, "पिजेन्ट्री एण्ड नेशनल इन्टीग्रेसन इन कनटेम्परेरी इन्डिया" सम्पादकः के.एन. पन्निकर, *नेशनल एण्ड लेफ्ट मुवमेंट इन इंडिया* (विकास पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली, 1980), पृ. 126.
10. डा. सी.पी.एन. ठाकुर, "किसान सभा की आधारभूत परिकल्पनाएं और स्वामी जी", ज्योति कलश, पूर्वोद्धृत, पृ. 89.
11. मार्क्स, कैपिटल खण्ड-1.
12. डा. रामनारायण राय, "स्वामी सहजानन्द के आर्थिक दर्शन में किसान" *निवेदिता*

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(स्वामी सहजानन्द सरस्वती जन्मसदी विशेषांक, स्वामी सहजानन्द सरस्वती विद्यापीठ महाविद्यालय, गाजीपुर, 1987-88).

13. उपरोद्धृत, पृ. 55.
14. सहजानन्द सरस्वती, क्रांति और संयुक्त मोर्चा (पूर्वोद्धृत) पृ. 35.
15. उपरोद्धृत, पृ. 42-46.
16. उपरोद्धृत, पृ. 53.
17. उपरोद्धृत, पृ. 55.
18. उपरोद्धृत.
19. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, *क्रांति और संयुक्त मोर्चा* (पूर्वोद्धृत) पृ. 1-5.
20. उपरोद्धृत, पृ. 3.
21. उपरोद्धृत, पृ. 5.
22. उपरोद्धृत, पृ. 24.
23. उपरोद्धृत, पृ. 20.
24. उपरोद्धृत, पृ. 21.
25. उपरोद्धृत, पृ. 34.
26. उपरोद्धृत, पृ. 35.
27. उपरोद्धृत, पृ. 123.
28. उपरोद्धृत, पृ. 123.
29. उपरोद्धृत, पृ. 161-62.
30. उपरोद्धृत, पृ. 302.
31. उपरोद्धृत, पृ. 326.
32. *बिहार प्रांतीय किसान सभा का घोषणा पत्र,* (बिहार किसान सभा, सीताराम आश्रम बिहटा, पटना) पृ. 5.
33. उपरोद्धृत, पृ. 6.
34. 1934 में जमींदारों के एक प्रतिनिधि मंडल को गांधी ने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस जमींदारी उन्मूलन के पक्ष में नहीं रहेगी। मराठा, 12 अगस्त, 1934.
35. शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पूर्वोद्धृत, पृ. 144.
36. *अखिल भारतीय किसान सभा की नियमावली,* (अखिल भारतीय किसान सभा की नियामतपुर, बिहार की बैठक में स्वीकृत) धारा-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

37. उपरोद्धृत, धारा-3.
38. *अखिल भारतीय किसान सभा का आठवां सम्मेलन, अध्यक्ष का* भाषण (विजयवाड़ा, 14-15 मार्च, 1944).
39. उपरोद्धृत.
40. उपरोद्धृत.
41. स्वामी सहजानन्द सरस्वती *'मेरा जीवन संघर्ष'*, पृ. 322.
42. उपरोद्धृत, पृ. 322-23.
43. द्वारा उद्धृत, शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, ज्योति कलश, पूर्वोद्धृत, पृ. 146.
44. स्वामी जी, *मेंरा जीवन संघर्ष*, पृ. 412.
45. स्वागताध्यक्ष यदुनन्दन शर्मा थे। *अखिल भारतीय किसान सभा, चतुर्थ अधिवेशन,* 9-10 अप्रैल, 1939 स्वागताध्यक्ष का भाषण, पृ. 2.
46. *उपरोद्धृत.*
47. उपरोद्धृत, पृ. 4.
48. उपरोद्धृत, पृ. 5.
49. विशेष विवरण के लिए देखें, सहजानन्द सरस्वती, दि अदर साइड आफ दि शिल्ड.
50. उपरोद्धृत, पृ. 7.
51. देखें, लेनिन, *राज्य और क्रांति* (मास्को).
52. स्वगताध्यक्ष का भाषण, चतुर्थ सम्मेलन, अखिल भारतीय किसान सभा, गया, 9-10 अप्रैल, 1939, पृ. 8-9.
53. उपरोद्धृत, पृ. 16-17.
54. स्वामी जी, मेरा जीवन संघर्ष, पृ. 440.
55. उपरोद्धृत.
56. उद्धृत द्वारा, शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, ज्योति कलश, पूर्वोद्धृत, पृ. 147.
57. उपरोद्धृत, पृ. 150.
58. उपरोद्धृत, पृ. 151.
59. अखिल भारतीय किसान सभा के 8वें अधिवेशन, 14-15 मार्च, 1944 विजयवाड़ा में *स्वामी जी का अध्यक्षीय भाषण* (अंग्रेजी) पृ. 2.
60. स्वामी सहजानन्द सरस्वती *'मेरा जीवन संघर्ष'*, पृ. 453.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

61. स्वामी सहजानन्द सरस्वती '*मेरा जीवन संघर्ष*', पृ. 456.
62. स्वामी सहजानन्द सरस्वती '*मेरा जीवन संघर्ष*', पृ. 459.
63. अखिल भारतीय किसान सभा में 8वें अधिवेशन, पूर्वोद्धृत, पृ. 5-8
64. *सभापति स्वामी सहजानन्द सरस्वती का अध्यक्षीय भाषण*, 13वां बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन (बेरमो, हजारीबाग, 29-30 जून, 1946) पृ. 12-13.
65. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, 'झारखण्ड के किसान' मनोहर पब्लिकेशन, 1995, पृ. 214., (वाल्टर हाडजर के 'द पिजेन्टस ऑफ झारखण्ड', मनोहर पब्लिकेशन, 1995 में प्रकाशित मूल हिन्दी पुस्तक से).
66. उपरोद्धृत, पृ. 217.
67. उपरोद्धृत, पृ. 221.
68. स्वामी सहजानन्द सरस्वती 'झारखण्ड के किसान' पृ. 322-25, मनोहर, 1995 जिसका प्रकाशन वालटर हाउजर ने अंग्रेजी में 'The Peasant of Jharkhand' के नाम से कराया है जिसमें स्वामी जी द्वारा लिखित हिंदीवाली पुस्तक पूरी तरह प्रकाशित है.
69. इन मांगों की तालिका के लिए देखें बिहार प्रांतीय सम्मेलन, बेरमो, 1946 उपरोद्धृत, पृ. 4-6.
70. उपरोद्धृत, पृ. 7.
71. उपरोद्धृत.
72. उपरोद्धृत.
73. उपरोद्धृत, पृ. 10.
74. स्वामी जी का अध्यक्षीय भाषण, बेरमो सम्मेलन, पृ.11, 1946, पूर्वोद्धृत
75. उपरोद्धृत, पृ. 13.
76. यह कांफ्रेंस 7 एवं 8 अप्रैल, 1947 को हुआ था.
77. *प्रथम टेरिफ बोर्ड की रिपोर्ट, पृ. 54.*
78. केन ग्रोवर कोओपरेटीव कांफ्रेंस, पटना के अवसर पर स्वगताध्यक्ष के रूप में *स्वामी जी का भाषण*, वर्ष 1947.
79. टी.एस. वेंकट रमण की रिपोर्ट, पृ. 3.
80. प्रथम टेरिफ बोर्ड रिपोर्ट, पृ. 54.
81. केन ग्रोवर कोओपरेटीव कांफ्रेंस, पटना में *स्वामी जी का भाषण*, (7-8 अप्रैल, 1947), पृ. 4.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

82. उपरोद्धृत, पृ. 5.
83. बिहार प्रांतीय संयुक्त किसान सम्मेलन के अध्यक्ष पद से *स्वामी जी का भाषण* (सोलहवां अधिवेशन, ढ़काइच, शाहाबाद, 12-13 मार्च, 1949) पृ. 1.
84. उपरोद्धृत, पृ. 3.
85. उपरोद्धृत, पृ. 4.
86. उपरोद्धृत, पृ. 15.
87. उपरोद्धृत, पृ. 23.
88. स्वामी सहजानन्द सरस्वती '*मेरा जीवन संघर्ष*', पृ. 409.
89. स्वामी सहजानन्द सरस्वती '*मेरा जीवन संघर्ष*', पृ. 510.
90. *किसानों के दावे और कार्यक्रम का खरीता* (अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा से स्वीकृत, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, बिहटा, पटना जुलाई, 1949.
91. स्वामी सहजानन्द सरस्वती '*मेरा जीवन संघर्ष*', पृ. 549.
92. पूर्वोद्धृत.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय - 4

किसानों एवं मजदूरों की समस्या और स्वामी जी

स्वामी जी गरीब किसानों तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कटिबद्ध थे। यही कारण था कि वे इनके लिए एक संगठन की वकालत करते थे जिसमें दोनों सम्मिलित होकर जमींदारों के साथ, शोषकों के साथ लड़ सकें। किसानों और मजदूरों की समस्याओं के प्रति स्वामी जी के एकीकृत दृष्टिकोण कां परिचय उनकी एक उक्ति, जिसके द्वारा उन्होंने किसान सभा को परिभाषित करने के संदर्भ में कहा था, से ही पता चल जाता है- वे कहते हैं, "संगठन के होने का अर्थ है कि भूख, गरीबी, गुलामी और अपमान की जिंदगी बिताने को किसान तैयार नहीं।"[1] उक्ति इस तथ्य का सटीक प्रमाण है कि किसान और अन्य भूमि पर आश्रित आबादी भूख और गरीबी की जिंदगी बिता रही थी, और वही वे समस्यायें थीं जिनका निवारण स्वामी जी किसान सभा द्वारा आयोजित आन्दोलनों में करना चाहते थे। स्वामी जी किसान सभा द्वारा खेती से संबंध रखने वाले और उसी के जरिये गुजर करने वाले शोषित एवं पीड़ित जनता का उत्थान करना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसान सभा किसी खास जमात की चीज नहीं है। किसानों को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए तथा खेती के मजदूरों के साथ अपना रवैया बदलना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में "बहुत से लोग किसान सभा और उसके आंदोलन में शरीक होकर यह समझ बैठे हैं कि किसान सभा से फायदा उठा लें। मगर खेती के मजदूरों के साथ अपना रवैया न बदलें- उनके साथ सख्ती और बेमुख्खती से पेश आते रहें। उन्होंने शायद यह समझ लिया कि किसान सभा एक खास जमात की चीज है, ठीक उसी तरह जैसे जमींदार सभा। लेकिन उन्हें जान लेना चाहिए कि किसी बंधी बंधाई जमात की चीज न हो के यह सभी खेती से संबंध रखने वाली और उसी के जरिये गुजर करने वाली शोषित एवं पीड़ित जनता की चीज है। इसीलिए जो जितना हो ज्यादा पीड़ित और दुखिया है उतना ही ज्यादा वह किसान सभा के नजदीक है।"[2] उनकी इस उक्ति से स्पष्ट है कि किसान सभा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सिर्फ किसानों की संस्था नहीं बल्कि गरीब किसानों के साथ-साथ सबसे पीड़ित जमात खेत मजदूरों के भी उतनी ही नजदीक है। उन्होंने इसी पृष्ठ पर आगे कहा है कि "खेत-मजदूर सबसे दुखिया होने के कारण किसान सभा की नजर सबसे पहले उन्हीं पर जानी चाहिए और जाती भी है"।

किसानों की दुर्दशा की चर्चा स्वामी जी ने की है तथा बताया है कि जमींदारों द्वारा अत्यधिक लगान वसूलने या महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज वसूलने के कारण असंख्य किसानों की जमीनें लुट रही हैं तथा वे खेतिहर मजदूर की श्रेणी में चले जा रहे हैं। उन्होंने 1911 से 1931 के बीच मजदूरों की बढ़ती संख्या तथा लगान वसूलने वाले जमींदारों की संख्या का जिक्र किया है। उनका कहना है कि सरकारी रिपोर्ट तथा गैर सरकारी आंकड़ों का भी मिलान करें तो "आसानी से पता लग जाएगा कि किस तेजी से खेती के मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसी के साथ सिर्फ लगान वसूलने वाले जमींदारों की भी।" 1911 में जमींदारों या जमीन के मालिकों की तादाद 28 लाख मनुष्य गणना में लिखी गई है। 1921 में वही बढ़ के 37 लाख और सन 1931 में 41 लाख हो गई। जबकि खुद खेती करने वाले किसानों की संख्या, जिनकी जमीन हो, जो सन 1921 में 7 करोड़ 46 लाख थी वही घट के सन 1931 में 6 करोड़ 55 लाख पहुंच गई। यानी दस साल में पूरे 91 लाख से ज्यादा किसानों की जमीने छिन गईं। इसी क्रम में वे लिखते हैं कि "जैसे एक ओर मुफ्तखोर लगानचट्ट जमीन वाले (जमींदार) बढ़ेंगे उसी तरह दूसरी ओर खेती के मजदूर बढ़ेंगे ही।"[3] इस तरह वे मानते हैं कि जब छोटे गरीब किसानों की स्थिति खराब होती है तो वे खेत-मजदूर हो जाते हैं।

किसानों और मजदूरों को परिभाषित करने के ही क्रम में उनकी समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया। किसान असल में गृहस्थ को कहते हैं और गृहस्थ शब्द का जो प्रचलित अर्थ है उसके भीतर बड़े-बड़े जमींदार, मालदार, राजे-महाराजें नहीं आते। व्यवहार में गृहस्थ उसे ही कहते हैं जो खेती-गृहस्थी से गुजर-बसर करता है, चाहे वह छोटा-मोटा जमींदार हो, रैयत हो या खेतों में हल चलाने आदि का काम (मजदूरी) करता हो ....[4], किसान सभा में हलवाहे, चरवाहे आदि मजदूरों का पूरा संगठन" स्वामी जी चाहते थे। स्वामी जी की परिकल्पना में किसान सभा मुख्यतः तीन भू-निर्भर जनों का, छोटे-छोटे जमींदारों, रैयतों और हलवाहे-चरवाहे का संयुक्त संगठन था जो इनकी समस्याओं के लिए संघर्ष का स्थल तथा इन तीन श्रेणियों के आपसी सद्भाव के तहत बड़े जमींदारों, उनकी पिष्टपोषक सरकारों तथा संगठन के प्रति दुर्भावना पूर्ण विचार रखने वालों के खिलाफ एक संयुक्त आन्दोलन के स्वरूप को विकसित

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

करने वाली संस्था के रूप में निरूपित था। इस वर्गीय मोर्चा का एक महत्व था, और वह था अपने वर्ग दुश्मन पर करारा प्रहार करना, जिससे शोषण का सिलसिला कम हो। इस वर्गीय संयुक्त मोर्चा के घटकों का वर्गीय स्वार्थ शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधों का नहीं था, बल्कि सामंजस्यपूर्ण अन्तर्विरोधों का था, उनके बीच के मतभेदों को-चाहे उनका स्वभाव किसी भी तरह का क्यों न हो, घर फूटे गंवार लूटे की कहावत का चरितार्थ होना था। अपने दृष्टिकोण में स्वामी जी किसान वर्ग में बने कई आर्थिक स्तरों में सबसे ऊपरी स्तर को छोड़ अन्य सभी को, यहां तक कि खेत-मजदूरों तक की समस्याओं को एक साथ देखते थे। उनका दृष्टिकोण द्वन्द्वात्मकता की उस ऊंचाई पर था जहां की रणनीति होती है वर्ग दुश्मन को अलग-अलग कर उस पर प्रहार करने की। इसलिए समस्त संघर्ष में अपनी कतार को लाभ बंद करना, वर्ग दुश्मन को अलग-थलग करना तथा संघर्ष में सम्पूर्ण एकता को समेट कर संघर्ष के मैदान में उतरना ही किसान मजदूरों की समस्याओं का माकूल हल था।

स्वामी जी मध्यम एवं गरीब किसान को खेत-मजदूर की श्रेणी में ही रखते थे तथा वे इस बात के पक्षधर थे कि इन्हें मिलकर अपने वर्ग-दुश्मन जमींदारों से लड़ना चाहिए। वे गरीब किसान को एक प्रकार के मजदूर ही मानते थे। उन्होंने विभिन्न तरह के किसानों का ब्यौरा दिया है तथा यह बताया है कि जब जमीन बंदोबस्त की जाती है। "एक से दूसरा आदमी जमीन लेकर तीसरे के हाथ बन्दोबस्त करता है और वह चौथे के साथ और जब इस प्रकार तांता बंध जाता है तो असली किसान में और मजूरी करने वाले खेत-मजदूर में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता।"[6] उन्होंने बाद में बात को और साफ करने के लिए कहा है कि खेत-मजदूर तथा दर रैयत में भेद करना अत्यन्त कठिन है। दर रैयत तो शायद ही नगद लगान पर जमीन पाता हो। आम तौर से उसे बटाई पर ही खेत मिलता है जिसमें पैदावार 40 से लेकर 60 तक, और कभी-कभी 80 हिस्से तक भी, जमीन का मालिक लेकर बाकी किसान (दर रैयत) के लिए छोड़ता है।[7] इसीलिए वे मानते हैं कि दोनों के बीच व्यवहार में कोई साफ अंतर नजर नहीं आता। वे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि "जो असल किसान हैं, जिन्हें गरीब या मध्यम किसान कहते हैं, उनकी हालत और 98 प्रतिशत खेत-मजदूर की दशा में कोई भी महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। जहां तक इन दोनों की आर्थिक दशा तथा माली हालत का ताल्लुक है खेत मजदूर तथा गरीब किसान में जिनकी संख्या 80 फीसदी से कम नहीं है, कोई भेद किया जा नहीं सकता-किसी भी भेद की गुंजाइश नहीं है।"[8] उन्होंने और आगे लिखा है कि किसानों की दशा बदतर होते-होते जो उसमें सबसे नीचे आ जाते हैं वही गरीब

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

किसान हैं, ठीक वैसे ही आमतौर पर उनकी दशा कुछ और गिर जाने से उन्हें खेत मजदूर कहने लगते हैं। मगर यह बताना कठिन है कि कहां से किसान कहना छूट के मजदूर कहने का श्री गणेश होता है। ऐसी कोई सीमा खींची जा सकती नहीं। इसीलिये खेत-मजदूर को, जिनसे आमतौर से हमारा ताल्लुक है, किसान ही मानना उचित है।

स्वामी जी खेत-मजदूर तथा किसानों में आपसी समझदारी के प्रबल पक्षधर थे। उनके अनुसार "खेत-मजदूरों से समानता और भाईचारा का सलूक बिना विलम्ब करना होगा।"[9] उनके अनुसार यदि किसान प्रेम का व्यवहार नहीं करते तो ऐसा करके वे अपना ही पांव काटते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि किसान उन्हें परिवार का व्यक्ति मानकर उनसे वैसा ही सलूक करें। उन्होंने इस बात को माना है कि किसान उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तभी तो वे कहते हैं कि "किसान खुद अपने दिल टटोल कर देखें और अपने आप से पूछें कि वे मजदूरों को दर असल किस नजर से देखते हैं।" इसलिए उनकी राय में मजदूरों के परिवार को अपने परिवार की तरह ही मानना चाहिए क्योंकि वे ही अन्न पैदा करता है, उनके बिना धान या दूसरे गन्ले की खेती नहीं हो सकती। वे कहते हैं "ऐसी दशा में उनके परिवार को अपने परिवार के अपेक्षा यदि ज्यादा न मान के अपने परिवार जैसा ही माने तो इसमें किसान कोई आश्चर्य या उपकार की बात तो करता नहीं।"

उनकी स्पष्ट राय थी कि गरीब किसान तथा मजदूर संगठित होकर जमींदारों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ें। उनके शब्दों में "इसलिए पहला काम तो यही है कि दोनों ही मिलके इन ग्राहों के पेट से उस पैदावार को बचायें। तभी पेट भरने की आशा है। मगर जब तक दोनों बराबर लड़ेंगे और एकमत होकर ग्राहों से न भिड़ेंगे कुछ होने जाने का नहीं। इसलिए पारस्परिक समझौता होना जरूरी है।"[10] वे जमींदारों के विरुद्ध उनकी संयुक्त लड़ाई के पक्षधर थे, लेकिन मजदूर तथा गरीब किसान के बीच समझौता तथा बातचीत द्वारा समस्या का समाधान चाहते थे।

संघर्ष की इस रणनीति का वास्तविक मतलब था कि वैधानिक या संसदीय संघर्ष के द्वारा मांगों की पूर्ति की संभावना का लोप हो जाना और संघर्ष ही एक मात्र उपाय रह जाना।

किसानों की मांगें

बिहार प्रांत के, जो स्वामी सहजानन्द सरस्वती का मुख्य कार्य क्षेत्र रहा था, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में किसानों को दुर्वव्यवस्था होने के कारण किसान

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पिछड़े तथा खेत-मजदूर तबाह थे, जिसका एक कुफल तो यह हुआ कि जिन छोटी मोटी रियायतों को संघर्षों के जरिए प्राप्त किया गया था उनसे भी बिहारी किसान और खेत-मजदूर वंचित रह गए जबकि अन्य प्रान्तों के किसानों ने उसे हासिल किया। दूसरी बात यह रही कि प्रान्त का राजनीतिक आन्दोलन किसानों की भौतिक एवं तात्कालिक दोनों ही मांगों से वंचित रह गया था।

किसानों की समस्याओं और मजदूरों की तंगहाली का मूल कारण, जैसा कि कतिपय भारतीय अर्थशास्त्रियों का विचार था, जमीन की गलत बंदोबस्तों तथा लगान प्रणाली व माल की वसूली को वर्तमान प्रणाली, कर्ज के लेन-देन का उस समय तरीका था और सबसे ऊपर था साम्राज्यवाद का क्रूर शोषण। इस कारण किसानों की उन्नति का रास्ता, जो बच रहा था, वह था भू-प्रबंध में तथा लगान-वसूली में व्याप्त दकियानूस तरीका का खात्मा, कर्ज गुलामी का समूलनाश तथा साम्राज्यवाद का खात्मा। इस प्रकार किसान संघर्ष की आखिरी परिणति ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खात्मे की राजनीतिक लड़ाई से जुड़ जाती थी, जो अर्थवाद से ऊपर उठ कर राजनीति संघर्ष का स्वरूप ग्रहण करता था। इसीलिए स्वामी ने किसानों को कुछ मौलिक मांगों को संघर्ष का मुख्य मुद्दा बनाया जो किसानों को उनकी उपर्युक्त कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने का रास्ता प्रशस्त करती। किसानों की मौलिक मांगे थीं:–

1. जमींदारी प्रथा का समूल नष्ट किया जाना,
2. किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया जाना,
3. जमीन के बन्दोबस्त को ऐसी प्रथा कायम किया जाना जिसके अनुसार किसान ही जमीन का मालिक हो और अपने परिवार की अच्छी तरह परवरिश के लिए जितनी आमदनी जरूरी हो उतनी या उससे कम आमदनी वालों का कोई लगान या टैक्स देना न पड़े।
4. जिनके पास जमीन न हो उनके लिए अच्छी रोजी का प्रबंध किया जाना।

इन मौलिक मांगों में जमीन एक ऐसी उत्पादन के साधन का स्वरूप ग्रहण करती है जिसमें वह मात्र रोजी-रोटी का साधन हैं, किसी अतिरिक्त मूल्य के सृजन का साधन नहीं है। इन मांगों की पूर्ति में साम्राज्यवाद एक अवरोधक का काम करता है, इसलिए उस अवरोध को हटाने के लिए जाने वाला संघर्ष स्वराज्य प्राप्ति के संघर्ष से जुट जाएगा। स्वामी जी किसानों एवं मजदूरों की इस लड़ाई को स्वराज्य के जंग से जोड़ देते हैं।

किसान-मजदूरों की इन मौलिक मांगों के, जिनकी प्राप्ति का संघर्ष अनन्तोगत्वा स्वराज्य-प्राप्ति या राजसत्ता के लिए होनेवाले संघर्षों से जुट पाता है, अलावा

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वर्तमान व्यवस्था के भीतर संघर्ष कर प्राप्त की जानेवाली मांगों को भी रखा गया जिसमें प्रमुख मांगें थीं :-[11]

1. जमीन पर किसानों का स्थायी अधिकार हो, वह बिना किसी रोक-टोक या सलामी के बेची, बदली या हस्तान्तरित की जा सके, किसान उसको और उसके पैदावार को चाहे जिस तरह काम में ला सके,
2. कानून के जरिए हर गांव में काफी गोचर भूमि का प्रबंध हो और खेती तथा घरेलू कामों के लिए जंगल से लकड़ी, घास, बांस, जलावन वगैरह मुफ्त और बिना रोक-टोक के लेने का किसानों को हक हो,
3. हर तरह के भावली की प्रथा का अंत हो,
4. ऐसी सभी जमीनों के लिए किसानों को कोई लगान या टैक्स न लगे, जिसमें मेहनत और खर्च के मुआफिक उनकी गुजर के लायक पैदावार न होता हो,
5. किसी तरह की अदालती डिग्री या बकाया लगान में न तो किसान गिरफ्तार या कैद किया जा सके और न उसके परिवार की जीविका के लिये जितनी जमीन जरूरी है वह, उसका मकान या सहन, दूध देने वाले और दूसरे पशु, घरेलू सामान और पशुशालाएं कुर्क या नीलाम हो सके,
6. जमींदारों को सर्टिफिकेट (जब्ती-कुर्की के जरिये लगान वसूल करने) का अधिकार न हो,
7. रसीद देने आवपाशी गिलन्दाजी आदि का प्रबंध करने, तथा नाजायज वसूलियों और बेगार आदि से संबंध के कानून ऐसे सख्त बना दिये जाय, जिसमें उनकी अवहेलना न कर सके,
8. बाकी लगान और एजाफे बिल्कुल मंसूख कर दिये जाय, लगान और नहर रेट साधारणतः आधा कर दिया जाय, भविष्य में कभी लगान या नहर रेट में एजाफा न हो,
9. जिस कर्ज को किसान बिना दिक्कत के अदा न कर सके, वह कानून के जरिये बिल्कुल मंसूख कर दिया जाय, सूद का दर ।।=) सैकड़े माहवारों से ज्यादा न रहे, दर सूद गैर कानूनी समझा जाय, किसी भी हालत में मूलधन के दूने से अधिक की वसूली गैर कानूनी करार दी जाय, आसान किस्तों में बिना और अधिक सूद के कर्ज चुकाने की इजाजत देने का अदालतों को अधिकार हो, गांवों में सूद पर रुपये लगानेवालों को सरकारी लाइसेन्स लेना जरुरी हो, किसानों को सस्ते दर पर कर्ज देने का सरकार की ओर से इन्तजाम हो,
10. खेती के मजदूरों को परवरिश लायक मजदूरी मिले,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

11. ईख की कम-से-कम कीमत इस तरह मुकर्रर की जाय जिसमें वह ।=) आने मन से शुरु हो और बढ़ते-बढ़ते ।।=) आने मन तक जाय,
12. चौकीदारी टैक्स उठा दिया जाय,
13. नमक, किरासन तेल और दियासलाई इत्यादि जैसी चीजों पर से टैक्स (चुंगी) उठा दी जाय जिसका बोझ अप्रत्यक्ष रूप से गरीबों पर ही पड़ता है,
14. रेल के तीसरे दर्जे (थर्ड क्लास) का किराया सस्ता कर दिया जाय और उसमें काफी आराम का प्रबंध रहे, पोस्ट कार्ड एक पैसे में तथा लिफाफा दो पैसे में मिले,
15. लड़के और लड़कियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा का प्रबंध हो, मध्य और उच्च शिक्षा सस्ती और सुलभ हो, दवा, सफाई और पीने लायक पानी का उचित प्रबंध किया जाय,
16. हर बालिग आदमी को वोट देने का अधिकार मिले,
17. अंग्रेजी तथा देशी भारत में किसानों, मजदूरों एवं राष्ट्रीयता के विरोधी जितने कानून आर्डिनेन्स या रेगुलेशन हैं सब रद्द कर दिये जायं, सभी किसान, मजदूर और राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जांय वे सजायाफ्ता हो या बिना मामला चलाये ही नजरबन्द हों,
18. आर्थिक या राजनैतिक आन्दोलनों में शामिल होने या सस्ती के चलते मालगुजारी न दे सकने के कारण जिन किसानों की जमीनें छिन गई हों वे उन्हें फिर से वापस मिल जाय,
19. खेती में सुधार और तरक्की लाने के लिये सरकार की ओर से नीचे लिखे तथा दूसरे जरूरी इन्तजाम हों :-
    (क) सिंचाई के लिए नहर, आहर, पैन आदि का तथा बाढ़ से रक्षा तथा चौर आदि के पानी के निकास का पूरा और व्याप्क प्रबंध हो,
    (ख) सस्ती खाद, उत्तम बीज और अच्छी नस्ल के पशुओं का इन्तजाम हो, फल पैदा करने, रेशम के कीड़े, दुधारु पशु और चिड़ियों के पालने इत्यादि के रोजगारों की उन्नति का प्रबंध हो,
    (ग) सरकारी कृषि विभाग को नये सिरे से ऐसा बनाया जाय जिससे किसानों की सेवा हो,
    (घ) गल्ले के बाजार दर पर ऐसा नियंत्रण हो, जिसमें नफा कमाने वाले व्यापारी किसानों को लूटने न पायें,
    (ङ) जंगल, परती तथा दूसरी बेकार जमीनों को खेती के लिये आबाद कराया जाय,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इस प्रकार स्वामी जी ने किसानों और मजदूरों की तात्कालिक मांगों की दो सूचियों के आधार पर साम्राज्यवादी राजसत्ता के खिलाफ संघर्ष और इसके अंदर संघर्ष कर सहूलियतें हासिल करने की अपनी दो बहुमुखी मांगों को रख संघर्ष की रणनीति का निरूपण किया।

किसान मजदूर एकता का प्रश्न

स्वामी जी गरीब किसानों तथा खेत मजदूरों के लिए एक संगठन चाहते थे। अनेक शब्दों में "एक महान संगठन के भीतर ही दोनों का रहना निहायत जरुरी है। यह मौलिक सिद्धान्त है।[12] न जमींदार और न ही धनी किसान आसानी से मानने वाले जीव हैं इसीलिये जबरदस्त लोकमत बनाना होगा। "किसानों और खेत-मजदूरों की संगठित तथा सम्मिलित शक्ति से ही यह काम करना होगा।" वे यह भी मानते थे कि शोषण तथा उत्पीड़न का अन्त तब तक नहीं होगा जब तक व्यक्तिगत संपति पर आधारित व्यवस्था समाप्त न हो जाये। समाज का आमूल परिवर्तन जरूरी है। उन्होंने इस सम्बन्ध में लिखा है कि शोषण का आधार रहा है व्यक्तिगत सम्पति उन्हीं के शब्दों में "अब तक इसका आधार ही है व्यक्तिगत सम्पति। इसीलिए शोषण इसकी नस-नस में समाया है। इस आधार को मिटा के जब सम्मिलित सम्पति को आधार बना दिया जायेगा तभी यह बात मिटेगी।[13] लेनिन के अप्रैल थेसिस (April Thesis) से उद्धरणों के आधार पर स्वामी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लेनिन गरीब किसानों से जुदा करके देखते हैं लेकिन गरीब किसानों को खेत-मजदूरों से जुदा करने का उनका खयाल नहीं है। इस तरह स्पष्ट है कि धनियों से गरीब किसानों का जुदा संगठन हो। जो अत्यन्त गरीब और संपत्तिहीन है वही तो खेत-मजदूर है।

उन्होंने इस बात को भी देखा है कि यदि धनी किसानों के विरुद्ध खेत-मजदूरों को लड़ना है तो इनका एक संगठन हो ही जाएगा। वैसी स्थिति में किसान सभा के लोग इस बात को देखें कि वे किसान सभा का विरोधी न बनने पायें। बाहर से ही उस पर नजर और निगरानी रखना जरूरी है। लेकिन किसान नेताओं तथा किसान सभा का यह ध्यान होना चाहिए कि "हम धनी किसानों के विरुद्ध उनके संघर्षों को मुस्तैदी के साथ संगठित रूप से चलते रहें।" वे बाद में लिखते हैं कि "किसान सभा और खेत-मजदूरों के इस प्रकार के संगठन में परस्पर विरोध भी नहीं हो सकता"[14] यह संगठन तो अत्यन्त शोषितों का ही होगा। दोनों का संगठन ऐसी परिस्थिति में अलग होगा। लेकिन जब किसान संसार में सबमें दुखिया लोगों को मजबूती के साथ उठाने का काम किया जायेगा तो हमारी नीयत का पता दुनिया

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

को चल जायगा। यही सभा, यही संगठन कुछ दिनों बाद किसानों की वास्तविक चीज हो जायगी। स्वामी जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है" जो किसान खुद शोषित है और जो दूसरों का शोषण खुद करना नहीं चाहते। प्रत्युत जो शोषण और जुल्म को संसार से मिटा देना चाहते हैं, वह सभी इस नये संगठन में ही धीरे-धीरे शरीक हो जायेंगे।" वर्तमान किसान सभा में जो लोग शोषण को किसी न किसी रूप में कायम करने के लिए शामिल हैं या रहेंगे वह धीरे-धीरे इससे कालान्तर में खिसकेंगे। फलतः दोनों सभाएं एक ही प्रकार के लोगों की होने के कारण अन्त में एक हो जायेगी।"[15] आगे इसी पृष्ठ पर स्वामी जी लिखते हैं कि "गरीब किसानों के साथ जब कभी इन मजदूरों का झमेला मजदूरी वगैरह को लेकर होगा तो वहां भी दोनों संगठन आपस में बातें करके आसानी से मामला तय करा देंगे।" इस तरह हम पाते हैं कि स्वामी जी गरीब किसानों तथा खेत-मजदूरों के बीच पूर्ण तालमेल एवं आपसी बातचीत में समझौता द्वारा समस्याओं के निदान की बात करते थे। दूसरी ओर जमींदारों तथा धनी किसानों में शोषण के विरुद्ध इनके संयुक्त एवं संगठित संघर्ष एवं लड़ाई के प्रबल समर्थक थे।

1935 के चुनावों के बाद की बनी सरकारों द्वारा किसानों को नाम मात्र की सुविधाएं दी गईं तथा कृषि के बुनियादी सवालों को हल करने संबंधी इन प्रांतीय सरकारों को प्रकट असमर्थता ने कांग्रेस द्वारा प्रचारित स्वराज्य की परिकल्पना के खोखलेपन को साबित कर दिया और प्रमाणित कर दिया कि इस समय को वर्तमान आर्थिक प्रथा को मिटाये बिना वास्तविक स्वराज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।[16] स्वराज का अर्थ स्वामी जी ने इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता से भी जोड़ा। ऐसी समस्याओं का समाधान स्वामी जी की कल्पना में भी ऐसी शासन-प्रणाली ही कर सकती जो स्वयं जनता द्वारा, बालिग मताधिकार के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित हो। ऐसी ही शासन प्रणाली "किसान मजदूरों का पंचायती राज्य होगा जिसको सब कुछ करने-धरने की शक्ति सम्पत्ति को उत्पादन करनेवाली जनता की हाथों में होगी।"[17]

स्वामी जी किसान मजदूर एकता के आधार पर उनकी मुक्ति के संघर्ष को राजसत्ता के संघर्ष के साथ एकाकार करते हुए इस स्थापना को स्वीकार करते हैं कि किसानों एवं मजदूरों की शोषण जन्य समस्यायें वर्गीय समस्यायें हैं जिनका समूलनाश साम्राज्यशाही का विनाश और किसान मजदूर राज्य की स्थापना के द्वारा ही फलित हो सका है, परन्तु स्वामी जी के संघर्ष में संसदीय रास्ता ही एक मात्र हल है, क्योंकि वे बालिग मताधिकार के आधार पर चुनी गई सरकार से ही

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अपेक्षा करते हैं कि वह वास्तविक पंचायती राज्य होगा और उसी में किसान मजदूरों की समस्याओं का निदान हो जाएगा। किसान-मजदूरों के संगठन को स्वामी जी एक वर्गीय संस्था जरूर मानते हैं, परन्तु राजसत्ता के स्वरूप निर्धारण में उनका दृष्टिकोण व्यापक उदार पूंजीवादी या पाश्चात्य सामाजिक जनवादियों का दृष्टिकोण है जो सर्वहारा की तानाशाही को नकारता है।

स्वामी जी का दृष्टिकोण किसान-मजदूरों के निदान में व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय और औद्योगिक-मजदूरों के संघर्षों की एकता के आधार पर किसान-मजदूरों की लाभबंदी का है। "………. मुल्क में और बाहर दूसरी भी जबरदस्त शक्तियां और बातें हैं जो न सिर्फ किसानों को बल्कि भारतीय जनता को भी इन्हीं और ऐसे ही लक्ष्यों की ओर तेजी से खींच रही हैं। युद्ध में किसानों के साथी और क्रान्ति के अग्रदूत जो कारखानों के मजदूर हैं उनके संगठन और संघर्ष उस हद तक पहुंच गए हैं जहां पहले कभी न थे। मजदूरों के संगठन। आन्दोलन में ज्यादा ताकतें आई हैं और मजदूरों की राजनीतिक चेतना बढ़ी है।"[18] कथन मूलगामी आर्थिक-राजनीतिक आन्दोलन द्वारा परिवर्तन में औद्योगिक-मजदूरों की अग्रणी भूमिका की स्वीकारता है और उनके साथ किसानों और कृषि-मजदूरों की एकता के आधार पर चालित आंदोलन का समर्थन है। मगर ऐसी लड़ाइयों के प्रति, जो व्यापक आर्थिक-राजनीतिक परिवर्तनों का संघर्ष है, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के प्रभाव को भी नहीं नकारता, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलनों के प्रसंग में उनकी प्रभावपूर्ण छाप को भारतीय आंदालनों पर स्वीकारते हुए मजदूरों के अंतराष्ट्रीय भाई-चारा का हामी भरता है, क्योंकि पूंजी, जिसके खिलाफ लड़कर ही मजदूर वर्ग अपनी मुक्ति पा सकता है, अंतराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है, इस कारण श्रम का स्वरूप भी उसी के माकूल अंतराष्ट्रीय चरित्रवाला हो, यह जरूरी है।

रियासतों में वास कर रहे किसान मजदूरों की समस्याओं को भी स्वामी जी मात्र नागरिक हकों एवं राजनीतिक आजादी का ही संघर्ष नहीं मानते, बल्कि आर्थिक मुक्ति के लिए भी संघर्ष मानते हैं। "………… रियासतों की पीड़ित जनता भी अपने आपको समझने लगी है और इस प्रकार शेष भारत के साथ अपनी मैत्री की जबरदस्त शृंखला जोड़ रही है।"[19] इस प्रकार की व्यापक एकता में अन्तर्निहित कारक किसान-मजदूरों की समस्याओं के स्वरूप, उनकी गहराइयों एवं विकास एक मंजिलों में समरूपता है जो उन्हें एक जगह ला खड़ी कर रही है, रियासतों की जनता की समस्यायें अन्य भारतीय जन की समस्याओं से भिन्न नहीं है। ऐसी ही स्थापना स्वामी जी करते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उपर्युक्त समस्याओं के लिए संघर्षरत किसान-सभा का दूरगामी लक्ष्य का प्रतिपादन करते हुए स्वामी जी ने स्थापित किया कि भारत में "..................... समाजवादी गणतांत्रिक राज्यों का ऐसा संघ स्थापित करना जिसमें सारी सत्ता श्रमजीवी शोषित जनता के हाथों में हो और इस तरह किसानों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा दूसरे शोषण से पूर्ण छुटकारा मिल सके।"[20] उसी लक्ष्य के लिये लड़ना किसान सभा का प्रमुख कार्य है। स्वामी जी की दृष्टि में चूंकि किसान-मजदूर संयुक्त रूप से सम्पूर्ण अबादी का 80 प्रतिशत पैदा करता है, इस कारण कोई भी राजनीतिक या आर्थिक कार्यक्रम, जो किसानों की विपन्नावस्था को दूर करने का कार्यक्रम नहीं रखता, राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं हो सकता। "किसी संस्था को, जो भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करती हैं, दिवालियों एवं अत्यन्त शोषित किसानों-रैयतों टेनेन्टों तथा खेत-मजदूरों के स्वार्थों को अपने कार्यक्रम में अग्रस्थान देना ही होगा, यदि इसे अपने दावे को सत्य सिद्ध करना है।"[21]

किसान मजदूरों की समस्याओं का स्वरूप

किसान मजदूरों की समस्याओं के स्वरूप निर्धारण में स्वामी जी की अन्तर्दृष्टि वर्गीय आधार और राजसत्ता के चरित्र के स्वरूप के अनुसार विभेदीकरण करती है। किसानों तथा खेत-मजदूरों के वर्गीय स्वार्थ अपने आप में एक दूसरे से नहीं टकराते, बल्कि मूल अंतर्विरोध जमींदारों तथा साम्राज्यवादी के स्वार्थों के आमने-सामने आते हैं। किसान-मजदूरों तथा सरकार के बीच के बिचौलियों जमींदार, ताल्लुकेदार, मालगुजार, इनामदार, पवाईगार तथा अन्य भू-स्वामी और मध्यवर्ती लोग किसान को अखरनेवाली मालगुजारी, भूखों मरनेवाली मजदूरी तो लाद ही दिए हैं साथ ही उन भूमि-सुधार कानूनों से भी वंचित करते हैं जिनका लाभ उठा किसान-मजदूर अपनी स्थिति कुछ सुधार सकते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वरूप भी ऐसा गढ़ा गया जिसमें किसानों-मजदूरों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मांगों को किसी तरह का स्थान ही नहीं दिया गया।

राष्ट्रीय आंदोलन के इस स्वरूप को, जिसमें किसान-मजदूरों की मांगों को उचित स्थान की नहीं दिया गया, स्वामी जी एक पूंजीवादी, जनवादी आंदोलन से ज्यादा कुछ नहीं मानते। यही कारण है कि उनका मतभेद कांग्रेस से कालान्तर में बढ़ते-बढ़ते कांग्रेस विरोध तक पहुंच गया था। राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन, जिसका स्वभाव स्वयं में साम्राज्यवाद-विरोधी होता है। वह पूंजीवादी जनतांत्रिक या व्यापक क्रांतिकारी दानों स्वरूप ग्रहण कर सकता है। चीन के आन्दोलन का स्वरूप जहां व्यापक क्रांतिकारी था, वहीं भारत में उसका स्वरूप पूंजीवादी जनवादी था। इसी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अवधारणा के कारण स्वामी जी कांग्रेस के वामपक्ष की तरफ रहे तथा व्यापक किसान-मजदूर एकता के, जिसमें औद्योगिक सर्वहारा भी सम्मिलित था, आधार पर राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वरूप को बदलने का प्रयास करते रहे और व्यापक वाम मोर्चा की संकल्पना के साकार न होने पर कांग्रेस और साम्यवादी दोनों से अलग हुए, क्योंकि दोनों ही संकल्पना को साकार होने में दोषी थे।

किसान-मजदूरों की दुर्दशा का कारण, जो मौलिक था, "जमीन के बंदोबस्त, मालगुजारी और कर्ज देने की प्रणाली .... जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने मुकम्मल बनाया है और जिसके द्वारा किसानों को सीधे न मारकर ज्यादा से ज्यादा उनसे चूसा जाय"[22] की नीति है, जिसे समाप्त किए बिना किसानों की स्थिति न सुधर सकती। इस प्रकार की स्थापना में कराधान की नीति, साम्राज्यवादी शोषण, इन समस्याओं के प्रति राष्ट्रीय आन्दोलन में एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव आदि के प्रति स्वामी जी की वेदना असह्य थी।

किसान-मजदूरों की समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण तथा उनके साथ बड़ी पूंजी और बड़ी *लतफुन्डिया* के अन्तर्विरोधों का जिक्र स्वामी जी ने अखिल भारतीय किसान सभा के विजयवाड़ा अधिवेशन में ही स्पष्ट कर दिया था "अपनी बुनियादी मांगों या उद्देश्यों की पूर्ति में सम्पूर्ण विश्व को एक नया स्वरूप देने का संघर्ष करना होगा। अगर क्रान्ति की सफलता को सुनिश्चित करना है तो जहां, तहां सुधार का पेबन्द कोई काम नहीं कर सकता। इस तरह के सामाजिक तंतुओं में परिवर्तन की प्रक्रिया मानसिक तंतुओं में हुए परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो समस्त दृष्टिकोणों में परिवर्तन लायेगी। बाहरी जगत में की जाने वाली क्रांति मानसिक जगत की क्रान्ति को सुनिश्चित करके ही प्राप्त की जा सकती है।"[23] किसान-सभा और किसान-मजदूरों का उससे संबंध, किसान सभा की राजनीतिक मसलों पर दृष्टिकोण तथा राजनीतिक दलों के साथ उसके संबंधों के विस्तृत वर्णन में स्वामी जी का एक ही दृष्टिकोण परिलक्षित होता है और वह है किसानों तथा खेत मजदूरों की समस्याओं के निदान कर संघर्ष और अन्य मजदूरों के साथ उसके भाईचारे की स्थापना कर एक सर्वांगीण कार्यक्रम के आधार पर आंदोलन गठित कर उसे राजनीतिक आंदोलन की ऊंचाई तक ले जाना।[24]

स्वामी जी ने चार कांग्रेसों शासन को प्रत्यक्षतः देखा था जिनमें 1937, 1943, 1946 और 1947 की सरकारें थीं और उन्होंने सभी सरकारों के स्वरूप में, किसान विरोध पाया था। 1937 की कांग्रेसी सरकार के संबंध में उनकी अवधारणा थी, "रह गई किसानों और मजदूरों की बात। सो तो बंबई और कानपुर की गोली और आंसू लगनेवाली गैस के प्रयोग आदि ही बताते हैं कि मजदूरों ने क्या पाया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उनकी हड़ताल को तोड़ने में बम्बई में सारी ताकत लगा दी गई। कानून भी ऐसा बना कि मजदूरों को उसका खुलेआम विरोध करना पड़ा और जब उन्होंने उसके विरोध में हड़ताल की तो कांग्रेसी सरकार और कांग्रेस की सारी ताकत उसे तोड़ने में लगी। .... जमशेदपुर, झरिया, डिहरी, बिहटा आदि मिलों के मजदूर बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल को क्या कभी भूलेंगे? .... जमींदारों ने इसी बीच में दो-दो बार बठबंधन करके किसानों के गले पर जो भोंथी छुरी चलाई गई उसे कौन नहीं जानता? खड़ी फसल की जप्ती को कानून के जरिये आसान करके किसानों को जो लाभ पहुंचाया गया, उसे तो वे पुश्त-दर-पुश्त न भूलेंगे। लगान घटाने में जो गोलमाल मचा तथा सब मिलकर अंत में किसानों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, वह भी भूलने का नहीं। जो भी कानून की एकाध बातें किसानों के फायदे की बनीं, उनकी भी शब्दावली ऐसी बनी कि जमींदारों ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। भावली की नगदी में आसानी की गई। मगर हजार चिल्लाने पर भी फसल काटने की मजदूरी और दूसरी बातों का कोई निर्णय न करने से किसानों को लेने के देने पड़ गए।"[25] 1947 की कांग्रेसी सरकार के प्रति भी उनका रुख इसी तरह था कि वह किसान मजदूर विरोधी है।

किसान-मजदूरों की मांगों के प्रति अपने दृष्टिकोण में स्वामी जी संविधान सभा को भी किसान-मजदूर विरोधी मानते हैं "प्रतिनिधित्व शून्य एवं अजनतांत्रिक मौजूदा विधान परिषद् के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को अमान्य ठहराने के लिए (किसान-सभा) जनता को ललकारेगी और कहेगी कि जनता की विधान परिषद् बुलाई जाय, जो सार्वजनिक बालिग मताधिकार के आधार पर चुनी जाय और भारत में समाजवादी प्रजासत्ताक राज्यों के संघ के लिए विधान बनाये, ताकि (अ) सरकार के संचालन में मजदूरों एवं किसानों को वाजिब स्थान मिले, (व) संघ में सम्मिलित सभी मांगों को पूर्ण स्वतंत्रता हो और (स) भाषा के आधार पर सभी भू-भागों का फिर से बंटवारा हो।"[31]

किसान और खेत-मजदूरों के सम्बन्ध में, 1942 ई. में शेरघाटी में बिहार प्रांतीय किसान सभा के नवें अधिवेशन में सभापति के पद से भाषण करते हुए स्वामी ने कहा—किसान सभा के वास्तविक आधार छोटे किसान और खेत-मजदूर ही है।[26] 1928 ई. में किसानों से उनका अभिप्राय उन सभी से था, "जिनका जीने का प्राथमिक स्रोत खेती था।"[27] 1934 ई. तक उनमें छोटे जमींदारों और रैयतों के अतिरिक्त ऐसे मजदूर भी शामिल हो गये थे जिन्हें अपने नियोक्ताओं से जमीन मिली हुई थी।[28] 1936 ई. में स्वामी जी ने खेत-मजदूरों को भी किसान कोटि में शामिल कर लिया।[29] खेत-मजदूरों को किसान वर्ग में इसलिए शामिल किया गया

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

चूंकि वे ही जमीन के जोतने-बोने वाले होते हैं और प्रतिवर्ष नौ लाख से भी ज्यादा किसान अपनी जोत की जमीन गंवाकर खेत-मजदूर बन रहे थे।[30]

स्वामी जी की इस अवधारणा पर उन विश्व क्रान्तिकारी आन्दोलनों का स्पष्ट प्रभाव नजर आता है, जहां मजदूरों ने शोषण रहित समाज की परिकल्पनाओं के तहत किसान-मजदूर राज्यों को कायम किया था तथा सर्वहारा की तानाशाही के द्वारा शोषण की प्रक्रिया को उल्टी दिशा में मोड़ दिया था। स्वामी जी किसान-मजदूर समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए वैसे क्रांतिकारी परिवर्तनों को स्वीकारते हैं, मगर सर्वहारा की तानाशाही की जगह बालिग मताधिकार के द्वारा चुनी गई समाजवादी सरकार की अवधारणा के पोषक हैं तथा राज्यों को व्यापक अधिकार दिये जाने के पक्ष में हैं।

अखिल भारतीय किसान सभा के निर्माण के बाद

असहयोग आंदोलन को शुरू कर किसान-मजदूरों की मांगों को उद्भासित करते हुए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन संघर्ष और आजादी की लड़ाई में एक वामपंथी रुझान के लिए, 1930 के नमक सत्याग्रह तथा कई बार जेल यात्रा के बाद 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के बाद जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर सभी किसानों के तथा मजदूरों के वर्ग-संघर्ष पर जब पाबंदी लगा दी तब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने सहयोगियों के साथ, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, के.एफ. नारीमन, किशोरी प्रसन्न सिंह आदि को कांग्रेस के इस किसान-मजदूर विरोधी प्रस्ताव का संपूर्ण भारत में घूमकर विरोध संगठित किया जिसके कारण उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के तहत इन वर्गों को तीन-तीन वर्षों तक कांग्रेस से किसी भी पद पर बने रहने से वंचित किया गया। इसके बाद भी स्वामी जी ने वर्ग संघर्ष की नीति का त्याग नहीं किया।

कांग्रेस कार्य समिति का यह प्रस्ताव 1936 से किसान सभा द्वारा जारी उसके घोषणा-पत्र वर्णित उन मुद्दों के खिलाफ था जिसमें किसान सभा का ध्येय "आर्थिक शोषण से पूरी तरह मुक्ति तथा किसानों, मजदूरों और अन्य वर्गों के द्वारा मुकम्मिल रूप से आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति हासिल करना"[32] स्थित किया गया था। इस घोषणा-पत्र में वह उल्लेख किया गया था कि किसान सभा का प्राथमिक कार्य है "अपनी कोरी राजनीतिक-आर्थिक मांगों के लिए संघर्ष करना जिससे हर प्रकार के आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण से पूरी तरह मुक्ति हासिल करने के लिए आखिरी लड़ाई की तैयारी हो सके।"[33] किसान-सभा के मंच से

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मजदूरों की सम्पूर्ण मुक्ति का प्रश्न पहली बार उठा था और उसके परिणामस्वरूप 1936 में ही किसान-सभा ने मई दिवस मनाया।

स्वामी जी के नेतृत्व में किसानों और मजदूरों की व्यापक एकता बनी। संपूर्ण मुक्ति के लिए दिया गया नारा तथा वर्गीय आंदोलनों का दृष्टिकोण उन्हें किसान-मजदूर प्रश्नों पर साम्यवादियों के निकट ज्यादा लाया गया तथा कांग्रेस, ने जो राष्ट्रीय पूंजी, बड़ी जमींदारियों तथा उच्च मध्यमवर्ग के सबसे वाचाल तबके का प्रतिनिधित्व करती थी, वर्गीय अंतर्विरोधों को पैदा कर दिया। इस वर्गीय समझ का प्रतिबिंब किसान सभा की नियमावली में ही परिलक्षित हुआ।[34]

वास्तव में अखिल भारतीय किसान सभा का वर्गीय दृष्टिकोण जैसे-जैसे किसान-मजदूर पक्षी होता गया, कांग्रेस का रुख इस सभा के प्रति द्वेषपूर्ण होता गया। यह 1937 के बाद से ही परिलक्षित होने लगा था। कांग्रेस का मेंबर बनकर किसान-सभा की सदस्यता ग्रहण किए जाने का कांग्रेस का प्रावधान वास्तव में किसान-मजदूर आंदोलनों के स्वतंत्र विकास पर एक पाबंदी थी और उसे इन आर्थिक सामाजिक स्वार्थों के साथ बांध देने की नीति थी, जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती थी। सम्पूर्णता में कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी थी, और इस हद तक उसकी नीतियां प्रगतिशील थीं, परंतु अपनी घरेलू नीति के मामलों में उसकी नीति देशी पूंजी और भारतीय *कुलकों* के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती थी, और यही कारण था कि किसान सभा का वह आंदोलन जिसकी मुख्य धारा साम्राज्यवाद विरोधी होती थी उसके पक्ष में कांग्रेस रहती थी मगर ज्योंही आजादी के संघर्ष को वर्ग विहीन राजसत्ता प्राप्ति का लक्ष्य आता वह किसान-सभा के खिलाफ ही जाती। मूलरूप में गांधीवादी दर्शन के तहत चलाया जा रहा राष्ट्रीय आंदोलन की नीतियों का सार दोहरा चरित्र वाला था, जिसके अंदर साम्राज्यवाद का विरोध तो था पर देशी पूंजी के हितों को लांघ कर नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर। इस प्रकार किसान सभा और कांग्रेस के मूल मतभेदों का आकलन करते हुए कहा जा सकता है कि किसान सभा स्वामी जी के नेतृत्व में अर्थनीति और आर्थिक कार्यक्रमों को लेकर चलती हुई उन्हें राजनीति द्वारा देखती थी, उसे साधन और आर्थिक बातों को साध्य मानती थी और इसीलिए राजनीतिक हार जीत की परवाह किए बिना सदा किसानों की आर्थिक बातों को ही देखती थी, और वैसा ही कार्यक्रम चाहती थी वहीं कांग्रेस राजनीति को ही अर्थ नीति द्वारा देखती थी। फलतः उसके लिए आर्थिक बातें मात्र साधन हैं साध्य तो राजनीति है। मगर जो लोग किसान-सभा पर स्वामी जी के विषय में ऐसी स्थापना करते हैं कि उसका साध्य मात्र आर्थिक लाभ था वे स्वामी जी या उनके द्वारा चालित किसान-सभा के उद्देश्यों की व्याख्या

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से करते हैं, क्योंकि किसान-सभा का अंतिम लक्ष्य किसानों या मजदूरों को कुछ तात्कालिक आर्थिक मांगों की प्राप्ति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसका दूरगामी कार्यक्रम किसान मजदूर राज्य की संकल्पना को, जिसमें मानव-द्वारा मानव के शोषण विहीन समाज की परिकल्पना निहित थी, कायम रखना था। इसमें किसान सभा आर्थिक मांगों को एक खास ऊंचाई पर राजनीतिक मांग उठाती थी, और उन मांगों की मूल दिशा संपत्ति के वर्तमान स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करना था- जैसे जमींदारी उन्मूलन। मुआवजा देकर जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ स्वामी जी की दलील थी कि इससे किसानों के भविष्य को पहले से ही जकड़ देने के बराबर है, क्योंकि उनकी कल्पना में ये रुपये किसानों से ही वसूले जाएंगे, जो कर्ज सरकार मुआवजा चुकाने के लिए लेगी उसकी पूर्ति का भार किसान-मजदूरों को उठाना होगा, अगर वही रकम किसान-मजदूर हित में खर्च होता तो उसका सुपरिणाम अधिक उत्पादन विकास आदि के रूप में सामने आता। इस प्रकार किसानों की रक्षा के व्रत का पालन न कर एक बड़ी रकम मुआवजा में दे देना अनुचित था- ऐसी धारणा स्वामी जी की थी।

कांग्रेस की मध्यमार्गियों की संस्था समझने वाले स्वामी जी को ऐसा लगा कि स्वराज्योपरान्त कांग्रेस की जो सरकार बनेगी उसका शासन सूत्र मध्यमार्गियों के हाथों में चला जाएगा उसका उपभोग जमींदार और पूंजीपति अपने वर्ग स्वार्थ में करेंगे, जिसका परिणाम होगा कि किसान मजदूरों का शोषण निर्वाधगति से चलता जाएगा, वे और ज्यादा संगठित और मालदार होंगे। इस प्रकार स्वामी जी को दिखने लगा कि आजादी के बाद वर्गीय ध्रुवीकरण की प्रक्रिया और अधिक तेज हो जाएगी तथा देश में निहित्त पूंजीपति तथा जमींदार स्वार्थों के खिलाफ एक और संघर्ष का दौर आएगा। अपने विश्लेषण में स्वामी जी का आंकलन शत प्रतिशत न सही मगर ज्यादातर सही था इसलिए उन्होंने जिस भारतीय राजसत्ता के स्वरूप का आकलन किया वह कांग्रेस-द्वारा पूरा होने वाला न था। उन्होंने अपनी परिकल्पना के स्वतंत्र भारत के स्वरूप की विवेचना करते हुए कहा था- "मैं कमानेवाली जनता के हाथ में सारा शासन औरों से छीन कर देने का पक्षपाती हूं। उनसे लेकर या उन पर दबाव डालकर देने दिलवाने की बात मैं गलत समझता हूं। हमें लड़कर छीनना होगा। तभी हम उसे रख सकेंगे। यों आसानी से मिलने पर छिन जाएगा यह सत्य है, जो मिले हुए को मैं सपने की संपति मानता हूं .... मैं लड़ाई और लड़ने वाला चाहता हूं। मैं आर्थिक लड़ाई को छोड़कर आजादी की लड़ाई का विरोधी हूं। मैं आर्थिक युद्ध को ही आजादी के युद्ध में परिणत करना चाहता हूं। मैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति चाहता हूं और भी दूसरी तरह से नहीं हो सकती।"[35]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

किसानों और मजदूरों के शोषण की सर्वनाशी व्यवस्था जमींदारी को, जिसको साम्राज्यवाद भारत में पालपोस रहा था, और जिसके खात्मे के लिए किसान सभा संघर्ष कर रही थी, खत्म करने पर सरकार के बयानों प्रस्तावों आदि की आलोचना करते समय स्वामी जी सरकार की इच्छा-शक्ति की आलोचना करते हैं जो बार-बार वादे कर किसानों और मजदूरों को झूठे आश्वासन दिए जा रही थी। मुआवजा देकर जमींदारी उन्मूलन का अर्थ था कि जब तक सभी जमींदारियों का सर्वे नहीं हो जाता, यह नहीं पता चल जाता कि किसकी कितनी आय है, कितनी जमीन है, कैसी जमीन है, तब तक मुआवजा नहीं दिया जा सकता। एक ही जमींदार को कई प्रांतों में फैली जमींदारियों का आकलन प्रायः असंभव सा है। यह बात अनेक विद्वानों ने की है कि भारत में जमींदारों को बड़ी रकम मुआवजे के रूप में दी गयी इसलिए जमींदारी अन्मूलन के बाद भी समाज में असमानता पर आधारित विभाजन बरकरार रहा। डेनियल थार्नर ने एगरेरियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया (1956) में कहा है कि बड़ी मात्रा में जमींदारों को मुआवजा भुगतान के कारण एक शक्तिशाली ग्रामीण अभिजात्य वर्ग का वहां विकास हुआ।[36] भूमिपति, आसामी तथा कृषि मजदूर के रूप में ग्रामीण समाज का स्पष्ट विभाजन बरकरार रहा। जमींदारों तथा भूमिपतियों का वर्चस्व बना रहा।

दूसरी बाधा मूल्य बाजार दर से पूरा-पूरा देने की है, जो मात्र बिहार में चार अरब से कम का नहीं होगा और तमाम प्रांतों में इसको चुकाने का अर्थ होगा मुद्रा-स्फीति जो कीमतों को बढ़ा देगी तथा ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगी जहां किसानों और मजदूरों को अपनी जरूरत के सामानों को खरीदने की शक्ति ही घट जाएगी।

इस प्रकार स्वामी जी घाटे के बजट और मुद्रा-स्फीति के परिणामस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों से प्रभावित होने वाले किसान मजदूरों को निजात दिलाने के लिए जमींदारों को किसी तरह का मुआवजा दिए बगैर जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए संघर्षरत थे। वास्तव में भारत में जमींदारी-उन्मूलन का जो रास्ता सरकार अपना रही थी वह इंग्लैंड के जुंकरों के ढंग के भू-स्वामी पूंजीवाद के दकियानूसी रास्ते को ही आगे बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि भूमि पर प्रभावी इजारेदारियों को बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा था तथा बिचौलियों को घरेलू फार्मों या खुदकाश्त के नाम पर बड़ी-बड़ी जमीन उनके पास रहने देने का प्रबंध किया जा रहा था। जमींदारी उन्मूलन एक मात्र प्रभावी नतीजा हो रहा था मात्र वसूलियों को सरकार के हाथों में लेना। फिर भी यह एक प्रगतिशील कदम था, जिसमें गैर हाजिर मिल्कियतों और कई किस्म की गैर-कानूनी वसूलियों पर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

रोक लग रही थी। इस भूमि-सुधार का अगर किसी अन्य देशों के भूमि-सुधारों के समरूपता थी तो वह फ्रांस के सुधारों से नहीं, बल्कि जापान के *मेइजी* नमूने से जिसके सामंती *दाइमार्यो* को बांडों के रूप में मुआवजे दिए गए थे जिसमें वे बड़े वित्त व्यापारी बनकर उभर सके थे और गांवों के स्तर पर *ओयकाता* को मालिकाना हक दिया गया था।[37] स्वामी जी भारतीय कृषि सुधार में इन प्रथाओं के अनुसरण के खिलाफ थे।

छोटानागपुर के खनिज-बहुल क्षेत्रों में खानों पर बड़ी पूंजी का स्वामित्व है और उनको लेना उस वर्ग को नाखुश करना था जो कांग्रेस का आर्थिक आधार था, जो चुनावों में पैसे देता था और कांग्रेस उनके खिलाफ जाने में हिचक रही थी।

जमींदारी-उन्मूलन के लिए किसान-सभा के नेतृत्व में चलाये जा रहे आन्दोलन की गंभीरता ने कांग्रेस के सम्मुख जिन समस्याओं को उत्पन्न कर दिया था उसके दो पहलू स्पष्टतः सामने थे। जमींदारी उन्मूलन न करके कांग्रेस किसानों और मजदूरों की उस भारी संख्या का, जो प्रायः आबादी का 80 प्रतिशत थी, सहयोग प्राप्त करने में वंचित हो रही थी, तो दूसरी तरफ बड़ी *लतफुंजियों* का तथा बड़ी पूंजी का, जो उसको आर्थिक आधार देती थी सहयोग जमींदारी उन्मूलन कर खो रही थी। अतः कांग्रेस एक ऐसे विकल्प की खोज में थी जो दोनों को उसके साथ रख सके और यह विकल्प था बिचौलियों की गैर कानूनी वसूलियों को समाप्त कर किसानों को कुछ राहत प्रदान कर देना तथा दूसरी तरफ जमींदारी को भारी मुआवजा देना और उनकी बड़ी जमीनों को खुदकाश्त के नाम पर उनके पास रहने देना। कांग्रेस ने यही किया मगर किसान सभा इसकी खिलाफत करती रहीं, क्योंकि किसानों और खेत मजदूरों का शोषण इससे समाप्त नहीं हो सका।

अपने उसी वर्ग स्वार्थ में कांग्रेस जमींदारों को समाप्त ही नहीं की मगर जमींदारी समाप्त करने की किसान-सभा की मांग के प्रचार-प्रसार के कारण किसानों के सम्मुख नई समस्या उत्पन्न करा दी गयी और वह समस्या कि "जमीनों की छीनाझपटी की।"[38] यह ठीक है कि जमींदारी उन्मूलन से किसानों को जमीन का प्रत्यक्ष अधिकार मिला लेकिन उनकी समस्यायें समाप्त नहीं हुईं।

1938 के बाद के किसान सभा अधिवेशन में किसान-मजदूर समस्या पर स्वामी जी :-

1938 में किसान सभा का जो अधिवेशन कोमिल्ला में संपन्न हुआ था उसमें स्वामी जी को किसान-मजदूर समस्याओं के प्रति अपने एकीकृत तथा विशद

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विचारों को रखना था। किसानों को संघर्ष करने के लिए उत्प्रेरित करते हुए उन्होंने ट्राटस्की का हवाला देते हुए कहा था कि "राजनीतिक भाषा में अहिंसा का अर्थ है कि वर्तमान प्रणाली और व्यवस्था को बदलने में हिंसा का जरा भी काम न किया जाय। लेकिन इसे कायम रखने के लिए क्रूर-से-क्रूर काम भी कर सकते हैं।"[39] अपने को इस उक्ति के साथ खड़ा कर किसान-मजदूर आंदोलन में अंहिसा के उस सिद्धांत को, जिसे गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ढोये जा रही थी, स्वामी जी ने नकारा तथा इसे एक प्रतिक्रियावादी रुझान के तहत पनपनेवाला दर्शन माना जो यथास्थितिवाद का पिष्टपोषक था और किसान मजदूर राज्य की, या शोषण-मुक्त राज्य की परिकल्पना के खिलाफ एक पूंजीवादी यथास्थितिवाद के प्रचारतंत्र का अंग माना। इसी आधार पर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही थी इस कारण किसान-सभा का अस्तित्व किसानों और मजदूरों के वर्गीय संघर्ष को चलाने के लिए अपरिहार्य्य था।[40]

किसान-मजदूरों के हक के संघर्ष में स्वामी जी हिंसा को वर्जित नहीं मानते थे[41] और जमींदारों के खिलाफ उन्होंने नारा दिया था; कैसे लोगे मालगुजारी, लट्ठ हमारा जिंदाबाद, कमानेवाला खायेगा, इसके चलते जो कुछ हो स्वामी जी का ऐसा नारा किसानों और मजदूरों को एक सशक्त संगठन के अंदर रखकर अपनी मांगों की प्राप्ति में गांधीवादी अहिंसा को इनकार कर देना था। इन नारों के साथ मुजफ्फर हसन, इन्दुलाल याज्ञिक, एन.जी. रंगा, शीलभ्रदयाजी, किशोरी प्रसन्न सिंह आदि नेताओं का संपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। आजादी संघर्ष के साथ किसान-मजदूर आंदोलन की एकात्मकता की उनकी स्पष्ट समझ थी कि किसानों की पूर्ण आजादी ही असली स्वराज है, कांग्रेस का स्वराज का नारा पूर्ण आजादी नहीं है। पूर्ण क्रांति की उनकी अवधारणा में यह सम्माहित था कि समाज के आर्थिक सामाजिक जांचे के सबसे निचले स्तर के जन आवाम की खुशहाली ही पूर्ण क्रांति होगी।[42]

स्वामी जी के इस दृष्टिकोण ने कांग्रेस की नीतियों के प्रति उन्हें एक आलोचक के रूप में खड़ा कर दिया और इसी का नतीजा था कि 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के मौके पर उन्होंने सुभाष बोस द्वारा आहूत समझौता विरोधी सम्मेलन की अध्यक्षता की तथा कांग्रेस की इस स्थापना की कि आजादी की लड़ाई के लिए जनता तैयार नहीं है कि आलोचना करते हुए घोषणा की कि जनता आजादी की लड़ाई के लिए तैयार है।[43]

किसानों और मजदूरों की समस्याओं के प्रति उनका लगाव दृष्टिकोण या सद्भावना क्या थी, उन्होंने लिखा है:-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रायेण देव मनुयः स्वविमुक्तिकाया,
मौनं चरन्ति बिजने न परार्थ निष्ठाः।
नेतान्विहाय कृपणानिवमुमुक्ष एको,
नान्यंत्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये।।[44]

स्वामी जी के सामने उन निहित स्वार्थों के संघर्ष का एक मोर्चा यह भी कहा था कि वे तथाकथित खेतिहर-मजदूरों के पक्षधर नेताओं की क्रांतिकारी लफ्फेबाजी के द्वारा किसान सभा से खेत-मजदूरों को अलग करना चाहते थे। "जमींदारों से दोस्ती और मजदूरों की सेवा दोनों विरोधी बाते हैं।"[45] स्वामी जी ने इस तरह के मिथ्या प्रचार-तंत्रों का खंडन किया। उनका खंडन पूंजीवादी राजसत्ता के चरित्र को आधार बनाकर किया गया था जिसमें वर्गो का ऐसा श्रेणीबद्ध बंटवारा कर दिया जाता है कि हर तबका अपने नीचे वाले का शोषण करने की योग्यता पा लेता है। परंतु शोषण की ऐसी प्रक्रिया में किसानों तथा मजदूरों, हालांकि किसान-मजदूर का शोषण करता है, का उत्पादन संबंध ऐसा अंतर्विरोध मुक्त रही है कि एक दूसरे का खात्मा करके ही जिन्दा रह सकता है। इसी बुनियादी सैद्धांतिक आधार पर स्वामी जी ने स्पष्ट किया "वे ही लोग किसान-सभा को शोषक-सभा कहा करते थे जो इसकी सही समझ नहीं रखते थे। कौन शोषण नहीं करता? क्या खेतिहर मजदूर अपने धोबी, हजाम का शोषण नहीं करते? पर जैसे यह शोषण नहीं है वैसे ही किसानों द्वारा अपनाया गया शोषण भी शोषण नहीं है। किसान-मजदूर में फर्क कहां? खेती से विमुख किसान मजदूर बनकर कल कारखाने चलाता है, सारे देश का विकास करता है। खेती से लेकर कल कारखाने तक किसान ही हैं-रूप अलग है। किसान द्वारा मजदूर के शोषण की जहां तक बात है तो शोषण को स्वामी जी ने दो प्रकार का शोषण बताया। एक तो जानबूझकर संगठित रूप से, दूसरा बेबसी के चलते असंगठित रूप से मजबूरन या सामाजिक स्थिति के चलते।[46]

स्वामी जी वर्ग-संघर्ष की ऐसी अवधारणा में समस्त अर्थव्यवस्था के संचालन में किसानों, दरिद्रीकृत किसानों एवं खेत मजदूरों की ही भूमिका देखते हैं, कहीं खेतों में और कहीं कारखानों में। इसीलिए किसान ही उनके भगवान हैं जो सर्वव्यापी और सारी सृष्टि को अपनी मेहनत से चलाते हैं।

आजादी के पश्चात् किसान-मजदूरों की समस्यायें और स्वामी जी

1947 के 15 अगस्त को जब राजसत्ता का हस्तांतरण भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के हाथों की गई तो किसानों की उम्मीदें बढ़ी थीं कि उनकी समस्याओं का स्थायी हल होगा–लगान, मालगुजारी तथा कर्ज देने की मनहूस प्रणाली का खात्मा कर दिया

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जाएगा, तथा मध्यवर्ती को समाप्त कर दिया जायेगा। मगर जो स्थिति उभरी उसमें जमींदारी-उन्मूलन के प्रस्ताव को विचाराधीन रखते हुए यह प्रयास जारी किया गया कि किसानों की मनोवृत्ति जमींदारों को भारी मुआवजा देने के प्रति तैयार हो जाय। कुछ प्रांतीय सरकारों ने थोड़ा कानून बनाया भी उसे लागू नहीं किया गया और लागू किए जाने के लिए किए जा रहे आंदोलन को सरकार बेरहमी से दबाती रही, दमन चक्र इतना प्रबल हुआ कि किसान कमेटियों, कई राजनैतिक दलों को गैर कानूनी घोषित किया गया। कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों का यह प्रमाण है कि वह निहित स्वार्थों की तरफ की जा रही है।

इसी अवधारणा के तहत स्वामी जी किसान-मजदूर राज्य की परिकल्पना करते हैं, "इसी तरह किसानों की लड़ाई किसान-मजदूर (मजदूर-किसान) राज्य की लड़ाई में परिणति हो जाती है और मिल जाती है।"[47] यह ऐसी परिस्थिति है जहां राजनीतिक आंदोलन आर्थिक एवं सामाजिक आंदोलनों को भी अपने में समाहित कर लेता है। किसान मजदूर समस्या का यह जंग राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर माल महकमों के आफिसरों, जमींदारों, साहूकारों एवं उनके दलालों के द्वारा की जानेवाली हजारों किस्म की बदमिजाजियों एवं दुर्व्यवहारों को मिटा देगी। इसलिए संघर्ष का स्वरूप निरा अर्थवाद रखना एक धोखा है, उसका राजनीतिकरण एक मान्य निदान। युद्ध के लिए किसानों, मजदूरों और उनके सहयोगी वर्गों का उनकी समस्याओं के मौलिक समाधान के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में उनकी हिस्सेदारी की गारंटी के लिए स्वामी जी दो मोर्चा पर अविराम संघर्ष करते रहने की बातें करते हैं:–1- स्वामी जी की धारणा है कि एक ओर तो पार्लियामेंट्री (वैधानिक) कार्यक्रम और हलचलें हैं जो स्थिर स्वार्थ एवं प्रतिक्रिया के दुर्ग पर निर्णायक धावा बोलने के लिए किसानों को बहुत कुछ तैयार कर सकती हैं, बशर्ते कि वे परीक्षित एवं विश्वसनीय नेताओं के द्वारा क्रांतिकारी दृष्टि से चलाई जाय।[48] मगर इस संवैधानिक लड़ाई के लिए स्वामी जी का संबंध मात्र इतनी ही दूरी तक है जितनी दूर तक यह मजदूरों एवं किसानों की राजनीतिक चेतना को एक ऐसी मंजिल तक ले जाती है जहां वे समझने लगते है कि यह "संवैधानिक संघर्ष तथा तरीके धोखा की टट्टी है।"[49] लेकिन स्वामी जी इस संघर्ष को, जो अपने स्वभाव में संवैधानिक है, मानते हैं कि "यह अंतिम बात तभी होती है जब पार्लियामेंट के भीतर की लड़ाई बाहर की प्रत्यक्ष लड़ाइयों के साथ-साथ चलती है।"[50] इस अर्थ में संसदीय संघर्ष का बाहर के प्रत्यक्ष कार्रवाईयों के अभाव में कोई महत्व स्वामी जी नहीं देते, बिना प्रत्यक्ष कार्रवाई के साथ जोड़े यह मिथ्या है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दूसरा तरीका, जिससे जनता को अपनी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है वह जो गैर संसदीय तरीका है, प्रत्यक्ष बाहरी कार्रवाई का तरीका है और यही बाहरी असंवैधानिक हलचलें किसानों का एकमात्र वर्ग संघर्ष ही तो है।[51] स्वामी जी मानते हैं कि किसान मजदूरों की वर्गीय लड़ाई वास्तव में औपनिवेशिक दासता के खिलाफ किए जाने वाले महती महत्व की कार्रवाई में प्रायः दबी रहती है, क्योंकि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता का व्यापक संघर्ष आम जनता तथा साम्राज्यवाद के स्वार्थों के बीच के महत्वपूर्ण अंतरविरोधों के ऊपर देशी पूंजी तथा श्रम के अंतर्विरोधों को नहीं रखा जा सकता। आजादी से पूर्व भारत में जनता का गुलामी के खिलाफ का संघर्ष तथा साम्राज्यवादी शोषण के बीच अंतर्विरोध सर्वोपरि था इस कारण एक व्यापक साम्राज्यवादी संयुक्त मोर्चा, जो खेत-मजदूरों तथा औद्योगिक-मजदूरों से लेकर राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग, तक का बना हुआ था। मगर आजादी के बाद भारत में "राष्ट्रीयता को आमतौर ये अब तक जैसा समझा तथा भारत में उसका प्रयोग किया जाता या उसकी वह आकर्षण शक्ति, जो वर्ग संघर्ष के रोकने का काम करती थी"[52] खत्म हो जाने के बाद समय आ गया कि वर्ग-संघर्ष को निर्बाध गति से चलाया जाय और जब तक आजादी की परिकल्पना में आर्थिक एवं सामाजिक आजादियों का समावेश न कर दिया जाता जिससे धनोत्पादक जनता का बखूबी स्वार्थ इससे संबद्ध न हो जाय तब तक आजादी सच्ची आजादी नहीं बन सकती।

इस प्रकार स्वामी जी खोखली राजनीतिक स्वतंत्रता को सच्ची स्वतंत्रता नहीं मानते, "यह तो एक लक्ष्य का साधन मात्र है और वह लक्ष्य है समाज में मनुष्य के हाथों मनुष्य का शोषण का निर्मूलन और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं पूरी उन्नति का सभी साधनों का सबके लिए सुलभ बनाना।"[53] स्वामी जी इसी कारण वर्ग-संघर्ष को महत्व देते हैं तथा मध्यमवर्गीय ढुलमुल नेतृत्व की आलोचना भी करते हैं।

किसान के व्यक्तिवादी चरित्र को जैसा बुखारिन ने कहा था, "अपने नन्हें से खेत से आगे देख सकता ही नहीं।"[54] वर्ग-संघर्ष तक लाने के लिए किसानों में वर्ग चेतना पैदा होने एवं करने की जरूरत पर स्वामी जी पूंजीवादी और सामंतवादी सरकारों के वर्ग चरित्र का खुलासा करते हैं कि यह "शोषक दल के द्वारा चालाकी से तैयार किया गया ऐसा यंत्र है जो धन पैदा करनेवालों को दबाकर सदा मातहती में रखे"।[55] वर्ग-संघर्ष हर किसान को उनकी अकर्मण्यता एवं मजदूरों के साथ मैत्री की आवश्यकता को जरुरी बनाना है, इस कारण किसान मजदूरों की मांगों, समस्याओं आदि के निदान का एक ही रास्ता है उनमें ऐसी वर्ग-चेतना का सृजन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

करना, जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक लड़ाइयों को एक साथ मिला बड़े जमींदारों व भू-स्वामियों समेत पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के खिलाफ एक समता मूलक समाजतंत्रात्मक सत्ता के निर्माण के जंग को उसकी पूर्णाहुति तक लड़ सके। यह संघर्ष किसानों की खास मांगों और दावों पर आधारित होना चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने किसानों के दावे और कार्यक्रम का एक खरीता तैयार किया जिसके 46 मुद्दों को उन्होंने समाहित किया जो निम्नांकित है :-

किसानों के दावे का खरीता[56]

1. क्योंकि जमींदारी (यू.पी. उत्कल, बंगाल, बिहार, मद्रास, आसाम) ताल्लुकेदारी (यू.पी. गुजरात) मालगुजारी (मध्य प्रांत), इस्तिमरारदारी (अजमेर), खोतो (दक्षिण) जन्मो (मालावार), इनामदारी, पवाईदारी, जागीरदारी आदि वर्तमान प्रथायें मध्यवर्गियों (जो खुद खेती नहीं करते) के हाथों में बहुत अधिक जमीनों का स्वामित्व, लगान की भारी रकम की वसूली तथा उसके उपभोग का अधिकार देती हैं- उन्हीं मध्यवर्तियों के हाथों में जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत में बनाया और पाला पोसा और इसीलिये ये प्रथायें किसानों के लिये अन्यायपूर्ण, अनुचित, भार तथा उत्पीड़क हैं, भूमि की पूरी पैदावार एवं तन्मूलक राष्ट्रीय सम्पत्ति की वृद्धि के मार्ग में रोड़े है ओर इसी के साथ-साथ पूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति में मुल्क के लिये जबर्दस्त बाधा स्वरूप हैः साथ ही ये जमींदार बगैरा बहुत ही खतरनाक जोंक है जो करोड़ों किसानों से अत्यधिक लगान लेने और उन्हें सताने के साथ-साथ सिंचाई के साधनों को दुरुस्त नहीं रखते तथा खेती में सहायता देने या उपज बढाने के लिये भी कुछ नहीं करते, इसलिये जमींदारों की ये सभी प्रथायें तथा जमीन के ऊपर जो भी मध्यवर्ती स्वार्थ है सब के सब बिना मुआवजे दिये ही फौरन मिटा दिये जायेंगे, सभी जमीनों पर असली किसानों एवं जोतने-कोड़ने वालों का अधिकार होगा और उन्हें क्रमिक वृद्धिशील कृषि आयकर देना पड़ेगा।
2. क्योंकि मालगुजारी-वसूली एवं जमीन के बंदोबस्त के वर्तमान तरीके, जिन्हें सरकार ने रैयतवारी इलाकों में जारी रखा है, अत्यंत उत्पीड़क तथा परेशान करनेवाले सिद्ध हो चुके हैं, जिनके चलते किसानों की दरिद्रता बढ़ती जा रही है, इसलिये ये सभी तरीके तथा वसूलियां फौरन उठा दिया जाएगा और उनकी जगह क्रमिक वृद्धिशील कृषि आयकर चालू होगा जो पांच प्राणियों तक के खानदान पर सालाना 1200/- या अधिक आयकर लगेगा।
3. क्योंकि गांवों में प्रचलित उत्पीड़क ऋणग्रस्तता एवं अत्यधिक सूद की दर के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

चलते किसान निर्दयता पूर्वक सतावें तथा ऋण भार से बहुत ही दबाये जाते हैं;

- क्योंकि अधिकांश किसानों की जमीनें या तो दूरवर्ती (काश्त न करने वाले) जमींदारों, साहुकारों या शहरी शोषक वर्गों के हाथों में चली जा चुकी या धीरे-धीरे चली जा रही हैं।
- और क्योंकि सरकार, उसकी जाब्ता दीवानी तथा कचहरियां हमेशा सूदखोरों की मददगार बनकर किसानों को तबाह करती जा रही हैं;
- इसलिये पुराने ऋणों तथा उनके सूदों की जबाबदेही से किसान फौरन पूर्ण मुक्त किये जायेंगे एवं किसानों की चालू जरूरतों के लिये सस्ती दर पर कृषि ऋण की व्यवस्था सरकार चटपट करेगी।

4. क्योंकि भूमिहीन किसानों, खेत-मजदूरों तथा ऐसे लोगों को, जिनके पास पांच प्राणियों के परिवार के वास्ते उत्तम, मध्यम या निकृष्ट जमीनें 10 से लगायत 25 एकड़ से कम है, खेती के लिये जमीन दी जायेगी, जिसमें वे भरसक पंचायती खेती करेंगे, लेकिन जिसे बेच न सकेंगे, और क्योंकि कुल कृषि-योग्य एवं बंजर जमीनों का आधा किसानों के पास न होकर सरकार और जमींदारों के हाथ में है, इसलिये ऐसी सभी जमीनें कृषि योग्य बनाकर उक्त किसानों के पास न होकर सरकार और जमींदारों के हाथ में है, इसलिये ऐसी सभी जमीनें कृषि योग्य बनाकर उक्त किसानों एवं मजदूरों को दे दी जायगी।
5. मालगुजारी तथा लगान का सभी बकाया रद्द होगा और सेल्स टैक्स फौरन उठाया जायगा।
6. सभी आयकर जमीनों का लगान, मालगुजारी तथा भावली (उपज के रूप में) लगान खत्म हो जायगा।
7. जब तक वर्तमान लगान तथा मालगुजारी की प्रथा का स्थान क्रमिक वृद्धिशील कृषि-आय कर नहीं ले लेता तब तक कोई जमींदार किसी भी दशा में उस रकम से ज्यादा लगान न ले सकेगा जो वैसी ही भूमि के लिये पड़ोसी प्रांतों या जिलों के रैयतवारी किसान सरकार को देते हैं। जो रैयत दाखिल या जमीन के स्वामी है उनके अधीनस्थ किसानों की सुविधा दिलाने एवं उनके हकों को निश्चित करने तथा उनकी रक्षा के लिये उचित काश्तकारी कानून बनेंगे।
8. जमींदार, तालुकेदार, इनामदार, मालगुजार, इस्तिमरारदार जन्मीं, स्रोत तथा दूसरे मध्यवर्तियों की सीर, खास या वकाश्त जमीनों को दरअसल जोतने वाले सभी रैयतों को उन जमीनों पर खेती का स्वामी (सनातन) हक फौरन दिया जायगा। हां, उन जमीनों को वे हस्तांतरित न कर सकेंगे। यदि इन जमीनों के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हक के बारे में तकरार हो तो वह किसानों और रैयतों का ही माना जायगा।

9. जमींदारों के सभी रैयतों तथा रैयतवारी के रैयतों को लगान माफी का हक तुरंत मिलेगा अगर फसल मारी जाय। जहां जमींदार या मध्यवर्ती पाये जाते हैं सर्वत्र जमीनों की पुनः बंदोबस्ती, लगान या मालगुजारी की सभी तरह की वृद्धि या सर्वे सेटलमेंट को सरकार रोक देगी।

10. जमींदारों तथा पूंजीपतियों की खेती संबंधी एवं अन्य आय पर चटपट क्रमिक वृद्धिशील आयकर, मृत्यु कर एवं उत्तराधिकार कर लगाये जायेंगे।

11. सभी तरह सामंती एवं परंपरा प्राप्त वसूलियों, बलात, कम पैसा देकर या अपना पैसा दिये काम कराना, जिसमें बेगार तथा गैरकानूनी वसूलियां भी शामिल हैं, उठा दी जायेंगी और दंडनीय होंगी।

12. ऋण, लगान या मालगुजारी न दे सकने की दशा में किसान को गिरफ्तारी या कैद से फौरन ही बरी किया जायगा।

13. सभी काम चलाऊ होल्डिंग (जमीन के तख्ते), पशुशालायें, निवास स्थान, घरेलू चीजें, दुधारु एवं अन्य पशु, खेती के औजार तथा साधन अदालती डिग्री या लगान एवं मालगुजारी की वसूली के लिये कुर्क न होंगे-ऐसा एलान फौरन करके उस पर अमल होगा।

14. सूदखोरों के सूद का दर दो रुपये सैकड़ा सालाना से ज्यादा न होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज गैर कानूनी होगा। सभी सूदखोरों को लाइसेंस लेना होगा, सरकार समय-समय पर उनके बही खातों को जांच होगी और बेकायदगी या जाल होने पर ऐसी सजा दी जायगी जो आदत छुड़ा दे।

15. 20 साल या अधिक मुद्दत के लिये सरकारी, सहयोग समितियों के या भूमि बंधकी बैंकों के द्वारा अधिक-से-अधिक दो करोड़ रुपये सैकड़ा सालाना सादे सूद पर कर्ज दिया जायगा, और सर्वत्र भूमि बंधकी बैंक जल्द चालू होंगे।

16. खेती-संबंधी चीजों की आवाजाही कर तथा थर्ड क्लास का किराया घटाया जायगा। सड़कों एवं नहरों के जरिये आवाजाही का प्रसार शीघ्र होगा।

17. किरासन तेल, चीनी, तंबाकू, दियासलाई आदि पर जो चुंगी (अप्रत्यक्ष) कर है फौरन उठाये जायेंगे। देहातों में कारखानों की बनी चीजों, कपड़े, चीनी, नमक, लोहा, सीमेन्ट, कोयला, किरासन तेल आदि के नियंत्रित दाम पर मिलने का पूरा-पूरा तथा उचित प्रबन्ध होगा।

18. फौरन ही लिफाफे का दाम दो पैसे और पोस्टकार्ड का एक पैसा कर दिया था।

19. विनिमय एवं मुद्रा नीति में आवश्यक हेरफेर करके या अन्य प्रकार से खेती की

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पैदावार का मूल्य एक उचित दर पर पक्का करके जारी होगा और कायम रखा जायगा।

20. किसानों तथा मजूरों को पूर्ण और निराबाध सुरक्षित हक होगा कि खेती गिरहस्ती जीविका के लिये, चरने की घास, लकड़ी, ईंधन, पत्थर और बालू आदि पहाड़ी एवं जंगली चीजों का उपयोग करें। चराई का कर उठा दिया जायगा। चराई एवं जंगल की लकड़ियों के बटवारे का प्रबंध ग्राम पंचायतों के हाथ में होगा। जंगल के तालाब, नदियां आदि सब किसानों तथा उनके पशुओं के लिये खुले होंगे। जंगली जानवरों से अपनी-अपनी फसलों तथा पशुओं की रक्षा के लिये किसानों को बंदूक आदि रखने का लाइसेंस होगा। ऐसे जानवरों को मारने पर केस न चलेगा और अगर इसके लिये कोई जमींदार निजी तौर पर दंड दे तो उसे सजा मिलेगी।

21. सभी प्रकार की सार्वजनिक जमीनों, चाहे जैसे भी उनका श्रीगणेश हुआ हो, तथा भूमि का प्रबंध ग्राम पंचायतें करेंगी।

22. किसी किसान परिवार के पास 50 एकड़ से ज्यादा जमीन न रहने दी जायगी।

23. जमींदारों तथा मध्यवर्तियों के पास 50 एकड़ से ज्यादा जमीन छीन कर भूमिहीन किसानों को दी जायगी। ऐसे लोगों को भी जिनके पास 5 प्राणियों के परिवार के लिए दस एकड़ से कम है यह जमीन दी जायगी ताकि उनके पास अपनी खेती के लिए 25 एकड़ तक हो जाय।

24. जमींदारों से छिनी भूमि का एक भाग सरकारी साहाय्य से संम्मिलित खेती के लिये दिया जायगा। जहां दीन किसान एवं भूमिहीन मजूर उसकी खेती के लिये बसाये जायेंगे।

25. किसानों के हकों को उनकी संघ शक्ति के जरिये सुरक्षित रखने के लिये 'किसान -संघ' कानून बनेगा।

26. सभी खेत-मजदूरों के लिये भरण पोषण योग्य मजूरी की निश्चित व्यवस्था होगी तथा मजदूरों की क्षतिपूर्ति का कानून उनके लिये भी लागू होगा।

27. खेत-मजदूरों, गांव के गरीबों एवं शिकमी किसानों को अपने वास की भूमि से दूनी पर, जिसमें वास भूमि भी शामिल हो, कायमी हक बिना लगान के होगा।

28. खानों के इलाकों में किसानों को सतह (ऊपर) की भूमि पर खेती का स्थायी हक होगा और जब तक उन्हें वैसी ही सुविधा अन्यत्र नहीं दी जाती वे वहां से हटाये न जायेंगे।

29. गांवों की जो कम-से-कम आधी जनसंख्या खेती में आज ही नहीं खप सकती उद्योग धन्धों में लगाई जायगी। इसी दृष्टि से राष्ट्र की अधीनता में मुस्तैदी से

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उद्योग धन्धों के विस्तार की ऐसी नीति सरकार अपनायेगी जिसमें ख्याल रखा जायेगा कि उद्योग धन्धों की अनुकूल स्थापना यत्र-तत्र हो और पिछड़े इलाकों को खास ख्याल रखा जाय।

30. प्रांतीय एवं केंद्रीय करों का बंटवारा सरकार इस प्रकार करेगी कि अलग-अलग या दोनों को मिलाकर तीन चौथाई कर का भार धनिक वर्ग पर हो। खर्च का प्रबन्ध भी ऐसा होगा कि तीन चौथाई खर्च मजूरों एवं किसानों के हितार्थ हो।
31. चीनी के संरक्षण कानून से किसान पूर्ण लाभ उठाये इसी विचार से गन्ने (उख) का कम-से-कम उचित मूल्य-निधार्रण सरकार के लिये अनिवार्य होगा जो क्रमिक वृद्धिशील होगा। इसी प्रकार जूट, रुई, नारियल तथा अन्य किराना (व्यापारिक) चीजों के उपजाने वालों के लिये भी लाभकारी मूल्य तय करके सरकार उनकी पूर्ण रक्षा करेगी।
32. सहकारी तथा सरकारी क्रय-विक्रय का प्रसार सरकार करेगी और इस तरह मध्यवर्तियों के हाथों किसानों का शोषण मिटायेगी।
33. बनियों के द्वारा सभी तरह के धर्मादा वसूलियां दण्डनीय होंगी और इस मद्द से जो भी धन मौजूद हो किसान सभाओं के हवाले कर दिया जायगा।
34. सरकार खेती तथा कल कारखानों में उत्पन्न वस्तुओं के मूल्य में पारस्परिक सामंजस्य रखेंगी।
35. अकाल से किसानों के रक्षार्थ सरकार सिंचाई एवं जल-निकास का प्रसार करेगी, किसानों को आपदाओं से बचाने के लिये अन्य उपाय भी करेगी तथा ऐसे इलाकों के लिये "जलाशय जीणोद्धार निधि" की स्थापना करेगी जिससे ठीक समय पर सिंचाई के साधनों एवं जलाशयों की मरम्मत और प्रगति की जाय।
36. सरकार बाग-बगीचों एवं कम जमीनों में अधिक उत्पादन का प्रसार करेगी तथा किसानों को सस्ते परीक्षित बीज देगी। वह उपयोगी खाद देगी, खेती के नवीनतम प्रकारों का प्रचार करेगी और संयुक्त किसान सभा के सहयोग तथा परामर्श से अपने खेती और व्यापार संबंधी कार्यों को चलाएगी।
37. सरकार किसानों के लिए पशु बीमा, अग्नि बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा का उपाय करेगी।
38. गांवों के नागरिक कामों के प्रबंध के लिये ग्राम पंचायतों की स्थापना होगी जिनके जिम्मे सिंचाई के पानी एवं जंगल की जरूरी चीजों के प्रबंध का भार रहेगा। गल्ले आदि की वसूली सरकार इन्ही पंचायतों के सहयोग से करेगी।
39. शारदा कानून जैसे मामलों में सरकार किसान संस्थाओं को अधिकार देगी कि

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उन सभी अफसरों तथा विशेषतः सार्वजनिक कार्य विभाग, आबकारी विभाग, माल महकमे, रेलवे और पुलिस महकमे वालों को, जो किसान-मजदूरों को दबाकर घूस वसूला जाता है उन्हें दंड से मुक्त करेगी।

40. किसानों के लिये भी दिवालिया कानून मुस्तैदी से पास होगा।
41. राष्ट्र की सभी चुनी संस्थाओं के लिये बालिग मताधिकार एवं प्रत्यक्ष, सीधे तथा गुप्त मतदान की व्यवस्था होगी।
42. भारतीय संघ के सभी किसान विरोधी, मजूर-विरोधी तथा जनतंत्र विरोधी कानून, फर्मान और नियम कायदे हटा दिये जायेंगे और सभी किसान एवं मजूर कैदी, चाहे दंड प्राप्त या नजरबंद हों, फौरन रिहा होंगे।
43. सभी किसानों की जो जमीन एवं सम्पतियों सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने या उनकी शक्ति के बाहर के कारणों के चलते लगान या मालगुजारी न दे सकने के कारण जब्त कर ली गई है उन्हें वापिस दे दी जायेगी।
44. मैट्रिकुलेशन तक के बच्चे-बच्चियों की शिक्षा फौरन अनिवार्य एवं मुफ्त कर दी जायगी, ऊंची शिक्षा किसानों के लिये सुलभ बनायी जायगी, मुस्तैदी से गांवों में दवादारु एवं सप्लाई की सहायता पहुंचाने का तथा पीने के पानी का काफी प्रबंध होगा और राष्ट्रीय गृह निर्माण संबंधी नीति को सरकार चटपट अपनायेगी।
45. सरकार किसानों को हर्वा हथियार रखने का अधिकार देगी।
46. स्थानीय, म्युनिसिपल, व्यवस्थापक तथा अन्य सभी सार्वजनिक संस्थाओं के मेंबरों की नामजदगी फौरन उठा दी जायगी।

"किसानों के दावे और कार्यक्रम का खरोता" में जिन नुक्तों, मांगों और उनसे उत्पन्न स्थितियों का आकलन किया गया है उनका मूल उद्देश्य संघर्षों को वर्गीय आधार प्रदान कर स्वतंत्र भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लड़ाई को प्रशस्त करना था। इसमें शोषण के विरुद्ध किसानों के भीतर प्रचलित अंध विश्वासों की समाप्ति आदि की वही संकल्पना परिलक्षित होती है, जो स्वामी जी के लेखन में किसानों और मजदूरों के प्रति कटिबद्ध है।[57]

किसान-मजदूर समस्या को प्रगति के नये आयाम से जोड़ते हुए स्वामी जी ने 1949 में ही फसल बीमा की मांग को उठाया, तथा अखिल भारतीय संयुक्त किसान-सभा के मंच से 1949 में उनका यही नारा था। वास्तव में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इजारेदार पूंजी की सबसे आक्रामक स्वरूप फासीवाद को पराजित करने तथा पुनः अपनी क्षमता से किसान-मजदूरों के राज्य की संकल्पना को साकार करते तत्कालीन सोवियत रूस तथा अन्य समाजवादी देशों ने विश्व क्रांतिकारी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रक्रिया को जिस तरह आगे बढ़ाया था उसका प्रभाव स्वामी जी के मानसपटल पर अमिट छाप छोड़ा था, इसी कारण किसान-मजदूर समस्याओं की स्वामी जी ने साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन और आजादी के बाद आर्थिक-सामाजिक आजादी प्राप्ति के संघर्ष के रूप में देखा। उन्होंने लिखा कि देश में शांति बनाई जाय, किसान पंचायत बनायें, हिन्दू-मुस्लिम जातियां कटुता न करे। सोवियत दोस्तों का मंडल कायम करे, पैदावार बढ़ाया जाय। जिस प्रकार रूस की स्त्रियां एवं पुरुषों ने देश की रक्षा के लिये युद्ध किया है वैसे ही भारत के किसानों को करना चाहिए।[58]

बकाश्त आंदोलन की समस्या और स्वामी जी

बकाश्त के बढ़ते झमेले का रहस्य स्वामी जी की दृष्टि में यह घोषणा थी कि जमींदारी जानेवाली है, जिसके कारण जमींदारों ने जोर मारा और प्रयास किया कि जितनी ज्यादा हो सके जमीन हथिया ली जाये। इस जमीन छीना-झपटी के पीछे सैद्धांतिक रहस्य था वह यह था कि जमींदारी, जो अब तक जमींदारों की आय का मुख्य स्रोत थी, जिससे किसानों और मजदूरों से कई प्रकार की गैर कानूनी वसूलियां की जाती रही थीं, उसकी सामाजिक भूसंबंधों में आया परिवर्तन अब जमींदारी को नहीं जमीन को ही जमींदारों के मुख्य आय का स्रोत बना रहा था। यह एक क्रांतिकारी कदम था जो भू-संबंधों में व्याप्त पुरानी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत स्थापित संबंधों को कृषि क्षेत्र से बिना कर रहा था, हालांकि अब सरकारी मुलाजिम नये जमींदार की भूमिका लेकर आते। जमींदारों के लिए यह अब जरूरी हो गया था कि वे ज्यादा-से-ज्यादा जमीनों को ले लें। वकाश्त का बढ़ता झमेला इसी नई जन्मी वस्तुगत परिस्थिति की उपज थी और इस पर पर्दा डालने के लिए वकाश्त बोर्ड का गठन किया गया था ताकि किसानों के खिलाफ जमींदारों की मदद की जा सके।[59]

स्वामी जी इस तरह के सरकार और जमींदार के संयुक्त हमले को गंभीरता से लेते हुए आंदोलन के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए आक्रामक जबाबी हमलों का नारा देते हैं। "सीधी लड़ाई मात्र एक रास्ता रह गई है। सो भी सत्याग्रह नहीं, जेल भी नहीं। अब तो लाठियों एवं गोलियों का ही सामना करना पड़ेगा, याद रहे।"[60]

नेहरू ने भी किसान-वर्ग की क्रांतिकारी शक्ति को पहचान कर ही उसे क्रांतिकारी नेतृत्व देने की आवश्यकता महसूस की थी।[61] रजनी पाम दत्त ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि किसान क्रांति में बिना नवीन भारत के निर्माण की बुनियाद और तदनुकूल परिवर्तन असंभव है।[62]

संघर्ष के ऐसे दौर में जब बड़ी पूंजी और बड़े स्वामित्व पर हमला का खतरा उत्पन्न हो जाय, जन आवाम भी क्रांतिकारी चेतना में उत्पादन के संबंधों के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिवर्तन की भावना जग जाय तब पूंजी निवेश का क्षेत्र भी बदलने लगता है। जिसका प्रमाण पूंजी के साथ सरकार की मिलीभगत से किसानों की जमीनों को हड़पने का दूसरा रास्ता भी अपनाया जाने लगा और यह था बड़ी-बड़ी कृषि फर्मों के निर्माण, कारखाने और मील खोलने के नाम पर भूमि के अधिग्रहण का तरीका। कृषि फार्म के नाम पर टुटपुंजिये किसानों की जमीनों को भी छीना जाने लगा तथा जिसके कारण उनके सामने भुखमरी का प्रश्न उत्पन्न हो गया था। बक्सर के पूरब आधे दर्जन करीब गांवों की जमीनों को मिल खोलने के नाम पर अधिग्रहण की योजना बनी वो किसानों की मौत की योजना से शायद ही कम थी। ऐसी साजिशों के खिलाफ संघर्ष का प्रश्न स्वामी जी के नेतृत्व में व्यापक जन आन्दोलन का स्वरूप ग्रहण किया।

बिहार के भू-प्रबंध में बकाश्त जमीनों का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न तब बन गया जब जमींदारी उन्मूलन का आंदोलन तेजी से चला। चूंकि भारतीय कृषि क्षेत्र में अंग्रेजों ने सामंती उत्पादन संबंधों की कई हद तक बरकरार रखा था और यूरोपीय कृषि-व्यवस्था की तरह पूंजीवादी कृषि का उदय नहीं हो पाया था। इस प्रकार के कृषि-उत्पादन संबंधों की यह विशेषता होती है कि अनुपस्थित जमींदारियों का एक सिलसिला इस कारण बन जाता है क्योंकि जमीन पर आबादी का ज्यादा बोझ जमीन के लगान क़ो भुखमरी के लगान की सीमा तक पहुंचा देता है। यही स्थिति बिहार की थी। जमींदारी उन्मूलन के लिए बढ़ रहे किसान संघर्षों से घबराया जमींदार वर्ग वैसी जमीनों को जिसका कोई दस्तावेजी सबूत किसानों के पास नहीं था, जमींदारों ने बड़ी तेजी से बेदखली शुरू की। बकाश्त आंदालनों के प्रति कांग्रेस का रुख जमींदार पक्षी होने के कारण किसान सभा को जो इस बकाश्त आंदोलन को चला रही थी, कार्यों को बदनाम करने का एक सिलसिला सा चल पड़ा। कांग्रेस की चाल के प्रति स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, "किसान सभा ...... लुक्का चोरी खेलना नही जानती ... आज जो कुछ जमींदार कर रहे हैं यदि वह रोका न गया तो हमें और सभा को इसमें मजबूरन पड़ना ही होगा।"[63]

कांग्रेस मंत्रिमंडल में जिस काश्तकारी कानून को संशोधित करने का प्रयास किया जा रहा था उसका स्वभाव ही किसान-विरोधी था। वास्तव में यह कानून संशोधन कांग्रेस संगठन के चरित्र का परिचायक था जो बड़े जमीन मालिकों एवं जमींदारों को स्वार्थपरता को खुली तरजीह दे रहा था। काश्तकारी कानून को दफा 69 से भावली वालों को जरा भी रक्षा नहीं हो रही थी और दफा 171 से जमींदारों को अधिकार मिल जाता था कि वह जमीन की पैदावार भी खायें तथा उसका पावना सूद-समेत किसानों के मत्थे मढ़ दे। इस जन-विरोधी कानून के खिलाफ

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी जी की मांग थी कि उसका नया मशविरा ऐसे वकीलों की एक कमेटी को भेजा जाये जिन वकीलों ने किसानों की कठिनाइयों को नजदीक से देखा है।

आर्थिक संघर्षों के एक रूप कानून के तहत लड़ते हुए उसकी खामियों का निराकरण किसान सभा को एक रणनीति के रूप में विकसित करने का श्रेय स्वामी जी के नेतृत्व में किसान सभा को जाता है।

किसानों की आर्थिक लड़ाइयों का राजनीतिक स्वरूप कैबिनेट मिशन के प्रश्न पर निखर कर तब सामने आया जब किसान-सभा ने तत्काल उसे अस्वीकार करते हुए उसके 16 जून की घोषणा को "कांग्रेस की फांसी और मिस्टर जिन्ना की गद्दी"[64] के संबोधनों से संबोधित किया। किसान-सभा की दृष्टि में आजादी के संघर्ष में अब समझौता की सारी गुंजायश समाप्त हो चुकी थी और जो कुछ बचा था साम्राज्यवाद के साथ अंतिम लड़ाई।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा अन्य समस्यायें

बिहार के किसानों और मजदूरों की एक अति विशिष्ट तथा कठोर समस्या थी कृषि में सिंचाई का प्रबंध और बाढ़ नियंत्रण, जिससे प्रतिवर्ष लाखों एकड़ फसलें बरबाद होती थीं। ब्रिटिश काल में चूंकि भू-राजस्व का एक हिस्सा ब्रिटेन को विभिन्न मदों में निर्यात कर दिया जाता था। इस कारण सरकार मुनाफे का बजट चलाती थी। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के दरम्यान ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के निर्माण, पोषण और विस्तार और एक विकसित पूंजीवाद के मूलक के रूप में निखारने का श्रेय उसके उन औपनिवेशिक जनता को जाता है जिनके श्रम का दोहन कर ब्रिटेन की कारखाने की चिमनियां लगातार निर्बाध गति से धुआं उगलती रहीं, मगर जिस कृषि की आय को निर्यात कर इंग्लैण्ड ले जाया जाता था, उसके सिंचाई प्रबंध, बाढ़ नियंत्रण आदि का कोई प्रबंध नहीं किया गया था।

इन किसानों की सुरक्षा का उपाय "स्वराजी शासक भी कुछ नहीं कर रहे हैं।"[65] स्वामी जी फिर कहते हैं "बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार से लाखों रुपए दिये जाने की घोषणा जरूर। मगर ये रुपये एक तो दाल में नमक के समान भी नहीं होते और जले पर नमक का काम करते हैं। दूसरे कि कुछ स्वार्थी नेताओं और उनके दलालों के ही पेट में चले जाते हैं।"[66]

सिंचाई सुविधाओं के लिए स्वामी जी कई विकल्प सामने रखते हुए कहते हैं कि नहर से पानी देना, पुनपुन, पैमार आदि जैसी छोटी नदियों पर बांध बनाकर उनके जल को खेतों तक ले जाना, बिजली, कुओं का प्रबंध तथा बरसात के जल को संग्रह करने के प्रबंध के साथ सिंचाई प्रबंध और बाढ़ नियंत्रण दोनों कठिनाइयों

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

से निपटा जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई-प्रबंध को स्वामी जी ऐसा उपाय मानते हैं, जिससे पैदावार और हर खेत दोफसिला हो सकता है।

नहरी इलाकों में लंबी मुद्दत के सट्टे के लिए जो नियम बने हुए हैं उन्हें तुरंत बदलने की जरुरत पर स्वामी जी बल देते हैं क्योंकि वे उनकी दृष्टि में "निहायत" बेहूदे हैं।[67]

किसान मजदूरों का प्रश्न कांग्रेस से मतभेद का कारण

लोहे का स्वाद वह घोड़ा जानता है जिसके मुंह में लगाम लगी है गरीबी की पीड़ा गरीब जानता है जो दिन-रात अभावों में जीता है।[68] इसी समझ के साथ स्वामी जी किसानों और कृषि कामगारों की समस्याओं को लेकर प्रस्थान किए। 1920 में गांधी के असहयोग आंदोलन से राजनीति में आए स्वामी जी ने 1927 में किसान-सभा बनाने की ओर झुके, मगर इस कार्य में कांग्रेसी नेताओं ने पहले कम, बाद में ज्यादा विरोध शुरू किया, मगर स्वामी जी ने इस विरोध के बावजूद भी किसानों और मजदूरों के व्यापक हितों की दृष्टि से किसी भी ऐसी कार्रवाई का जो कांग्रेस को नष्ट करना चाहती थी, समर्थन नहीं किया।

वास्तविकता यह है कि बहुत दिनों तक किसान-सभा समझौतावादी नीतियों के तहत चलती रही और स्वामी जी का विश्वास था कि साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में किसानों को सहभागिता भारत को एक ऐसे राजसत्ता के निर्माण की तरफ ले जाएगी, जिसमें किसानों और मजदूरों के व्यापक हितों को रक्षा की जा सकती है। मगर साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के आगे बढ़ने, उसमें बामपंथ की ताकतों को ज्यादा मुखरित होते देख कर कांग्रसे नेतृत्व किसान-सभा के खिलाफ ज्यादा स्पष्टतर होता गया। प्रथम दौर में अनेकानेक बंदिशों को किसान-सभा पर लादा गया और उसे पूर्णतः उन्हीं स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने पर विवश किया जाने लगा जिनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस स्वयं पर करती थी-उच्च मध्यम वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीगत वर्ग का।

कांग्रेस के अलावा अलग किसान-सभा के औचित्य नहीं रह जाता। मगर कांग्रेस के अंदर 90 फीसदी किसान हैं, अतः अलग किसान-सभा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मगर कांग्रेस में जमींदारों का वर्चस्व तथा उसे अपने स्वार्थ की रक्षा में इस्तेमाल करने की प्रवृति का विरोध करते हुए स्वामी जी ने कहा था कि अगर जमींदार कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं तो किसानों को आगे बढ़कर कांग्रेस कमेटियों पर कब्जा कर लेना चाहिए। अन्य अभिव्यक्ति स्वामी जी के परस्पर विरोधी विचारों के एक अजीब घोल मेल को प्रस्तुत करते हैं- जमींदारों की

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वर्चस्व संस्था पर किसानों का कब्जा कर लेना जितना सामान्य लग रहा या उतना नहीं था जिसका प्रमाण बाद के वर्षों में स्वामी जी को खुद मिला कि वे कांग्रेस छोड़ दिए मगर उस पर कब्जा नहीं कर सके और न कांग्रेस किसान-सभा बन सकी जैसा उनका नारा था।

वास्तव में कांग्रेस के भीतर का जमींदार लॉवी इतना न मजबूत था कि जमींदारी उन्मूलन भावली के प्रश्न तथा बकाश्त जमीनों की लड़ाई में वह किसान-मजदूरों का साथ नहीं दे सकता था, क्योंकि जिन वर्गीय सवालों को स्वामी जी उठा रहे थे उसके आधार पर व्यापक जनता का ध्रुवीकरण कांग्रेस के खिलाफ जाता। इन मुद्दों पर स्वामी जी का कहना था कि ऊपर देखने पर तो सर्वथा सही लगता है कि कांग्रेस ही किसानों की संस्था है, किसान-सभा है। वह आजादी की लड़ाई में देश की बेचैनी और सक्रियता का मूर्तरूप है। इसलिए किसानों को कांग्रेस से एकाकार होना ही चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीयता की भावुकता और भौतिक हितों की व्यावहारिकता को साथ लेकर चल रही है। यह उनकी चालाकी और व्यवहार की कुशलता है कि वह किसानों और जमींदारों दोनों को साथ लेकर चल रही है। इस चालाकी का खात्मा होते ही कांग्रेसी नेताओं की नेतागिरी नष्ट हो जाएगी, इसलिए वे दो नावों पर चढ़कर चल रहे हैं। स्वामी जी आजादी की प्राप्ति तक सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन आजादी के बाद वे चाहते हैं कि कांग्रेस केवल किसानों की हो। कांग्रेसी नेता केवल एक पक्ष में नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए स्वामी जी कांग्रेस के मुद्दे पर सहयोग करते हैं, अंतिम सीमा तक जाकर ताकि आजादी शीघ्र मिले मगर वे आजादी के साथ-साथ किसानों का हित और जमींदारों का खात्मा चाहते हैं। यही उनकी कांग्रेस से मतभेद हैं।[69]

अपनी ऐसी स्थापना में स्वामी जी कांग्रेस की समझौतावादी नीतियों से आगे निकलने का प्रयास किए, क्योंकि उनपर एक ऐसी विचारधारा का प्रभाव हो चुका था जो वर्ग समन्वय को अस्वीकार करता था। क्योंकि उनकी अब वह धारणा बन चुकी थी कि जमींदारी मिटाने मात्र से कांग्रेस किसान-सभा नहीं बन जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि स्वामी जी क्रांतिकारी तरीके से जमींदारी मिटाना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में क्रांतिकारी तरीका है जबरदस्ती जमींदारों की जमींदारी और सारी सम्पति छीन लेना और उनकी राह का भिखारी बना देना। कांग्रेस क्रांतिकारी रास्ते से नहीं हृदय-परिवर्तन के गांधीवादी रास्ते से जमींदारी मिटाना चाहती है जो स्वामी जी की दृष्टि में बहुत कमजोर तरीका है।[70]

कांग्रेस के साथ स्वामी जी के मतभेद मुख्यतः किसानों और मजदूरों के हित के प्रश्न पर ही था, जिसे इस प्रकार रखा जा सकता है :

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी जी की दृष्टि में किसानों का कहना था कि 1936-37 में जमींदारी मिटनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने 1946 में हवा का रुख पहचान कर जमींदारी मिटाने की घोषणा की। इससे कांग्रेसी नेताओं की अवसरवादिता और किसानों का हित चिन्तक होने की अयोग्यता सिद्ध होती है।

स्वामी जी किसान-सभा और कांग्रेस के दृष्टिकोण का बुनियादी अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि किसान-सभा अर्थनीति और आर्थिक कार्यक्रम को राजनीति की दृष्टि से देखते हुए राजनीति को साधन और अर्थनीति को साध्य मानती है। इसलिए राजनीतिक चुनावों में हार-जीत गौण मानती और किसान-हित को प्रधानता देती है। इसके विपरीत कांग्रेस राजनीति को साध्य और अर्थनीति को साधन मानती है। इसका लक्ष्य आर्थिक कार्यक्रमों की सहायता से चुनाव जीतना है।

यह सत्य है कि किसानों को किनारा करके कांग्रेस नहीं बढ़ सकती है। राजनीति में सफल होने के लिए उसे किसानों को साथ लेना ही होगा। इसलिए किसान-हित कांग्रेसी नेताओं का साध्य न होकर चुनाव जीतने और सत्ता में आने का साधन है। इसके विपरीत किसान-सभा किसानों के हित को सर्वोपरि और सत्ता प्राप्ति को गौण -स्थान देती है। इसलिए हित-साधन के लक्ष्य की दृष्टि से भी किसान-सभा और कांग्रेस में अंतर है और यह अंतर कांग्रेस के रहते हुए किसान-सभा की उपयोगिता और आवश्यकता को अकाट्य बना देती है।

स्वामी जी मानते हैं कि किसी संख्या के प्रगतिशील और सजीवता के लिए उसपर लगातार दबाव आवश्यक है। किसान सभा स्वतंत्र न रहकर कांग्रेस का ही एक अंग होती है, एक शाखा होती तो यह पिछलग्गू बन जाती और अपना दायित्व किसान-हित, कभी भी पूरा नहीं का पाती। एक परमुखोपेक्षी संगठन न तो कोई मौलिक काम कर सकता है और न कोई स्वतंत्र कदम उठा सकता है।

कांग्रेस ने मुआवजा देकर जमींदारी खत्म करने की बात स्वीकार की थी और यही हुआ भी। किसान-सभा इसका विरोधी थी। उनका कहना था कि मुआवजे की राशि अन्ततः किसानों से ही वसूली जाएंगी, अतः हमें ऐसा जमींदारी उन्मूलन नहीं चाहिए। बिना मुआवजा दिये ही जमींदारों से सारी जमींदारी छीन ली जानी चाहिए।

स्वामी जी कांग्रेस के भीतर इस कांग्रेस-विरोध की ब्रेक को संज्ञा देते हैं। जिस तरह ब्रेक के बिना गाड़ी पर नियंत्रण नहीं होता उसी तरह पार्टी के भीतर विरोधी की भूमिका निभाने वाले लोग पार्टी के हित-साधक होते हैं, बाधक नहीं। इससे गलतियों के परिमार्जन और नीतियों के सही कार्यान्वित में सुविधा होती है और जनहित का कार्य ज्यादा सही दिशा में होता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी जी किसान-सभा के स्वतंत्र अस्तित्व द्वारा कांग्रेस के प्रति ऐसे ही मित्र की भूमिका को निभाना चाहते थे। इसलिए किसान-सभा सही कार्यों पर कांग्रेस के साथ सहयोग को मुद्दा धारण करना चाहती थी और गलत कार्यों पर विरोध किया। चूंकि कांग्रेस के भीतर रहकर या उसका अंग बनकर कार्य करना न तो आसान था और नही सर्वथा संभव। इसलिए स्वामी जी ने न केवल स्वतंत्र किसान-सभा के अस्तित्व का समर्थन किया अपितु अपने कर्मठ एवं दृढ़ हाथों से उसके स्वतंत्र और सजीव व्यक्तित्व का निर्माण भी किया।[71]

किसान मजदूरों के हाथ में सत्ता सौंपने के प्रति स्वामी जी के विचार

स्वामी जी के विचारों में किसानों-मजदूरों की समस्याओं का मौलिक हल था उनके हाथों में राजसत्ता का सौंपा जाना, जिसका उपयोग कर वे एक किसान-मजदूर राज्य का निर्माण कर सकते थे। 15 अगस्त, 1947 का सत्ता के हस्तांतरण के बाद कांग्रेस के इस प्रचार का कि अब वह सत्ता किसानों-मजदूरों के हाथों में सौंप देगी को स्वामी जी एक भ्रामक प्रचार मानते हैं। इस संबंध में स्वामी जी कई प्रश्न उठाते हैं।[72] मजदूर-किसानों के शासन सत्ता का प्रश्न जब भी उठा कांग्रेस चिल्लाती रही कि किसान-मजदूर सत्ता सम्हालने के योग्य नहीं है। मगर इन्हें उस योग्य न बना देने की जिम्मेवारी कांग्रेस पर ही है। "दूसरे लोग तो बराबर चिल्लाते थे कि श्रमजीवियों को राजनीतिक चेतना दी जाय, वे तैयार किए जायं।" लेकिन ऐसा सुनकर ये नेता ही छाती पिटते थे कि ऐसा होने पर चौपट होगा।[73] जो लोग साम्राज्यवाद के द्वारा सत्ता हस्तानान्तरण को शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं उन्हें क्रांति और समझौता का अंतर ही नहीं मालूम।

स्वामी जी का ऐसा चिन्तन मुख्यतः दो प्रणालियों के बीच सामंजस्य नहीं है, बल्कि साम्राज्यवाद से भारत की आजादी मात्र सत्ता-हस्तांतरण नहीं कही जा सकती। वास्तविकता यह थी कि पूंजीवादी जनतांत्रिक क्रांति का साम्राज्यवाद पर विजय एक प्रगतिशील उपलब्धि थी, जिसे न स्वीकार करते हुए स्वामी जी अपने विचारों में एक संकीर्णात्मक रुझान लिए हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के इस दावे को कि वह सत्ता किसान मजदूरों को सौंप देगी, इसे असंभव बताते हुए स्वामी जी कांग्रेस तथा उसके द्वारा प्रबंधित राजसत्ता के चरित्र का सम्यक विवेचन करते हैं और धारणा में वे सही साबित होते हैं। मगर इस तरह की उनकी पूर्व में की गई उम्मीदें, जिनका जिक्र वे करते हैं, वास्तविकता को नहीं लगती, क्योंकि राजसत्ता सर्व कल्याणकारी नहीं वर्ग कल्याणकारी होता है।

वर्ग स्वार्थ की प्रबलता स्वामी जी जानते हैं, तभी वे कहते हैं ...... किसान

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मजदूर राज्य व साम्यवाद के नाम से भी इन लीडरों को भी बुखार चढ़ जाता था और बहाने करते थे कि मुल्क में वर्ग विद्वेष पैदा हो जाएगा .... क्या सचमुच भारत के जमींदार मालदार इतने भोले-भाले और भले हैं कि उन्हें अपने वर्ग स्वार्थ का ज्ञान अब तक था ही नहीं?[74] अनुभव ने स्वामी जी को बताया था कि जेल के अन्दर रहकर भी तथा कांग्रेस में शामिल रहते हुए इन मालदारों ने किसानों-मजदूरों का खून चूसने में कोई कसर नहीं रखी थी। इस कारण किसान-मजदूरों की सत्ता सौंपने की कांग्रेसी बातें भ्रामक हैं।

स्वामी जी चेतना पूर्वक इस स्थापना को व्यक्त करते हैं कि अगर किसान-मजदूरों की क्रांति होती तो मालदार लोग गद्दी पर आसीन नहीं होते। कांग्रेस के इस दावे को कि वह एक पार्टी बनी रहेगी और अलग से किसान और मजदूर संगठन बनाएगी की धारणा कोई धोखा नहीं थी। कांग्रेस हमेशा एक पार्टी रही मगर छुपे रुस्तम क्योंकि साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में लड़ने-मरने का कार्य किसान-मजदूर ही कर सकते थे इसलिए कांग्रेस ने उनका भरपूर उपयोग किया और स्वराज लाया। मालदारों के लिए जातीय, वर्गीय संस्थाओं के पीछे छिपा कांग्रेस का एक वर्ग स्वार्थ है, जिसकी अभिव्यक्ति शंकर राव देव ने की है।

"कांग्रेस में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, किसान कांग्रेस या इसी तरह की कांग्रेस के द्वारा पुनरपि संगठित वर्ग संस्थाओं के प्रतिनिधि भी लिए जाएंगे, ताकि वह जनसमूह की संस्था रहे। इसका सीधा अर्थ यही है कि नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और किसान कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की मातहती में है -- कांग्रेस के द्वारा संगठित है, और अगर कदाचित वह कांग्रेस को मातहती से इनकार करे, तो कांग्रेस द्वारा वैसी दूसरी संस्थाएं बनाई जा सकती है। मगर हाल ही श्री गुलजारी लाल नन्दा ने इसकी सफाई देते हुए जो पुस्तिका "आक्षेपों का उत्तर" छापी है, उसके चौथे पृष्ठ में लिखा है कि "नई नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक संस्था से स्वतंत्र है और रहेगी और इसकी स्वतंत्र हस्ती में कोई फर्क न होगा, कांग्रेस का पुछल्ला न बनेगी।"[75]

वही सरकार जो दमन और आक्रामक कार्रवाइयों में अपना सानी रखती थी लगातार चुनावों में मात खाती रही तब ग्रामीण जनता को उसकी शक्ति का एक ऐसा अहसास हुआ कि वह साम्राज्यवाद को शिकस्त दे सकती थी। 1930-32 के सत्याग्रह और 1934 के केंद्रीय चुनाव में इस पर कस के मुहर लगा दी। 1936-37 के चुनाव ने तो स्पष्ट बता दिया कि ग्रामीण जनता के पास अपरम्पार शक्ति है, जो किसी को झुका सकती है। उसी भाव ने जनशक्ति, और इसी ज्ञान ने किसान आंदोलन को जन्म दिया। ग्रामीण जनता ने सोचा कि हम अपार बलशाली

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

साम्राज्यशाही को पछाड़ सकते हैं तो इन जमींदार-मालगुजारों और सूदखोरों की क्या हस्ती? ये तो उसी साम्राज्यशाही के बनाए हुए हैं। यदि संगठन जन-आंदोलन ने सरकार को मात किया तो संगठित किसान-आंदोलन ही जमींदारों को करारा पाठ पढ़ायेगा, यह निष्कर्ष किसानों और उनके सेवकों ने स्पष्टतया निकाला। 1927-28 तक यह आंदोलन किसान सभा के रूप में जन्म लेकर क्रमशः पुष्ट और शक्तिशाली होता गया, ज्यों-ज्यों किसानों को अपनी अपार शक्ति का मान होता गया उनमें मजबूती आती गई। 1936-37 या इसके बाद 1938-39 में तो किसान आंदोलन एक बार साम्राज्यवादी और उनके पिट्ठुओं को जड़ से हिला दिया।

इस प्रकार राष्ट्रीय आजादी के जंग में, कांग्रेस के जन आंदालनों में किसान सभा क्रांतिकारी शक्तियों का प्रतीक बन गई। सोशलिस्ट पार्टी, फारवर्ड ब्लाक आदि विभिन्न राजनीतिक दलों का अविर्भाव इसी काल में हुआ। इन दलों के नेता कर्मठ कांग्रेस जन ही रहे।

1927-28 से शुरू होकर प्रायः 15 साल तक किसान-आंदोलन सर्वथा पीड़ित किसानों के उच्च वर्ग का संगठन रहा मगर 1942 के बाद से उसमें गांवों के सर्वहारा वर्ग के लोग आने लगे। समाज से सबसे ऊंचे तबके से शुरू कर यह सबसे नीचे तबके में घुसा। गांवों के अर्ध सर्वहारा जागे और अपने कर्तव्यों को पहचानने लगे। शहरों और कारखानों से पूर्ण सर्वहारा के साथ उनका अभी पूर्ण सामंजस्य नहीं हो पाया था।

समस्त समाज के सबसे निचले हिस्से को आजादी की यह तड़प की आग धू-धू कर जलाने लगी। पटना की एक रैली के संबंध में स्वामी जी का कथन था कि कुछ चतुर जमींदारों ने देखा था और उनकी समझ थी कि उससे ज्यादातर भूखा किसान खेत-मजदूर ही थे, जो दिखाता था कि आग नीचे तक जा चुकी है। शोषित-पीड़ित जनता के इस तरह के करवट बदलने को ही स्वामी जी विप्लव या क्रांति कहा था। इस क्रांति को सफल बनाने के लिए स्वामी जी ने किसी नई पार्टी के गठन का विचार नहीं रखा बल्कि उन सभी दलों को जो मार्क्सवादी अवधारणा के वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, एक साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा या किसी पार्टी कमेटी के निर्माण का प्रस्ताव रखते थे। उस प्रकार किसानों मजदूरों के संयुक्त संघर्षों द्वारा एक समाजवादी समाज की रचना, जिसमें पूर्ण समता हो, स्वामी जी का उद्देश्य था और उसे ही किसानों की मुक्ति का मार्ग मानते थे।

इस तरह हम पाते हैं कि स्वामी जी एक शक्तिशाली किसान-मजदूर संगठन की कामना करते थे तथा वे ग्रामीण क्षेत्र में एक शोषणमुक्त, समतावादी समाज की स्थापना के पक्षधर थे। उनके द्वारा किसानों को जगाने तथा संगठित करने का जो

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

काम किया गया वह बेमिसाल है। उन्होंने स्वतंत्र भारत में किसान-मजदूरों की भूमिका का जो खाका खींचा वह बड़े कांग्रेसी जनों तथा जमींदारों को नापसंद था इसी के कारण स्वामी जी को कांग्रेस से वितृष्णा हुई और वे इनका एक मजबूत संगठन मार्क्सवादी विचारों के तहत चाहते थे जो वाकई उनका हो तथा उनकी समस्याओं को समझ कर सही हल निकाल सके। भारतीय समाज के उत्थान का जो सही रास्ता होगा उसके लिए उन्होंने किसान मजदूरों की अग्रणी भूमिका का निर्धारण किया तथा भारतीय ग्रामीण स्वरूप को देखते हुए उन्होंने इसके विकास के लिए जो 46सूत्री कार्यक्रम किसानों के दावे का खरीता के रूप में पेश किया उससे स्पष्ट है कि वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें गरीब किसान-मजदूरों की स्थिति बदलेगी तथा वे अपनी तरह से उसे संजोयेंगें एवं संचालित करेंगे जो शोषण मुक्त होगा तथा एक सच्चे जनवादी समाज की स्थापना होगी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सन्दर्भ

1. द्वारा उद्धत, डा. सी.पी.एन. ठाकुर "किसान सभा की आधारभूत परिकल्पनाएं और स्वामी जी" ज्योति कलश, पूर्वोद्धृत पृ. 89.
2. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, 'खेत मजदूर', मनोहर पब्लिकेशन, 1994, पृ. 132.

   नोटः वाल्टर हाउजर द्वारा प्रकाशित 'एग्रीकल्चरल लेबर एण्ड द रुरल पुअर' स्वाजी जी के 'खेत मजदूर' का अंग्रेजी अनुवाद के रूप में प्रकाशित कराया गया है.
3. स्वामी जी के 'खेत मजदूर' का मूल हिन्दी लिपि भी प्रकाशित किया गया। उधरित पृ. 145.
4. *बिहार प्रांतीय किसान सभा का घोषणा पत्र* (प्रवेशिका) (बिहार प्रांतीय किसान सभा) पृ. 2.
5. *उपरोद्धृत*
6. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, *खेत मजदूर*, पूर्वोद्धृत, पृ. 169.
7. *खेत मजदूर*, पूर्वोद्धृत, पृ. 169-70.
8. *खेत मजदूर*, पूर्वोद्धृत, पृ. 170-71.
9. *खेत मजदूर*, पूर्वोद्धृत, पृ. 185.
10. *खेत मजदूर*, पूर्वोद्धृत, पृ. 198.
11. बिहार प्रांतीय किसान सभा का घोषणा पत्र और किसानों की मांगें पृ. 9-12.
12. *खेत मजदूर*, पूर्वोद्धृत, पृ. 201.
13. वही।
14. *खेत मजदूर*, पूर्वोद्धृत, पृ. 206.
15. *खेत मजदूर*, पूर्वोद्धृत, पृ. 207.
16. *किसानों के दावे और कार्यक्रम का खरीता* (अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा बिहटा, पटना, 1949) पृ. 1-2.
17. उपरोक्त, पृ. 2.
18. उपरोद्धृत, पृ. 3.
19. उपरोद्धृत, पृ. 4.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

20. उपरोद्धृत, पृ. 4.
21. उपरोद्धृत, पृ. 5
22. उपरोद्धृत, पृ. 6
23. अखिल भारतीय किसान सभा के 8वें महाअधिवेशन, 14-15 मार्च 1944, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) के अध्यक्ष पद से दिया गया स्वामी जी का *अध्यक्षीय भाषण* (लक्ष्मी पावर प्रेस तेनाली) पृ. 2.
24. *उपरोद्धृत*, मूल भाषण को देखें, अंग्रेजी।
25. द्वारा उद्धृत, अशोक कुमार, पूर्वोद्धृत, पृ. 31.
26. सरस्वती, स्वामी सहजानन्द, अध्यक्षीय भाषण, नंवा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन शेरघाटी, गया, 1942.
27. रिपोर्ट ऑन नेटीभ न्यूजपेपर्स (बिहार), मार्च 1928.
28. स्पेशल ब्रान्च इंसपेक्टर रिपोर्ट, पटना, डेटेड 11.6.1934, फाईल 10/1934. होम पोलिटिक्ल (स्पेशल ब्रांच), गवर्मेंट ऑफ बिहार एण्ड उड़ीसा.
29. होम पोलिटिक्स (स्पेशल ब्रांच), मेमो न. 68/1936. गवर्मेंट ऑफ बिहार एण्ड उड़ीसा
30. सरस्वती, स्वामी सहजानन्द किसान सभा का संस्मरण, पृ. 18
31. अशोक कुमार द्वारा उद्धृत, उपरोद्धृत, पृ. 31.
32. 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा जारी किया गया *किसान सभा का घोषणा पत्र से*.
33. उपरोद्धृत.
34. देखें : अखिल भारतीय किसान सभा की नियमावली, धारा 2 और 3.
35. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष, पृ. 336-37.
36. डेनियल थार्नर, एगरैरियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, 1956.
37. उत्सा पटनायाक, "कृषि का सवाल और भारत में पूंजीवाद का विकास" सांचा (मार्च 1988), पृ. 47.
38. बिहार प्रांतीय संयुक्त किसान सम्मेलन के 16वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद से *स्वामी जी का भाषण*, (12, 13 मार्च 1949 ढकाइच, शाहाबाद), पृ. 18.
39. द्वारा उद्धृत, डॉ. श्यामबिहारी राय, *पूर्वोद्धत*, पृ. 63.
40. किसान सभा के कोमिल्ला अधिवेशन स्वामी जी का *अध्यक्षीय भाषण*, पृ. 7.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

41. उपरोक्त, पृ. 9,.
42. उपरोद्धृत, पृ. 19 और देखें, स्वामी सहजानन्द, *गीता हृदय*, अध्याय-V श्लोक-25.
43. अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन, रामगढ़, स्वामी जी का स्वागत भाषण, पृ. 12-13.
44. स्वामी सहजानन्द सरस्वती द्वारा *मेरा जीवन संघर्ष* में उद्धृत भागवत गीता, अध्याय-9, श्लोक-44.
45. अखिल भारतीय किसान सभा के तीसरे अधिवेशन में सभापति पद से दिया गया स्वामी जी का भाषण (13, 14 और 15 मई 1938).
46. डा. सी.पी.एन. ठाकुर, पूर्वोद्धृत, पृ. 91.
47. *किसानों के दावे और कार्यक्रम का खरीता*, (अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, बिहटा, पटना, जुलाई 1949) पृ. 9.
48. उपरोद्धृत, पृ. 11.
49. उपरोद्धृत.
50. उपरोद्धृत.
51. उपरोद्धृत, पृ. 12.
52. उपरोद्धृत, पृ. 12.
53. उपरोद्धृत, पृ. 12.
54. *किसानों के दावे और कार्यक्रम का खरीता* में उद्धृत, पृ. 13.
55. उपरोद्धृत, पृ. 14.
56. पूर्वोद्धृत, पृ. 15-23.
57. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, *क्रांति और संयुक्त मोर्चा*, उपखंड वर्ग संघर्ष ही क्यों? और *किसानों के दावे और कार्यक्रम का खरीता*, पृ. 12.
58. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, *जंग एवं राष्ट्रीय लड़ाई*, पृ. 15-16.
59. बिहार प्रांतीय संयुक्त किसान सम्मेलन में *स्वामी जी का अध्यक्षीय भाषण* (ढकाहच, शहाबाद, 12-13 मार्च 1949) पृ. 18.
60. उपरोद्धृत, पृ. 19.
61. नेहरू, जवाहरलाल, आत्मकथा, पृ. 237.
62. दत्त, रजनी पाम, *आज का भारत*, पृ. 523-24.
63. स्वामी जी का अध्यक्षीय भाषण, ढकाइच, उपरोद्धृत, पृ. 11.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

64. उपरोद्धृत, पृ. 13.
65. उपरोद्धृत, पृ. 20.
66. उपरोद्धृत.
67. उपरोद्धृत.
68. प्रो. अवधेश्वर प्रताप सिंह "किसान सभा एवं कांग्रेस : सहयोग एवं असहयोग के मुद्दे" *स्वामी सहजानन्द सरस्वती, ज्योति-कलश,* (स्वामी सहजानन्द सरस्वती विकास सेवा संस्थान, ठाकुर नर्सिंग होम परिसर मुजफ्फरपुर, 1989) पृ. 94.
69. पूर्वोद्धृत, पृ. 96.
70. उपरोद्धृत, पृ. 96.
71. उपरोद्धृत, पृ. 97.
72. विशेष वर्णन के लिए देखें, सम्पादक त्रिवेणी शर्मा सुधाकर, *स्वामी सहजानन्द का* वसीयतनामा (लूना प्रिंटिंग प्रैस मुसल्लहपुर, पटना, 1989) पृ. 2-3.
73. उपरोद्धृत, पृ. 3.
74. उपरोद्धृत, पृ. 4.
75. उपरोद्धृत, पृ. 6.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्याय-5

सारशं एवं निष्कर्ष
तथा
स्वामी जी की प्रासंगिकता

यह शोध प्रबंध "स्वामी सहजानन्द सरस्वती का सामाजिक-आर्थिक चिंतन" इस अध्याय को लेकर कुल पांच अध्यायों का है। विभिन्न अध्यायों में स्वामी सहजानन्द सरस्वती के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनके सामाजिक आर्थिक चिंतन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान अध्याय में उनका सारांश एवं निष्कर्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है। सारांश एवं निष्कर्ष के रूप में स्वामी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व उनका दर्शन उनके चिंतन के अन्य आयाम, उनकी आर्थिक नीतियां, कांग्रेस राजसत्ता का वर्ग चरित्र आदि के विश्लेषण के क्रम में उनके सामाजिक-आर्थिक चिंतन को कई दृष्टियों से विभाजित किया जा सकता है। उनके व्यक्तित्व में हुए विभिन्न परिवर्तनों को प्रारंभ से रेखाकिंत किया गया है जिसे यों देखा जा सकता है:

1. **उनके व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों की दृष्टि से:**
   - (क) बाल्यकाल तथा बाल्यकाल का सामाजिक आर्थिक परिवेश
   - (ख) जातीय उत्थान के कार्यों का विश्लेषण
   - (ग) भारतीय मुक्ति-संग्राम में उनकी हिस्सेदारी,
   - (घ) किसान सभा के कार्यों के प्रति जागृत अभिरुचि
   - (ङ) वामपंथी दर्शन के प्रति झुकाव
   - (च) कांग्रेस से विरक्ति
   - (छ) साम्यवादियों से मतभेद
   - (ज) संयुक्त किसान सभा और संयुक्त वामपंथ के आंदोलनों का प्रयास आदि।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

एक दूसरे दृष्टिकोण : कालबद्ध दृष्टिकोण से उनके सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक चिंतन का काल-विभाजन नीचे लिखे कालबद्धता के परिवेश में किया जा सकता है:

2. कालबद्ध विभाजन

(क) 1889 से 1906 तक जन्म एवं शिक्षा
(ख) 1907 से 1914 तक संन्यास धर्म की दीक्षा
(ग) 1915 से 1920 तक धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में समर्पण
(घ) 1921 से 1927 तक राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता
(ङ) 1927 से 1936 तक किसान सभा के कार्यों में समर्पण (बिहार में)
(च) 1936 से 1947 तक अखिल भारतीय किसान सभा का अर्थ,
(छ) 1948 से आगे संयुक्त किसान सभा का कार्य

ऊपर वर्णित विभाजनों को मुख्य दो भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. धार्मिक और जातीय उत्थान का कार्य, तथा
2. राजनीतिक क्रियाकलापों में हिस्सेदारी

धार्मिक एवं जातीय उत्थान के कार्यालय में उनकी मूल कार्य-योजना आध्यात्मिक दौर पर भगवान की खोज, तपस्या का मार्ग ढूंढने, संस्कृत वांङ्मय का अध्ययन करने तथा इसी संदर्भ में भारत में विभिन्न हिस्से जंगलों, पहाड़ों तीर्थ स्थानों के भ्रमण तथा संन्यास धर्म दीक्षा में बीता। संस्कृत वांङ्मय के अध्ययन ने उनमें प्राचीन भारतीय दर्शनों सनातन, वैदिक, सांख्य, वैशेषिक दर्शनों से लेकर बौद्ध और जैन दर्शनों में उन्हें पारंगत किया तथा उनमें व्याप्त आध्यात्मिकता तथा भौतिकवादिता दोनों ही के दर्शन कराये। उसमें अपारनाथ मठ के भारतीय दर्शन के विद्वान वृद्ध सन्यासी अच्चुतानन्द महाराज से लेकर हरिनारायण जी महाराज से तक शिक्षा ग्रहण की।

1907 के बाद उनका भ्रमण कार्यक्रम चला जिसमें उन्होंने चित्रकूट, तुलसीदास की जन्मभूमि का भ्रमण करते हुए नर्मदा की घाटियों में घूमते रहे, वहां से नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) के माने ग्राम की यात्रा की वहां से उज्जैन पहुंचे, उज्जैन से मथुरा, हाथरस, अनूपशहर, बिजनौर होते हुए गंगा और हिमालय के गोद में स्थित ऋषिकेश की यात्रा की, बद्रीनाथ तक की यात्रा एक साल में पूरा की थी। इसके बाद गुजरात और मिथिला की यात्रा में उन्होंने मिथिला में बालकृष्ण मिश्र से मीमांसा का अध्ययन किया। इसके बाद में काशी से दूर अजमेर सिद्धपुर, पाटन, पुष्कर आदि स्थानों का भ्रमण किया। इन सारे भ्रमणों में भारतीय दर्शन का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अध्ययन तथा अनेकता में एकता वाले भारत का दर्शन तो उन्हें जरूर मिला, परंतु जिस भगवान की खोज उन्हें थी वह न मिल सका उल्टे संन्यासियों की भोग-लिप्सा ने उन्हें संन्यास के शास्त्रीय ढंग से विरक्ति पैदा कर दी।

फिर भी स्वामी जी पर संस्कृत वांङ्मय का जो प्रभाव था उसके ऊपर 20वीं सदी के मशीनीकृत सभ्यता संस्कृति का प्रभाव अभी नहीं पड़ा था। पौराणिक भारतीय संस्कृति के वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने कट्टर ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक जंग सा छेड़ दिया, जिसका मुख्य लक्ष्य था भूमिहारों को ब्रह्मणत्व प्राप्त कराने की लड़ाई लड़ना। इस भावना ने स्वामी जी को एक जाति विशेष की परिधि में बांध रखा। उन्होंने, जाति प्रथा का विरोध इसको संस्थागत रूप के खिलाफ न कर भूमिहारों को ब्राह्मणों के समकक्ष खड़ा कराने के लिए किया। कुछ लोग इसे संकीर्ण जातीयता कहते हैं लेकिन उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि यह भी उस बड़ी लड़ाई का ही अंग है जिसमें दबे को सम्मान दिलाने का प्रयास किया गया था।

अपनी इस अवस्था में स्वामी जी ने अपने विचारों का संकलन, *'ब्राह्मण समाज की स्थिति'*, *'ब्रह्मर्षि वंश विस्तर'*, *'झूठा भय मिथ्याभिमान'*, *'कर्मकलाप'* आदि में किया। इन पुस्तकों में उन्होंने ब्राह्मणों की सही स्थिति, अपने अधिकारों की सूझबूझ सदपयोग दुरुपयोग के संबंध में लिखा और कहा कि "पठन-पाठन से विमुख ब्राह्मण पुआल की आग की भांति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए उसे देव-पितृकार्य में कुछ नहीं देना चाहिए।

इन्होंने *'ब्रह्मर्षि समाज को स्थिति'* एवं *'ब्रह्मर्षि वंश विस्तर'* नामक पुस्तकों में याचक और अयाचक ब्राह्मणों के लक्षणों को दर्शाते हुए भूमिहारों की सामान्यतः अयाचक ब्राह्मण की श्रेणी में रखा है। उसे कुछ समाजशास्त्री या सामाजिक वैज्ञानिक मानव धर्म की शिक्षा देने वाली पुस्तक मानते हैं। आचार्य परमानन्द शर्मा ने कहा है कि यह पुस्तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा देती है। देश भक्ति और कर्तव्य-प्रेम की ओर भी अन्यतम संकेत करती है।

"झूठा भय मिथ्याभिमान" में उन्होंने अयाचक ब्राह्मणों के संबंध में लिखते हुए कहा है कि उन्हें संस्कृत और शास्त्र को भली-भांति अध्ययन, पुरोहिती कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार उनके द्वारा रचित *कर्म कलाप* भी पुरोहित कर्म करने वाले ब्राह्मणों को भी एक अनुपम सीख प्रदान करती है। स्वामी जी की इन कृतियों में भूमिहारों के साथ ब्राह्मण शब्द जुड़ा रहने का प्रयास किया गया है। भूमिहार ब्राह्मणों को महासभाओं में भाषण कर उन्हें संस्कृत पढ़ने तथा पुरोहिती कर्म अपनाने की दीक्षा देना स्वामी जी का मुख्य कार्य रहा, 1914 में उन्होंने बलिया में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आयोजित भूमिहार-ब्राह्मण अधिवेशन को संबोधित किया तथा पुरोहिती वृत्ति अपनाने और संस्कृत पाठ करने पर जोर दिया जिसका कालांतर में कुलीन भूमिहारों द्वारा विरोध किया गया।

ब्राह्मणों द्वारा भूमिहारों को ब्राह्मण जाति में रखने तथा पुरोहिती कार्य करने के खिलाफ संगठित मुहिम चलाए जाने के बाद में स्वामी जी ने वाराणसी आदि कई जगहों पर इन सभाओं में जाकर उनके मतों का खंडन किया तथा, अपने अकाट्य तर्कों, जिनका आधार पौराणिक वांङ्मय संस्कृत साहित्य पर आधारित था, के द्वारा स्थापित किया कि भूमिहार भी ब्राह्मण ही है।

स्वामी जी स्वयं जुझौतिया ब्राह्मण थे जिनके वंशवालों ने भूमिहारों से शादी-संबंध कर दिया था। उन्होंने समाज को जागृत करने का प्रयास किया। वास्तविकता यह है कि इस काल अवधि 1907 से 1914-15 तक स्वामी जी भूमिहारों के जातीय उत्थान के लिए कार्य करते रहे, जिसके कारण उन पद जातीयता का आरोप लगाया जाता है। जो भी हो उनका यह कार्य निश्चित रूप से दो परस्पर विरोधी तथ्यों को प्रदर्शित करता है-1- ब्राह्मणों की जातीय महत्ता के खिलाफ उनका संघर्ष एक पुरानी दकियानूसी संस्थागत रूप ग्रहण किए वर्णाश्रम धर्म के प्रति संघर्ष था, जो प्रगतिशील कहा जा सकता है। मगर जाति प्रथा के संस्थागत स्वरूप के सम्पूर्णता में हमला न करते हुए ब्राह्मणों के समान्तर भूमिहारों को खड़ा करने तथा ब्राह्मणों को प्राप्त सामाजिक आदर को भूमिहारों को भी दिलाने का कार्य एक दकियानूसी प्रथा के, जो भारत में प्राक-ऐतिहासिक काल से चली आ रही थी, ऊपर समग्रता में हमला न होकर उसके स्वरूप में थोड़ा हेरा-फेरी करने का कार्य निश्चित रूप से धार्मिक पुनरुत्थान को जन्म देता था, जो प्रतिक्रियावादी था। स्वामी जी का यह कार्य 20वीं सदी के दूसरे दशक तक, तब तक चलता रहा जब तक कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गांधी के साथ न जुट सके थे। इस बीच वे गाजीपुर, कोटवा नारायणपुर, विश्वंभरपुर, घरौली आदि में घूम-घूम कर जातीय उत्थान कार्यों में लगे रहे। लेकिन बाद में इनमें आमूल परिवर्तन हुआ तथा उन्होंने जातीय संगठन-भूमिहार महासभा के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय आंदोलन में : 1919 में पंजाब में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो रोलट एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने वालों पर जनरल डायर द्वारा किया गया था, खिलाफत आंदोलन के प्रसंग में गांधी के असहयोग आंदोलन गठित करने की तैयारी में उनके बिहार आगमन पर स्वामी जी की गांधी तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ बातचीत के बाद असहयोग आंदोलन में उनके प्रवेश से शुरू होता है। 1921 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का रुख

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आंदोलनोन्मुख हुआ जिसने स्वामी जी को प्रभावित किया तथा उस वक्त से 1924-25 तक स्वामी जी पूर्णतः गांधीवादी दर्शन, गांधीवादी आर्थिक दर्शन तथा सत्य अहिंसा के प्रति उनका लगाव प्रतिबद्धतापूर्वक बना रहा।

कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के बाद स्वामी जी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में जेल जाने के लिए पूर्णतः तैयार हुए। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के प्रसंग में 2 जनवरी, 1922 को उन्हें प्रथम बार जेल जाना पड़ा। कई जेलों की यात्रा ने अनेकों बार गांधीवादी विचारधारा को इस कारण धक्का पहुंचाया क्योंकि उन्होंने देखा कि अपने को सम्पूर्णता में गांधीवाद के प्रति समर्पित करने वाले कांग्रेसी नेताओं का जेलों में आचरण सर्वथा गांधीवाद के आदर्शों के खिलाफ था। स्वामी जी का जेल-जीवन गांधीवादी आस्था और उनके अनुयायियों (गांधी के) के आचरण के बीच व्याप्त अंतर्विरोधों ने उन्हें पुनः चिंतन का दूसरा मार्ग अपनाने पर बाध्य किया। यह काल स्वामी जी के शुरुआती राजनीतिक जीवन में पुनः एक संक्रमण काल साबित हुआ जो उन्हें पुनः जातीय उत्थान के लिए कार्य करने को प्रेरित किया। 1925 में युक्त प्रांतीय भूमिहार-ब्राह्मण अधिवेशन-अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासभा आदि के कार्यों में लग गए। मगर कुलीन भूमिहारों के द्वारा उसका पुनः विरोध किया गया। सर गणेशदत्त ने कहा, आप तो भूमिहारों को चौपट कर रहे हैं। गांधी जी के सत्याग्रह में लड़कों और जवानों को पढ़ना छुड़वाया, जेल भेजवाया, अब भिखमंगीवाला पुरोहिती का काम सिखाकर रहे-सहे को भी चौपट करना चाहते हैं। भूमिहार ब्राह्मण का बच्चा कथा बांच कर पैसा ले और खायें तो यह सब मरने की बात रहेगी। उक्त मन्तव्य पुरोहिती के खिलाफ कुलीन भूमिहारों की प्रतिवाद की भावना का प्रतीक है।

पटना में होनेवाले भूमिहार ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पद को लेकर स्वामी जी का राष्ट्रवाद और कुलीन भूमिहारों का जातिवाद गांव के लोगों के सामने खड़ा हो गया। 1921-22 के जेल जीवन के बाद अपने रचनात्मक कार्यों के लिए बिहटा में सीताराम आश्रम का निर्माण और संस्कृत शिक्षा का संबंध उन्होंने भूमिहार छात्रों के लिए किया।

1926 के कौंसिल चुनावों में कांग्रेस की जातिवादी नीति के कारण जब कई महत्वपूर्ण भूमिहारों को टिकट नहीं मिला तो स्वामी जी ने सर गणेशदत्त जैसे उम्मीदवारों के समर्थन की घोषणा कर दी। 1926-27 में समस्तीपुर प्रवास के समय एक प्रेस खरीदकर साप्ताहिक पत्र *'लोक संग्रह'* का प्रकाशन किया। लेकिन बाद के वर्षों में भूमिहार-ब्राह्मण-सभा पद बड़े नेताओं और जमींदारों के प्रभाव को

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

देख स्वामी जी का जातीय उत्थान का वह स्वप्न जो वर्षों से संजोया गया था टूट गया और अब वे समझने लगे कि वास्तविक जनजागरण का कार्य क्या है। उन्हें ज्ञात हुआ कि बड़े जमींदार किस तरह जातीय संगठन का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं।

किसान सभा के कार्य: 1927 में बिहार प्रांतीय किसान-सभा का गठन किया गया और स्वामी जी किसान-सभा के कार्यों में लगे। किसान-सभा के कार्यों को करते हुए उनकी मुख्य आर्थिक नीति रही कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा भारत में स्थापित भू-प्रबंध का, जिसमें कई तरह के बिचौलिए आ गए थे, उन्मूलन किया जाना। 1927 से 1934-35 तक, यानी अखिल भारतीय किसान-सभा के निर्माण काल के पूर्व ही, जब क़िसान आंदोलन, जिसकी सबसे प्रमुख मांग थी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और वह भी बिना मुआवजा दिए, तेज होता गया। सामंती तत्व किसान सभा से धीरे-धीरे विमुख होते गए। इसका स्पष्ट मतलब था कि शुरु के अपने निर्माण, विकास और संघर्षों में किसान सभा एक सुधारवादी आंदोलन से ज्यादा नहीं था और जब उसने एक क्रांतिकारी वर्ग संगठन का रूप ग्रहण करना शुरु किया तो प्रति क्रांतिकारी तत्व उससे आलोपित होते गए।

किसान सभा के कार्यों की अवधि में स्वामी जी ने किसान सभा के वर्ग चरित्र, उसको राजनीति तथा कार्य नीति पर कई किताबें लिखी जिनमें *"किसान कैसे लड़ते हैं"*, *"किसान सभा के संस्मरण"*, *"किसान क्या करें"*, *"किसानों के दावे तथा कार्यक्रम का खरीता"*, झारखंड के किसान, *"खेत मजदूर"*, *"किसानों को फंसाने की तैयारियां"*, *"महारुद्र का महाताण्डव"*, *"जमींदारी प्रथा का खात्मा कैसे हो"*, *"जमींदारी क्यों उठा दी जाय"*, *"अब क्या हो"*, *"द अदर साइड ऑफ द शिल्ड"*, *"रेंट रिडकसन इन बिहार : हाउ इट वर्क्स"* आदि। इन किसान आंदालनों की मुख्य मांग थी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। 26 दिसम्बर 1929 को सीतामढ़ी की एक किसान-सभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा था, "बिहार में या हमारे मुल्क में इन जमींदारों की क्या जरुरत है? वे लोग कौन-सा काम हमारे मुल्क के लिए करते हैं? सुना है, किसानों को बहुत सताते हैं, और इनसे किसान बहुत डरते हैं, इनसे क्या डरना? ये तो बहुत कमजोर हैं। यदि हाथ में इनका सिर पकड़ कर दबा दिया जाए तो भेजा बाहर निकल आए।"

नमक सत्याग्रह के बाद

1930 में कांग्रेस द्वारा आयोजित सदरनाफरमानी आंदोलन में नमक कानून तोड़ते हुए पुनः जेल गए। भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में स्वामी जी को जेल जीवन के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अनुभवों ने उन्हें पुनः गांधीवादी नेताओं के प्रति एक शंका को जन्माया और 1932 के आंदोलन मैं स्वामी जी ने, अपने पिछले अनुभवों के आधार पर, इसमें हिस्सा नहीं लिया, परंतु ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने आंदोलन तोड़क कार्यों का विरोध किया, जिसके कारण एक क्षद्‌म किसान-सभा बनाने की साजिश को नाकाम किया गया जिसके लिए पटना में 1932-33 के फरवरी में ऐसा प्रयास हुआ।

1932-33 के आस-पास स्वामी जी के किसान-सभा के कार्यों के संगठन में बिहार का दौरा कर इसे एक सशक्त संगठन बनाना चाहा, मगर 1934 के सत्यानाशी भूकम्प के कारण इसमें बाधा आई। मगर 1935 के आते-आते किसान-सभा ने जमींदारी उन्मूलन का नारा दिया तथा संघर्ष में जुट गई। 1935 के बीतते-बीतते हाजीपुर में आहूत बिहार प्रांतीय किसान-सभा में जमींदारी प्रथा के नाश का प्रस्ताव पारित हुआ। 1936 के करीब मेरठ में वामपंथी नेताओं द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के गठन का एक प्रस्ताव लिया गया और 1936 में लखनऊ में हुए कांग्रेस महाधिवेशन के अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कर दिया गया। फैजपुर में अखिल भरतीय किसान सभा के अधिवेशन के बाद एसेम्बलियों के चुनाव में किसान सभा ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उस चुनाव को मुद्दा बना लिया।

बिहार प्रांतीय किसान कान्फ्रेंस बछवारा तथा बिहार प्रांतीय किसान अधिवेशन दरभंगा, बैनी के प्रस्तावों और फैसलों, क्रमशः 1937-1939 के बाद बिहार में किसानों और जमींदारों के बीच ऐसी ठनी कि कांग्रेस के अन्दर का जमींदार भावी, किसान-सभा को कई तरह के इल्जामों के आधार पर बदनाम करने की कोशिश करने लगा। अखिल भारतीय किसान-सभा में वामपंथी रुझान का बोलबाला रहा जिसके कारण जब किसान सभा का तृतईय अधिवेशन कोमिल्ला में 1938 में हुआ तो उसमें साम्प्रदायिक एकता के प्रश्न को मजबूती से रखा। स्वामी जी की अध्यक्षता में उसने इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र को भी प्रभावित किया। किसान-सभा के झण्डे में हंसिया हथौड़ा रखने की बात पर अखिल भारतीय किसान अधिवेशन के नियामतपुर और कलकत्ता की बैठकों में मुहर लगा दी गई। किसान-सभा को किसानों, मजदूरों के वर्गीय संगठन के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के प्रस्तावों को हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में, जो सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में हुई, मान लिया गया तथा उसके बाद अखिल भारतीय किसान-सभा का चौथा अधिवेशन गया में तथा 1940 में विशाखापत्तनम के बुग्गा में सम्पन्न हुआ। त्रिपुरी कांग्रेस महाधिवेशन से समाजवादियों की नीतियों के कारण स्वामी जी को बड़ा आघात लगा और वे सुभाषचन्द्र बोस के नजदीक आए। 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अधिवेशन के मौके पर उन्होंने सुभाषचन्द्र बोस के साथ मिलकर समझौता विरोधी आन्दोलन किया।

1941 में जर्मनी के सोवियत रूस पर हमले के बाद स्वामी जी ने साम्यवादियों के साथ इस युद्ध को लोकयुद्ध कहा और मित्र राष्ट्रों की मदद की नीति पर चले। अपने जीवन काल में उन्होंने वामपंथियों की सम्पूर्ण एकता के लिए प्रयास किया।

स्वामी जी का राजसत्ता के प्रति दृष्टिकोण

अपने राजनीतिक जीवन में स्वामी जी मार्क्सवाद-लेनिनवाद से काफी प्रभावित हुए तथा उनके आर्थिक सामाजिक चिंतनों के अंदर वर्ग विभाजित समाज और वर्गों के बीच के आर्थिक अंतर्विरोधों के सिद्धांत को स्वीकार किया। इस वर्ग-संघर्ष की अवधारणा में स्वामी जी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में मुख्य अंतर्विरोध जमींन्दारों तथा किसानों और खेत-मजदूरों के बीच विश्लेषित करते थे, जिसमें अन्तर्विरोध के एक छोर पर बड़े जमींदार थे तो उनके खिलाफ तमाम तबकों के किसानों एवं खेत-मजदूरों को विशाल आबादी थी, जो इन जमींदारों द्वारा शोषित हो रही थी। उसी शोषित तबका के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती किसान-सभा इनका एक वर्गीय संगठन थी, जो साम्राज्यवाद तथा देशी शोषण की शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में किसान-हित का प्रतिनिधित्व करती थी। किसान-सभा के संघर्षों के मुख्य मुद्दों को स्वामी जी दो भागों में विभाजित कर देखते थे: प्रथम किसानों की मौलिक मांगें और दूसरी किसानों की तात्कालिक मांगे। इन मांगों का संबंध किसान-सभा के दूरगामी और अल्पगामी लक्षणों से था। मौलिक मांगों का निराकरण यह अंतर्दृष्टि देता था कि इनके समाधान के लिए किसान, मजदूरों को राजसत्ता पर कब्जा करना होगा, क्योंकि ये ऐसी वर्गीय मांगे हैं जिनका सम्बन्ध और लक्ष्य दूरगामी है। तात्कालिक मांगों का सम्बन्ध वर्तमान राजसता और सामाजिक संरचना के अंदर संघर्ष कर प्राप्त किया जा सकता था। इसी आधार स्वामी जी ने किसानों की मौलिक एवं तात्कालिक मांगों में विभाजित किया।

स्वामी जी की अवधारणा में तत्कालीन राजसत्ता पूंजीपतियों एवं जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए एक संगठित यंत्र थी जिसमें पुलिस और फौज उसका संगठित गुण्डा दस्ता था। उनके अनुसार राजसत्ता की लड़ाई में अहिंसा का सिद्धांत और कुछ नहीं, बल्कि यथा स्थितिवाद के खिलाफ आवाज उठाने पर एक किस्म की पाबंदी थी, वर्गीय हिंसा नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी शासन तंत्र रोज हिंसा करता रहता है। उस कारण स्वामी जी गांधी के हिंसा के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। उनकी मान्यता में किसानों एवं मजदूरों की सम्पूर्ण मुक्ति किसान-मजदूर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

राज्य की स्थापना के बाद ही हो सकती है, इसलिए इनकी तमाम लड़ाइयों को राजनीतिक संघर्ष को दिशा में उन्मुख करना किसान-सभा का कार्य है। संक्षेप में स्वामी जी मार्क्सवादी अवधारणा में राजसत्ता का जो स्वरूप है उसे मानते थे मगर उससे उसकी एक भिन्नता है कि वे सर्वहारा ही तानाशाही की जगह प्रजासत्तात्मक राज्य की कल्पना करते हैं।

स्वामी जी का वर्ग दृष्टिकोण

भारतीय आर्थिक संरचना में स्वामी जी का वर्ग दृष्टिकोण भारतीय विकास के क्रम में उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप जन्मा है, जिसमें पूर्व ब्रिटिशकालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो साम्राज्यवाद ने ध्वस्त किया मगर उसकी जगह पर यूरोपीय किस्म की औद्योगिक आर्थिक संरचना को भी नहीं जन्म दिया, बल्कि पौराणिक ग्रामीण व्यवस्था के भंग होने पर दरिद्रीकृत कारीगर दस्तकार अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर रहने के लिए बाध्य किए गए। आजादी के बाद कृषि सुधारों में क्रांतिकारी परिवर्तनों के अभाव में ग्रामीण शोषण बरकरार रहा और किसानों, खेत मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सका।

इस स्थापना से स्वामी जी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरचना में किसानों का ही वर्चस्व पाते हैं, किसान सभा खेत-मजदूरों का वह वर्ग है जो मुख्यतः खेती में अपनी जीविका चलाता है। मिल मजदूर ने देहातों में किसानों में दरिद्रीकरण के फलस्वरूप, शहरों की तरफ पलायन किया किसान है तथा सिपाही और फौज का जवान इसी तरह में श्रम पलायन का अंग है-सबों का वर्गाधार या तो किसान है या खेत-मजदूर। यही भारतीय क्रांति के स्वरूप तथा उसके वर्गाधार का सही आकलन होगा।

स्वामी जी किसान वर्ग की व्यक्तिवादिता को स्वीकार करते हैं कि वह अपने छोटे से खेत के टुकड़े से आगे नहीं देख पाते, इस संदर्भ में वह औद्योगिक मजदूरों की तुलना में कम क्रांतिकारी है। मध्यम वर्ग की ढुलमुल नीति के प्रति स्वामी जी आश्वस्त हैं फिर भी क्रांति की सफलता में वे एक विस्तृत संयुक्त मोर्चा की संकल्पना, *क्रांति और संयुक्त मोर्चा* में करते हैं। सफल क्रांति के लिए पूंजीपति वर्ग तथा जमींदारों के खिलाफ संघर्ष में तमाम वर्गों के संयुक्त मोर्चा के समर्थक हैं, उसके बावजूद कि कांग्रेस जो लड़ाई का नेतृत्व करती है, और फिर जिसमें पूंजी और सामंती तत्वों का एक हद तक बोलबाला है। इजारेदार पूंजी के सबसे घृणित स्वरूप फासीवाद के खिलाफ संघर्ष में स्वामी जी साम्राज्यवाद के साथ भी मोर्चा के समर्थक हैं। यही कारण है कि पूंजी और श्रम के संघर्ष में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी जी श्रम का, राष्ट्रीय आजादी और साम्राज्यवादी के बीच संघर्ष में राष्ट्रीय लड़ाई का तथा फासीवाद और उसके खिलाफ लड़नेवाले किसी भी तर्क के बीच संघर्ष में साम्राज्यवाद के साथ भी मोर्चा के कायल हैं। इसीलिए वे द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में खड़े हुए।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्रांति की सफलता तथा क्रांति के सफल वाहक तत्व के रूप में स्वामी जी सिर्फ औद्योगिक मजदूरों को ही मुख्य कारक नहीं मानते, बल्कि क्रांति में उनकी भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए किसान और कृषि-मजदूरों को भी एक क्रांतिवाहक तत्व ही मानते हैं। क्रांति मौलिकता में चीनी क्रांति ज्यादा सम है बशर्ते रूसी समाजवादी क्रांति के, स्वामी जी किसानों मजदूरों की जीत तथा एक वर्ग विहीन समाज की संरचना में एक मील का पत्थर मानते हैं। 1926 में हुनान (उस समय हुनान प्रान्त चीन के किसान आन्दोलन का केन्द्र था) के किसान अपने हमले का मुख्य निशाना स्थानीय निरंकुश तत्वों व बुरे शरीफजादों और स्वेच्छाचारी जमींदारों को बनाते हैं, लेकिन लगे हाथों वे पितृसत्तात्मक विचारधारा .... खाक में मिल जाते हैं। परिणामस्वरूप हजारों साल से सामन्ती जमींदार जिन विशेषाधिकारों का उपभोग कर रहे थे, उन्हें चूर-चूर किया जा रहा है। जमींदारों ने अपनी जो मान-मर्यादा और इज्जत बता रखी थी बह रत्ती-रत्ती धूल में मिलाई जा रही है। जमींदारों की सत्ता के चकनाचूर किये जाने पर किसान सभा ही सत्ता लागू करने वाली एक मात्र संस्था रह गई है और 'सारी सत्ता' किसान-सभा के हाथ में हो' का ही लोकप्रिय नारा एक वास्तविकता बन चुका है। (हुनान के किसान आन्दोलन की जांच की रिपोर्ट' माओ त्से-तुंग प्रकाशित '*फिलहाल*' अक्तूबर-नवंबर-1999)।

क्रांति को स्वामी जी शास्त्रीय मार्क्सवादी परिभाषा के ही फ्रेम में रखकर विश्लेषित करते हैं, जहां शासन सत्ता एवं वर्ग के हाथ से निकलकर दूसरे वर्ग के हाथों में आती है, अन्य तरह की क्रांतियों को स्वामी जी मात्र सत्ता का हस्तांतरण मानते हैं, जैसे 1789वीं फ्रांसीसी क्रांति को वे सामंतवाद के ऊपर एक क्रांति मानते हैं जिसका वाहक पूंजीवाद था, 1917 की इसी क्रांति पूंजीवाद में ऊपर आजादी आंशिक है, क्योंकि पूर्ण आजादी तभी आती है जब सबों को आर्थिक आजादी भी मिल जाय। जो भारत में नहीं हो सका। इसलिए 15 अगस्त, 1947 को प्राप्त समाजवाद की क्रांति, चीन की क्रांति आदि क्रांतियां थी, मगर 1947 को मिली आजादी को स्वामी जी क्रांति नहीं सत्ता का हस्तांतरण मानते हैं। स्वामी जी की परिकल्पना में 15 अगस्त, 1947 को प्राप्त स्वतंत्रता की जिन्होंने क्रांति या पूर्ण आजादी मानी उनकी स्थापनाओं के साथ स्वामी जी नहीं रहे। उन्होंने पूर्ण आजादी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

या आर्थिक आजादी के लिए आजादी के उपरांत भी किसानों और मजदूरों को संघर्ष के लिए उद्धेलित करने का कार्य करते रहना आवश्यक समझा।

कांग्रेस के प्रति स्वामी जी का दृष्टिकोणः सहयोग-असहयोग के मुद्दे

स्वामी जी ने लिखा कि पहले वे कांग्रेस के ही संपर्क में आए और 1920 के बाद के आंदोलनों से प्रेरणा ग्रहण कर 1927 में किसानों की दशा सुधारने के लिए किसान सभा के कार्यों में लगे, मगर पहले तो कांग्रेस जनों ने इसमें कुछ रुचि ली, परंतु बाद के दिनों में उन्होंने वह रुचि नहीं दिखाई। स्वामी जी का 'किसान सभा का संस्मरण' बताता है कि स्वामी कांग्रेस में लड़ते-झगड़ते हुए भी कांग्रेस में बने रहे। उनका विश्वास था कि कांग्रेस ही विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ लड़नेवाली एकमात्र संस्था है।

भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में स्वामी जी जमींदारों को किसानों का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे मगर कांग्रेस जमींदारों को नकार कर नहीं चलना चाहती थी। वे कांग्रेस के जमींदार मोह पर जमकर प्रहार करते थे। कांग्रेस में रहकर किसान सभा चलाने पर स्वामी जी के खिलाफ एक मुहिम भी चलाई गई जिसका प्रतिवाद वे हमेशा करते रहे।

कहा गया कि कांग्रेस में 90 प्रतिशत किसान और फैजपुर में ज़मींदारी मिटाने का प्रस्ताव इसका प्रमाण है कि कांग्रेस किसान पक्षी है, लेकिन स्वामी जी की दृष्टि में कांग्रेस राष्ट्रीयता की भावना और भौतिक हितों को साथ लेकर चल रही है और किसानों तथा जमींदारों को साथ लेकर चलती है।

स्वामी जी की दृष्टि में मात्र जमींदारी मिटा देना ही किसान-हित की रक्षा नहीं, बल्कि जमींदारी समेत जमींदारों के उन सारे भौतिक हितों को क्रांतिकारी तरीके से छीन लेना था जिसका उपयोग कर जमींदार किसानों का शोषण करते थे- यह एक क्रांतिकारी तरीका था जिसे कांग्रेस लागू नहीं कर सकती थी।

जमींदारी उन्मूलन स्वामी जी के अनुसार 1936-37 में ही किया जाना चाहिए था, जबकि कांग्रेस ने हवा का रुख देखकर 1946 में इस प्रस्ताव को पास किया। स्वामी जी की दृष्टि में किसान-सभा आर्थिक नीति और आर्थिक कार्यक्रम की राजनीति की दृष्टि से देखती हुई अर्थ-नीति का साध्य तथा राजनीति की साधन मानती है। यानी राजनीतिक सत्ता का प्रयोग कर आर्थिक बुनियादी परिवर्तनों के पक्ष में है, मगर कांग्रेस राजनीतिक साध्य के लिए आर्थिक कार्यक्रम को साधन मानती है या आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक सत्ता मात्र प्राप्त करता चाहती है, अर्थनीति में परिवर्तन उसका लक्ष्य नहीं है।

किसानों को बहुसंख्यक आबादी को संगठित कर कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

चुनाव जीतना है, किसान सभा की उपयोगिता कांग्रेस के लिए है अन्यथा कुछ नहीं है। उनकी अवधारणा में किसान सभा कांग्रेस के अंदर रहकर उसका पिछलग्गू बन जाएगी इसलिए उसका कांग्रेस में स्वतंत्र अस्तित्व आवश्यक है।

कांग्रेस मुआवजा देकर जमींदारी-उन्मूलन के पक्ष में थी। स्वामी जी बिना मुआवजा दिए जमींदारी-उन्मूलन चाहते थे। कांग्रेस के अंदर विरोध पक्ष कांग्रेस को सही रास्ते लाने का एक साधन था जिसको स्वामी जी एक अच्छा लक्षण मानते थे, मगर कांग्रेस इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। स्वामी जी ने देखा कि कांग्रेस किसानों के हितों की रक्षा पूरी तरह नहीं कर रही है तथा उसका रुख जमींदार-पक्षी है तो उन्होंने किसान सभा के स्वतंत्र अस्तित्व पर बल दिया ताकि वह इनके हितों के लिए संघर्ष कर सके। कांग्रेस के किसान हित रक्षक होने के दावे का उन्होंने अपनी बुकलेट्स 'द अदर साइड ऑफ शिल्ड' तथा रेन्ट रिडक्सन इन बिहारः हाऊ इट वर्क्स? में किया है। कांग्रेस से उनका विरोध इतना बढ़ा कि किसान-मजदूर हित में अन्ततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया।

इसी तरह से अन्य मुद्दों पर उनका कांग्रेस के साथ विरोध था जो द्वितीय विश्वयुद्ध कार्य में उभरा और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया।

भूमि संघर्ष के मुख्य मुद्दे

स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने किसान-आंदोलन की यों तो एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में विकसित किया, परंतु जिस राजनीति और कार्यनीति का उन्होंने अनुसरण किया–आर्थिक मांगों की प्राप्ति में राजनीतिक संघर्ष एक साधन और जो जंग उन्होंने वर्गाधार को समझकर किसानों के मुख्य दुश्मनों के खिलाफ छेड़ा उनमें सबसे प्रमुख जमींदारी उन्मूलन, भावली जमीनों के लिए संघर्ष तथा बकाश्त आंदोलन प्रमुख थे। इन मुद्दों पर सम्पूर्ण बिहार में स्वामी जी ने आंदोलन गठित किया। बिहार टिनेंसी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन, जो रैयतों के हक के खिलाफ जाता था, के खिलाफ किसान-सभा ने आंदोलन गठित कर उसे वापस कराया यह किसान-सभा की बड़ी जीत थी।

प्रो. अरविन्द नारायण दास ने अपने लेख 'बिहार किसान सभा : कल, आज और कल' जो नवभारत टाइम्स, 2 मार्च, 1889 को प्रकाशित हुआ था, उसमें स्वामी जी के सिद्धान्त के सन्दर्भ में निम्नलिखित उद्देश्य को प्राथमिकता प्रदान की है :"मुनि लोग तो अपने ही मुक्ति के लिए एकांत वास करते हैं। लेकिन मैं ऐसा हर्गिज नहीं कर सकता। सभी दुखियों को छोड़ मुझे सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं चाहिए। मैं तो इन्हीं के साथ रहूंगा और मरूंगा, जिऊंगा।"

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

केन ग्रोवर कानफ्रेंस में स्वामी जी ने ईख उपजाने वाले किसानों को ईख की उचित कीमत दिलाने के संघर्ष का नेतृत्त्व करते हुए ईख की सघन खेती करने तथा उसमें मिल मालिकों तथा किसानों के सहयोग के कई ऐसे प्रस्ताव रखे जिनमें वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में किसानों एवं मील मालिकों को सहयोग से परस्पर लाभ पर आधारित एक व्यवस्था को कायम किया जा सके। स्वामी जी किसानों एवं मजदरों के मसीहा थे जो क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्षधर थे जिसमें किसान-मजदूरों का वर्चस्व हो तथा सही ढंग से उनके हितों की रक्षा हो सके।

कांग्रेस से अलग होने तथा साम्यवादियों से मतभेद के बाद स्वामी जी का अथक प्रयास रहा कि तमाम वामपंथी ताकतों में एकजुटता कायम की जाये और जिस आर्थिक आजादी की संकल्पना स्वामी जी ने की थी, और जो स्वतंत्र भारत में किसानों मजदूरों को प्राप्त न हो सकी थी, इसे प्राप्त किया जाए। मगर उनका स्पप्न साकार न हो सका, क्योंकि समाजवादियों ने उनके इस कार्य के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई। कई बार वामपंथियों को बैठकों को आहूत किया जाता रहा मगर समाजवादी नेतागण उसमें हिस्सा नहीं लिए। स्वामी जी का इस प्रकार के वाम मोर्चा की संकल्पना के साकार होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई।

स्वामी जी की प्रासंगिकता

स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने अपने जीवन काल में मुख्यरूप से शोषित, दलित, दबे-कुचले लोगों के उत्थान के कार्य को अंजाम देने का कार्य किया। कुछ लोग यह कह कर उनकी आलोचना करते हैं कि उन्होंने जातीय उत्थान के कार्य को महत्व दिया था। वे भूमिहारों को ब्राह्मण की श्रेणी में लाकर रखना चाहते थे तथा समाज में एक सम्मान का स्थान दिलवाना चाहते थे। इसके लिए उन पर जातीयता का इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन वास्तविकता इससे परे थी। वे किसी ऐसे समाज का उत्थान चाहते थे जिसे सताया जा रहा था तथा जिसका शोषण हो रहा है। वे उस जाति में विश्वास जगाकर उन्हें अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे थे यह कार्य भी उनके वृहतर उद्देश्य-शोषितों पीड़ितों के उत्थान, की ही एक कड़ी थी। उन पर जातीयता का इल्जाम लगाने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि उन्होंने चुनाव में एक दबंग भूमिहार नेता के खिलाफ एक धोबी जाति के व्यक्ति का साथ दिया था। इसके अतिरिक्त उनकी शोषण विरोधी व्यक्तित्व तथा कृतत्व का सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि उन्होंने बड़े-बड़े भूमिहार जमींदारों के खिलाफ ही अपनी मुहिम चलाई थी तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए गरीब छोटे एवं सीमांत किसानों को गोलबन्द्र करने का कार्य किया था। बिहार स्तरीय प्रांतीय किसान सभा या

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अखिल भारतीय किसान-सभा के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने इस कार्य को बखूबी किया था। उन्होंने सक्रिय रूप से जमींदारों, बड़े किसानों का विरोध किया था तथा छोटे, सीमांत गरीब किसानों, खेतिहर-मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जंग छेड़ा था। 1930 के बाद की अवधि में उन्होंने इन कार्यों का नेतृत्व किया जिसमें सिर्फ ऊंची जाति के ब्राह्मण, भूमिहार राजपूत तथा कायस्थ जाति के ही लोग नहीं थे बल्कि उनके साथ मध्यम जातियों कोइरी, कुर्मी, यादव जाति के लोग भी थे तथा दलित हरिजन जाति के लोग भी। इसलिए जातीयता के इल्जाम को उस व्यक्ति के महानता एवं महत्व को कम करने का मात्र एक प्रयास ही माना जाना चाहिए। वाल्टर डाउजर ने भी यह विचार व्यक्त किया है कि इस तरह की सोच व्यक्ति के दिमाग तथा सक्रीयता को अत्यंत कम करने की समझ थी। उस व्यक्ति की सामान्य विशेषता थी कि वह बौद्धिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दिशा में हमेशा परिवर्तन की दिशा में अग्रसर हो रहा था। उनकी यह दशा मात्र परिवर्तन के लिए न थी बल्कि न्याय तथा समानता के लिए थी। जहां भी अन्याय तथा शोषण था उसके विरुद्ध था। इस तरह स्वामी जी जो परिवर्तन लाना चाहते थे वह सुधारवादी तथा परिवर्तनवादी था। वे गरीब किसानों कृषि मजदूरों का उत्थान चाहते थे तथा उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने शोषण, अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष एवं मुहिम चलाया था। वे पूरी तरह अत्यन्त गरीबों–चाहे वह किसान हो या कृषि मजदूर, उसकी मुक्ति के लिए पूरी तरह समर्पित थे,कृतसंकल्प थे, चाहे वह किसी भी जाति का हो।

उन्होंने जिन मुद्दों के लिए संघर्ष किया ग्रामीण क्षेत्र की दयनीय स्थिति, गरीब एवं कृषि मजदूरों की दुर्दशा जमींदारों, धनी लोगों के द्वारा उनका शोषण, सेठ, साहूकारों तथा महाजनों द्वारा शोषण, बढ़ती हुई गरीबी, काश्तकारी कानून की खामियां, कृषि की दुरावस्था के कारण गरीब किसानों की बढ़ती हुई परेशानियां तथा अंत में उनका कृषि श्रमिक की श्रेणी में परिवर्तन, श्रमिकों का शोषण, अत्यन्त कम मजदूरी, बीमारी की हालत में भी काम का सवाल, कर्ज का सवाल एवं बंधुआ मजदूर का प्रश्न, जमीन पाने का सवाल, श्रमिकों के साथ बर्ताव एवं उनकी इज्जत का प्रश्न, झारखण्ड के लोगों को उनके साधनों, जमीन से बंचित रखने का प्रश्न, सदियों से प्राप्त प्राकृतिक साधनों-जंगल, लकड़ी, फल-फूल इत्यादि के प्रयोग से वंचित करने का प्रश्न, प्राकृतिक परिवेश तथा वातावरण के लाभ को छीनने का प्रश्न- ये सभी महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके बारे में स्वामी जी ने लिखा, उनका विश्लेषण किया था शोषण से मुक्ति के लिए संघर्ष का रास्ता बताया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जो प्रश्न स्वामी जी द्वारा उठाये गये थे उनमें से बहुत से आज भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका समाधान 50 वर्षों बाद भी स्वतंत्र भारत में बचे हुए हैं। मजदूरी का प्रश्न, कृषि में उत्पादन बढ़ाकर कृषकों तथा मजदूरों की स्थिति सुधारने का प्रश्न, काश्तकारी कानून को गरीब किसानों एवं श्रमिकों के हित में बदलने का प्रश्न एवं उनके सही क्रियान्वयन जैसे प्रश्न आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। शोषण के विरुद्ध लड़ाई, उचित मजदूरी के लिए झगड़े तथा खूनी संग्राम, श्रमिकों के साथ बर्ताव एवं सलूक का प्रश्न ये सभी मुद्दे आज भी बने हुये हैं। स्वामी जी ने आग्रह किया था कि यदि इनका समाधान सही ढंग से नहीं होगा तो स्थिति भयावह हो जायेगी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि "अन्याय के बल पर मौज करने वालों की जिन्दगी को नर्क तथा दोजख बना देनेवाला जमाना आ गया है। यह शोषित और पीड़ितों का युग है, उनके आगे बढ़ने का जमाना है।" उन्होंने गरीब किसानों तथा कृषि मजदूरों को संगठित होकर जमींदारों तथा शोषकों के विरुद्ध लड़ने का आह्वान किया था। साथ ही यह भी आगाह किया था कि वे आपसी झगड़े मिल बैठ कर आपसी समझदारी के आधार बात करके सुलझा लें। यह भी कहा था कि मजदूरी के प्रश्न पर केवल आदर्शवादी न बनके व्यावहारिक बनना चाहिए। मजदूर ऐसी मांग पेश न करें कि घरबार और खेत बेचकर भी उसे किसान पूरी न कर सकें। यदि मांग बहुत अधिक या अव्यावहारिक होगी तो फलतः सिर्फ कलह और वैमनस्य ही हाथ लगेगा। जब तक किसानों की आर्थिक दशा में भारी परिवर्तन नहीं हो जाता मजदूरी में बहुत अधिक छलांग की गुंजाइश कम है। लेकिन मिलकर एक ऐसा समाधान निकालना होगा जो दोनों के पेट भरने के लिए आवश्यक है। आज भी स्वामी जी द्वारा बताये गये उपाय एवं रास्ते सटीक प्रतीत होते हैं जिन पर अमल करके अशांत ग्रामीण वातावरण को समाप्त किया जा सकता है तथा किसानों एवं श्रमिकों के सम्मिलित प्रयास एवं समझदारीपूर्ण व्यवहार से खूनी वारदातों, नर-संहारों को समाप्त किया जा सकता है। अतः स्वामी जी के विचार, उनका विश्लेषण तथा उनके द्वारा बताए गए उपाय एवं समाधान आज भी हमारे लिए प्रदर्शक का काम कर सकते हैं। उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।

आजादी के चार दशकों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में भूमि-सुधार का प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। भू-प्रबंध में आजादी के बाद सरकार और किसानों के बीच जमींदार, नामदार, ताल्लुकेदार आदि कई तरह के बिचौलिए वर्तमान थे, जिनका उन्मूलन 1956 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद किया जा सका। मगर इन बिचौलियों की समाप्ति के बाद भू-प्रबंध को ऐसी कमजोर कोशिश

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

की गई कि जमीन का केंद्रीकरण बड़े पैमाने पर पुराने जमींदारों के हाथों में ही रह गया तथा कानून में कृषि फार्म या खुद काश्त के नाम पर जमींदारों को जो सुविधा दी गई उससे बड़े पैमाने पर बेदखलियों का सिलसिला चला जिसने किसान सभा की मांग जमीन जोतनेवालों को फलित नहीं होने दिया।

स्वामी जी के घोषणा पत्र में प्रदत मांगों की यथार्थता आज भी बरकरार है, और अगर आज कुछ किसानों को महाजनों के क्रूर दमन, भारी सूद आदि से कुछ राहत मिल सकी है तो उसे लिए स्वामी जी के घोषणा पत्र की तीसरी मांग का नतीजा कहा जा सकता है। पुराने भूमिकरों के खात्में, गैर आर्थिक भूमि के लगान की माफी, प्राकृतिक प्रकोप से फसल नष्ट हो जाने पर मालगुजारी माफी, फसल बीमा, घर, मवेशी आदि को नीलाम न किए जाने, भूमि बंधक बैंक की स्थापना, खेत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, किसानों को उपज की लाभकारी कीमत, कृषि उत्पादित मालों की ढुलाई में कमी, ग्रामीण सरकारी समितियों का गठन या इस तरह की किसी भी मांग को आज जब उठाया जाता है तो उसका समावेश स्वामी जी के घोषणा पत्र में अवश्य पाया जाता है।

किसान घोषणा-पत्र की राजनीतिक मांगों को जब देखते हैं तब पता चलता है कि मताधिकार का समान अधिकार, सभी विधायिका में कार्यकारी प्रतिनिधित्व के सवाल की मांग 1936 में ही किया था, सभी तरह के मजदूर विरोधी, कृषि मजदूर विरोधी कानूनों को रद्द करने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, सम्पूर्ण नागरिक सुविधा, आवासीय सुविधा, स्वास्थ्य तथा आवासीय नीति लागू करने की मांग आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है।

आज हम जिन ग्रामीण समस्याओं से उलझ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त हिंसा, जातीय दंगा आदि का उभार हो रहा है उसमें एक प्रमुख कारण है जनवाद के समानुपातिक आर्थिक सुधारों की कमी। कृषि संबंधों में प्रस्तावित सुधार कानून जैसे हदबंदी से फाजिल जमीनों का भूमिहीनों में बंटवारा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण प्रबंध सघन खेती की व्यवस्था आदि के कारगर ढंग से लागू न करने का परिणाम है कि कृषि क्षेत्र में पूंजीवादी विकास की एक प्रक्रिया सी चलती नजर आ रही है। इन पूंजीवादी प्रक्रिया का लाभ कुछेक किसानों को ही मिल पाया है जबकि बहुसंख्यक सीमांत छोटे किसान एवं मजदूर इससे वंचित रहे हैं।

भारत में भूमि पर प्रभावी इजारेदारियों की जानबूझकर बनाये रखा गया है इसका प्रत्यक्ष सबूत है कि बाजार में माल के रूप में बिकने के लिए आने वाले अनाजों का 1960-61 के दशक में 70-75 फीसदी उन्हीं परिवारों से आता था जिनका प्रतिशत कुल जनसंख्या का मात्र 12 प्रतिशत था। बढ़ती महंगाई, घाटे की

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वित्त व्यवस्था तथा कर्ज आधारित बजट ने कीमतों को जब काफी ऊंचा उठा दिया है तब मजदूरी पैसों रुपयों (कैश) में दी जाने लगी है जबकि मजदूर सामानों (काईन्ड्स) में मजदूरी मांगते हैं। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था, बड़ी पूंजी और बड़े भू-स्वामियों के हिस्से को राष्ट्रीय आय में बढ़ा देती है तथा भू-स्वामी किसी भी तरह से इसका विरोध बर्दाश्त नहीं करते, जो हमारे देश में हरिजन दहन में देखा जा रहा है क्योंकि वर्ण आधारित समाज में सवर्णों की अपेक्षा निचली जातियों पर जुल्म ज्यादा किए जाते हैं। यह जुल्म अब केवल तथाकथित ऊंची जातियों द्वारा ही नहीं बल्कि भूमि से जुड़े अन्य ऊंची जातियों द्वारा भी किया जा रहा है तथा पिसते हैं गरीब, हरिजन एवं मजदूर।

जनवादी विकास के साथ-साथ जब आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों में समता का भाव आया है तब ग्रामीण हलकों में यह विद्रोह कभी मजदूरी के सवाल पर तो कभी सवर्ण और पिछड़ी जातियों के बीच सामाजिक जोर-जुल्म के सवाल पर हिंसात्मक रूप में ले रहा है। बहुत सारी ऐसी वारदातें होती हैं जिनका बुरा असर कृषि उत्पादन पर तो निश्चित रूप से पड़ता है साथ ही रोजगार की कमी मजदूरों को भी बुरी तरह प्रभावित करता है।

ये तथ्य प्रमाणित करते हैं कि स्वामी जी के विचारों, कार्यक्रमों आदि के आधार पर भूमि सुधार लागू किया गया होता तो आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप कुछ दूसरा ही होता। मगर यह भी एक सत्य है कि आजादी के बाद भारत में शासन करनेवाले वर्ग ने भूमि सुधारों के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जिससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था विकास की मंजिल तक नहीं जा सकी और इस असफलता का प्रदर्शन ग्रामीण हिंसा में हो रहा है। दूसरी तरफ पश्चित बंगाल तथा केरल की वामपंथी सरकारों ने इस कर्तव्य को पूरा किया इसलिए वहां की स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है।

आजादी के बाद जो सरकार बनी, उनके वर्ग-चरित्र में असली को वर्णन करते हुए स्वामी जी अपनी प्रक्रिया 'हुंकार' (वर्ष-9, अंक-7, 16 जुलाई, 1950) में कहा है कि "आज सरकार की सारी ताकत जमींदारों के लिए, पूंजीपतियों के लिए सारी सहूलियतें मुहैय्या करने में लगी है, उनके लिए सरकार की पूरी तैयारी है, ... उसमें बिड़ला, डालमियां, टाटा, सिंहानियां को कारखाना खोलने में सहूलियत मिलेगी, किसानों और मजदूरों को कोई सुख-सुविधा नहीं मिल सकती। यह सरकार मालदारों की है, जमींदारों की है .....कहा जाता है, अपनी सरकार बन गई, अंग्रेज चले गए; लेकिन किसान और मजदूर को क्या मिला ..... जिसके बल पर सरकार बनी और कायम है? .... आपने देखा उन्होंने (कांग्रेस) एसेम्बली

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में किसानों को भेजा?– सिर्फ जमींदारों या उनके पिट्ठुओं को। किसानों की बात बोलने वाला वहां कौन है? जहां ऐसी एसेम्बली है, वहां किसानों का खुदा हाफिज ... स्वराज नहीं यह तो पुलिस राज है। एम.एल.ए. का राज है। पुलिस जो चाहती है, कर रही है, पुलिस का रवैया तो पहले से खराब है .... एम.एल.ए. जो चाहते हैं कर रहे हैं।"उपर्युक्त वाक्य आज अक्षरशः सत्य प्रतीत हो रहे हैं। आज भी किसानों एवं मजदूरों का कौन सुनने वाला है। स्वामी जी भी उपर्युक्त वक्तव्य की प्रासंगिकता आज भी प्रतीत हो रही है।

आज भी 75 से 80 प्रतिशत आबादी का खेती पर निर्भर रहना तथा कृषि उत्पादन संबंधों में पूर्ण सुधार न होने के कारण ग्रामीण विकास अवरुद्ध है और सारी सरकारी योजनाओं का लाभ बड़े खेत मालिकों को मिलता है। ऐसी स्थिति में स्वामी जी द्वारा निर्देशित भूमि-सुधारों की प्रासंगिकता बनी हुई है। आवश्यकता इस बात की है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन इस भांति किया जाए ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ अवश्य मिले। बहुसंख्यक ग्रामीण जनसंख्या के माली स्थिति में सुधार पर देश का विकास बहुद हद तक निर्भर करता है। हमें इस बात की भी गारंटी करनी होगी की देश में जनवादी आधार पर पंचायती राज प्रणाली मजबूत बने तथा गरीब स्वयं उसमें हिस्सेदार हों तभी उनके हितों की रक्षा सही ढंग से हो पायेगी। तभी एक सुदृढ स्वरूप में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का निर्माण एवं विकास संभव होगा।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिशिष्ट-1

स्वामी सहजानन्द सरस्वती का संक्षिप्त जीवन वृत्त

1889 ई. महाशिवरात्रि के दिन गाजीपुर जिले के देवा ग्राम में श्री बेनीराय के कनिष्ठ पुत्र के रूप में जन्म। नाम नवरंग राय।

1892 ई. माता को देहान्त।

1898 ई. जलालाबाद मदरसा में पढ़ाई प्रारंभ।

1900 ई. यज्ञोपवीत।

1901 ई. लोअर तथा अपर प्राईमरी की छः वर्ष की शिक्षा 3 वर्षों में समाप्त।

1904 ई. मिडिल परीक्षा में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में छठा स्थान प्राप्त कर छात्रवृत्ति प्राप्ति।

1905 ई. विवाह (वैराग्य से बचने के लिए) मैट्रिक में पढ़ते समय ही।

1906 ई. वर्ष के प्रारम्भ में पत्नी की मृत्यु। गर्मी में वाराणसी तथा हरिद्वार की यात्रा संन्यासी बनने के विचार से। फिर जुलाई में वापस स्कूल में गाजीपुर।

1907 ई. पुनः विवाह की बात जानकर महाशिवरात्रि को घर से प्रस्थान कर काशी पहुंचकर दसनामी संन्यासी स्वामी अच्युतानन्द सरस्वती से दीक्षा ग्रहण कर नवरंग राय से स्वामी सहजानन्द सरस्वती बने।

1908 ई. प्रायः वर्ष पर्यन्त गुरु तथा ईश्वर की खोज में भारत की प्रायः सम्पूर्ण तीर्थों का भ्रमण।

1909 ई. पुनः काशी पहुंचकर दशाश्वमेघ घाट स्थित श्री दण्डी स्वामी अद्वैतानन्द सरस्वती से दीक्षा और दंड ग्रहण कर दंडी स्वामी बने।

1910-12 ई. काशी तथा दरभंगा में संस्कृत साहित्य व्याकरण, न्याय तथा मीमांसा का गहन अध्ययन।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

1913 ई. बलिया में 28 दिसम्बर को हथुआ महाराज की अध्यक्षता में सम्पन्न अखिल भारतीय भूमिहार-ब्राह्मण महासभा में स्वामी पूर्णानन्द जी के प्रयास से प्रथम बार उपस्थित तथा ब्राह्मण धर्म तथा ब्राह्मण समाज की स्थिति पर भाषण।

1914-15 ई. भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण, ब्राह्मणों के परस्पर वैवाहिक संबंधों तथा अन्य एकता से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन तथा संकलन करना। मुजफ्फरपुर से श्री युगेश्वर सिंह के संपादकत्व में प्रकाशित *"भूमिहार ब्राह्मण"* मासिक पत्र में हिन्दी कविता तथा लेखों का प्रकाशन।

1916 ई. 1916 से काशी *"भूमिहार ब्राह्मण"* मासिक निकला और प्रथम अंक में पत्र निकालने के उद्देश्य संबंधी अपील, 1916 ई. में ही *"भूमिहार ब्राह्मण परिचय"* लिखकर पूरा किया। 'झूठा भय मिथ्या अभिमान' लिखकर पूर्ण करना। काशी के अतिरिक्त विश्वम्भरपुर गाजीपुर में निवास।

1917 ई. प्रथम बार भोजपुर के डुमरी में आगमन तथा कान्य कुब्ज और शाकद्वीपी ब्राह्मणों के विवाद में पंडित देवराज चतुर्वेदी द्वारा आमंत्रित *"भूमिहार ब्राह्मण परिचय"* की आय से भूमिहार ब्राह्मण प्रेस (काशी) की स्थापना तथा इसी प्रेस में *"भूमिहार ब्राह्मण"* मासिक को छपना।

1918 ई. कोटवा नारायणपुर (बलिया, गाजीपुर सीमा) में निवास, *"गीता और तिलक"* शीर्षक लेख, *"भूमिहार ब्राह्मण"* के कई अंको में प्रकाशित। *"गीता हृदय"* लिखने का श्री गणेश करना।

1919 ई. सिमरी (आरा) आकर पुनः विश्वंभरपुर (हाजीपुर) वापस।

1920 ई. 5 दिसम्बर को पटना में श्री मजहरुलहक के निवास पर ठहरे, महात्मा गांधी से राजनीतिक बातों तथा राजनीति में प्रवेश का निश्चय कर कांग्रेस में शामिल।

1921 ई. गाजीपुर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना तथा अहमदाबाद कांग्रेस में शामिल होना।

1922 ई. 2 जनवरी को गिरफ्तार होकर एक वर्ष का कारावास।

1923 ई. जेल से छूटने पर सिमरी (भोजपुर) में निवास।

1924 ई. सिमरी तथा आसपास, अपने प्रयत्न से खादी वस्त्रोत्पादन के लिए 500 चर्खे तथा 4 करघे का चलवाना प्रारंभ। सिमरी में चार महीने में *"कर्मकलाप"* (1200 पृष्ठों का) हिन्दी में विधि सहित विशाल ग्रंथ की रचना।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

1925 ई. काशी में आयोजित "संयुक्त प्रांतीय भूमिहार ब्राह्मण सभा" में भूमिहार ब्राह्मण द्वारा पुरोहित करने से संबंधित भाषण। "*भूमिहार ब्राह्मण परिचय*" का परिवर्तन कर "*ब्रह्मर्षि वंश विस्तर*" नाम से प्रकाशन।

1926 ई. "*कर्मकलाप*" का काशी में प्रकाशन (अमिला, घोषी, आजमगढ़ में आयोजित भूमिहार ब्राह्मण महासभा में भाषण तथा संस्कृत शिक्षा प्रचार का संदेश।

1927 ई. समस्तीपुर से आकर पटना जिले के बिहटा में श्री सीताराम दास जी द्वारा प्रदत्त भूमि में श्री सीताराम आश्रम बनाकर स्थायी निवास तथा पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना।

1928 ई. सोनपुर में 17 नवम्बर को सम्पन्न, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया।

1929 ई. अंतिम बार मुंगेर की 'अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासभा' में सम्मिलित मतभेद के कारण वापस।

1930 ई. विक्रम (पटना) में 26 जनवरी को नमक कानून भंग के कारण 6 माह का कारावास। हजारीबाग जेल में "*गीता हृदय*" की रचना। जेल से लौटकर कांग्रेस तथा किसान सभा के कार्यों में संलग्न होना।

1934 ई. भूकम्प पीड़ितों की सेवा हेतु बिहार में समिति गठित कर सेवा कार्य का संचालन।

1935 ई. पटना जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रादेशिक कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सदस्य चुना गया।

1936 ई. अखिल भारतीय किसान महा-सभा का गठन तथा प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष पद ग्रहण (लखनऊ)।

1937 ई. 13 मई से 15 मई तक सम्पन्न अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष (कोमिला, बंगाल)।

1939 ई. अखिल भारतीय किसान-सभा के महामंत्री निर्वाचित तथा 1943 तक उक्त पद पर अवस्थित।

1940 ई. (19-20 मार्च) को रामगढ़ में श्री सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में आयोजित अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में स्वागताध्यक्ष। उपर्युक्त सम्मेलन में भाषण के लिए तीन वर्ष का कारावास।

1941-43ई. जेलों में कई पुस्तकों की रचना।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

1944 ई.	14-15 मार्च को विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष।
1948 ई.	6 दिसम्बर को कांग्रेस की प्राथमिक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस की सदस्यता का त्याग तथा साम्यवादी सहयोग से किसान मोर्चा का संचालन।
1949 ई.	महाशिवरात्रि को बिहटा (पटना) में हीरक जयंती समारोह समिति द्वारा साठ लाख रुपये की थैली का भेंट तथा उसका तदर्थ दान। 9 अप्रैल (रामनवमी) को अयोध्या में सम्पन्न अखिल भारतीय विरक्त महामंडल में प्रथम अधिवेशन में शंकराचार्य के बाद अध्यक्षीय भाषण।
1950 ई.	अप्रैल में रक्तचाप से विशेष पीड़ित होकर प्राकृतिक चिकित्सार्थ डा. शंकर नायर, (मुजफ्फरपुर) से चिकित्सा प्रारम्भ। मई-जून में अपने अनन्य अनुयायी किसान नेता प. यमुना कार्यी (समस्तीपुर) के निवास पर निवास।
26 जून, 1950	पुनः डा. नैयर को दिखाने आने पर मुजफ्फरपुर में ही पक्षाघात का आक्रमण तथा 26 जून की रात्रि दो बजे प्रसिद्ध वकील पं. मुचकुन्द शर्मा के निवास पर देहान्त।
27 जून,	शव का पटना गांधी मैदान में लाखों लोगों द्वारा अंतिम दर्शन। डा. महमूद की अध्यक्षता में शोक सभा, अन्य नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि।
28 जून	डा. श्री कृष्ण सिंह, मुख्यमंत्री तथा अन्य नेताओं का अर्थी के साथ श्री सीताराम आश्रम (बिहटा) में पहुंचना तथा वहीं अन्तिम समाधि। डा. राजेन्द्र प्रसाद आदि का शोक संदेश।
संदर्भ	चौधरी राजनारायण शर्मा विशारद "स्वामी जी का जीवन घटना क्रम" *स्वामी सहजानन्द सरस्वती, ज्योति कलश* (स्वामी सहजानन्द सरस्वती विकास सेवा संस्थान, ठाकुर नर्सिंग होम परिसर, मुजफ्फरपुर, 842001, 1984, पृ. 60-62

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिशिष्ट-2

अखिल भारतीय किसान-सभा की नियमावली

(अखिल भारतीय किसान कमेटी की नियामतपुर, बिहार, 14-15 जुलाई की बैठक द्वारा स्वीकृत।)

धारा-1 इस संस्था का नाम "अखिल भारतीय किसान-सभा" है।

धारा-2 "जनता को आर्थिक और राजनीतिक शोषणों से हर तरह का छुटकारा मिलने के साथ ही उसके हाथ में पूर्ण रूप से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति आ जाय" यही किसान-सभा का लक्ष्य है।

धारा-3 इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये किसान-सभा किसानों को उनकी तात्कालिक मांगों के आधार पर संगठित करेगी और उनकी प्रतिदिन की लड़ाइयों को चलायगी ताकि अन्य शोषित और पीड़ित दलों के साथ मिलकर किसान पूर्ण स्वतंत्रता के राष्ट्रीय युद्ध में भाग लें और उसे जबर्दस्त बनायें।

धारा-4 अखिल भारतीय किसान सभा के अंग ये हैं:

1. प्रारम्भिक सदस्य
2. प्रांतीय किसान संस्थाओं के नियमानुसार संगठित थाना, तहसील या अन्य स्थानीय किसान संस्थायें,
3. जिला किसान संस्थायें,
4. प्रांतीय संस्थायें,
5. अखिल भारतीय किसान कमेटी,
6. केन्द्रीय किसान कांउसिल और
7. अखिल भारतीय किसान सभा का वार्षिक अधिवेशन।

धारा-5 18 वर्ष या अधिक उम्र का कोई आदमी जो 2,3 धाराओं के मंतव्यों में विश्वास करें, इस बात की लिखित प्रतिज्ञा करें और मेम्बरी फार्म पर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हस्ताक्षर करें साधारणतया अधिक-से-अधिक एक आना सालाना चन्दा देने पर अखिल भारतीय किसान-सभा का सदस्य होगा और इसी काम के लिये अधिकार प्राप्त किसी भी कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा लेगा। लेकिन कोई भी आदमी एक ही समय दो कमेटियों का प्रारम्भिक सदस्य नहीं हो सकता।

धारा-6 अखिल भारतीय किसान-सभा का कार्य क्षेत्र देशी रियायतों के सहित समस्त भारतवर्ष होगा।

धारा-7

(क) किसी चुनाव की तिथि से पूर्व लगातार एक साल तक जिस सदस्य का नाम मेम्बरों के रजिस्टर में दर्ज न हो वह उस चुनाव में मत नहीं दे सकेगा।

(ख) पूर्व उपधारा (क) के अनुसार मतदाता होने पर भी कोई आदमी किसी कमेटी की मेम्बरी या किसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता यदि (1) वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमींदार साहुकार आदि शोषक वर्ग की आर्थिक या राजनीतिक संस्थाओं या इस वर्ग के स्वार्थ साधकों की सभाओं का सहायक हो, या (2) जो 2-3 धारा के भावों और सभा के द्वारा समय-समय पर स्वीकृत कार्यक्रम के विरुद्ध काम करता हो।

धारा-8

(क) अखिल भारतीय किसान-सभा के वार्षिक अधिवेशन के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक से अधिक दो हजार होगी जिसमें देशी रियायतों के प्रतिनिधि 500 से ज्यादा न होंगे।

(ख) देशी रियासतों को केन्द्रीय किसान कौंसिल बीस विभागों में बांटेगी और हर विभाग 25 से ज्यादा प्रतिनिधि भेज न सकेगा। लेकिन केन्द्रीय किसान कौंसिल इन संख्या को घटा बढ़ा सकेगी और हर विभाग को अधिकार होगा कि वहां कोई भी स्वीकृत किसान संस्था होने पर कम से कम प्रतिनिधि अवश्य भेजें।

(ग) हर प्रांत ज्यादा से ज्यादा 100 प्रतिनिधि भेजेगा लेकिन प्रारम्भिक मेम्बरों की संख्या का विचार किये बिना ही हर प्रांत को हर हालत में 10 प्रतिनिधि भेजने का हक होगा और चुनाव के लिये केन्द्रीय किसान कौंसिल समय-समय पर नियम बनायेगी।

(घ) किसान-सभा के 200 सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि चुनेंगे यदि

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

इसमें इसी धारा को उपधारा (क) किसी प्रकार बाधक न हो। आवश्यकतानुसार केन्द्रीय किसान कौंसिल इस 200 की संख्या को बढ़ायेगी।

(ङ) केन्द्रीय किसान कौंसिल के द्वारा निर्धारित तिथि तक जो प्रांत अपने प्रतिनिधि न चुनेगा किसान-सभा के वार्षिक या दूसरे अधिवेशनों में अपने प्रतिनिधि भेज न सकेगा।

(च) इस प्रकार चुने गये हर प्रतिदिन आठ आना प्रतिनिधि शुल्क देकर ही अपने अधिकारों को काम में ला सकेंगे।

धारा-9

(क) प्रतिनिधियों के चुनाव के बाद 5 या अधिक प्रतिनिधि मिलकर वार्षिक अधिवेशन के सभापतित्व के लिए किसी प्रतिनिधि की नामजद कर सकते हैं, बशर्ते कि यह नामजदगी केन्द्रीय किसान कौंसिल के पास निश्चित तिथि तक पहुंच जाय।

(ख) अखिल भारतीय किसान सभा का प्रधानमंत्री वार्षिक अधिवेशनों के सभापतित्व के लिये इस प्रकार प्राप्त नामजद सज्जनों की सूची प्रकाशित कर देगा और एक तिथि नियत करेगा जिस दिन हर प्रांत के प्रतिनिधि अपने-अपने प्रांत में एक निश्चित स्थान पर जमा होकर नीचे लिखे काम करेंगे। (1) वार्षिक अधिवेशन के सभापति का चुनाव; (2) अपने ही में से निर्धारित संस्थायें अखिल भारतीय किसान कमेटी के सदस्यों का चुनाव।

(ग) ज्योंही प्रधानमंत्री की सभापतित्व के (1) लिये नाम और हर नाम के लिये दिये गये प्रांतों के वोटों की तादाद मिल जाए उसके बाद जितनी जल्दी हो सके के.कि.कौं. सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को सभापति घोषित करेगी। (2) उस प्रकार चुने सभापति की मौत, इस्तीफा आदि हो जाने पर अखिल भारतीय किसान कमेटी सभापति चुनेगी।

धारा-10 अखिल भारतीय किसान कमेटी के सदस्य प्रति दस प्रतिनिधि या उसके भाग पर एक के हिसाब से चुने जायेंगे।

(क) कमेटी सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 200 होगी जिसमें देशी रियासतों के 50 से ज्यादा न होंगे।

(ख) हर सदस्य को वार्षिक शुल्क एक रुपया देना होगा जिसके बिना ये भाग न ले सकेंगे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(ग) हर प्रांत से कम से कम एक सदस्य अवश्य चुना जाएगा बशर्ते कि वहां कोई स्वीकृत किसान संस्था हो।

(घ) अखिल भारतीय किसान-कमेटी के सदस्य एक वर्ष के लिये चुने जायेंगे। लेकिन नये चुनाव में फिर खड़े हो सकेंगे। एकबार चुने गये मेम्बर तब तक उस पद पर रहेंगे जब तक नये मेम्बरों की बैठक नहीं होती। साल के बीच में किसी वजह से मेम्बर की जगह खाली होने पर उसकी पूर्ति प्रांतीय किसान सभायें करेंगी। लेकिन जो अखिल भारतीय किसान सभा फैजपुर में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रस्ताव के द्वारा बनी है वह अप्रैल, 1938 तक या जब तक अगला वार्षिक अधिवेशन न हो काम करेगी।

धारा-11

(क) केन्द्रीय किसान कौंसिल-अखिल भारतीय किसान कमेटी के पदाधिकारियों को मिलाकर कुल 21 सदस्यों की होगी उनके सिवाय चार स्थानापन्न मेम्बर भी होंगे। कोरम 7 होगा।

(ख) सभापति के अलावा इन सभी मेम्बरों का चुनाव अखिल भारतीय किसान कांग्रेस करेगी।

(ग) केन्द्रीय किसान कौंसिल के सदस्य एक वर्ष के लिये चुने जायेंगे और जब तक नई कौंसिल की बैठक नहीं होती वे बराबर काम करते रहेंगे।

धारा-12

(क) केन्द्रीय किसान कौंसिल के द्वारा निर्धारित तिथि और समय यदि वह बढाया न जाए, तक हर प्रांतीय किसान सभायें अपने यहां दर्ज प्रारम्भिक सदस्यों की प्रामाणिक संख्या प्रधानमंत्री के पास भेज देगी।

(ख) जो सदस्य नियमित रूप से दर्ज होंगे वही प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग ले सकेंगे।

(ग) केन्द्रीय किसान कौंसिल के द्वारा निश्चित तिथि तक प्रतिनिधियों और अखिल भारतीय किसान कमेटी के सदस्यों की सूची हर प्रांत से कौंसिल को पहुंच जानी चाहिए। लेकिन ऐसा न होने पर दशा विशेष में कौंसिल अपने असाधारण अधिकार से काम लेकर पीछे से भेजी सूची के प्रतिनिधियों और मेम्बरों को भी वार्षिक अधिवेशन की अखिल भारतीय किसान कमेटी की बैठक में भाग लेने का हक दे सकती है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

धारा-13

(क) अखिल भारतीय किसान-सभा का सालाना जलसा पूर्व अधिवेशन में निश्चित समय और स्थान पर ही आमतौर से होगा लेकिन असाधारण स्थिति में के.कि.कौं. दूसरे समय और स्थान पर होने का भी निश्चय कर सकती है।

(ख) वार्षिक अधिवेशन सभापति और प्रतिनिधियों को मिलाकर ही माना जाएगा

धारा-14 जिस प्रांत में वार्षिक अधिवेशन होगा वहां की प्रांतीय किसान-सभा उसके लिए आवश्यक प्रबंध करेगी और उसके लिए एक स्वागत समिति बनायगी। जिसके सदस्य वे लोग भी हो सकते हैं जो प्राथमिक किसान-सभा के मेम्बर न हों।

धारा-15

(क) वार्षिक अधिवेशन से कम से कम दो दिन पूर्व अखिल भारतीय किसान कमेटी की बैठक विषय समिति के रूप में मनोनीत सभापति की अध्यक्षता में होगी।

(ख) विषय समिति कार्यक्रम पर विचार करेगी और खुले अधिवेशन के प्रस्ताव तैयार करेगी।

धारा-16 हर वार्षिक अधिवेशन में नीचे लिखे क्रम में काम होगाः

1. विषय समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव,
2. ऐसे मूल प्रस्ताव जो उपधारा (1) में न आये, लेकिन विषय समिति के कम से कम जिसके दस सदस्य समर्थक हों और खुले अधिवेशन के प्रारम्भ होने से पूर्व दो प्रांतों के पांच प्रतिनिधि जिनके पेश करने की लिखित प्रार्थना सभापति के पास भेज दें।

धारा-17 प्रधानमंत्री के.कि.कौं. में सालाना रिपोर्ट और आय व्यय का हिसाब ओडिटर की रिपोर्ट के साथ पेश करेंगे। इसके बाद वह अखिल भारतीय किसान कमेटी में स्वीकृति के लिए पेश की जायगी। जब तक कोई ओडिटर का काम करे तब तक वह के.कि.कौं. या अखिल भारतीय किसान कमेटी का सदस्य न होगा।

धारा-18

(क) के.कि.कौं. या तो अपने ही विचार से या तीन या अधिक प्रांतीय किसान कमेटियों, जो स्वीकृति हो, की सम्मिलित प्रार्थना पर अखिल भारतीय किसान-सभा के विशेष अधिवेशन करायेगी, यदि इस

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मामले पर वह अखिल भारतीय किसान कमेटी की राय लेना न चाहे। विशेष अधिवेशन का समय और स्थान परिस्थिति के अनुसार के.कि.कौ. या अखिल भारतीय किसान कमेटी तय करेगी।

(ख) उस वर्ष के सभापति और प्रतिनिधि ही विशेष अधिवेशन के भी सभापति और प्रतिनिधि होंगे।

धारा-19

(1) अखिल भारतीय किसान-सभा का सभापति साल भरके लिए एक बार विधान में उक्त नियमों के अनुसार चुना जायगा और जब तक नया सभापति चुना जाकर उस पद को ग्रहण नहीं करता वह उस पद पद रहेगा।

(2) अखिल भारतीय किसान-सभा का सभापति ही उतने समय के लिए के.कि.कौं, अखिल भारतीय किसान कमेटी का भी सभापति होगा। उसकी अनुपस्थिति में उस बैठक के लिए कमेटी या कौंसिल का कोई भी सदस्य आवश्यकतानुसार चुना जायगा।

धारा-20

(क) केन्द्रीय किसान कौंसिल, अखिल भारतीय किसान सभा और किसान कमेटी का कार्यकारिणी कमेटी होगी और इसीलिये उनके द्वारा निर्धारित नीति और कार्यक्रम को पूरा करने का उसे अधिकार होगा। उन्हीं के प्रति वह जवाबदेह होगी।

(ख) के.कि.कौ. को अधिकार होगा कि वह (1) उपनियम बनायें, विधान का अर्थ लगायें और अ.भा.कि.क. और सभा की मातहती में ऐसी हिदायतें जारी करे जिसमें विधान कार्यान्वित हो। वह ऐसी हिदायतें भी दे सकती है जिनका उल्लेख कहीं न हो। (2) के.कि.कौं. कम से कम हर छः महीने में एक बार बैठेगी।

धारा-21

(क) सभापति और धारा 10 के अनुसार चुने गए सदस्यों की ही अखिल भारतीय किसान कमेटी होगी।

(ख) अखिल भारतीय किसान-सभा के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की वह कमेटी पूर्ण करेगी और इसके कार्य काल में जो नई बातें आ जायें उन्हें भी सुलझायेंगी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिशिष्ट-3

13 फरवरी, 1942 को अखिल भारतीय किसान कौंसिल द्वारा पारित नागपुर-प्रस्ताव

पिछले साल लड़ाई में सोवियत रूस के शामिल हो जाने से दुनिया के सभी लोगों के लिये इस लड़ाई के महत्व और इसकी अहमियत में गहरी तबदीली हो गई है। जनतंत्र शासन, जम्हूरियत और सोशलिज्म के जबर्दस्त गढ़ सोवियत रूस पर होने वाले हमले का जो शानदार मुकाबला वहां की लाल फौजें कर रही हैं उससे सभी लोगों में यह उम्मीद हो आई है कि फासिस्ट ताकतों के जड़ मूल से बर्बाद हो जाने पर एक निराली दुनियां बनेगी जिसमें साम्राज्यवाद, शाहंशाहियत की ताकतें नेस्तनाबूत हो जायंगी, न्यायं और इन्साफ की बिना पर-उसी आधार पर-समाज और सोसायटी की बुनियाद शुरु की जायगी और गुलाम लोगों की जंजीरें चकनाचूर हो जायंगी। तभी से फासिज्म के खिलाफ मिल के लड़नेवाले सभी मुल्कों के लोग सोवियत रूस को अगुआ बना कर तेजी से आपस में मिलते जा रहे हैं ताकि मानव समाज और इन्सानों के सबसे बड़े दुश्मन को रत्ती-रत्ती तबाह करने के लिए एक साथ कोशिश की जा सके और दुनिया की आजादी हासिल हो सके। इससे हिटलर और उसके दोस्तों को ताज्जुब और घबराहट हो रही है।

एक हजार मील लंबे मोर्चे पर रूसी फौजें और वहां के लोग जो लासानी लड़ाई लड़ रहे हैं वह मानव-समाज के इतिहास में हिम्मत और बहादुरी की एक निहायत ही आला और शानदार चीज है। यह तो सोशलिष्ट राष्ट्र और मुल्क के ही लोगों का काम है कि अपने मुल्क और अपनी जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए ऐसी अनोखी बहादुरी के साथ ऐसे खूनी हमलों का सामना कर सके। खासकर रूसी किसानों, लुक छिप के लड़ने वालों, उनकी औरतों और यहां तक कि उनके बच्चों को भी यह हालत है कि अपनी कमाई को सोलह आने खुंद ही भोगते रहने की वजह से अपने मुल्क के लिए लड़नेवालों में वे सबसे बहादुर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

साबित हो रहे और शहीद बन रहे हैं। उन्होंने जो गैर मामूली करामातें की हैं, उनकी कहानियों से यहां के करोड़ों-करोड़ किसानों के ख्यालों में बिजली और दिलों में जोश दौड़ जाना चाहिये जिससे हमारे अपने मुल्क के सभी लोगों के साथ समाज और सोसाइटी के भीतर इन्साफ हो और सर्वों की आजादी मिलने के लिये पूरी कोशिश की जा सके।

रूस पर होनेवाले हमने के कारण लड़ाई की मुसीबतें हिन्दुस्तान के भी दरवाजे खटखटाने लगी हैं। हिटलर के जो फासिस्ट गिरोह के रूस में खून-खराबा और बर्बादी मचा रहे थे वे अभी-अभी रोके जा सके हैं और सोवियत फौजों ने जो अपने शानदार हमले जारी किए हैं उनके चलते उन फासिस्ट फौजों को लेनिनग्राद, मास्को, रोस्तोक और सेवास्तोपोडल के पड़ोस से पीछे भागने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिर भी काकेशस और ईरान में मिलने वाले तेल की उसे बहुत ज्यादा जरूरत होने के कारण हिटलर की आंखें उस पर लगी है। यह भी कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के लोगों और यहां की सभी चीजों पर अड्डा जमाने के भी मंसूबे उसने बांध रक्खे हैं।

पूरब में लगातार चार साल की खूंखार लड़ाई के बाद भी जब जापान-चीन के निराले मुकाबले का जवाब न दे सका तो उसे दक्खिन-पूरब प्रशान्त सागर (पेसिफिक) के मुल्कों पर बेरहमी के साथ हमला शुरु करके एशिया और आस्ट्रेलिया पर अपनी हुकूमत जमाने की आखिरी बाजी लगाई है। हिन्दुस्तान के पड़ोसी मुल्कों पर दगाबाजी के साथ हमला करने से शुरु-शुरु में जो कामयाबी उसे मिली है उससे लड़ाई की आफतें हमारे दरवाजे तक आ पहुंची है और लोगों में यह खौफ समा गया है कि हम कुछ कर-धर सकते ही नहीं।

एक ओर फौजी चाल और साम्राज्य की हिफाजत का ख्याल और दूसरी ओर ब्रिटेन और अमेरिका की आजादी चाहनेवाले आमलोगों का दबाव, इन दोनों बातों के चलते मुल्कों को फासिस्टों के खिलाफ लड़ने के लिए रूस और चीन की कतार में खड़ा होना पड़ा है। इसलिए हालत ऐसी हो गई है कि अबतक सोवियत रूस के मुतल्लिक इंग्लैंड और अमेरिका के इरादों के बारे में लोगों का जो शकशुभा था वह जाता रहा। इसका नतीजा यह हुआ है कि ब्रिटेन और अमेरिका की पूंजीवादी सरकारों से अब रूस और चीन की आम जनता की सरकारों के साथ एक जबरदस्त समझौता इसलिए किया है कि फासिज्म के इस शैतान का खात्मा किया जा सके जो स्पेन से लेकर काकेशस हो के हिन्दुस्तान और आस्ट्रेलिया तक के लंबे मोर्चे पर लड़ रहा है। सोवियत रूस की शानदार जीत और फौजी ताकत ने फासिस्टों के खिलाफ लड़ने वालों के बीच उसके लिए पक्की इज्जत की जगह

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हासिल कर ली है और यहां उस बात की गारंटी भी है कि आजादी जम्हूरियत और तरक्की चाहनेवाली ताकतों की ही आखिरी जीत होगी।

ऐसी हालत में सेन्ट्रल किसान कौंसिल यह महसूस करती है कि अब लड़ाई और उसकी कोशिशों के मुतल्लिक अपने रूख को बदलना ही उसके लिए मुनासिब है। शान्ति और अमन की तरह लड़ाई भी टुकड़ों में बांटी जा सकती नहीं; इसलिए रूस और चीन की और उनके दोस्तों की, जो दुनिया भर में उन्हीं दोनों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लड़ाई में कोई बनावटी फर्क नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भारत के क़िसानों पर रूस, चीन और उनसे मिली तरक्की पसन्द ताकतों और प्रगतिशील शक्तियों की कतार में खड़ा होने के लिये जोर देन और इस तरह फासिज्म के आखिरी खात्में के लिसे बेदर्दी के साथ लड़ाई चालू करने में इस कौंसिल को जरा भी हिचक नहीं है क्योंकि अगर नात्सी, जर्मनी और उसके साथियों की जीत हो जाय तो भारत के किसानों और आम लोगों की आजादी, आर्थिक और माली तरक्की और हिफाजत की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जायगी और उनपर भारी तबाही आ धमकेगी।

तानाशाह फासिस्ट मुल्कों के खिलाफ लड़ी जाने वाली यह अपने ढंग की जो निराली लड़ाई है वह तभी सफलता के साथ लड़ी जा सकती है जबकि खुशी-खुशी दिल खोल के सभी दलों और तबकों के लोग उसे सचमुच अपनी आजादी और भलाई के ही लिये लड़ें। जनता और आमलोगों की ऐसी ही लड़ाई बड़ी कामयाबी के साथ रूस और चीन में लड़ी जा रही है। इंग्लैंड, अमेरिका और उनसे मिले दूसरे मुल्कों में भी यह लड़ाई तेजी के साथ जनता की आजादी की लड़ाई बनती जा रही है। उसी तरह यह लड़ाई हिन्दुस्तान के आम लोगों की लड़ाई तभी बखूबी बन सकती है जब कि इसे यहां की कौमी राष्ट्रीय सरकार चलाये और जब उसमें चाह के साथ दिल खोलकर सभी लोग मदद करें।

इसी के साथ कौंसिल यह भी महसूस करती है कि मौजूदा हालत में भारत की अपार जन, धन, शक्ति और ताकत का इस्तेमाल इस लड़ाई को सफलता के साथ चलाने के लिए नहीं किया जा सकता है। स्वामी सहजानन्द सरस्वती, प्रो. रंगा, राहुल सांकृत्यायन और बाबा सोहन सिंह वगैरह किसान-सभा के हजारों लीडर और कार्यकर्ता अभी भी आर्डिनेन्सी हुकूमत के चलते जेलों में बन्द है। अमन और कानून के नाम पर सरकार नए-नए हुक्म रोज जारी करती जा रही है जिनसे लोगों के रोज के काम में रुकावटें खड़ी हो जाती है। बहुत जगह फसलों के कमवेश खराब हो जाने, बहुत सी किराने की चीजों में दाम बहुत ज्यादा गिर जाने और कारखाने की बनी चीजों के दाम बेहद बढ़ जाने के कारण करोड़ों किसानों और

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मजदूरों में बहुत ज्यादा बेचैनी फैली हुई है। मुल्क के रोजगार-व्यापार करनेवाले लोग भी इसलिए रंज है कि जब सब उन्होंने कल-कारखाने खोल के मुल्क की माली हालत सुधार की कोशिश की है तो सरकार ने अनगिनत रोड़े अटकायें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लड़ाई के बाद ही भारत आजाद हो जायगा उस बात की घोषणा और एलान अभी कर देने और फौरन यहां राष्ट्रीय सरकार कायम करने की जो मांग मुल्क ने पेश की है, उसके जवाब में सरकार ने एक तो गोलमोल बातें कही हैं; दूसरे वायसराय की कौंसिल में अपने मन से सिर्फ कुछ और मेम्बर बढ़ा दिये गये हैं और बहुत ही थोड़े राजनैतिक कैदी छोड़े गए हैं। यह कौंसिल महसूस करती है कि उस लड़ाई को सफलता के साथ चलाने और अपने मुल्क की रक्षा और हिफाजत करने के लिए भारत के करोड़ों लोगों को तैयार करने में आज जो सबसे बड़ी रुकावट है वह है भारत सरकार और सबों की सरकारों के नाम से बनी हुई गैर-जिम्मेदार और अपनी मर्जी से हुकूमत करनेवाली नौकरशाही, जिसके लिए इस मुल्क के करोड़ों आदमियों के दिलों में कोई माया-ममता नहीं है- जिससे उनका कोई भी दिली नाता नहीं है।

इसलिए हिन्दुस्तान की जनता अपनी आजादी को हासिल करने के अरमान और फासिज्म के खतरे को मिटा डालने की अपनी तमन्ना और ख्वाहिश को जिस तरह अमल में ला सकती है ठीक उसी बात का ख्याल करके यह कौंसिल सरकार पर जोर देकर कहती है कि वह फौरन नीचे लिखे काम करे:

(1) साफ शब्दों में यह एलान कर दें कि भारत को आजाद होने और लड़ाई के बाद फौरन ही अपनी हुकूमत का ढांचा (शासन विधान) खुद बनाने का पूरा हक है।

(2) फौरन भारत में ऐसी राष्ट्रीय सरकार कायम करे जो असेम्बली और भारत की जनता के समान जिम्मेवार हो।

(3) सूबों में जनता की बजारतें और मंत्रिमंडल कायम करे।

(4) सभी राजनीतिक, किसान और मजदूर कैदियों और नजर बन्दों को छोड़ दें।

(5) लोगों को अपने जायज कामों के करते रहने के लिए आजादी दे दें।

(6) ऐसी नीति और पालिसी अख्तियार करें जिससे तेजी से मुल्क में कल-कारखाने खुले, लड़ाइयों के लिए सभी हथियार तैयार हो सकें और जिन्दगी के लिए रोज की जरूरी चीजें इतनी बनें कि रहन-सहन ऊंची हो सके।

(7) मुल्क की बाहरी हिफाजत और भीतरी अमन के लिए जनता की फौज तैयार करके उसे हथियार दे।

(8) सभी तरह के दमन और दबाव डालने और सतानेवाले हुक्म और आर्डिनेंस हटा लें।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(9) किसानों पर जो लगान और टैक्स का नमुनासिब बोझ है उसे कम कर दे ताकि उनके दिलों में जोश हो और इस तरह यह लड़ाई जीतने की ताकत उनमें बढ़े।

(10) देहातों या शहरों में जो मजदूर काम करते हैं उन्हें चटपट आराम पहुंचाने के ख्याल से मंहगाई का भत्ता दिया जाए और गल्ले की सस्ती दुकानें खोली जावें।

यह कौंसिल इस मुल्क की कांग्रेस, मुसलिम लीग, आल इंडिया ट्रेड यूनियन आदि जमातों से भी जोरदार शब्दों में अपील करती है कि ऊपरी मांगों की बुनियाद पर मुल्क पे बड़े से बड़ा एका हासिल करें और उन्हें चटपट हासिल करने के लिए मिल जुलकर काम करें। इसी सिलसिले में वर्धा में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पास हुए प्रस्ताव के जो माने निकलते हैं उससे इस कौंसिल को इसलिए खुशी है कि अबतक जो हालत थी उससे कुछ तरक्की तो हुई-वह कुछ सुधरी तो सही। उसमें जो यह माना गया है कि इस लड़ाई में दुनिया को खतरा है जो व्यक्तिगत (शख्सी) सत्याग्रह को भी बन्द कर दिया गया है यह बात ठीक ही हुई है। लेकिन कौंसिल यह महसूस करती है कि सरकार क्या करती है सिर्फ इस बात पर नजर लगाने के बजाय कांग्रेस को चाहिए था कि कोई ऐसा रास्ता निकालती जिससे मौजूदा राजनैतिक झमेला मिट के कोई समझौता हो जाता। खासकर मुल्क की सबसे बड़ी राजनीतिक जमात होने के नाते कांग्रेस से यह कौंसिल दस्तखत करती है कि इस मामले में खुद आगे बढ़े और मुस्लिम लीग के साथ, हिन्दुस्तान की ओर सभी सूबों की भी सरकारों को बनाये जाने के बारे में कोई सुलह समझौता कर डाले ताकि मुल्क में यहां की लोगों की अपनी सरकार कायम न होने देने में ब्रिटिश सरकार के लिए आज जो बहाना मौजूद है वह जाता रहे क्योंकि इस कौसिल को यकीन है कि सभी दलों की मिलीजुली जो सरकारें भारत में और इसके सभी सूबों के कायम होगी और टिकने के काम करेगी वही इस मुल्क के लोगों और यहां की सभी चीजों को अच्छी तरह संगठित और तैयार कर सकती है जिससे भारत की रक्षा की जा सके, यह लड़ाई कामयाबी के साथ चलाई जा सके और फासिज्म का सत्यानाश तेजी से हो सके।

इसके सिवाय किसानों और किसान-कार्यकर्ताओं से भी जोर देकर यह कौंसिल कहती है कि वे नीचे लिखी निहायत जरूरी बातों पर ध्यान दें।

(1) इस प्रस्ताव में लड़ाई के मुतल्लिक कही गई बातों का प्रचार करना।

(2) रूस और चीन को सभी तरह की मदद पहुंचाना और सोवियत के दोस्तों की मण्डली और गिरोह जगह-जगह कायम करना।

(3) ऊपर लिखी राष्ट्रीय मांगों का लोगों में प्रचार करने में सभी लागों के साथ मिल-जुल कर काम करना।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(4) जगह-जगह की हालतों के मुताबिक मालगुजारी, लगान, कर्ज और दूसरी वसूलियों में छूट आदि के जरिये लोगों को आराम पहुंचाना।

(5) देहातों में अमन और शान्ति बनाए रहने के लिए कांग्रेस और दूसरी जमातों से मिलकर गांव, तालुका और जिले में पंचायतें बनाना और जनता के स्वयंसेवकों का तैयार करना।

(6) को-ओपरेटिव सोसायटियां कायम करना ताकि लोगों को उधार पैसे मिल सके, उनकी पैदावार नफे से कम न हो सके और जरुरत की चीजें आसानी से रास्ते में मिल सकें।

(7) भीतरी अमन और हिफाजत के लिए सभी जातियों और वर्गों के बीच दोस्ती और मेल बढ़ाना।

(8) खाने की चीजों, दूध, खेती, गोशालाओं की और भी चीजों की पैदावार बढ़ाने की कोशिश करना

(9) जगह-जगह पुराने कारोबारों को फिर से जगाना और जिलाना।

(10) इस खतरे के वक्त सभी कामों में अपने ऊपर भरोसा करना।

अन्त में यह कौंसिल भारत के किसानों पर जोर देती है कि मुल्क के इतिहास में किस्मत का फैसला करनेवाली इस घड़ी में मर्दानों और बहादुरों जैसा काम करें और कुछ देहातों में फैले खौफ और घबराहट की हालत को दूर करे। उन्हें अपने घर-बार की हिफाजत के लिय कन्धे से कन्धा भिड़ा हो जाना चाहिए। फासिस्टों के जरिये फैलाये गये वहशियाना और पाशविक दहशत के सामने चीन और सोवियत रूस के मर्दों और औरतों ने जिस निराली हिम्मत और बहादुरी का सबूत दिया है उसे हमें अपने दिलों में बैठा लेना होगा, अपने मुल्क की हिफाजत और रक्षा के लिए हमें अपने दिमाग को ठीक करना होगा, दिल को इस्पात बनाना होगा और धुन को और भी जबरदस्त कर पक्की बनाना होगा, ताकि हम मुस्तैदी के साथ ठिकाने से यह कार्य कर सकें क्योंकि जो किसान मजबूत और हिम्मत वाले हैं और अपने मुल्क और जमीन के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हैं वहीं आजादी के बेशकीमत विरासत और उत्तराधिकार को हासिल करके उसे बचा सकते हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिशिष्ट-4

मैंने कांग्रेस क्यों छोडी?

स्वामी सहजानन्द सरस्वती

अभी-अभी छः दिसम्बर को मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से और इसीलिए उसकी अखिल भारतीय कमेटी से लेकर नीचे की सभी कमेटियों की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है, लोग इसकी वजह जानना चाहें। इसलिए संक्षेप में उसे बता देना उचित मानता हूं।

1920 के दिसम्बर में नागपुर के अधिवेशन से लेकर आज तक मैंने कांग्रेस कभी नहीं छोड़ी और यथाशक्ति उसकी सेवा की है। बीच में नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस के साथ ही मेंरे जैसे ही कुछ तुच्छ व्यक्तियों को भी कांग्रेस से हटाया गया था जरूर; मगर इसमें हमारी मजबूरी थी। हम उस समय कांग्रेस छोड़ना चाहते न थे। आजादी की जंग के दर्म्यान ऐसा करना हम देश के साथ गद्दारी समझते थे, चाहे उसकी नीति के संबंध में हाई कमांड के साथ हमारा मौलिक मतभेद क्यों न था। उसी समय कांग्रेस के प्रमुख नेता साम्राज्यशाही से समझौता करने को परेशान थे। इसलिए उसने बम्बई वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में किसानों, मजदूरों एवं शोषित जनता की सीधी लड़ाइयों को बन्द कर देना तय कर दिया, बावजूद समस्त प्रगतिशीलों एवं वामपंथियों के सम्मिलित विरोध के। वे यह भी चाहते थे कि कांग्रेस में एक ही विचारधारा (होमोजेनिटी) रहे। यह खतरनाक बात थी। सुभाष बाबू के नेतृत्व में हमने इसका खुला प्रतिवाद किया, जिससे हाईकमांड हम सबों पर टूट पड़ा। लेकिन इतना तो हुआ कि कांग्रेस में एक ही विचार धारा लाने की कोशिश बंद हुई; कुछ समय तक तो जरुर ही।

कांग्रेस की दो बातें बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण रही हैं- आजादी की लड़ाई और उसका नेतृत्व। नागपुर में कांग्रेस ने जब करवट बदली, तो जंगे आजादी को–साम्राज्यशाही के विरोध में सीधी लड़ाई और प्रत्यक्ष युद्ध को–आगे रखा। यह परम्परा 1945 तक चली आई। यह बात 1921, 1930, 1932 और 1942 में

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

साफ देखी गई। 1934 और 1936-39 में उसने अप्रत्यक्ष या वैधानिक संघर्ष की ओर पांव बढ़ाया सही, फिर भी यही कह के कि यह उसी प्रत्यक्ष युद्ध का पोषक है; अंग है–इसी की तैयारी है। यह जंगे आजादी उसकी पहली बुनियादी और मौलिक चीज रही है। इसी के साथ नेतृत्व का भी प्रश्न रहा है। यह युद्ध था कांग्रेस का और इसलिए उसके द्वारा मुल्क का नेतृत्व किसके हाथों में रहे, कौन, कब, किस ओर मुल्क को, और कांग्रेस को भी, कैसे चलाए, यह सवाल उसकी दूसरी बुनियादी बात रही है। एक ही विचारधारा वाला झमेला इसी दूसरी बात का बाहरी रूप था जो उठकर दब गया और पहली ही आगे रही- ऊपर रही, 1945 वाले असेंबली के चुनावों के पूरे होने तक इसे कहने में अत्युक्ति नहीं है कि इन 25 वर्षों के दर्म्यान सब मिलाकर कांग्रेस योग-संस्था रही है, योगियों की चीज रही है–उन धुनी मतवाली, लगन के पक्के लोगों की जमात रही है जिन्होंने मुल्क की आजादी अपने प्राप्त की और उसके लिए सर्वस्व स्वाहा कर दिया। प्राणों तक की बाजी लगा दी अनेक यातनाएं झेली। योगी और साधक भी कभी-कभी चौंकते हैं। मगर इससे वे सच्चे योगी ही होते हैं। इस बीच भोगी लोग भी उसमें आसन जमाने की कोशिश करते थे आ घुसते थे। फिर भी वह बेशक योग संस्था ही रही।

लेकिन 1945 के चुनावों की समाप्ति के बाद उसमें पतन के चिन्ह दीखने लगे और 15 अगस्त, 1947 के आते न आते वह खांटी भोग संस्था, भोगियों जमायत उनका मठ बन गई। महात्माजी के उस समय के व्यथापूर्ण उद्‌गार इसे साफ बताते हैं। यही कारण है, उनमें अपने बलिदान के एक दिन पूर्व–29 जनवरी को– बेलाग एलान किया था कि कांग्रेस तोड़ दी जाए और उसका स्थान लोक सेवक संघ ले ले। सारांश, कांग्रेस जन योगी बने रहके अब उसे लोक सेवक संघ के रूप में बदल दें। यही बात वे लिख के भी दे गए–इसी की वसीयत कर गए। मगर भोगी लोग इसे कब मानते? उनने महात्मा की महान आत्मा को रुलाया और कांग्रेस की भोगवादिता पर कसके मुहर लगा दी। महात्मा चाहते थे, कांग्रेस चुनावों के पाप पंक में न फंसे, मगर उनके प्रधान चेलों ने न माना। कांग्रेस भोगियों का अड्डा बन गई, यह तो चोटी में नेता लोग साफ स्वीकार करते ही हैं। कौन-सी सार्वजनिक सभा नहीं है, जिसमें वे यह बात कबूल नहीं करते, सो भी साफ-साफ धिक्कार के साथ?

भोगवादिता के साथ ही कांग्रेस में एक ही विचारधारा वाला प्रश्न भी बड़ी तेजी से उठा और महात्मा जी महायात्रा के फौरन बाद ही दिल्ली वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में फैसला हो गया कि उसके भीतर के राजनीतिक दलों के लोगों के लिए नुमायश नहीं रही! ठीक ही है, ये राजनीतिक दल तो योगवादी ठहरे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

न? उन्हें शोषित-पीड़ित जनता को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता दिलानी है न? इसलिए उन्हें निरन्तर संघर्ष चलाना है न? फिर भोगियों के साथ उनकी पटे तो कैसे? यह फैसला, मेरे जैसों के लिए नोटिस थी कि कांग्रेस से भागो, भागो, भागो; फलतः एक प्रकार से मैंने तय कर लिया था कि अब उसमें नहीं रहना है क्योंकि जहां सांप का बिल, वहीं पूत का सिरहाना? मगर कोई जल्दबाजी न थी। इसलिए जब कांग्रेस के नए प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो मैंने प्रांतीय कांग्रेस के अधिकारियों से छः सात मास पूर्व ही लिखकर पूछा कि सार्वात्मना स्वतंत्र किसान सभावादी मेरे जैसा आदमी क्या उस पर हस्ताक्षर कर सकता है? यदि में हस्ताक्षर करूं तो क्या यह अनुचित होगा? मैंने और भी प्रश्न किए; मगर आज तक उत्तर नदारद। सिर्फ यही कहा गया कि आपका पत्र दिल्ली मंगा लिया गया है।

उधर कांग्रेस कमेटियों का वायुमंडल ऐसा विषाक्त हो गया है कि जैसा गला घुट जाए। कम-से-कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। एक नमूना पेश करता हूं। कांग्रेसी बजारतें 1937 में भी बनी थी और, 1939 तक हमने रेबड़ा जैसे बकाश्त संघर्ष चलाए। लेकिन कांग्रेस ने निकालने या अनुशासन की धमकी कभी न दी गई। यहां तक कि हमारे आदमियों ने असेंबली में भी कांग्रेस पार्टी की बात किसानों के मामले में मानी। फिर भी उनपर अनुशासन की तलवार न गिरी। मगर आज बड़ी मुस्तेदी से वकास्त संघर्ष रोका जाता है और एलान होता है कि कांग्रेसजन उसमें हर्गिज-हर्गिज न पड़े। यह संघर्ष ही किसानों एवं किसान सभा की जान ठहरी और कांग्रेस में रहके हम वही न करें, जान गंवा दे, यह कैसे होगा? यदि हमारी जमीन-जायदाद पर कोई लुटेरा धावा करे, तो भारतीय दंड विधान की आत्मरक्षा वाली धाराओं के अनुसार हम मारपीट एवं खून-खराबा भी कर सकते हैं और कांग्रेस में भी रह सकते हैं। मगर कांग्रेस के ही सिद्धांतानुसार शांतिपूर्ण लड़ाई, सत्याग्रह या संघर्ष करें, तो हमपर अनुशासन की तलवार पड़ेगी! यह अजीब बात है! यदि यह विषाक्त एवं गलघोटू वायुमंडल नहीं, तो आखिर है क्या? तब जानबूझकर हम गला घुटने दें क्यों? आत्महत्या करें कैसे?

कहा जाता है, कि कांग्रेस की ही सरकार है, मगर है दरअसल सरकार की ही कांग्रेस या यों कहिए कि सरकारी कांग्रेस। ठोस सत्य यही है। एक ताजा दृष्टांत काफी है। हाल में प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने बयान दिया कि ईख की कीमत फीमन दो रुपए से कम हर्गिज न हो। प्रांतीय कार्यकारिणी ने और खुद प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जो भी सर्वसम्मति से तय कर दिया कि दो रुपए से कम कीमत न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि चीनी के कारोबार के लिए भी घातक है। मगर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सरकार ने क्या किया? युक्त प्रांत में एक रुपए दस आने और बिहार में एक रुपए तेरह आने तय कर दिया ओर दिल्ली की सरकार ने इसी पर मुहर लगा दी! नहीं-नहीं, दिल्ली और यू.पी. की सरकारें तो सवा रुपए चाहती थी। अब बोलिए कि कांग्रेस की सरकार है या सरकार ही कांग्रेस? ऐसी दशा में कांग्रेस में रहना स्पष्ट ही सरकार परस्त बनना है और मेरे जैसा आदमी यह कैसे करेगा? क्या किसान मजदूर राज्य हो गया कि ऐसा करूं? जब कांग्रेस परस्ती के माने सीधे सरकार परस्ती हो गई, तब मेरे लिए वहां स्थान कहां? पटना के प्रधान न्यायाधीश के शब्दों में अधिकार ने शासकों को नीचे गिरा दिया, दूषित बना दिया। फिर दूषित परस्ती कैसी?

यह सभी बातें मन में महाभारत मचा रही थी। इतने में ऊंट की पीठ पर अंतिम तृण आ गया। दानापुर सबडिवीजन में जो असेंबली थी उप-चुनाव जनवरी के मध्य में होगा, उसके लिए उम्मीदवार चुनने में कांग्रेसी कर्णधारों ने देश सेवा को गर्दनिया दे त्याग-बलिदान को ताक पर रख खूनी जातीयता को ही तराजू बनाया और उसी पर तोलकर अपना उम्मीदवार घोषित किया। सभी जातियों के त्यागी, योगी धुनी लोग दानापुर इलाके में भरे पड़े हैं। मगर किसी की पूछ न हुई; हालांकि लाख अनुनय विनय की गई। हंसों का निपट निरादर करके कौवे की पुकार हुई और कम से कम मेरे लिए यह असाध्य था—ऊंट की कमर पर अन्तिम तृण था।

फलतः अब मैं कांग्रेस से हटकर दानापुर सबडिविजन से असेंबली वाले उप चुनाव में श्री रामचन्द्र शर्मा का दिल से समर्थक हूं और कहता हूं कि "लाल बक्स" में वोट दीजिए-दिलाइए।

—ओरिएण्ट प्रेस, पटना

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ग्रंथ एवं संदर्भ सूची

स्वामी जी की रचनाएं, भाषण एवं लेख आदि

किसान सभा के संस्मरण, (इलाहाबाद ब्लौक वर्क्स लि., 1947)

मेरा जीवन संघर्ष, (सीताराम आश्रम बिहटा, पटना, 1952)

द अदर साइड ऑफ दि शिल्ड (द न्यू टाइम्स प्रिंटरी बम्बई, 1938)

एवोलिसन ऑफ जमींदारी : हाउ टू एचीव इट (ओरियन्ट प्रेस पटना, 1946)

अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष के पद से दिया गया भाषण (1940 रामगढ़)

बिहार प्रदेश किसान सभा का 9वां वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण (शेरघाटी, गया)

ढ़काइच में दिया गया भाषण (12 मार्च, 1949)

इनआगरल एड्रेस एण्ड सेशन ऑफ द बंगाल प्रोविन्सियल स्टुडेन्ट कांफ्रेंस (मैमन सिंह, 1 जून, 1945)

बिहार प्रदेश किसान सभा के 14वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण, (21-22 जून, 1947)

झूठा भय और मिथ्याभिमान (हित चिंतक प्रेस, रामघाट काशी, 1916)

महारुद्र का महाताण्डव

जंग और आजादी की लड़ाई (12 फरवरी, 1942 नागपुर में अखिल भारतीय किसान सभा के केन्द्रीय किसान काउन्सिल में पारित प्रस्ताव)

मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? (एक हैन्डबिल)

13वें बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सभापति पद से दिया गया भाषण (वेरमों, हजारीबाग 29-30 जून, 1946)

केन ग्रोवर्स को-ओपरेटिव कांग्रेस पटना स्वागताध्यक्ष के रूप में दिया गया भाषण (पटना 7-8 अप्रैल, 1947)

ब्राह्मण समाज की स्थिति (सीताराम आश्रम, बिहटा पटना)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

क्रांति और संयुक्त मोर्चा (श्रमजीवी पुस्तकमाला बांकीपुर, पटना)
भूमिहार ब्राह्मण परिचय,
ब्रह्मर्षि वंश विस्तर, गीता हृदय, कर्म कलाप
किसान कैसे लड़ते हैं?
जमींदारी का खात्मा कैसे हो?
किसानों के दोस्त और दुश्मन
किसान क्या करें?
किसान को फंसाने की तैयारियां
किसानों! हाल में बने काश्तकारी कानून का विरोध करो
दसवें बिहार प्रान्तीय किसान सम्मेलन में सभापति के पद से भाषण (सोनपुर, 1943)
जमींदारी क्यों उठा दी जाय?
झारखण्ड के किसान
भूमि व्यवस्था कैसी हो?
किसान आंदोलन क्यों और क्या?
रेन्ट रिडक्सन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स?
खेत मजदूर
गया जिले में सवा दो मास
कांग्रेस तब और अब?
अब क्या हो?
क्षय?
अप्रकाशित डायरी
सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज और फाइलें
प्रोग्रेस ऑफ लैन्ड रिफार्म्स (योजना आयोग, दिल्ली, 1963)
इमप्लीमेंटेसन ऑफ लैण्ड रिफार्म्स (योजना आयोग, दिल्ली, 1966)
किसान संगठन सभा, गवर्नमेन्ट ऑफ बिहार एण्ड उड़ीसा पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट स्पेशल सेक्शन फाइल न.-281/1939
ऑफिस ऑफ कमिश्नर तिरहुत डिविजन, पोलिटिकल स्पेशल डिपार्टमेन्ट फाइल न.-1571/1917
गर्वमेन्ट ऑफ बिहार एण्ड उड़ीसा, पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट (स्पेशल सेक्शन) फाइल न.-33/1934
(लेटर फ्राम डिपुटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (सी.आई.डी.) टू दि चीफ

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सेक्रेटरी 31 मार्च, 1934।

फोर्टनाइटली रिपोर्ट ऑफ पटना कमिशन आन दि एग्रेरियन ट्रबल्स फॉर दि पेरियड इन्डिंग, 13 नवम्बर, 1938 (एम.सी.आर.ओ. 62/1938)

लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, बिहार फ्राम *चीफ सेक्रेटरी,* 10 जनवरी, 1939 *पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट (स्पेशल सेक्शन) फाइल न.-29(11)1939* शाहाबाद में कलक्टर का मुख्य सचिव बिहार सरकार को लिखा गया पत्र फाइल न. 34/1931

बिहार विधान-परिषद की कार्रवाही, (पटना 21 मार्च, 1947)

किसान सभा द्वारा प्रकाशित रचनाएं तथा दस्तावेज

बिहार प्रांतीय किसान सभा की नियमावली (कन्सटीट्यूशन ऑफ बिहार प्रांतीय किसान सभा मुजफ्फरपुर, यमुना कार्यी संयुक्त मंत्री, 1930)

स्वामी सहजानन्द सरस्वती का अखिल भारतीय किसान सभा के तीसरे अधिवेशन, कोम्मिला में *अध्यक्षीय भाषण*

स्वामी जी द्वारा अखिल भारतीय किसान-सभा के आठवे वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर दिया गया *भाषण* (विजयवाड़ा 14-15 मार्च, 1944)

किसान के दावे और कार्यक्रम का खरीता (बिहटा, पटना, 1949)

अखिल भारतीय किसान-सभा की नियमावाली (अखिल भारतीय किसान कोंसिल की नियामतपुर बैठक द्वारा स्वीकृत)।

अखिल भारतीय किसान सभा चतुर्थ अधिवेशन स्वागताध्यक्ष यदुनन्दन शर्मा का भाषण (9-10 अप्रैल, 1939)

बिहार प्रांतीय किसान सभा का घोषणा-पत्र (सीताराम आश्रम बिहटा, पटना)

पुस्तकें

डी. थार्नर तथा ए थार्नर, *लैण्ड एण्ड लेबर इन इंडिया* (एशिया प्रकाशन, 1965)

डी. थार्नर तथा ए थार्नर, *एग्रेरियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया,* (एलाइड, 1976)

पी. सुन्दरैया, *दि लैण्ड क्वेश्चन,* (अखिल भारतीय किसान-सभा 1976)

कार्ल मार्क्स, *कैपिटल* खण्ड-1 अध्याय-8 (प्रगति प्रकाशन मास्को)

डा. डी चैम्बर्स तथा जी.ई.मेंजी, *एग्रीकल्चरल रिवोल्यूसन* 1750-1880 (लन्दन, 1966)

गोसिन, *एग्रीकल्चरल ट्रेन्डस इन इन्डिया* 1891-1947 फिलाडेम्फिया, 1996) ए.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

के. बागची, *प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंन्डिया 1900-1939*, ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1972

टी.जे. थाइर्स, सम्पादक, *शेयर क्रोपिंग एण्ड शेयर क्रापर्स* (काल्स, लन्दन, 1982)

पी.सी. जोशी, *लैण्ड रिफार्म्स इन इन्डिया* (एलायड, दिल्ली, 1982)

एच नार्मन, *ओरिजिन्स ऑफ मोडर्न जापानिज इस्टेट्स* (पेथिएन, 1975)

ए. भादुरी, *लेवर एब्सोर्व्शन इन इन्डियन एग्रीकल्चर* (ए.आई.टी.ई.पी. बैंकाक, 1978)

मिसाल कालेखी, *प्राब्लेम्स आफ डेवेलप्ड इन नान सोशलिस्ट इकानामी* (सेन्टर फॉर रिसर्च ऑन अन्डर डेवेलप्ड इकानामिज, वर्सा, 1961)

जे. हैलीडे, *पोलीटिकल इकानामी जापानीज कैपिटालिज्म*, (पेथिएन बुक्स, 1957)

वीलिकट, *लैण्ड रिफार्म्स एण्ड इकानामिक डेवेलपमेंट इन चाइना*, (न्यूयार्क, 1974)

यू. पटनायक तथा एम. डिंग स्वामी, सम्पादक, *चेन्स ऑफ सवीच्यूड वाण्डेज एण्ड स्लेवेरी इन इंडिया* (संगम बुक, दिल्ली, 1985)

ए. मिश्रा, टर्म्स ऑफ ट्रेड एण्ड क्लास रिलेसन, (कास्स, 1977)

वी.के.आर.बी. राव, *इंडियन* नेशनल इन्कम 1950-1980 (सेल्स, 1983)

ई.एच.नार्मन, *जापान्स इमर्जेन्स एज ए मार्डन स्टेट*

एच. काल्बर्ट, *वेल्थ एण्ड वेलफेयर ऑफ पंजाब* (लंदन) 1936)

एम.आई डार्लिन्ग, *पंजाब पीजेन्टस इनप्रोस्पेरिटी एण्ड ट्रेड* (आक्सफार्डे यूनिवर्सिटी प्रेस, 1928)

आर. हिल्टन, सम्पादक, *ट्रान्जीसन फ्रोम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म* (टाटलेज एण्ड केग्रानपाल लंदन, 1959)

के.एस. पन्निकर, सम्पादक, *नेशनल एण्ड लेफ्ट मुवमेंट इन इंडिया* (विकास पब्लिकेशन हाउस दिल्ली, 1980)

डा. राजेन्द्र प्रसाद, *आत्म कथा* (साहित्य संसार, पटना, 1947)

अनुग्रह नारायण सिंह, मेरे संस्मरण, (कुसुम प्रकाशन, पटना, 1961)

अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, *बिहार प्रांतीय किसान-सभा की रपट* 1929-1935, पटना, 1935)

कौशल किशोर शर्मा, *वोमेन्स पार्टीसिपेसन इन पीजेन्टस इन बिहार* (अलीगढ़, 1982)

चन्द्रभूषण, *किसान आन्दोलन का विकास* (वाराणसी, 1986)

डी.ए. मैक्स हकर्ट, *कांग्रेस एण्ड दि राज*, (दिल्ली, 1977)

त्रिवेणी शर्मा सुधाकर, *स्वामी सहजानन्द स्मृति ग्रंथ* (पटना, 1983)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

त्रिवेणी शर्मा सुधाकर, *स्वामी सहजानन्द का वसीयतनामा* (ज्ञानगेह राजेन्द्र पथ गया, 1989)

त्रिवेणी शर्मा सुधाकर, *स्वामी सहजानन्द सरस्वती* (ज्ञानगेह राजेन्द्र पथ गया, 1988)

डा. राम किशोर चौधरी, *स्वामी सहजानन्द सरस्वती ज्योति कलश* (स्वामी सहजानन्द सरस्वती विकास सेवा संस्थान, ठाकुर नर्सिंग होम परिसर मुजफ्फरपुर, 1989)

विजय चन्द्र प्रसाद चौधरी (संपादक) *स्वामी सहजानन्द सरस्वती : ओंकार से हुंकार* तक, राहुल प्रेस, पटना, 1990

ईश्वरी प्रसाद (सम्पादक) *भारत का किसान आंदोलन*, ग्रामीण साहित्य माला, दिल्ली, 1993

अरविन्द नारायण दास, '*इन्डिया इन्वेन्डेन्ट : ए नेशन इन द मेकिंग*', मनोहर, 1994

कुछ निबन्ध

ए. थार्नर तथा डी. थार्नर, "कैपिटलिष्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया" *शीलिंग ऑफ मोर्डन इंडिया*, (एलाएड, 1981)

सुलेखा चन्द्र गुप्ताः "न्यू ट्रेन्डस आफ ग्रोथ इन इंडिया" *सेमिनार* अंक 38 (नई दिल्ली अक्टूबर, 1992), "सम आसपेक्ट्स आफ इंडियन एग्रीकल्चर" *एन्क्वायरी* अंक 6 नई दिल्ली, "इंडियाज एग्रेरियन स्ट्रकचर" *मनेस्ट्रीम*, 1966

यू. पटनायक, "क्लास डिफरेन्सियसन विदिन पीजेन्ट्री; एन स्पीच टू दि एनालिसिस आफ इंडियन एग्रीकल्चर "*इकोनिमिक एण्ड पोलिटिकल विकली*" खण्ड-9 अंक 39 (1976)

आर साहू, "एथियेरी आफ रेन्ट एण्ड एग्रेरियन रिलेसन्स" *इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल विकली* खण्ड-15, अंक-9 (1980)

एस. शिव सुब्रमण्यम, "एस्टीमेटस आफ अनपुट फार अनडिभाइटेट इंडिया" सम्पादक-वी.के. आर.बी. राव पेपर्स आन नेशनल इन्कम एण्ड एलायडं टापिक्स, खण्ड-1 (लन्दन, 1960)

ए. भादुरी, "एकानामिक वैक्वाडिनेश अन्डर सेमी फ्यूडालिज्म" *इकोनोमिक जर्नल* (1972)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मिसाल कालेसी, *"प्राबलेम्स आफ फिनान्सिंग इकोनोमिक डेवेलेप्मेन्टस, "इकानामिक रिव्यू*, 1955

के.एन.राज प्राइस बिहेवियर इन इंडिया 1949-1966: एन एक्सप्लानेटरी हाइपोथेसिस, *"इंडियन इकानामिक रिव्यू* (अक्टूबर, 1968)

यू. पटनायक, "आल्टनेटिव स्ट्रनेटिव स्टेटेजी आफ एग्रेरियन चेंज इन रिलेशन एण्ड डेवलपमेंट फाइनेस" (मार्क्स, किन्स तथा शुम्पीटर पर आइ.सी.एस. एस.आर. द्वारा आयोजित सेमिनार, जनवरी, 1984 दिल्ली में पढ़ा गया आलेख)

यू. पटनायक तथा एम. हिंग स्वामी "दि इवोल्यूसन आफ क्लास एग्रीकल्चर लेबरर्स इन इंडिया" *सोशल साइन्टिस्ट*, क्रमांक 122, (जुलाई, 1988)

यू. पटनायक "कन्ट्रीव्यूसन टू आउटपुट एण्ड मार्केटेबुल सरप्लस आफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टस बाई कल्टीवेटिंग ग्रुप्स इन इंडिया, 1960-61", इकानोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली (1976), पृष्ठ ए-90

वी.आई. लेलिन, "लैण्ड क्वेश्चन एण्ड रुख पुअर "क्लेक्टेड वर्क्स, खण्ड-19

एग्रेरियन क्वेश्चन इन एशिया टुवार्डस द क्लोज आफ नाइन्टीन सेंचुरी *क्लेक्टेड वर्क्स*, खण्ड-19, "दि एग्रेरियन प्रोग्राम आफ शोसल डेमाक्रेसी इन फर्स्ट एशियन रिजोल्यूसन" क्लेक्टेड वर्क्स-1905, 13

शीला भल्ला "नियू रिलेसन्स आफ प्रोडक्शन इन हरियाणा एग्रीकल्चर", *इकानामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली* खण्ड-9, संख्या-13 (मार्च, 1976)

विपिन चन्द्रा "पिजेन्ट्री एण्ड नेशनल इन्टग्रिसन इन कन्टेम्प्रेरी इंडिया" के.एन. पान्निकर सम्पादक-*नेशनल एण्ड लेफ्ट मुवमेन्ट इन इंडिया* विकास पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 1980)

निर्मल सेन, "*कास्ट एण्ड पोलिटिक्स इन बिहार*" गैल सम्पादक, लैण्ड *कास्ट पोलिटिक्स* इन *इन्डिया*

उत्सा. पटनायक, "कृषि का सवाल और भारत में पूंजीवाद का विकास" सांचा, (मार्च, 1988)

पी-एच.डी. थेसिस

आर्गनाइजेसन बेसिस आफ इंडिया एग्रीकल्चर विद स्पेशल रिफरेन्स टू दि डेवेलपमेंट आफ कैपिटालिस्ट प्रोडक्शन (आक्सफोर्ड, 1972 प्रकाशित)

मंजीत सिंह, *माइग्रेट लेवर इन रुरल पंजाब* (एम. फिल शोध प्रबन्ध, पंजाब यूनिवर्सिटी)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

वाल्टर हाउजर "बिहार प्रीमिन्सियल किसान सभा, (1929-1942) ए स्टडी आफ एन इंडियन पीजेन्ट मूवमेन्ट (शिकागो विश्व विद्यालय)

रेणु कुमारी शर्मा, *स्वामी सहजानन्द सरस्वती और बिहार का किसान आंदोलन* (बिहार यूनिवर्सिटी, 1981)

कौशल किशोर शर्मा, *एग्रेरियन प्रावलेम्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस एण्ड दि पीजेन्टस मुवमेन्ट इन बिहार* (अप्रकाशित, 1985)

पत्रिका एवं समाचार पत्र

जर्नल आफ पीजेन्ट स्टडीज (अक्टूबर, 1982, जनवरी से अप्रैल, 1983, अक्टूबर, 1984)

सोशल साइंटिस्ट न. 138, (दिसम्बर, 1984)

इंडियन इकानामिक रिव्यू खण्ड-3, अंक-2

इकानामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खण्ड-20 संख्या-16 (20 अप्रैल, 1985 तथा दिसम्बर 4, 11 और 18, 1982)

दि इंडियन नेशन (पटना 16 नवम्बर, 1937)

जनता (16 अगस्त, 1939)

हुंकार (9 दिसम्बर, 1941, 3 जनवरी, 1942, 23 मार्च, 1943 तथा 2 जनवरी, 1949)

सर्चलाइट, पटना, 9 दिसम्बर, 1948, 15 मार्च, 1947, 22 अगस्त, 1947, 7 जून, 1947

सर्चलाइट तथा *इंड़ियन नेशन* पटना (1947 के विभिन्न अंक)

ब्रह्मर्षि संदेश (ब्रह्मर्षि समाज, कानपुर, मार्च 1986)

निवेदिता (स्वामी सहजानन्द सरस्वती जन्मशती विशेषांक स्वामी सहजानन्द सरस्वती विद्यापीठ महाविद्यालय गाजीपुर, कल्पना प्रेष, राम कटोरा रोड वाराणसी 1987-88 और 1988-89)

नवयुग (मार्च, 1990)

भूमिहार ब्राह्मण, काशी, कलकत्ता

कल्याण, (गोरखपुर)

विशाल भारती, (कलकत्ता)

कृषक, *लोकसंग्रह* (समस्तीपुर)

इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पत्राचार आदि हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अनुक्रमणिका

अ

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 152, 201,206,207, 208, 216

अखिल भारतीय किसान सभा 22, 24, 111, 115, 152, 186, 187,194, 203, 208

अखिल भारतीय कायस्त महासभा 68

अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासभा 7,11

अगस्त क्रान्ति 28

अग्नि बीमा 165

अच्चयुतानन्द 2, 4, 52, 182, 199

अजमेर 4, 161, 182

अथर्ववेद 45

अर्द्ध सर्वहारा 106

अद्ध सामंतवादी 4

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन 148

अनूप शहर 182

अप्रत्यक्ष कर 163

अपार नाथ मठ 4, 11

अप्रैल थेसिस 146

अबुल रसूल 70

अभिजात्य वर्ग 155

अमवारी 29

अमावा स्टेट 22, 60, 75, 114

अमेरिका 102, 210

आयाचक ब्राह्मण 8

अयोध्या सिंह 47

अरविन्द नारायण दास 192

अल्पमत क्रान्ति 103, 104

अवधेश प्रसाद सिंह 48

अश्विनी कुमार 69

अशोक कुमार 44

अहमदाबाद 15, 185, 200

आ

आचार्य कृपालानी 15

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 32

आजमगढ़ 201

आन्ध्र प्रदेश 24, 28, 120

आवयाशी 144

आर्य समाज 3, 68

आर्यावर्त XII

आर.एच. टोली 134

आशाम 161

आस्ट्रेलिया 210

इ

इंग्लैण्ड 34, 102, 109, 155, 169, 210, 211

इटली 2

इन्दुलाल याज्ञिक 23, 28, 81, 157

इनामदार 162

इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 174

इन्डियन नेशन XII

इस्ट इण्डिया कम्पनी 54

इस्लामिया आन्दोलन 70

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ई
ईसाई धर्म 3

उ
उपनाम 161
उद्योग पर्व 45
उत्तराधिकार कर 163

ऋ
ऋगवेद 45
ऋषिकेश 35

ए
ए.के. वागची 85
ए.एम. खुसरो II
एन.ए. सिमोनिया 86
एन.जी. रंगा 23, 81, 157
एज ऑफ कान्सेट बिल 50, 67
ए.एन. सिन्हा XII
एंजेल्स 102, 105, 117
एमोलिनबाटीन 55
एम.एल.ए. 198
एशिया 28, 210
एशियाई उत्पादन प्रणाली 92
ए. थार्नर 134

ओ
ओयकाता 156
ओंकारेश्वर 35

औ
औद्योगिक क्रान्ति 97, 109

अं
अंग्रेज 3, 59

क
कराधान नीति VIII
कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र 97, 100
कलकत्ते 30, 187
कल्याण 42
कानपुर XII, 29, 44, 150
कान्ट 36
कान कुब्ज ब्राह्मण 8, 52
कालीकट 34
काश्तकारी अधिनियम 21
काशी 35, 78, 182, 199
काश्मीर यात्रा 35
किशोरी प्रसन्न सिंह 26, 152, 157
किसान डिक्टेटरशिप 98
किसान संघ 164
कृष्ण सिंह 20, 21
कुरमी महासभा 68
कुरांव 123
कूका विद्राह 19
केन्द्रीय किसान कौंसिल 206, 207, 209
के.एफ. नारीमन 152
केन ग्रोवर्स कोओपरेटिव कान्फ्रेंस पटना 127, 193
केदारनाथ 35
केवट महासभा 68
केरल 73
के. दामोदरन 85
कोटवा नारायणपुर 184
कोम्मिल्ला 23, 24, 81, 156, 187

ख
खिलाफत आन्दोलन 14
खेत-मजदूर X
खेतिहर प्रोग्राम 111
खेरा किसान आन्दोलन 93
खोटा सिक्का 130

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ग

गया 21, 23, 24, 27, 64, 65, 81, 115
गाजीपुर XII, 1, 2, 3, 15, 45, 184, 199, 200
गायघाट 33
गांधी 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 35, 78, 80, 93, 94, 95, 112, 114, 119, 157, 184
गांधीवादी 96, 110, 115, 130, 157, 171, 185, 186
गांधी मैदान 202
ग्रामीण अर्थव्यवस्था 191
गिरिडीह 125
गीता 5
गुजरात VIII, 161
गोखले 66
गो रक्षा समिति 67
गोरखपुर 11, 42
गो हत्या 70
गोप महासभा 68
गौतम 45, 78
गंगा 182

घ

घाटे की बजट व्यवस्था 131
घाटे की वित्त व्यवस्था VIII, 196, 197

च

चम्पारण 14, 24
चमनलाल रेड्डी 84
चवनियां मेम्बर 117
चान्द मियां 70
चित्रकूट 182
चीन V, VII, 28, 29, 190, 210, 211, 213
चीनी क्रान्ति 190
चौरी-चौरा 80, 88

छ

छोटानागपुर 65, 156

ज

ज्योति कलश 44
जनवादी क्रान्ति 34
जनरल डायर 184
जर्मन मिशन 52
जर्मनी 11, 34, 211
जमशेदपुर 29, 251
जयपुर 4
जय प्रकाश नारायण 30
जलालबाद 199
जलाशय जीणोद्धार निधि 165
जहानाबाद 22
जलियावाला बाग 184
जवाहर रोजगार योजना VIII
जान स्ट्रेची 35
जापानी VII, 210
जीवननाथ मिश्र 11
जुझौतिया ब्राह्मण 52
जुकरों 155
जंगबहादुर राय 44

झ

झरिया 29, 125, 154
झारखंड के किसान IV, X, 40,121
झूमचास 124

ट

टण्डन जी 113
ट्रस्टीशिप 112
टयूडर 60
टाटा 122, 125, 197
ट्राटस्की 157
टी.एस. वेंकटरमण 128
टिकारी 60, 75, 114
टुटपुंजिए किसानों 112

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ड

डण्डाकल्ट 34, 132

डण्डावाद 132

डालमियां 197

डिकुश 40, 122

डिहरी 29, 151

डुमरांव 35

डुमरी 200

डेविड बारबर 55

डोमा सिंह 21

ढ

ढकाइच 179

त

तिलक 36, 50, 80

तुलसीदास 182

थ

थार्नर 61, 155

द

दयाकोब 84

दरभंगा 16, 22, 24, 78

दसबार 78

दादा भाई नौरोजी 56, 66, 84, 86

दानापुर 218

द्वारिका 18

द्वितीय विश्वयुद्ध 131, 166, 190, 192

दिल्ली 4, 17

दिसम्बर 7, 14

देवराज चतुर्वेदी 200

देशबन्धु 17, 55

देवाग्राम 199

दोनवार 78

न

नमक कानून 186

नर्मदा 35, 182

नरसिंहपुर 182

नरसंहार 195

नरहन 78

नरेन्द्र देव 24

नवयुग 44

नवरंग राय 3, 199

नागपुर 14, 15, 28, 79

नागपुर अधिवेशन 184, 215

नाई महासभा 68

नित्यानंद 11

नियामतपुर 187, 203

निरामक्कारी 19

नीलगिरि 19

नेताजी भवन 30

नेहरू 17, 23, 71, 81, 87, 130, 179

प

पटना XII, 14, 21, 24, 30, 42, 45, 175, 187, 200, 201, 218

पटेल 21, 22, 186

प्रथम विश्वयुद्ध 13, 17

प्रथम टेरिफ बोर्ड–129

प्रदीप XII

प्रयाग 11

परमानन्द शर्मा 44, 183

पलासा 23, 24, 81

पबाईगार 149

पशु बीमा 165

पश्चिम पटना किसान सभा 18, 20, 21

पहाड़िया 123

प्रशान्त महासागर 210

पंजाब III, 184

पंडागिरि 130

पंडौल 29

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पांतजलि 45
पाटन 182
प्रिंस ऑफ वेल्स 80
पी.सी. जोशी 82
पुरी 18
पुष्कर 182
पूंजीवादी क्रान्ति 104
पूर्णानन्द जी 7, 31, 190
पूर्णिया 24
पोंगापंथी 4
पोलेटारियन डिक्टेटरशिप 107

फ
फरवरी 1, 4
फागुन 1
फ्रान्स 34, 102
फारवर्ड ब्लाक 175
फासिस्ट फौजें 210
फासीवाद 189, 190
फिरोजशाह मेहता 80
फिलहाल 190
फैक्ट्री एक्ट 55
फैजपुर 23, 25, 37, 81, 113, 191
फैजाबाद 15, 16, 17

ब
ब्रह्मर्षि समाज XII
ब्रह्मपुर 70
बढहिया 29
बदरीनारायण 35
बनारस 11, 31, 33, 184
बम्बई 28, 34, 116, 150
बलदेव सहाय 24
बलिया 7, 183
बस्ती 11
बहुमत क्रान्ति 103
ब्रह्मोसमाज 68
बंगभंग 3, 69
बंगाल 28, 56, 57, 67, 73, 161, 120
बंधुआ मजदूर 111
बाबा सोहन सिंह 24, 211
बाम्बे न्यूज 56
बालिग मताधिकार–147
बारदौली 17, 22
बांगला देश 24
बॉकीपुर 16
बिड़ला 197
बिहार III, XI, 3, 12, 15, 17, 19, 64, 109, 120, 161
बिहार प्रदेश किसान सभा XI, 21, 194
बिहार प्रांतीय किसान सभा 113, 121, 152, 187
बिहार टेनेन्सी एक्ट 16
बिपिन चन्द्रा 84
बिरनों 1
बिहटा XI, 11, 12, 17, 29, 35, 57, 121, 151, 185
ब्रिटिश संसद 54
ब्रिटिश साम्राज्यवाद 10
ब्रिटेन 54, 64, 65, 169, 210
बी.एस. पाबगी 33
बी.टी. रणदिवे 83
बुग्गा 187
बुन्देलखण्ड 52
बुटवारिन 82, 98
बेतिया 60, 75, 78
बेनीराय 44

भ
भकना 24
भागलपुर 24
भारत V, 23
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी XII, 23, 29
भी.सी.पी. चौधरी 85

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भूमिहार ब्राह्मण महासभा 8, 9, 199, 201
भूमिहारों 7, 8, 12
भूमि बंधकी बैंक 163
भोगेन्द्र झा 45
भोजपुर 200

म
मखना 23, 81
मझियावा 27, 29, 65
मथुरा 35, 182
मनुस्मृति 46
मलाया 28
मद्रास 161
मद्रास मेल 56
मसौढ़ी 21
महाशिवरात्रि 1, 4, 50, 199, 201
महाधिकार पत्र 24
महाराष्ट्र 23, 34, 73
मई-दिवस 111, 153
मौर्य 26
मार्क्स 82, 92, 96, 97, 101, 102, 105, 117, 130
मार्क्सवाद 97, 101, 118, 188
मार्क्सवादी 110, 114
मारवाड़ी यंग मैन एसोशिएशन 68
माओ त्से तुंग 190
मालगुजार 162
मास्को 210
मिथिला 35
मिस्टर जिन्ना 126, 169
मृत्युकर 163
मुजफ्फरपुर 20, 24, 43, 44
मुजफ्फरहसन 157
मुंगेर 24, 53, 25
मुचकुन्द शर्मा 202
मुस्लिम लीग 69, 70
मुहम्मद जुबैर 94
मुद्रा नीति 163
मुद्रा स्फीति 131
मेरठ 8
मैक्समुलर 8
मैथिल ब्राह्मण 8, 11, 52
मैनचेस्टर 55
मोतीलाल नेहरु 17
मोपला 19, 34
मोहम्मद अली 17
मोहन लाल गौतम 23, 81
मौलाना मयहरुलहम 14
मौलाना आजाद 14, 184
मौलाना मुहम्मद सिराजी 69
मौटेक्यू 80
मोलासेस 130

य
यजुर्वेद 45
यमुना कार्यी 202
यज्ञोपवीत 199
याचक 8
युगेश्वर सिंह 200
यूरोप 63
यूरोपीय दर्शन 5

र
रजनी क्रांति शास्त्री 32
रजनी पाम दत्त 47
रबानी कहार सभा 68
राघवपुर 11
राघव दास 15
राजपूत सभा 68
राजघाट 31
राजा राधिका रमण सिंह 21
राजेन्द्र बाबू 16, 21, 25, 37
रामगढ़ 26, 157
रामचन्द्र शर्मा 218

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

रामवृक्ष बनीपुरी 20
राम विलास राय 44
रामकृष्ण पिल्लई 69
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण-II
रानाडे 56
राजनीतिक क्रान्ति 154
राहूल सांस्कृत्यायन 211
रूसी फौजें 209
रूस 102, 108, 211 213
रूसी समाजवादी क्रान्ति 190
रेवड़ा 217
रोलट एक्ट 184
रंगा 211

ल
लखनऊ 15, 22, 23
लखनऊ पैक्ट 69
लखिसराय 74
लतफुन्डिया 150
लट्ठ हमारा जिन्दाबाद 34, 132
लार्ड कार्नवालिस 57, 125
लार्ड कर्जन 55
लाल कृष्ण मिश्र 4
लाला लाजपत राय 72, 86
लाला हरदयाल 69
लेनिन IV, 82, 85, 96, 99, 102, 105, 106, 117, 146, 188
लेलिनग्राद 210
लैण्ड होल्डर्स एसोसिएशन 21, 68
लोक संग्रह 185
लौह पुरुष 22
लंकाशायर 55

व
वर्ग-संघर्ष 94
वस्तु विनिमय प्रणाली 127
वाल्टर हाउजर 136, 137, 177, 194
विजयवाड़ा 23, 24, 81, 111, 119, 150, 178, 201
विशाखापट्टनम 24, 187
वृद्धिशील आयकर 163
विनिमय 163
विश्वम्भरपुर 200
वैदिक धर्म 3

श
श्याम बिहारी राय 44
शहाबाद 19, 24, 30
शारदा कानून 165
शिवहर 78
शीलभ्रद याजी 26, 48 157
शैदपुरा 1
शंकर जी भट्टाचार्य 3, 11
शंकर गोत्र 32
शंकर नायर 202
शंकर राय देव 174
शंकराचार्य 6, 18
शोर्पन हाबर 36

स
सर्च लाईट XII
सनातन धर्म 3
समस्तीपुर 185
सम्पूर्णानन्द 15
सर्वहारा क्रान्ति 34, 104
सर गणेश दत्त सिंह 78, 185
समाजवादी दल 23
सच्चिदानन्द सिन्हा 21
साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन 60
सिमरी 19, 200
सिन्हा लाइब्रेरी XII
सारण 24
सादियाबाद 1

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सिंहानिया 197
सितम्बर 23
सीताराम आश्रम ग्, 11, 12, 19, 185, 202
सीतामढ़ी 21, 186
सुन्दर राय 44
सुभाष चन्द्र बोस 25, 26, 81, 152 157, 187, 188, 201, 215
सुरसंड 78
सुरेन्द्र नाथ वनर्जी 66
स्वास्थ्य बीमा 165
स्टेट मैन 56
स्पेन 210
सेल्स टैक्स 131
सोशलिस्ट पार्टी 30, 178
सोवियत रूस 81, 166
सोवियत फौजें 210
साम्यवाद 173
संघ शक्ति 109
संथाल विद्रोह 19
संयुक्त मोर्चा IX, 15

ह
हथुआ 60, 75
हथुआ महाराज 8
हजारी बाग 16, 26, 35, 36, 201
हजारी बाग सेन्ट्रल जेल 38
हरिजन दहन V
हरिनारायण जी 4, 11, 82
हरिद्वार 35, 199
हाथरस 182
हाब्स 36
हाजीपुर 21, 24, 187
हिन्दू धर्म 3, 18
हिटलर 82
हिमालय 82
हिन्दुस्तान 210
हीगेल 5
हीरक जयंती समारोह 201
हुनान 190
होमोजेनिटी 215
होरेन मुखर्जी 87
हुंकार 197

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

डॉ. दलीप कुमार : एक परिचय

पटना जिला के नौबतपुर थानान्तर्गत कोपाकलां गांव के एक संभ्रांत किसान-परिवार में 3 जनवरी' 1963 को जन्म। मालती धारी कॉलेज, नौबतपुर से अर्थशास्त्र ऑनर्स एवं मगध वि.वि. से प्रथम श्रेणी में एम.ए. पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में "स्वामी सहजानंद सरस्वती का सामाजिक-आर्थिक चिन्तन" विषय पर पी.एच.डी.। 1988 से 1995 तक मालतीधारी कॉलेज नौबतपुर में अध्यापन। 1995 से 1997 तक वि.वि. गिरि नेशनल लेबर इन्सिच्यूट नोयडा में शोध सहायक्। अगस्त' 1997 से पूरे एक वर्ष सिविलियन गज़टेड ऑफिसर के रूप में भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, के आर्मी कैडेट कॉलेज में अध्यापन। 16 अगस्त, 1998 से 16 अगस्त, 1999 तक इन्सिच्यूट फॉर ह्यूमैन डेवलॉपमेंट, नई दिल्ली में शोध-सहायक। 16 अगस्त 1999 से नेशनल कांउसिल ऑफ एप्लायड एकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली में कन्सल्टेंट के रूप में कार्यरत। इण्डियन एकोनॉमिक एसोशियेशन तथा इण्डियन सोसायटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की आजीवन सदस्यता। इण्डियन सोसायटी ऑफ लेबर एकोनॉमिक के त्रैमासिक जर्नल के सहायक प्रबंधक-संपादक। आपकी रूचि अध्ययन, अध्यापन, शोध के साथ संगीत एवं सामाजिकता में पूर्णतया सराही जाती है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्वामी सहजानन्द सरस्वती के शब्दों में

- फना के बाद हमसे बेकसों को कौन पूछेगा?
  मगर ए बेकसी रोया करेगी तू हमें बरसों,
  करेगी याद ये गम, तू हमें बाद-ए-फना बरसों।
  खिलाया है जिगर बरसों, पिलाया है लहू बरसों।।
- जो अन्न वस्त्र उपजायेगा, अब सो कानून बनायेगा।
  भारतवर्ष उसी का है, अब शासन वही चलायेगा।

हुंकार, वर्ष-9, अंक-7ए 16 जुलाई 1950

- क्रान्ति की आग भूखे पेट और नंगे तन से पैदा होती है। पेट की ज्वाला पेट और शरीर को जलाने के बाद संसार को जला कर ही दम लेती है।

किसान कैसे लड़ते हैं

- जुल्म और तबाही ऐसी पाठशालायें हैं, जो पीड़ितों को अपनी आंच में तपाकर पक्के बना देती है।

किसान कैसे लड़ते हैं

- जमींदारी एक ऐसी जोंक और ऐसी पिशायी है कि किसानों का रक्त बूंद-बूंद करके चूस लेती है और उन्हें मरणासन्न छोड़ देती है। जमींदारों के अम्ले प्लेग के कीटाणुओं की तरह जहां पहुंचे उसे उजाड़ छोड़ा, उनके नाम से किसानों का कलेजा कांपता है।

किसान कैसे लड़ते हैं

- हमारा बादशाह किसान-मजदूर है, जिसकी कमाई से बासमती, गेहूं, दूध, घी, चीनी-शक्कर, कपड़े और हमारे आराम की तमाम चीजें तैयार हो रही हैं। हमारा बादशाह दूसरा कौन? जिस बादशाह की कमाई हम खाते हैं, हम उसी की सरकार अपने मुल्क में चाहते हैं।

हुंकार, वर्ष-9, अंक-7, 16 जुलाई 1950

- मुनी लोग तो स्वामी बनके अपनी ही मुक्ति के लिए एकांतवास करते हैं। लेकिन मैं ऐसा हर्गिज नहीं कर सकता। सभी दुखियों को छोड़ मुझे सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं चाहिए। मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगा और मरूंगा-जिऊंगा।

मेरा जीवन संघर्ष

मानक
पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

जी. 19, तीसरा तल, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092
फोन: 245 3894 फैक्स: 241 8599
E-mail: manak _publications@hotmail.com

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.